



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30102024-258345
CG-DL-E-30102024-258345

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग 2 — अनुभाग 1क

PART II — Section 1A

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 3]
No. 3]

नई दिल्ली, गुरुवार, 30 मई, 2024/9 ज्येष्ठ, 1946 (शक)
NEW DELHI, THURSDAY, MAY 30, 2024/JYAISHTHA 9, 1946 (SAKA)

[खंड LX
[VOL. LX

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 30 मई, 2024/9 ज्येष्ठ, 1946 (शक)

दि नेशनल कमीशन फार हैम्योपैथी ऐक्ट, 2020; (2) दि नेशनल बैंक फार फाइनेंसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऐक्ट, 2021; (3) दि नेशनल इंस्टीट्यूट्स आफ फूड टेक्नोलोजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट ऐक्ट 2021; (4) दि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप (अमेंडमेंट) ऐक्ट 2021; (5) दि डेम सेफ्टी ऐक्ट 2021; (6) दि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, दि कोस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एंड दि कंपनी सेक्रेटरीज (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2022; (7) दि कांस्टिट्यूशन (शिड्यूल्ड कास्ट्स एंड शिड्यूल्ड ट्राइब्स) आर्डर्स (सेकेंड अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2022; (8) दि न्यू दिल्ली इन्टरनेशनल आर्बिट्रेशन सेन्टर (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2022; (9) दि कांस्टिट्यूशन (शिड्यूल्ड ट्राइब्स) आर्डर (सेकेंड अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2022; (10) दि कांस्टिट्यूशन (शिड्यूल्ड ट्राइब्स) आर्डर (फोर्थ अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2022; और (11) दि फाइनेंस ऐक्ट, 2023 के निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किए जाते हैं और ये राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन उनके हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझे जाएंगे :—

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, May 30, 2024/Jyaishtha 9, 1946 (Saka)

The Translation in Hindi of the following, namely:— The National Commission For Homoeopathy Act, 2020 (2) The National Bank For Financing Infrastructure And Development Act, 2021; (3) The National Institutes Of Food Technology, Entrepreneurship And Management Act, 2021; (4) The Limited Liability Partnership (Amendment) Act, 2021; (5) The Dam Safety Act, 2021; (6) The Chartered Accounts, the Cost and Works Accountants and the Company Secretaries (Amendment) Act, 2022; (7) The Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Second Amendment) Act, 2022; (8) The New Delhi International Arbitration Centre (Amendment) Act, 2022; (9) The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Second Amendment) Act, 2022; (10) The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Fourth Amendment) Act, 2022; and (11) The Finance Act, 2023 are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative texts thereof in Hindi under clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963):—

राष्ट्रीय हाम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्यांक 15)	537
The National Commission For Homoeopathy Act, 2020	
राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम संख्यांक 17)	571
The National Bank for Financing Infrastructure and Development Act, 2021	
राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम संख्यांक 19)	601
The National Institutes of Food Technology, Entrepreneurship and Management Act, 2021	
सीमित दायित्व भागीदारी (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम संख्यांक 31)	619
The Limited, Liability Partnership (Amendment) Act, 2021	
बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम संख्यांक 41)	635
The Dam Safety Act, 2021	
चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत और संकर्म लेखापाल और कंपनी सचिव (संशोधन) अधिनियम, 2022 (2022 का अधिनियम संख्यांक 12)	663
The Chartered Accountants, The Cost and Works Accountants and the Company Secretaries (Amendment) Act, 2022	
संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2022 (2022 का अधिनियम संख्यांक 20)	713
The Constitution (Scheduled Castes and Schedule Tribes) Orders (Second Amendment) Act, 2022	
नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थता केंद्र (संशोधन) अधिनियम, 2022 (2022 का अधिनियम संख्यांक 23)	717
The New Delhi International Arbitration Centre (Amendment) Act, 2022	
संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2022 (2023 का अधिनियम संख्यांक 1)	721
The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Second Amendment) Act, 2022	
संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (चौथा संशोधन) अधिनियम, 2022 (2023 का अधिनियम संख्यांक 2)	723
The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Fourth Amendment) Act, 2022	
वित्त अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 8)	725
The Finance Act, 2023	

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020

(2020 का अधिनियम संख्यांक 15)

[20 सितम्बर, 2020]

ऐसी चिकित्सा शिक्षा पद्धति के लिए, जो देश के सभी भागों में क्वालिटी और सस्ती आयुर्विज्ञान शिक्षा तक पहुंच बनाने में अभिवृद्धि करती है; जो पर्याप्त और उच्च क्वालिटी वाले होम्योपैथी चिकित्सा वृत्तिकों की उपलब्धता को सुनिश्चित करती है ; जो ऐसी साम्यापूर्ण और सार्वभौमिक स्वास्थ्य देख-रेख का संवर्धन करती है जिससे सामुदायिक स्वास्थ्य परिप्रेक्ष्य को बढ़ावा मिलता है और सभी नागरिकों के लिए होम्योपैथी चिकित्सा वृत्तिकों की सेवाओं को सुगम और वहन करने योग्य बनाती है; जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्बन्धी लक्ष्यों का संवर्धन करती है; होम्योपैथी चिकित्सा वृत्तिकों को उनके कार्य में नवीनतम चिकित्सा अनुसंधान को अंगीकृत करने और अनुसंधान में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करती है; जिसका उद्देश्य आयुर्विज्ञान संस्थाओं का आवधिक और पारदर्शी रूप से निर्धारण करना और भारत के लिए होम्योपैथी चिकित्सा रजिस्टर के रखरखाव को सुकर बनाना तथा चिकित्सीय सेवाओं के सभी पहलुओं में उच्च नैतिक मानकों को लागू करना है; जो परिवर्तनशील आवश्यकताओं को अंगीकार करने के लिए सुनम्य है और जिसमें एक प्रभावी शिकायत समाधान तंत्र सम्मिलित हो तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहतरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त
विस्तार
प्रारम्भ ।

नाम,
और

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 है ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे :

परंतु इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि यह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “स्वायत्त बोर्ड” से धारा 18 के अधीन गठित कोई स्वायत्त बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ख) “होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड” से धारा 18 के अधीन गठित बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ग) “अध्यक्ष” से धारा 5 के अधीन नियुक्त राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(घ) “आयोग” से धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अभिप्रेत है ;

(ङ) “परिषद्” से धारा 11 के अधीन गठित होम्योपैथी सलाहकार परिषद् अभिप्रेत है ;

(च) “होम्योपैथी” से होम्योपैथिक आयुर्विज्ञान प्रणाली अभिप्रेत है जिसके अन्तर्गत ऐसे जैव रसायन उपचार का उपयोग करना है जो ऐसे आधुनिक अभिदाय, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक विकास द्वारा अनुपूरित हैं जिन्हें आयोग, केन्द्रीय सरकार के परामर्श से समय-समय पर अधिसूचना द्वारा घोषित करे ;

(छ) “होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड” से धारा 18 के अधीन होम्योपैथी शिक्षा के लिए गठित बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ज) “अनुज्ञप्ति” से धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन मंजूर की गई होम्योपैथी का व्यवसाय करने के लिए अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है ;

(झ) “होम्योपैथी चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड” से धारा 18 के अधीन गठित चिकित्सा संस्थाओं का निर्धारण और रेटिंग बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ञ) “चिकित्सा संस्था” से भारत के भीतर या उसके बाहर की कोई ऐसी संस्था अभिप्रेत है जो होम्योपैथी में उपाधि, डिप्लोमा या अनुज्ञप्ति प्रदान करती है और इसके अंतर्गत सहबद्ध महाविद्यालय और मानित किए जाने वाले विश्वविद्यालय भी हैं ;

(ट) “सदस्य” से धारा 4 में निर्दिष्ट आयोग का कोई सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत उसका अध्यक्ष भी है ;

(ठ) “राष्ट्रीय रजिस्टर” से धारा 32 के अधीन होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड द्वारा अनुरक्षित राष्ट्रीय होम्योपैथी चिकित्सा रजिस्टर अभिप्रेत है;

(ड) “अधिसूचना” से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और “अधिसूचित करना” पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(ढ) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ण) “प्रधान” से धारा 20 के अधीन नियुक्त स्वायत्त बोर्ड का प्रधान अभिप्रेत है;

(त) “विनियम” से इस अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं ;

(थ) “राज्य चिकित्सा परिषद्” से किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन होम्योपैथी व्यवसायियों के व्यवसाय को विनियमित करने और उनका रजिस्ट्रीकरण करने के लिए गठित राज्य होम्योपैथी चिकित्सा परिषद् अभिप्रेत है ;

(द) “राज्य रजिस्टर” से होम्योपैथी व्यवसायियों का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अनुरक्षित राज्य होम्योपैथी रजिस्टर अभिप्रेत है ;

(ध) “विश्वविद्यालय” का वह अर्थ होगा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (च) में है और इसके अंतर्गत कोई स्वास्थ्य विश्वविद्यालय भी है ।

1956 का 3

अध्याय 2

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग

3. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के नाम से ज्ञात एक आयोग का गठन करेगी जो उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और उसको समनुदेशित कृत्यों का पालन करेगा ।

राष्ट्रीय होम्योपैथी
आयोग का
गठन ।

(2) आयोग, पूर्वोक्त नाम का एक निगमित निकाय होगा जिसके पास शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी और जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने तथा संविदा करने की शक्ति होगी और वह उक्त नाम से वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा ।

(3) आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा ।

4. (1) आयोग, निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

आयोग की
संरचना ।

(क) अध्यक्ष ;

(ख) सात पदेन सदस्य ; और

(ग) उन्नीस अंशकालिक सदस्य ।

(2) अध्यक्ष, उत्कृष्ट योग्यता, प्रमाणित प्रशासनिक क्षमता और सत्यनिष्ठा वाला ऐसा व्यक्ति होगा, जिसके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से होम्योपैथी में स्नातकोत्तर उपाधि हो और होम्योपैथी के क्षेत्र में कम से कम बीस वर्ष का अनुभव हो जिसमें से कम से कम दस वर्ष स्वास्थ्य देख-रेख परिदान, होम्योपैथी की उन्नति और विकास या उसकी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी के रूप में रहा हो ।

(3) निम्नलिखित व्यक्ति, केन्द्रीय सरकार द्वारा आयोग के पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाएंगे, अर्थात् :—

(क) होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड का प्रधान ;

(ख) होम्योपैथी चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड का प्रधान ;

(ग) होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड का प्रधान ;

(घ) आयुष मंत्रालय में सलाहकार (होम्योपैथी) या भारत सरकार का संयुक्त सचिव, जो होम्योपैथी का भारसाधक है ;

(ङ) निदेशक, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता ;

(च) निदेशक, पूर्वोत्तर आयुर्वेदिक और होम्योपैथी संस्थान, शिलांग ; और

(छ) महानिदेशक, केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद्, जनकपुरी, नई दिल्ली ।

(4) केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति आयोग के अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाएंगे, अर्थात् :—

(क) योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाले व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाने वाले ऐसे तीन सदस्य, जिनके पास होम्योपैथी, प्रबंध, विधि, स्वास्थ्य अनुसंधान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में विशेष ज्ञान और वृत्तिक अनुभव हों ;

(ख) सलाहकार परिषद् में राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के नामनिर्देशितियों में से चक्रानुक्रम आधार पर ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, दो वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाने वाले दस सदस्य ;

(ग) धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (घ) के अधीन राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के नामनिर्देशितियों में से ऐसी रीति में जो विहित की जाए, दो वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाने वाले सलाहकार परिषद् के छह सदस्य :

परंतु कोई सदस्य या तो स्वयं या अपने कुटुम्ब सदस्यों में से किसी सदस्य के माध्यम से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी प्राइवेट या गैर-सरकारी आयुर्विज्ञान संस्था, जो इस अधिनियम के अधीन विनियमित है, के प्रबंध निकाय का स्वामी नहीं होगा या उसके साथ सहबद्ध नहीं होगा या उसके साथ कोई संबंध नहीं रखेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा और धारा 19 के प्रयोजन के लिए “अग्रणी” पद से कोई विभागाध्यक्ष या किसी संगठन का प्रधान अभिप्रेत है ।

5. (1) केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित से मिलकर बनी खोजबीन समिति की सिफारिश पर धारा 4 में निर्दिष्ट अध्यक्ष और धारा 20 में निर्दिष्ट स्वायत्त बोर्डों के प्रधान की नियुक्ति करेगी,—

अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए खोजबीन समिति ।

(क) मंत्रिमंडल सचिव - अध्यक्ष ;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो विशेषज्ञ, जिनके पास होम्योपैथी के क्षेत्र में उत्कृष्ट अर्हताएं और कम से कम पच्चीस वर्ष का अनुभव हो - सदस्य ;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ग) में यथानिर्दिष्ट सदस्यों में से, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक विशेषज्ञ - सदस्य ;

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक ऐसा व्यक्ति, जो उत्कृष्ट अर्हताएं और स्वास्थ्य अनुसंधान, प्रबंध, विधि, अर्थशास्त्र या विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कम से कम पच्चीस वर्ष का अनुभव रखता हो - सदस्य ;

(ङ) आयुष का भारसाधक, भारत सरकार का सचिव, जो संयोजक होगा - सदस्य :

परन्तु धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (क) में निर्दिष्ट आयोग के अंशकालिक सदस्यों, धारा 8 में निर्दिष्ट सचिव और धारा 20 में निर्दिष्ट स्वायत्त बोर्डों के अन्य सदस्यों के चयन के लिए खोजबीन समिति खंड (ख) से खंड (घ) में विनिर्दिष्ट सदस्यों और संयोजक-सदस्य के रूप में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के संयुक्त सचिव से मिलकर बनेगी तथा इसकी अध्यक्षता भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के भारसाधक सचिव द्वारा की जाएगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार, किसी रिक्ति के होने, जिसके अन्तर्गत, अध्यक्ष या किसी सदस्य की मृत्यु, पदत्याग या हटाए जाने के कारण हुई रिक्ति भी है, की तारीख से एक मास के भीतर या अध्यक्ष अथवा सदस्य की अवधि की समाप्ति से पूर्व तीन मास के भीतर रिक्ति को भरने के लिए खोजबीन समिति को निर्देश करेगी ।

(3) खोजबीन समिति, उसको निर्दिष्ट प्रत्येक रिक्ति के लिए कम से कम तीन नामों के एक पैनल की सिफारिश करेगी ।

(4) आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति की सिफारिश करने से पूर्व, खोजबीन समिति स्वयं का यह समाधान करेगी कि ऐसा व्यक्ति कोई वितीय या अन्य हित तो नहीं रखता है, जिससे ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ।

(5) अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति केवल खोजबीन समिति के किसी सदस्य की किसी रिक्ति या अनुपस्थिति के कारण अविधिमान्य नहीं होगी ।

(6) उपधारा (2) से उपधारा (5) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, खोजबीन समिति अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित कर सकेगी ।

6. (1) अध्यक्ष और सदस्य (पदेन सदस्यों से भिन्न) तथा धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ख) के अधीन नियुक्त सदस्य चार वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और वे किसी विस्तार या पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे :

अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें ।

परंतु ऐसा व्यक्ति सत्तर वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा।

(2) किसी पदेन सदस्य की पदावधि तब तक बनी रहेगी, जब तक वह उस आधार पर, जिसका वह ऐसा सदस्य है, पद धारण करता है।

(3) जहां पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य, आयोग के तीन क्रमवर्ती साधारण बैठकों में अनुपस्थित रहता है और उसकी ऐसी अनुपस्थिति का कारण आयोग की राय में कोई विधिमान्य कारण नहीं माना जा सकता वहां ऐसे सदस्य के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अपना स्थान रिक्त कर दिया है।

(4) अध्यक्ष और किसी पदेन सदस्य से भिन्न सदस्य को संदेय वेतन तथा भत्ते और उसकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं।

(5) अध्यक्ष या कोई सदस्य—

(क) केन्द्रीय सरकार को कम से कम तीन मास की लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकेगा ; या

(ख) धारा 7 के उपबंधों के अनुसार उसे पद से हटाया जा सकेगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार ऐसा विनिश्चय करती है तो ऐसा व्यक्ति तीन मास से पहले कर्तव्यों से मुक्त किया जा सकेगा या तीन मास से आगे जब तक कोई उत्तरवर्ती नियुक्त नहीं हो जाता है, बने रहने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(6) आयोग का अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य अपना पद ग्रहण करते समय और अपना पद छोड़ते समय अपनी आस्तियों तथा दायित्वों की घोषणा करेगा और अपनी वृत्तिक तथा वाणिज्यिक वचनबंध या अन्तर्गस्तता को भी ऐसे प्ररूप और रीति में घोषित करेगा जो विहित की जाए और ऐसी घोषणा आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।

(7) अध्यक्ष या कोई सदस्य, उस रूप में पद धारण करने से प्रविरत हो जाने पर, ऐसे पद को त्यागने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए किसी भी हैसियत में, जिसके अन्तर्गत कोई परामर्शी या कोई विशेषज्ञ भी है, किसी प्राइवेट होम्योपैथी चिकित्सा संस्था में या जिसका मामला ऐसे अध्यक्ष या सदस्य द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः निपटाया गया है, कोई नियोजन स्वीकार नहीं करेगा:

परंतु इसमें अंतर्विष्ट किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसे व्यक्ति को केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या अनुरक्षित किसी निकाय या संस्था, जिसके अन्तर्गत होम्योपैथी चिकित्सा संस्था भी है, में कोई नियोजन स्वीकार करने से निवारित करती है।

(8) उपधारा (7) में की कोई बात, केन्द्रीय सरकार को अध्यक्ष या किसी सदस्य को किसी ऐसे प्राइवेट होम्योपैथी चिकित्सा संस्था में किसी भी हैसियत में, जिसके अन्तर्गत कोई परामर्शदाता या विशेषज्ञ भी है, जिसका मामला ऐसे अध्यक्ष या सदस्य द्वारा निपटाया गया है, में कोई नियोजन स्वीकार करने से निवारित नहीं करेगी।

7. (1) केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को पद से हटा सकेगी—

(क) जिसे दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है ; या

(ख) जिसे ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त है ;

(ग) जो अध्यक्ष या सदस्य के रूप में शारीरिक या मानसिक रूप से कार्य करने में असमर्थ हो गया है; या

(घ) जो विकृतचित्त का है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसी घोषणा विद्यमान है; या

(ङ) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(च) जिसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है जिसके कारण उसका पद पर बने रहना लोक हित के प्रतिकूल है ।

(2) किसी सदस्य को उपधारा (1) के खंड (ङ) और खंड (च) के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे मामले में सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान न कर दिया गया हो ।

8. (1) आयोग का एक सचिवालय होगा जिसका प्रधान सचिव होगा, जिसकी नियुक्ति धारा 5 के उपबंधों के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी ।

आयोग के सचिव, विशेषज्ञों, वृत्तिकों, अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति ।

(2) आयोग का सचिव प्रमाणित प्रशासनिक योग्यता और सत्यनिष्ठा वाला ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास ऐसी अर्हताएं और अनुभव हो, जो विहित किया जाए ।

(3) सचिव, केन्द्रीय सरकार द्वारा चार वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा और वह किसी विस्तार या पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

(4) सचिव, आयोग के ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो आयोग द्वारा उसे समनुदेशित किए जाएं और जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(5) आयोग, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा सृजित पदों पर ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे ।

(6) आयोग के सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन तथा भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं ।

(7) आयोग, विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, उतनी संख्या में, जितनी वह आवश्यक समझे, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में आयोग की सहायता करने के लिए सत्यनिष्ठा और उत्कृष्ट योग्यता वाले ऐसे विशेषज्ञों और वृत्तिकों को नियुक्त कर सकेगा, जो होम्योपैथी का विशेष ज्ञान तथा होम्योपैथी, लोक स्वास्थ्य, प्रबंध, अर्थशास्त्र, प्रत्यायन, रोगी परामर्शी सेवा, स्वास्थ्य अनुसंधान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, प्रशासन, वित्त, लेखा या विधि में अनुभव रखते हैं ।

9. (1) आयोग, प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगा जो अध्यक्ष द्वारा नियत किया जाए ।

आयोग की बैठकें ।

(2) अध्यक्ष, आयोग की बैठक की अध्यक्षता करेगा और यदि किसी कारण से अध्यक्ष, आयोग की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है तो अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट ऐसा कोई सदस्य, जो किसी स्वायत्त बोर्ड का प्रधान है, बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

(3) जब तक आयोग की बैठकों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, विनियमों द्वारा अन्यथा उपबंधित नहीं कर दी जाती है तब तक आयोग के सदस्यों की कुल संख्या के आधा, जिसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है, से गणपूर्ति होगी और आयोग के सभी विनिश्चय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किए जाएंगे तथा मतों के बराबर होने की दशा में, अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपधारा (2) के अधीन नामनिर्दिष्ट स्वायत्त बोर्ड के प्रधान का निर्णायक मत होगा ।

(4) आयोग के प्रशासन का साधारण अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण अध्यक्ष में निहित होगा ।

(5) आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि—

(क) आयोग में कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि है ; या

(ख) अध्यक्ष के रूप में या सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है ।

(6) ऐसा कोई व्यक्ति, जो धारा 30 की उपधारा (4) के अधीन दिए गए विनिश्चय के सिवाय, आयोग के किसी विनिश्चय से व्यथित है, वह ऐसे विनिश्चय की संसूचना के पंद्रह दिन के भीतर ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार को अपील कर सकेगा ।

आयोग की शक्ति
और कृत्य ।

10. (1) आयोग निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :—

(क) होम्योपैथी की शिक्षा में उच्च गुणवत्ता और उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए नीतियां अधिकथित करना और इस निमित्त आवश्यक विनियम बनाना ;

(ख) आयुर्विज्ञान संस्थाओं, चिकित्सा अनुसंधानों और चिकित्सा वृत्तियों को विनियमित करने के लिए नीतियां अधिकथित करना और इस निमित्त आवश्यक विनियम बनाना ;

(ग) स्वास्थ्य देख-रेख में अपेक्षाओं, जिनके अंतर्गत स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन और स्वास्थ्य संबंधी देख-रेख अवसंरचना भी हैं, का निर्धारण करना; और ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कार्य योजना विकसित करना ;

(घ) ऐसे विनियम बनाकर जो आयोग, स्वायत्त बोर्डों और राज्य होम्योपैथी चिकित्सा परिषदों के उचित कार्यकरण के लिए आवश्यक हों, मार्गदर्शक सिद्धांत विरचित करना और नीतियां अधिकथित करना ;

(ङ) स्वायत्त बोर्डों के बीच समन्वय को सुनिश्चित करना ;

(च) ऐसे उपाय करना, जो इस अधिनियम के अधीन उनके प्रभावी कार्यकरण के लिए इस अधिनियम के अधीन विरचित मार्गदर्शक सिद्धांतों और बनाए गए विनियमों का राज्य होम्योपैथी चिकित्सा परिषदों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों ;

(छ) स्वायत्त बोर्डों के विनिश्चयों के संबंध में अपीली अधिकारिता का प्रयोग करना ;

(ज) चिकित्सा व्यवसाय में वृत्तिक नैतिकता का पालन सुनिश्चित करने और चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा देख-रेख की व्यवस्था के दौरान नैतिक आचरण का संवर्धन करने के लिए विनियम बनाना ;

(झ) ऐसे प्राइवेट आयुर्विज्ञान संस्थाओं और मानित विश्वविद्यालयों में के, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन शासित होते हैं, पचास प्रतिशत स्थानों के संबंध में फीस और अन्य सभी प्रभारों को अवधारित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत विरचित करना ;

(ज) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो विहित किए जाएं ।

(2) आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय सचिव के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे तथा आयोग, सचिव को प्रशासनिक और वित्तीय विषयों पर अपनी ऐसी शक्तियों को प्रत्यायोजित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

(3) आयोग उपसमितियों का गठन कर सकेगा और उनको अपनी उन शक्तियों को प्रत्यायोजित कर सकेगा, जो विनिर्दिष्ट कार्यों को पूरा किए जाने हेतु उन्हें समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों ।

अध्याय 3

होम्योपैथी सलाहकार परिषद्

11. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा होम्योपैथी सलाहकार परिषद् नामक एक सलाहकार निकाय का गठन करेगी ।

होम्योपैथी
सलाहकार परिषद्
का गठन और
संरचना ।

(2) परिषद्, एक अध्यक्ष और निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

(क) आयोग का अध्यक्ष परिषद् का पदेन अध्यक्ष होगा;

(ख) आयोग का प्रत्येक सदस्य परिषद् का पदेन सदस्य होगा;

(ग) प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य, जो उस राज्य में किसी विश्वविद्यालय का कुलपति हो, जिसके पास होम्योपैथी में अर्हताएं हों, जिसे उस राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए और प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य, जो उस संघ राज्यक्षेत्र में के किसी विश्वविद्यालय का कुलपति हो, जिसके पास होम्योपैथी में अर्हताएं हों, जिसे भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए :

परंतु जहां होम्योपैथी में अर्हताएं रखने वाला कुलपति उपलब्ध नहीं है, वहां होम्योपैथी में अर्हताएं रखने वाला कोई संकायाध्यक्ष या संकाय के प्रधान को नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ;

(घ) राज्य होम्योपैथी चिकित्सा परिषद् के निर्वाचित सदस्यों में प्रत्येक राज्य और प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक ऐसा सदस्य, जिसे उस राज्य की चिकित्सा परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए ;

(ङ) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ;

(च) निदेशक, राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद् ;

(छ) चार सदस्य, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय प्रबंध संस्थानों और भारतीय विज्ञान संस्थान में निदेशक के पद धारण करने वाले व्यक्तियों में से केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएं ;

(ज) परिषद् में गैर-पदेन सदस्यों की पदावधि चार वर्ष की होगी ।

होम्योपैथी
सलाहकार परिषद् के
कृत्य ।

12. (1) परिषद्, ऐसा प्राथमिक मंच होगा जिसके माध्यम से राज्य और संघ राज्यक्षेत्र आयोग के समक्ष अपने विचार तथा सरोकार रख सकेंगे और जो होम्योपैथी की चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास से संबंधित समग्र कार्यसूची, नीति और कार्रवाई को तैयार करने में सहायक हो सके ।

(2) परिषद्, आयोग को ऐसे उपायों के बारे में सलाह देगी जो चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास संबंधी सभी मामलों में न्यूनतम मानकों का अवधारण करने तथा उनको बनाए रखने और उनके रखरखाव का समन्वय करने से संबंधित हो ।

(3) परिषद्, आयोग को चिकित्सा शिक्षा तक साम्यापूर्ण पहुंच की वृद्धि करने के उपायों पर सलाह देगी ।

होम्योपैथी
सलाहकार परिषद्
की बैठकें ।

13. (1) परिषद्, वर्ष में कम से कम दो बार ऐसे समय तथा स्थान पर बैठक करेगी जो अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाए ।

(2) अध्यक्ष, परिषद् की बैठक की अध्यक्षता करेगा और यदि किसी कारण से अध्यक्ष, परिषद् की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है तो अध्यक्ष द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट ऐसा अन्य सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

(3) जब तक कि विनियमों द्वारा प्रक्रिया अन्यथा उपबंधित न की जाए, तब तक अध्यक्ष सहित परिषद् के आधे सदस्यों से गणपूर्ति होगी और परिषद् के सभी कार्य उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे ।

अध्याय 4

राष्ट्रीय परीक्षा

राष्ट्रीय पात्रता-सह-
प्रवेश परीक्षा ।

14. (1) इस अधिनियम के अधीन शासित सभी आयुर्विज्ञान संस्थाओं में होम्योपैथी की स्नातकपूर्व में प्रवेश के लिए एक समान राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा होगी ।

(2) आयोग, ऐसे अभिहित प्राधिकारी के माध्यम से और ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा अंग्रेजी और ऐसी अन्य भाषाओं में संचालित करेगा ।

(3) आयोग विनियमों द्वारा, इस अधिनियम के अधीन शासित सभी आयुर्विज्ञान संस्थाओं में प्रवेश के लिए अभिहित प्राधिकारी द्वारा सामान्य काउंसेलिंग संचालित करने की रीति विनिर्दिष्ट करेगा :

परन्तु सामान्य काउंसेलिंग—

(i) अखिल भारतीय स्थानों के लिए केन्द्रीय सरकार ; और

(ii) राज्य स्तर पर शेष स्थानों के लिए राज्य सरकार ,

के अभिहित प्राधिकारी द्वारा संचालित होगी ।

15. (1) राष्ट्रीय निकास परीक्षा के नाम से ज्ञात सामान्य अंतिम वर्ष स्नातकपूर्व चिकित्सा परीक्षा का आयोजन होम्योपैथी के चिकित्सा व्यवसायी के रूप में व्यवसाय करने हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए और यथास्थिति, राज्य रजिस्टर या राष्ट्रीय रजिस्टर में नामांकन के लिए किया जाएगा ।

राष्ट्रीय निकास परीक्षा ।

(2) आयोग, ऐसे अभिहित प्राधिकारी के माध्यम से और ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अंग्रेजी और ऐसी अन्य भाषाओं में होम्योपैथी के लिए राष्ट्रीय निकास परीक्षा संचालित करेगा ।

(3) राष्ट्रीय निकास परीक्षा उस तारीख से, जिसको यह अधिनियम प्रवृत्त होता है, तीन वर्ष के भीतर ऐसी तारीख से जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे, प्रवर्तनशील होगी ।

(4) विदेशी चिकित्सा अर्हता रखने वाले किसी व्यक्ति को होम्योपैथी के चिकित्सा व्यवसायी के रूप में होम्योपैथी व्यवसाय करने के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु और यथास्थिति, राज्य रजिस्टर या राष्ट्रीय रजिस्टर में नामांकन के लिए राष्ट्रीय निकास परीक्षा, ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अर्हित करना होगा ।

16. (1) इस अधिनियम के अधीन शासित सभी आयुर्विज्ञान संस्थाओं में होम्योपैथी के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक समान स्नातकोत्तर राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा संचालित की जाएगी ।

स्नातकोत्तर राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा ।

(2) आयोग, ऐसे अभिहित प्राधिकारी के माध्यम से और ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अंग्रेजी और ऐसी अन्य भाषाओं में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा संचालित करेगा ।

(3) आयोग, विनियमों द्वारा इस अधिनियम के अधीन शासित सभी आयुर्विज्ञान संस्थाओं में स्नातकोत्तर सीटों के लिए प्रवेश हेतु अभिहित प्राधिकारी द्वारा सामान्य काउंसेलिंग संचालित करने की रीति विनिर्दिष्ट करेगा ।

17. (1) राष्ट्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा होम्योपैथी के उन स्नातकोत्तरों के लिए पृथक्कृतः संचालित की जाएगी जो उस विधाशाखा में अध्यापन व्यवसाय अपनाने की वांछा रखते हैं ।

होम्योपैथी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा ।

(2) आयोग ऐसे अभिहित प्राधिकारी के माध्यम से और ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, राष्ट्रीय होम्योपैथी अध्यापक पात्रता परीक्षा संचालित करेगा ।

(3) राष्ट्रीय होम्योपैथी अध्यापक पात्रता परीक्षा उस तारीख से, जिसको यह अधिनियम प्रवृत्त होता है, तीन वर्ष के भीतर ऐसी तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, प्रवर्तनशील होगी :

परन्तु इस धारा की कोई बात, उपधारा (3) के अधीन अधिसूचित तारीख से पूर्व नियुक्त अध्यापकों को लागू नहीं होगी ।

अध्याय 5

स्वायत्त बोर्ड

18. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा आयोग के समग्र पर्यवेक्षण के अधीन, निम्नलिखित स्वायत्त बोर्डों का, इस अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्डों को समनुदेशित

स्वायत्त बोर्ड का गठन ।

कृत्यों का पालन करने के लिए गठन करेगी, अर्थात्:—

- (क) होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड ;
- (ख) होम्योपैथी चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड ; और
- (ग) होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक बोर्ड, एक स्वायत्त निकाय होगा जो आयोग द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का पालन करेगा ।

स्वायत्त बोर्डों की संरचना ।

19. (1) स्वायत्त बोर्डों की संरचना निम्नानुसार होगी, अर्थात्:—

(क) होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड, होम्योपैथी की विधाशाखा से एक प्रधान और चार सदस्यों से मिलकर बनेगा ;

(ख) होम्योपैथी चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड होम्योपैथी की विधाशाखा से एक अध्यक्ष और दो सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनमें से एक सदस्य होम्योपैथी की विधाशाखा से होगा और दूसरा सदस्य प्रत्यायन विशेषज्ञ होगा ;

(ग) होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड, होम्योपैथी की विधाशाखा से एक अध्यक्ष और दो सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनमें से एक सदस्य होम्योपैथी की विधाशाखा से होगा और दूसरा सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा, जो चिकित्सा आचार पर कार्य के लोक अभिलेख का प्रदर्शन कर चुका है या गुणवत्ता आश्वासन, लोक स्वास्थ्य, विधि या रोगी पक्ष समर्थन में से किसी विधाशाखा से चुना गया हो ।

(2) उपधारा (1) के अधीन चुने जाने वाले स्वायत्त बोर्ड के प्रधान और सदस्य उत्कृष्ट योग्यता, प्रमाणित प्रशासनिक क्षमता और सत्यनिष्ठा वाले व्यक्ति होंगे, जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विधाशाखाओं में स्नातकोत्तर उपाधि हो और जो संबंधित क्षेत्रों में कम से कम पंद्रह वर्ष का अनुभव रखते हों जिनमें से कम से कम सात वर्ष अग्रणी के रूप में रहे हों:

परन्तु होम्योपैथी के प्रधान और सदस्य की दशा में, अग्रणी के रूप में सात वर्ष होम्योपैथी में स्वास्थ्य, उन्नति और शिक्षा के विकास के क्षेत्र में रहे हों ।

प्रधान और सदस्यों की नियुक्ति के लिए खोजबीन समिति ।

20. केन्द्रीय सरकार, धारा 5 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार तदधीन गठित खोजबीन समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर स्वायत्त बोर्डों के प्रधान और सदस्यों की नियुक्ति करेगी ।

प्रधान और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें ।

21. (1) प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड का प्रधान और सदस्य चार वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए पदधारण करेंगे और किसी विस्तार या पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे:

परन्तु ऐसा व्यक्ति सत्तर वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा।

(2) स्वायत्त बोर्ड के प्रधान और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं ।

(3) आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों से

संबंधित धारा 6 की उपधारा (3), उपधारा (5), उपधारा (6), उपधारा (7) और उपधारा (8) और उनके पद से हटाए जाने से संबंधित धारा 7 में अन्तर्विष्ट उपबंध, स्वायत्त बोर्डों के प्रधान और सदस्यों को भी लागू होंगे ।

22. (1) होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड के सिवाय प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड की सहायता विशेषज्ञों की ऐसी सलाहकार समितियों द्वारा की जाएगी जो इस अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्डों के कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए आयोग द्वारा गठित की जाएं ।

विशेषज्ञों की सलाहकार समिति ।

(2) होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड की सहायता विशेषज्ञों की ऐसी नैतिक समितियों द्वारा की जाएगी जो इस अधिनियम के अधीन उस बोर्ड के कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए गठित की जाएं ।

23. धारा 8 के अधीन नियुक्त विशेषज्ञों, वृत्तिकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को स्वायत्त बोर्डों को, उतनी संख्या में और ऐसी रीति में उपलब्ध कराया जाएगा जो आयोग द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

स्वायत्त बोर्डों के कर्मचारिवृन्द ।

24. (1) प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड मास में कम से कम एक बार ऐसे समय और स्थान पर, जो वह नियत करे, बैठक करेगा ।

स्वायत्त बोर्डों की बैठकें ।

(2) ऐसे विनियमों के अधीन रहते हुए, जो इस निमित्त बनाए जाएं, स्वायत्त बोर्डों के सभी विनिश्चय सर्वसम्मति से किए जाएंगे और यदि सर्वसम्मति संभव नहीं है तो विनिश्चय, प्रधान और सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा ।

(3) ऐसा कोई व्यक्ति, जो स्वायत्त बोर्ड के किसी विनिश्चय से व्यथित है, ऐसे विनिश्चय की संसूचना के तीस दिन के भीतर ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध आयोग को अपील कर सकेगा ।

25. (1) आयोग, प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड के प्रधान को निर्विघ्न और दक्षतापूर्ण कार्य करने के लिए ऐसे बोर्ड को समर्थ बनाने के लिए अपनी सभी या किन्हीं प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन कर सकेगा ।

शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

(2) किसी स्वायत्त बोर्ड का प्रधान उस बोर्ड के किसी सदस्य या अधिकारी को अपनी शक्तियों में से किसी शक्ति का और प्रत्यायोजन कर सकेगा ।

26. (1) होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड निम्नलिखित कार्य करेगा, अर्थात्:—

होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ।

(क) स्नातकपूर्व, स्नातकोत्तर और अति विशिष्ट स्तरों पर शिक्षा के मानकों का अवधारण करना और उनसे संबंधित सभी पहलुओं का पर्यवेक्षण करना ;

(ख) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार सभी स्तरों पर होम्योपैथी के लिए सक्षमता आधारित गत्यात्मक पाठ्यक्रम को ऐसी रीति में विकसित करना जो स्नातकोत्तर और अति विशिष्ट छात्रों में समुचित कौशल, ज्ञान, दृष्टिकोण, मूल्यों और नैतिकता को विकसित करता है और उन्हें स्वास्थ्य देख-रेख उपलब्ध कराने, चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने तथा चिकित्सा अनुसंधान करने में समर्थ बनाता है ;

(ग) देश की आवश्यकताओं, वैश्विक सन्नियमों और इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों को ध्यान में रखते हुए, होम्योपैथी में स्नातकपूर्व,

स्नातकोत्तर और अतिविशिष्ट पाठ्यक्रमों को प्रदान करने वाली आयुर्विज्ञान संस्थाओं की स्थापना करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त विरचित करना ;

(घ) स्थानीय स्तरों पर सृजनात्मक आवश्यकताओं और इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों को ध्यान में रखते हुए, आयुर्विज्ञान संस्थाओं में पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं को संचालित करने के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं और मानकों को अवधारित करना ;

(ङ) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार, होम्योपैथी आयुर्विज्ञान संस्थाओं में शिक्षा और अनुसंधान की अवसंरचना, संकाय और क्वालिटी के लिए मानकों और सन्नियमों का अवधारण करना ;

(च) होम्योपैथी आयुर्विज्ञान संस्थाओं द्वारा अपने ऐसे कृत्यों के संबंध में, जो विभिन्न पणधारियों, जिनमें छात्र, संकाय, आयोग और सरकार भी हैं, के हित से संबंधित हैं, इलैक्ट्रानिक रूप से और अन्यथा अनिवार्य वार्षिक प्रकटन के लिए सन्नियम विनिर्दिष्ट करना ;

(छ) संकाय सदस्यों के विकास और प्रशिक्षण को सुकर बनाना;

(ज) अनुसंधान कार्यक्रम को सुकर बनाना ;

(झ) सभी स्तरों पर होम्योपैथी चिकित्सा अर्हताओं को मान्यता प्रदान करना ।

(2) होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड, अपने कृत्यों के निर्वहन में, आयोग को ऐसी सिफारिशें कर सकेगा और ऐसे निदेश की मांग कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे ।

होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ।

27. (1) होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्:—

(क) धारा 32 के उपबंधों के अनुसार, होम्योपैथी के सभी अनुज्ञप्त व्यवसायियों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर रखना ;

(ख) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार, वृत्तिक आचरण को विनियमित करना और चिकित्सीय नैतिकता का संवर्धन करना ;

परन्तु होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड, उस दशा में जहां ऐसी राज्य चिकित्सा परिषद् को संबंधित राज्य अधिनियमों के अधीन चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा वृत्तिक या नैतिक कदाचार की बाबत अनुशासनिक कार्रवाई करने की शक्ति प्रदत्त की गई है, वहां राज्य चिकित्सा परिषद् के माध्यम से वृत्तिक और नैतिक आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करेगा ;

(ग) होम्योपैथी चिकित्सा व्यवसायियों के आचरण को प्रभावी रूप से अभिवृद्धि करने और विनियमित करने के लिए राज्य होम्योपैथी चिकित्सा परिषद् के साथ निरन्तर संपर्क बनाए रखने के लिए तंत्र विकसित करना ;

(घ) धारा 31 के अधीन किसी राज्य चिकित्सा परिषद् के द्वारा की गई

कार्रवाई के संबंध में अपीलीय अधिकारिता का प्रयोग करना ।

(2) होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड अपने कृत्यों के निर्वहन में, आयोग को ऐसी सिफारिशें कर सकेगा और उससे ऐसे निदेशों की मांग कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे ।

28. (1) होम्योपैथी चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्:—

होम्योपैथी
चिकित्सा निर्धारण
और रेटिंग बोर्ड
की शक्तियां और
कृत्य ।

(क) इस अधिनियम के अधीन बनाए विनियमों के अनुसार, आयुर्विज्ञान संस्थाओं के निर्धारण और रेटिंग की प्रक्रिया का होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा अधिकथित मानकों का उनके अनुपालन के आधार पर अवधारण करना ;

(ख) धारा 29 के उपबंधों के अनुसार, नई आयुर्विज्ञान संस्था की स्थापना करने या किसी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को प्रारंभ करने या स्थानों की संख्या को बढ़ाने के लिए अनुज्ञा प्रदान करना ;

(ग) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार, ऐसी संस्थाओं के निर्धारण और रेटिंग के लिए आयुर्विज्ञान संस्थाओं का निरीक्षण करना :

परन्तु होम्योपैथी चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड, यदि यह आवश्यक समझे, तो ऐसी संस्थाओं के निर्धारण और रेटिंग के लिए आयुर्विज्ञान संस्थाओं का निरीक्षण करने हेतु किसी अन्य तृतीय पक्षकार अभिकरण या व्यक्तियों को किराए पर ले सकेगा और उन्हें प्राधिकृत कर सकेगा :

परन्तु यह और कि जहां आयुर्विज्ञान संस्थाओं का निरीक्षण होम्योपैथी चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड द्वारा प्राधिकृत ऐसे तृतीय पक्षकार अभिकरण या व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, वहां ऐसी संस्थाओं के लिए बाध्यकारी होगा कि वे ऐसे अभिकरण या व्यक्ति तक पहुंच का उपबंध करें ;

(घ) ऐसी सभी आयुर्विज्ञान संस्थाओं को उनके खुलने की ऐसी अवधि के भीतर और उसके पश्चात् प्रत्येक वर्ष ऐसे समय पर और रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, संचालित करने, उनका निर्धारण करने तथा उनका रेट करने के लिए स्वतंत्र रेटिंग अभिकरणों को संचालित करना या जहां यह आवश्यक समझे, उन्हें पैनलीकृत करना ;

(ङ) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार, आयुर्विज्ञान संस्थाओं के निर्धारण और रेटिंग को नियमित अन्तरालों पर अपनी वेबसाइट पर या लोकाधिकारी क्षेत्र में उपलब्ध कराना ;

(च) किसी आयुर्विज्ञान संस्था के विरुद्ध, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड के द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानकों को बनाए रखने में उसकी असफलता के लिए ऐसे उपाय करना, जिनके अन्तर्गत चेतावनी जारी करना, धनीय शास्ति का अधिरोपण करना, प्रवेश के अन्तर्ग्रहण या ठहराव को कम करना और आयोग को मान्यता की वापसी के

लिए सिफारिश करना भी है ।

(2) होम्योपैथी चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड, अपने कृत्यों के निर्वहन में, आयोग को ऐसी सिफारिशें कर सकेगा और उससे ऐसे निदेशों की मांग कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे ।

नई आयुर्विज्ञान
संस्था स्थापित
करने के लिए
अनुज्ञा ।

29. (1) कोई व्यक्ति होम्योपैथी चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किए बिना कोई नई आयुर्विज्ञान संस्था की स्थापना नहीं करेगा या कोई स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ नहीं करेगा या स्थानों की संख्या नहीं बढ़ाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, “व्यक्ति” पद के अन्तर्गत कोई विश्वविद्यालय या कोई न्यास या कोई अन्य निकाय भी है किन्तु इसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार नहीं है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए, कोई व्यक्ति होम्योपैथी चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड को एक स्कीम, ऐसी विशिष्टियों को अन्तर्विष्ट करते हुए, ऐसे प्ररूप में, ऐसी फीस के साथ और ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, प्रस्तुत कर सकेगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन प्राप्त स्कीम पर विचार करते समय, होम्योपैथी चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड शिक्षा और अनुसंधान मानकों, अवसंरचना और संकाय संबंधी मानकों और सन्नियमों, आयुर्विज्ञान संस्थाओं की स्थापना करने संबंधी मार्गदर्शक सिद्धान्तों और होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा अवधारित अन्य अपेक्षाओं को ध्यान में रखेगा और ऐसी स्कीम की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर स्कीम का अनुमोदन या अननुमोदन करने वाला कोई आदेश पारित करेगा :

परंतु ऐसी स्कीम को अननुमोदित करने से पहले, संबंधित व्यक्ति को त्रुटियों का, यदि कोई हो, सुधार करने के लिए अवसर प्रदान करेगा ।

(4) जहां, उपधारा (3) के अधीन कोई स्कीम अनुमोदित की जाती है, वहां ऐसा अनुमोदन नई आयुर्विज्ञान संस्था स्थापित करने के लिए उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा होगी ।

(5) जहां, कोई स्कीम उपधारा (3) के अधीन अननुमोदित की जाती है या जहां उपधारा (2) के अधीन किसी स्कीम को प्रस्तुत करने के तीन मास के भीतर कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है, वहां संबंधित व्यक्ति, आयोग को, यथास्थिति, ऐसे अननुमोदन के पंद्रह दिन के भीतर या तीन मास बीत जाने के पश्चात्, ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, अपील कर सकेगा ।

(6) जहां, आयोग ने स्कीम का अननुमोदन कर दिया है या उपधारा (5) के अधीन अपील करने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर कोई आदेश पारित नहीं किया है, वहां संबंधित व्यक्ति, केन्द्रीय सरकार को यथास्थिति, ऐसे अननुमोदन की संसूचना के सात दिन के भीतर या पंद्रह दिन की विनिर्दिष्ट अवधि बीत जाने पर दूसरी अपील कर सकेगा ।

(7) होम्योपैथी चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड किसी पूर्व सूचना के बिना किसी

भी समय या तो सीधे या किसी अन्य विशेषज्ञ के माध्यम से, जिसे चिकित्सा वृत्ति में सत्यनिष्ठा और अनुभव हो, किसी विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था का मूल्यांकन और निर्धारण कर सकेगा तथा ऐसे विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था के निष्पादन, मानकों और निर्देश चिह्नों का निर्धारण और मूल्यांकन कर सकेगा ।

30. धारा 29 के अधीन किसी स्कीम का अनुमोदन या अननुमोदन करते समय, यथास्थिति, होम्योपैथी चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड या आयोग निम्नलिखित मानदंडों पर विचार करेगा, अर्थात्:—

स्कीम का अनुमोदन या अननुमोदन करने के लिए मानदंड ।

(क) अवसंरचना और वित्तीय संसाधनों की पर्याप्तता ;

(ख) क्या पर्याप्त शैक्षणिक संकाय, अध्यापनेतर कर्मचारिवृंद और ऐसी अन्य आवश्यक सुविधाओं का आयुर्विज्ञान संस्था के समुचित कार्यकरण को सुनिश्चित करने हेतु उपबंध किया गया है या स्कीम में विनिर्दिष्ट समयसीमा के भीतर उपबंध कर दिया जाएगा ;

(ग) क्या पर्याप्त चिकित्सालय सुविधाएं प्रदान की गई हैं या स्कीम में विनिर्दिष्ट समयसीमा के भीतर प्रदान कर दिया जाएगा ;

(घ) ऐसे अन्य कारक, जो विहित किए जाएं :

परन्तु केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के अधीन रहते हुए, ऐसी आयुर्विज्ञान संस्थाओं के लिए जो ऐसे क्षेत्रों में स्थापित हैं, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, मानदंडों को शिथिल किया जा सकेगा ।

31. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष के भीतर, यदि किसी राज्य में कोई राज्य होम्योपैथी चिकित्सा परिषद् विद्यमान नहीं है तो वह उस राज्य में ऐसी परिषद् की स्थापना करेगी ।

राज्य चिकित्सा परिषद् ।

(2) जहां कोई राज्य अधिनियम, राज्य चिकित्सा परिषद् को, होम्योपैथी के किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी के किसी वृत्तिक या नैतिक कदाचार के संबंध में अनुशासनिक कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान करता है, वहां राज्य चिकित्सा परिषद् इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों और विरचित मार्गदर्शक-सिद्धान्तों के अनुसार कार्य करेगी :

परन्तु उस समय तक, जब तक कि किसी राज्य में राज्य होम्योपैथी चिकित्सा परिषद् की स्थापना नहीं हो जाती है, होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड, उस राज्य में ऐसी प्रक्रिया के अनुसार जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, उस राज्य में होम्योपैथी के रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी के किसी वृत्तिक या नैतिक कदाचार से संबंधित परिवादों और शिकायतों को प्राप्त करेगा :

परन्तु यह और कि यथास्थिति, होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड या राज्य चिकित्सा परिषद् ऐसे किसी व्यवसायी को, कोई आदेश पारित करने या कोई कार्रवाई करने से पूर्व, जिसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध धनीय शास्ति अधिरोपित किया जाना भी है, सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा ।

(3) कोई होम्योपैथी व्यवसायी, जो निम्नलिखित द्वारा पारित किसी आदेश या की गई कार्रवाई से व्यथित है—

(क) उपधारा (2) के अधीन राज्य चिकित्सा परिषद्, होम्योपैथी नैतिक और

रजिस्ट्रीकरण बोर्ड के समक्ष अपील कर सकेगा और उस पर होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड का विनिश्चय, यदि कोई हो, ऐसी राज्य चिकित्सा परिषद् पर तब तक आबद्धकर होगा, जब तक कि उपधारा (4) के अधीन दूसरी अपील फाइल नहीं कर दी जाती है ;

(ख) होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड उपधारा (2) के पहले परंतुक के अधीन आयोग को अपील कर सकेगा ।

(4) ऐसा कोई होम्योपैथी चिकित्सा व्यवसायी, जो होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड के विनिश्चय से व्यथित है, ऐसे विनिश्चय की संसूचना के साठ दिन के भीतर आयोग को अपील कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “राज्य” के अंतर्गत कोई संघ राज्यक्षेत्र भी है और किसी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में “राज्य सरकार” और “राज्य होम्योपैथी चिकित्सा परिषद्” पदों से क्रमशः “केन्द्रीय सरकार” और “होम्योपैथी संघ राज्यक्षेत्र चिकित्सा परिषद्” अभिप्रेत है;

(ख) “वृत्तिक या नैतिक कदाचार” पद के अंतर्गत ऐसे किसी कार्य को करना या उसका लोप भी है, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

होम्योपैथी का
राष्ट्रीय रजिस्टर
और राज्य
रजिस्टर ।

32. (1) होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड एक राष्ट्रीय रजिस्टर रखेगा, जिसमें होम्योपैथी के किसी अनुज्ञप्त चिकित्सा व्यवसायी का नाम, पता और उसके द्वारा धारण की जाने वाली सभी मान्यताप्राप्त अर्हताएं और ऐसी अन्य विशिष्टियां होंगी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(2) राष्ट्रीय रजिस्टर ऐसे प्ररूप में, जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक प्ररूप भी है, और ऐसी रीति में रखा जाएगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(3) राष्ट्रीय रजिस्टर में किसी नाम या अर्हता को जोड़े जाने या उससे हटाए जाने की रीति और उसके हटाए जाने के आधार वे होंगे, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(4) राष्ट्रीय रजिस्टर, होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड की वेबसाइट पर डालकर जनसाधारण को उपलब्ध कराया जाएगा ।

(5) प्रत्येक राज्य चिकित्सा परिषद्, विनिर्दिष्ट इलैक्ट्रानिक रूपविधान में एक राज्य रजिस्टर रखेगी तथा उसे नियमित रूप से अद्यतन करेगी और उसकी एक प्रति इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन मास के भीतर होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड को प्रदाय करेगी ।

(6) होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि राष्ट्रीय रजिस्टर और राज्य रजिस्टर ऐसी रीति में इलैक्ट्रानिक रूप से समसामयिक रहे कि ऐसे किसी एक रजिस्टर में कोई परिवर्तन स्वतः ही अन्य रजिस्टर में प्रतिबिंबित हो ।

राष्ट्रीय रजिस्टर में
नामांकित किए जाने
वाले व्यक्तियों के
अधिकार और इस
संबंध में उनकी
बाध्यताएं ।

33. (1) ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसके पास इस अधिनियम के अधीन होम्योपैथी में कोई मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता है और जो धारा 15 के अधीन आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय निकास परीक्षा में अर्हता प्राप्त करता है, उसे होम्योपैथी में व्यवसाय करने की अनुज्ञप्ति होगी और उसके नाम तथा अर्हताओं को, यथास्थिति, राष्ट्रीय रजिस्टर या किसी राज्य रजिस्टर में नामांकित किया जाएगा :

1973 का 59

परंतु ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसे इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व और धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन राष्ट्रीय निकास परीक्षा प्रचालित होने से पहले होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 के अधीन रखे गए होम्योपैथी के केन्द्रीय रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत किया गया है, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया समझा जाएगा और उसे इस अधिनियम के अधीन प्रथमतः अनुरक्षित राज्य रजिस्टर में और तत्पश्चात् राष्ट्रीय रजिस्टर में नामांकित किया जाएगा ।

(2) ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसने भारत से बाहर के किसी देश में स्थापित आयुर्विज्ञान संस्था से होम्योपैथी में कोई अर्हता अभिप्राप्त की है और जो उस देश में होम्योपैथी के चिकित्सा व्यवसायी के रूप में मान्यताप्राप्त है, इस अधिनियम के प्रारंभ तथा धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन होम्योपैथी की राष्ट्रीय निकास परीक्षा के प्रचालन में आने के पश्चात् होम्योपैथी के राष्ट्रीय रजिस्टर में तब तक नामांकित नहीं किया जाएगा, जब तक वह होम्योपैथी की राष्ट्रीय निकास परीक्षा अर्हित नहीं कर लेता है ।

(3) जब ऐसा कोई व्यक्ति, जिसका नाम, यथास्थिति, राज्य रजिस्टर या राष्ट्रीय रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाता है, कोई उपाधि, डिप्लोमा, विज्ञान या चिकित्सा में प्रवीणता संबंधी ऐसी कोई अर्हता अभिप्राप्त करता है जो, यथास्थिति, धारा 34 या धारा 35 के अधीन एक मान्यताप्राप्त अर्हता है, तो वह, ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी उपाधि, डिप्लोमा या अर्हता को राज्य रजिस्टर या राष्ट्रीय रजिस्टर में अपने नाम के सामने प्रविष्ट किए जाने का हकदार होगा ।

34. (1) यथास्थिति, राज्य रजिस्टर या राष्ट्रीय रजिस्टर में नामांकित व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति,—

व्यक्तियों का व्यवसाय करने का अधिकार ।

(क) एक अर्हित व्यवसायी के रूप में होम्योपैथी में व्यवसाय करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ;

(ख) चिकित्सक या शल्य चिकित्सक के रूप में कोई पद या ऐसा कोई अन्य पद, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, धारण नहीं करेगा, जिसे, यथास्थिति, चिकित्सक या शल्य चिकित्सक द्वारा धारित किया जाना है ;

(ग) सम्यक् रूप से किसी अर्हित चिकित्सा व्यवसायी द्वारा हस्ताक्षरित या अधिप्रमाणित किए जाने के लिए, किसी विधि द्वारा अपेक्षित है, किसी चिकित्सा या आरोग्य प्रमाणपत्र या किसी अन्य ऐसे प्रमाणपत्र पर, हस्ताक्षर करने या उसे अधिप्रमाणित करने का हकदार नहीं होगा ;

1872 का 1

(घ) किसी मृत्यु-समीक्षा में या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 45 के अधीन विशेषज्ञ के रूप में होम्योपैथी से संबंधित किसी विषय पर किसी न्यायालय में साक्ष्य देने का हकदार नहीं होगा :

परंतु आयोग ऐसे व्यवसायियों की एक सूची, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा :

परंतु यह और कि ऐसे किसी विदेशी नागरिक को, जो अपने देश में, उस देश में ऐसे व्यवसायियों के रजिस्ट्रीकरण को विनियमित करने वाली विधि के अनुसार होम्योपैथी में व्यवसायी के रूप में नामांकित है, उसे भारत में ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अस्थायी रजिस्ट्रीकरण अनुज्ञात किया जा सकेगा ।

(2) ऐसे किसी व्यक्ति को, जो इस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में कोई कार्य करता है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

(3) उपधारा (2) की कोई बात निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगी कि,—

(क) किसी राज्य रजिस्टर में होम्योपैथी के व्यवसायी के रूप में नामांकित किसी व्यक्ति के किसी भी राज्य में व्यवसाय करने के अधिकार को, केवल इस आधार पर प्रभावित नहीं करेगी कि उसके पास इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को होम्योपैथी में मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता नहीं है ;

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति के, जो किसी राज्य में कम से कम पांच वर्ष से होम्योपैथी में व्यवसाय कर रहा है, उस राज्य में व्यवसाय जारी रखने के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी, जिसमें इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को होम्योपैथी का राज्य रजिस्टर अनुरक्षित नहीं किया जाता है ।

अध्याय 6

होम्योपैथी की अर्हताओं को मान्यता

भारत में
विश्वविद्यालयों या
आयुर्विज्ञान
संस्थाओं द्वारा
अनुदत्त अर्हताओं को
मान्यता ।

35. (1) भारत में किसी विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था द्वारा होम्योपैथी में स्नातकपूर्व या स्नातकोत्तर या अति विशिष्ट स्तर पर प्रदान की गई चिकित्सा अर्हताओं को होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, सूचीबद्ध और अनुरक्षित किया जाएगा तथा ऐसी चिकित्सा अर्हता इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त अर्हता होगी ।

(2) भारत का कोई ऐसा विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था, जो होम्योपैथी में स्नातकपूर्व या स्नातकोत्तर या अति विशिष्ट अर्हता प्रदान करता है, किंतु उसे होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा अनुरक्षित सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है, वह ऐसी अर्हता को मान्यता प्रदान करने के लिए उस बोर्ड को आवेदन कर सकेगा ।

(3) होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड, मान्यता प्रदान करने के लिए किसी आवेदन की, छह मास की अवधि के भीतर ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, परीक्षा करेगा ।

(4) जहां, होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड, मान्यता प्रदान करने का विनिश्चय करता है, वहां, वह ऐसी अर्हता को उसके द्वारा अनुरक्षित सूची में सम्मिलित करेगा और ऐसी मान्यता को प्रभावी करने की तारीख भी विनिर्दिष्ट करेगा, अन्यथा वह मान्यता प्रदान न करने के अपने विनिश्चय की संसूचना संबद्ध विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था को देगा ।

(5) व्यथित विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था, होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड के विनिश्चय की संसूचना की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, आयोग को अपील कर सकेगी ।

(6) आयोग, उपधारा (5) के अधीन प्राप्त अपील की दो मास की अवधि के भीतर परीक्षा करेगा और यदि यह विनिश्चय करता है कि ऐसी चिकित्सा अर्हता को मान्यता प्रदान की जा सकेगी तो वह संबद्ध बोर्ड को, ऐसी अर्हता को उस बोर्ड द्वारा अनुरक्षित सूची में ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, सम्मिलित करने का निदेश दे सकेगा ।

(7) जहां आयोग उपधारा (6) के अधीन मान्यता प्रदान न करने का विनिश्चय करता है या विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर विनिश्चय करने में असफल रहता है, वहां व्यथित विश्वविद्यालय या संबंधित आयुर्विज्ञान संस्था, यथास्थिति, ऐसे विनिश्चय की संसूचना की तारीख से या विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार को दूसरी अपील कर सकेगा ।

(8) ऐसी सभी चिकित्सा अर्हताओं को, जिन्हें इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्व मान्यता प्रदान की गई है और जिन्हें होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा भी ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, उसे सूचीबद्ध और अनुरक्षित किया जाएगा ।

36. (1) जहां भारत से बाहर किसी देश में कोई प्राधिकरण, जिसे उस देश की विधि द्वारा, उस देश में होम्योपैथी की अर्हताओं की मान्यता का कार्य सौंपा गया है, भारत में ऐसी अर्हता को मान्यता प्रदान करने हेतु आयोग को कोई आवेदन करता है, वहां आयोग, ऐसे सत्यापन के अधीन रहते हुए, जिसे वह आवश्यक समझे, उस चिकित्सा अर्हता को मान्यता प्रदान कर सकेगा या मान्यता प्रदान करने से इंकार कर सकेगा ।

भारत के बाहर आयुर्विज्ञान संस्थाओं द्वारा अनुदत्त चिकित्सा अर्हताओं की मान्यता ।

(2) जहां आयोग, उपधारा (1) के अधीन किसी चिकित्सा अर्हता को मान्यता प्रदान करता है, वहां ऐसी अर्हता, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त अर्हता होगी और उसे ऐसी रीति में, जो विनिर्दिष्ट की जाए, आयोग द्वारा अनुरक्षित सूची में सम्मिलित किया जाएगा :

परंतु उस दशा में, जहां आयोग किसी अर्हता को मान्यता प्रदान न करने का विनिश्चय करता है, वहां आयोग ऐसी मान्यता को प्रदान करने से इंकार करने से पूर्व उस प्राधिकरण को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा ।

(3) जहां आयोग, उपधारा (2) के अधीन किसी चिकित्सा अर्हता को मान्यता प्रदान करने से इंकार करता है, वहां संबद्ध प्राधिकरण मान्यता प्रदान किए जाने के लिए केन्द्रीय सरकार को अपील कर सकेगा ।

(4) ऐसी सभी अर्हताएं, जिन्हें इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्व मान्यता प्रदान की गई है और जिन्हें होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 की तीसरी अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भी मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हताएं होंगी और उन्हें आयोग द्वारा ऐसी रीति में, जो

विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, सूचीबद्ध और अनुरक्षित किया जाएगा ।

अर्हता की मान्यता
वापस लेना या
मान्यता समाप्त
करना ।

37. (1) जहां आयोग को, होम्योपैथी चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड से कोई रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अन्यथा यह प्रतीत होता है कि—

(क) किसी विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था द्वारा चलाए जा रहे अध्ययन पाठ्यक्रम और परीक्षा या उसके द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में अभ्यर्थियों से अपेक्षित प्रवीणता, होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप नहीं है; या

(ख) होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा यथा अवधारित आयुर्विज्ञान संस्थाओं में अवसंरचना, संकाय और शिक्षा की गुणवत्ता के लिए मानकों और सन्नियमों का किसी विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था द्वारा अनुपालन नहीं किया जाता है और ऐसा विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था विनिर्दिष्ट न्यूनतम मानकों को बनाए रखने हेतु आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने में असफल रही है,

वहां आयोग, उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई आरम्भ कर सकेगा :

परंतु आयोग स्वप्रेरणा से किसी विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था द्वारा प्रदान की गई चिकित्सा अर्हता को अनुदत्त मान्यता वापस लेने की कार्रवाई करने से पूर्व धारा 28 की उपधारा (1) के खंड (च) के उपबंधों के अनुसार शास्ति अधिरोपित करेगा ।

(2) आयोग, ऐसी और जांच करने के पश्चात्, जिसे वह ठीक समझे, और राज्य सरकार तथा संबद्ध विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था के प्राधिकारी से परामर्श करने के पश्चात्, इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि किसी चिकित्सा अर्हता को अनुदत्त की गई मान्यता को वापस लिया जाना चाहिए, तो वह आदेश द्वारा, ऐसी चिकित्सा अर्हता को अनुदत्त की गई मान्यता को वापस ले सकेगा और होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड को यह निदेश दे सकेगा कि वह उस बोर्ड द्वारा अनुरक्षित सूची में संबद्ध विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था के सामने की प्रविष्टियों में इस प्रभाव का संशोधन करे कि ऐसी अर्हता को अनुदत्त की गई मान्यता, उस आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से वापस ली जाती है ।

(3) यदि आयोग की, भारत से बाहर किसी देश के प्राधिकरण से सत्यापन के पश्चात्, यह राय है कि कोई मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता की, जिसे उसके द्वारा अनुरक्षित सूची में सम्मिलित किया गया है, मान्यता को समाप्त किया जाना है, वहां वह आदेश द्वारा, ऐसी चिकित्सा अर्हता की मान्यता को समाप्त कर सकेगा और उसे ऐसे आदेश की तारीख से आयोग द्वारा अनुरक्षित सूची से हटा सकेगा ।

कतिपय दशाओं में
अर्हताओं की
मान्यता के लिए
विशेष उपबंध ।

38. जहां आयोग ऐसा करना आवश्यक समझता है, तो वह अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगा कि भारत से बाहर किसी आयुर्विज्ञान संस्था द्वारा प्रदान की गई होम्योपैथी में कोई अर्हता, ऐसी तारीख के पश्चात्, जिसे उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त अर्हता होगी :

परंतु ऐसी अर्हता रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा चिकित्सा व्यवसाय को केवल तभी अनुज्ञात किया जाएगा यदि ऐसे व्यक्ति को उस देश में तत्समय प्रवृत्त चिकित्सा

व्यवसायी के रजिस्ट्रीकरण को विनियमित करने वाली विधि के अनुसार किसी चिकित्सा व्यवसायी के रूप में नामांकित किया गया है :

परंतु यह और कि ऐसी अर्हता रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा चिकित्सा व्यवसाय ऐसी अवधि के लिए सीमित होगा, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए :

परंतु यह भी कि ऐसी अर्हता रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा चिकित्सा व्यवसाय को केवल तभी अनुज्ञात किया जाएगा यदि ऐसा व्यक्ति राष्ट्रीय निकास परीक्षा अर्हित करता है ।

अध्याय 7

अनुदान, संपरीक्षा और लेखा

39. केन्द्रीय सरकार, इस निमित्त संसद् की विधि द्वारा सम्यक् विनियोग के पश्चात्, आयोग को ऐसी धनराशि का अनुदान कर सकेगी, जो केन्द्रीय सरकार ठीक समझे । केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान ।

40. (1) “होम्योपैथी राष्ट्रीय आयोग निधि” नामक एक निधि का गठन किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा— होम्योपैथी राष्ट्रीय आयोग निधि ।

(क) आयोग और स्वायत्त बोर्डों द्वारा प्राप्त सभी सरकारी अनुदान, फीस, शास्तियां और प्रभार ;

(ख) आयोग द्वारा ऐसे अन्य स्रोत से, जो उसके द्वारा विनिश्चित किया जाए, प्राप्त सभी धन राशियां ।

(2) इस निधि को निम्नलिखित के मददे संदाय करने के लिए उपयोजित किया जाएगा—

(क) आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों, स्वायत्त बोर्डों के प्रधान और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्तों तथा प्रशासनिक व्ययों, जिनके अंतर्गत आयोग तथा स्वायत्त बोर्डों के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते भी हैं ;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए उपगत व्ययों या उपगत होने वाले व्ययों, जिसके अंतर्गत आयोग और स्वायत्त बोर्डों के कृत्यों के निर्वहन से जुड़े व्यय भी हैं ।

41. (1) आयोग, उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और ऐसे प्ररूप में, जो भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित किया जाए, लेखाओं का एक वार्षिक विवरण तैयार करेगा । संपरीक्षा और लेखा ।

(2) आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, की जाएगी और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय, आयोग द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को संदेय होगा ।

(3) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक और आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किन्हीं अन्य व्यक्तियों को उस संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे, जो सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में साधारणतया, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के होते हैं और विशिष्ट रूप से अभिलेखों, पुस्तकों, लेखाओं, संबद्ध वाउचरों तथा अन्य दस्तावेजों और कागज-पत्र पेश किए जाने की मांग करने और उस तक पूर्ण पहुंच बनाने तथा आयोग के कार्यालयों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित आयोग के लेखे, उस पर संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ आयोग द्वारा वार्षिक रूप से केन्द्रीय सरकार को भेजे जाएंगे, जिन्हें प्राप्त करने के पश्चात् वह उसे यथासंभव शीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

विवरणियों और रिपोर्टों का केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किया जाना।

42. (1) आयोग, केन्द्रीय सरकार को ऐसे समय पर, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए या जैसा केन्द्रीय सरकार निदेश दे, ऐसी रिपोर्टों और विवरणियों तथा आयोग की अधिकारिता के अधीन किसी विषय से संबंधित ऐसी विशिष्टियां को, जिनकी केन्द्रीय सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे, प्रस्तुत करेगा।

(2) आयोग, प्रत्येक वर्ष में एक बार, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का एक संक्षिप्त विवरण देते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उस रिपोर्ट की प्रतियां केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित की जाएंगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट की एक प्रति केन्द्रीय सरकार द्वारा उसकी प्राप्ति के पश्चात्, यथासंभव शीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

अध्याय 8

प्रकीर्ण

केन्द्रीय सरकार की आयोग और स्वायत्त बोर्डों को निदेश देने की शक्ति।

43. (1) इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आयोग और स्वायत्त बोर्ड, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में और कृत्यों के निर्वहन में, नीति के प्रश्नों पर ऐसे निदेशों से आबद्ध होंगे, जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर उन्हें लिखित में दे :

परंतु आयोग और स्वायत्त बोर्डों को, यथासाध्य, इस उपधारा के अधीन कोई निदेश दिए जाने से पूर्व अपने विचार अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

(2) क्या कोई प्रश्न नीति का है या नहीं, केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

केन्द्रीय सरकार की राज्य सरकारों को निदेश देने की शक्ति।

44. केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के सभी या किन्हीं उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए किसी राज्य सरकार को ऐसे निदेश दे सकेगी, जिन्हें वह आवश्यक समझे और राज्य सरकार ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगी।

आयोग द्वारा दी जाने वाली जानकारी और उसका

45. (1) आयोग, केन्द्रीय सरकार को ऐसी रिपोर्ट, अपने कार्यवृत्त की प्रतियां, अपने लेखाओं का सार और अन्य जानकारी देगा, जिसकी वह सरकार अपेक्षा करे।

प्रकाशन ।

(2) केन्द्रीय सरकार, ऐसी रीति में, जो वह ठीक समझे, उपधारा (1) के अधीन उसे दी गई रिपोर्ट, कार्यवृत्तों, लेखाओं का सार और अन्य जानकारी को प्रकाशित कर सकेगी ।

46. इस अधिनियम के अधीन आने वाला प्रत्येक विश्वविद्यालय और आयुर्विज्ञान संस्था हर समय एक वेबसाइट अनुरक्षित करेगी और अपनी वेबसाइट पर ऐसी सभी सूचनाएं प्रदर्शित करेगी, जो यथास्थिति, आयोग और किसी स्वायत्त बोर्ड द्वारा अपेक्षित हो ।

विश्वविद्यालयों और आयुर्विज्ञान संस्थाओं की बाध्यताएं ।

47. (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कोई छात्र, जो इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पूर्व किसी आयुर्विज्ञान संस्था में किसी डिग्री या डिप्लोमा के लिए अध्ययन कर रहा था, वैसे ही अध्ययन करता रहेगा और ऐसी डिग्री या डिप्लोमा के लिए अपने पाठ्यक्रम को पूरा करेगा तथा ऐसी संस्था, ऐसे प्रारंभ से पूर्व यथा विद्यमान पाठ्यचर्या और अध्ययन के अनुसार, ऐसे छात्र के लिए अनुदेश उपलब्ध कराती रहेगी तथा परीक्षाओं का आयोजन कराती रहेगी और ऐसे छात्र के बारे में यह माना जाएगा कि उसने इस अधिनियम के अधीन अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर लिया है तथा उसे इस अधिनियम के अधीन डिग्री या डिप्लोमा प्रदान की जाएगी ।

आयुर्विज्ञान संस्थाओं में पाठ्यक्रमों का पूरा किया जाना ।

(2) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी आयुर्विज्ञान संस्था को प्रदान की गई मान्यता व्यपगत हो गई है, चाहे यह समय के बीत जाने के कारण हुआ हो या स्वेच्छया अभ्यर्पण के कारण या किसी अन्य कारण से हुआ हो, वहां ऐसी आयुर्विज्ञान संस्था उस समय तक, जब तक कि ऐसे सभी अभ्यर्थी उस संस्था में अपने अध्ययन को पूरा करने में समर्थ नहीं हो जाते हैं, आयोग द्वारा यथा अनुमोदित न्यूनतम मानकों को बनाए रखेगी और उसका उपबंध करेगी ।

48. आयोग का अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और अन्य कर्मचारी तथा स्वायत्त बोर्डों के प्रधान और सदस्यों के बारे में, जब वे इस अधिनियम के किसी भी उपबंध के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या कार्य का किया जाना तात्पर्यित हो, तो उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा ।

आयोग, स्वायत्त बोर्डों के अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों का लोक सेवक होना ।

49. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही सरकार, आयोग या किसी स्वायत्त बोर्ड या किसी राज्य चिकित्सा परिषद् या उसकी किसी समिति या इस अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले सरकार या आयोग के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण ।

50. कोई न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान, यथास्थिति, आयोग या होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड या राज्य चिकित्सा परिषद् द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा की गई लिखित शिकायत के सिवाय नहीं करेगा ।

अपराधों का संज्ञान ।

51. (1) यदि किसी भी समय केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि—

केन्द्रीय सरकार की आयोग को अधिकृत करने की शक्ति ।

(क) आयोग, इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित कृत्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है ; या

(ख) आयोग ने, इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किसी निदेश के अनुपालन में या इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में बारबार व्यतिक्रम किया है,

तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, आयोग को छह मास से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए अधिक्रांत कर सकेगी, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए :

परंतु इस उपधारा के अधीन कोई अधिसूचना जारी करने से पूर्व केन्द्रीय सरकार, आयोग को इस बात का कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगी कि उसे अधिक्रांत क्यों न कर दिया जाए और आयोग द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों और आक्षेपों पर, यदि कोई हों, विचार करेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन आयोग को अधिक्रांत करने वाली किसी अधिसूचना के प्रकाशन पर,—

(क) सभी सदस्य अधिक्रमण किए जाने की तारीख से अपना पद उसी रूप में रिक्त कर देंगे ;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या इसके अधीन आयोग द्वारा या उसके निमित्त प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियों या निर्वहन किए जाने वाले कृत्यों और कर्तव्यों का, उपधारा (3) के अधीन आयोग का पुनर्गठन किए जाने तक ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसा केन्द्रीय सरकार निदेश दे, प्रयोग और निर्वहन किया जाएगा ;

(ग) आयोग के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन सभी संपत्ति, उपधारा (3) के अधीन आयोग का पुनर्गठन किए जाने तक केन्द्रीय सरकार में निहित होंगी ।

(3) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अतिष्ठिति काल के अवसान पर,—

(क) अतिष्ठिति काल को, छह मास से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तारित कर सकेगी, जो वह आवश्यक समझे ; या

(ख) नई नियुक्ति द्वारा आयोग का पुनर्गठन कर सकेगी और ऐसी दशा में ऐसे सदस्य, जिन्होंने उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन अपने पद रिक्त किए थे, नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं समझे जाएंगे :

परंतु केन्द्रीय सरकार, अतिष्ठिति काल, चाहे वह अवधि मूल रूप से उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट की गई हो या इस उपधारा के अधीन यथाविस्तारित अवधि हो, के अवसान से पूर्व, किसी भी समय, इस उपधारा के खंड (ख) के अधीन कार्रवाई कर सकेगी।

(4) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन एक अधिसूचना जारी करेगी और इस धारा के अधीन की गई किसी कार्रवाई और ऐसी कार्रवाई को किए जाने वाली परिस्थितियों से संबंधित एक पूरी रिपोर्ट को सर्वप्रथम अवसर पर संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी ।

आयोग, राष्ट्रीय
भारतीय चिकित्सा
पद्धति आयोग और
राष्ट्रीय चिकित्सा
आयोग की संयुक्त

52. (1) होम्योपैथी भारतीय चिकित्सा पद्धति और आधुनिक आयुर्विज्ञान पद्धति के बीच इंटरफेश का संवर्धन करने के लिए वर्ष में कम से कम एक बार, ऐसे समय और स्थान पर, जो परस्पर नियत किया जाए, आयोग, राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति

बैठकें ।

आयोग और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की संयुक्त बैठक की जाएगी ।

(2) संयुक्त बैठक की कार्यसूची संबद्ध आयोगों के अध्यक्षों के बीच पारस्परिक सहमति से प्रस्तुत की जा सकेगी ।

(3) संयुक्त बैठक में, उपस्थित और मतदान करने वाले सभी सदस्यों के सकारात्मक मत द्वारा, ऐसे विनिर्दिष्ट शैक्षणिक और चिकित्सा मापदंड या कार्यक्रमों को अनुमोदित करने का विनिश्चय किया जा सकेगा, जिन्हें सभी चिकित्सा पद्धतियों में स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में आरंभ किया जा सकेगा और इस प्रकार चिकित्सा बहुलवाद की अभिवृद्धि की जा सकेगी ।

53. प्रत्येक राज्य सरकार, लोक स्वास्थ्य का पता लगाने या उसकी अभिवृद्धि करने के प्रयोजनों के लिए स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिकों की क्षमता में वृद्धि करने हेतु आवश्यक उपाय कर सकेगी ।

राज्य सरकार द्वारा लोक स्वास्थ्य की अभिवृद्धि करना ।

54. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

नियम बनाने की शक्ति ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ख) के अधीन सलाहकार परिषद् में राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के नामनिर्देशितियों में से चक्रानुक्रम आधार पर आयोग के पांच सदस्यों को नियुक्त करने की रीति ;

(ख) धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ग) के अधीन सदस्यों को नियुक्त करने की रीति ;

(ग) धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा एक विशेषज्ञ को नामनिर्दिष्ट किए जाने की रीति ;

(घ) धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें ;

(ङ) धारा 6 की उपधारा (6) के अधीन घोषणा करने का प्ररूप और रीति ;

(च) धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन सचिव द्वारा धारण की जाने वाली अर्हताएं और अनुभव ;

(छ) धारा 8 की उपधारा (6) के अधीन आयोग के सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें ;

(ज) धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (झ) के अधीन आयोग द्वारा प्रयोग की जाने वाली अन्य शक्तियां और पालन किए जाने वाले अन्य कृत्य ;

(झ) धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन किसी स्वायत्त बोर्ड के प्रधान और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;

(ञ) धारा 30 के खंड (घ) के अधीन अन्य कारक;

(ट) धारा 33 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के अधीन व्यवसायियों की सूची प्रस्तुत करने की रीति ;

(ठ) धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करने का प्ररूप ;

(ड) धारा 42 की उपधारा (1) के अधीन वह समय, जिसके भीतर और वह प्ररूप तथा रीति, जिसमें आयोग द्वारा रिपोर्ट और विवरण तथा किसी ऐसे विषय से संबंधित विशिष्टियां, जिसके संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा अपेक्षा की जाए, प्रस्तुत किए जाएंगे;

(ढ) धारा 43 की उपधारा (2) के अधीन वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने का प्ररूप और समय ;

(ण) धारा 58 की उपधारा (3) के दूसरे परंतुक के अधीन नियोजन को समयपूर्व समाप्त करने के लिए प्रतिकर ;

(त) ऐसा कोई अन्य विषय, जिसके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है ।

विनियम बनाने की शक्ति ।

55. (1) आयोग, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए, इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों से सुसंगत विनियम बना सकेगा ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन आयोग के सचिव द्वारा निर्वहन किए जाने वाले कृत्य ;

(ख) वह प्रक्रिया, जिसके अनुसार धारा 8 की उपधारा (7) के अधीन विशेषज्ञों और वृत्तिकों को नियोजित किया जा सकेगा तथा ऐसे विशेषज्ञों और वृत्तिकों की संख्या ;

(ग) धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन आयोग की बैठकों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत उसकी बैठकों में गणपूर्ति भी है ;

(घ) धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन होम्योपैथी की शिक्षा में बनाई रखी जाने वाली गुणवत्ता और मानक ;

(ङ) धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन आयुर्विज्ञान संस्थाओं, चिकित्सा अनुसंधानों और चिकित्सा वृत्तिकों को विनियमित करने की रीति ;

(च) धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन आयोग, स्वायत्त बोर्डों और राज्य चिकित्सा परिषदों के कार्यकरण को विनियमित करने की रीति ;

(छ) धारा 13 की उपधारा (3) के अधीन चिकित्सा सलाहकार परिषद् की बैठकों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत इसकी बैठकों में गणपूर्ति भी है ;

(ज) धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन ऐसी अन्य भाषाएं, जिसमें अभिहित

प्राधिकरण ऐसे माध्यम से और ऐसी रीति में राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा का आयोजन करेगा ;

(झ) धारा 14 की उपधारा (3) के अधीन अभिहित प्राधिकरण द्वारा आयुर्विज्ञान संस्थाओं में प्रवेश हेतु सामान्य काउंसेलिंग कराए जाने की रीति ;

(ञ) धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन ऐसी अन्य भाषाएं, जिसमें अभिहित प्राधिकरण ऐसे माध्यम से और ऐसी रीति में राष्ट्रीय निकास परीक्षा का आयोजन करेगा ;

(ट) धारा 15 की उपधारा (4) के अधीन वह रीति, जिसमें ऐसा व्यक्ति, जिसके पास विदेशी चिकित्सा अर्हता है, राष्ट्रीय निकास परीक्षा अर्हित करेगा ;

(ठ) धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन ऐसी अन्य भाषाएं, जिसमें अभिहित प्राधिकरण ऐसे माध्यम से और ऐसी रीति में जिसमें स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश संचालित किया जाएगा ;

(ड) धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन अभिहित प्राधिकरण द्वारा सभी आयुर्विज्ञान संस्थाओं में स्नातकोत्तर स्थानों में प्रवेश हेतु सामान्य काउंसेलिंग कराए जाने की रीति ;

(ढ) धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन होम्योपैथी राष्ट्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन करने की रीति और अभिहित प्राधिकरण, जिसके माध्यम से ऐसी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा ;

(ण) धारा 23 के अधीन विशेषज्ञों, वृत्तिकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या और वह रीति, जो आयोग द्वारा स्वायत्त बोर्डों को उपलब्ध कराई जाएगी ;

(त) धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन वह रीति, जिसमें स्वायत्त बोर्डों का विनिश्चय किया जाएगा ;

(थ) धारा 26 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन सभी स्तरों पर सक्षमता आधारित सक्रिय पाठ्यचर्या ;

(द) धारा 26 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन होम्योपैथी में स्नातकपूर्व, स्नातकोत्तर और अति विशिष्ट पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए आयुर्विज्ञान संस्थाएं स्थापित करने की रीति ;

(ध) धारा 26 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन आयुर्विज्ञान संस्थाओं में पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं के संचालन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं और मानक ;

(न) धारा 26 की उपधारा (1) के खंड (ड) के अधीन होम्योपैथी की आयुर्विज्ञान संस्थाओं में की अवसंरचना, संकाय और शिक्षा तथा अनुसंधान की गुणवत्ता संबंधी मानक और सन्नियम ;

(प) धारा 27 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन वृत्तिक आचरण को विनियमित करने और चिकित्सा नैतिकता का संवर्धन करने की रीति ;

(फ) धारा 28 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन आयुर्विज्ञान संस्थाओं के निर्धारण और रेटिंग की प्रक्रिया ;

(ब) धारा 28 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन आयुर्विज्ञान संस्थाओं के निर्धारण और रेटिंग का निरीक्षण करने की रीति ;

(भ) धारा 28 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन सभी आयुर्विज्ञान संस्थाओं का संचालन, निर्धारण और रेटिंग करने के लिए स्वतंत्र रेटिंग अभिकरणों को संचालित करने की रीति और उन्हें पैलबद्ध करने की रीति ;

(म) धारा 28 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के अधीन आयुर्विज्ञान संस्थाओं के निर्धारण और रेटिंग को वेबसाइट या लोकाधिकारी क्षेत्र में उपलब्ध कराए जाने की रीति ;

(य) धारा 28 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन किसी आयुर्विज्ञान संस्था द्वारा न्यूनतम अनिवार्य मानकों को बनाए रखने में असफल रहने पर उनके विरुद्ध किए जाने वाले उपाय ;

(यक) धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन नए आयुर्विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना करने के लिए स्कीम का प्ररूप, उसकी विशिष्टियां, उसके साथ लगाई जाने वाली फीस और स्कीम को प्रस्तुत करने की रीति ;

(यख) धारा 29 की उपधारा (5) के अधीन स्कीम के अनुमोदन के लिए आयोग को अपील करने की रीति ;

(यग) धारा 30 के परंतुक के अधीन ऐसे क्षेत्र जिनके संबंध में मानदंड शिथिल किए जा सकेंगे ;

(यघ) धारा 31 की उपधारा (2) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के विरुद्ध वृत्तिक या नैतिक कदाचार के लिए किसी राज्य चिकित्सा परिषद् द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई करने की रीति और होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड द्वारा परिवाद और शिकायतें प्राप्त करने की प्रक्रिया ;

(यङ) धारा 31 के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अधीन कारित ऐसे कृत्य या लोप, जो वृत्तिक या नैतिक कदाचार की कोटि में आता है ;

(यच) धारा 32 की उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रीय रजिस्टर में अंतर्विष्ट की जाने वाली अन्य विशिष्टियां ;

(यछ) धारा 33 की उपधारा (2) के अधीन राष्ट्रीय रजिस्टर के अनुरक्षण का प्ररूप, जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक प्ररूप और उसकी रीति भी है;

(यज) धारा 34 की उपधारा (3) के अधीन वह रीति, जिसमें किसी नाम या अर्हता को राष्ट्रीय रजिस्टर में जोड़ा जा सकेगा या हटाया जा सकेगा और उन्हें हटाए जाने के लिए आधार ;

(यझ) धारा 35 की उपधारा (3) के अधीन राज्य रजिस्टर या राष्ट्रीय रजिस्टर में उपाधि, डिप्लोमा या अर्हता को प्रविष्टि करने की रीति ;

(यञ) धारा 34 की उपधारा (1) के तीसरे परंतुक के अधीन वह रीति, जिसमें और वह अवधि, जिसके लिए किसी विदेशी नागरिक का अस्थायी

रजिस्ट्रीकरण अनुज्ञात किया जा सकेगा ;

(यट) धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन किसी विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था द्वारा प्रदान की गई चिकित्सा अर्हताओं की सूची तैयार करने और उसका अनुरक्षण करने की रीति ;

(यठ) धारा 35 की उपधारा (3) के अधीन मान्यता प्रदान करने के लिए आवेदन का परीक्षण करने की रीति ;

(यड) धारा 35 की उपधारा (5) के अधीन मान्यता प्रदान किए जाने के संबंध में आयोग को अपील करने की रीति ;

(यढ) धारा 36 की उपधारा (6) के अधीन बोर्ड द्वारा अनुरक्षित सूची में कोई चिकित्सा अर्हता सम्मिलित करने की रीति ;

(यण) धारा 35 की उपधारा (8) के अधीन वह रीति, जिसमें होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड ऐसी चिकित्सा अर्हताओं की सूची बनाएगा और उसका अनुरक्षण करेगा, जिन्हें इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्व मान्यता प्रदान की गई है ;

(यत) धारा 36 की उपधारा (4) के अधीन वह रीति, जिसमें आयोग उन चिकित्सा अर्हताओं की सूची बनाएगा और उसका अनुरक्षण करेगा, जिन्हें इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्व मान्यता प्रदान की गई है ।

56. इस अधिनियम के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम और प्रत्येक विनियम को, इसके बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाते हैं, या दोनों सदन सहमत हो जाते हैं कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् वह नियम या विनियम, यथास्थिति, ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या वह निष्प्रभावी हो जाएगा, किन्तु इस प्रकार, उस नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना ।

57. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हो :

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

परंतु इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात्, इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

58. (1) उस तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 निरसित हो जाएगा और उक्त

निरसन और व्यावृत्ति ।

अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् विघटित हो जाएगी ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम के निरसन के होते हुए भी, निम्नलिखित पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा,—

(क) इस प्रकार निरसित अधिनियम के पूर्व प्रवर्तन या उसके अधीन सम्यक् रूप से की गई किसी बात या किसी कार्यवाई पर ; या

(ख) इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर ; या

(ग) इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन किसी उल्लंघन के संबंध में उपगत किसी शास्ति पर ; या

(घ) यथापूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व या शास्ति के संबंध में किसी कार्यवाही या उपचार पर और ऐसी किसी कार्यवाही या उपचार को उसी प्रकार संस्थित किया जा सकेगा, जारी या प्रवृत्त रखा जा सकेगा या ऐसी कोई शास्ति वैसे ही अधिरोपित की जा सकेगी, मानो वह अधिनियम निरसित ही नहीं किया गया है ।

(3) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् के विघटन पर, उस परिषद् के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त व्यक्ति और सदस्य के रूप में नियुक्त अन्य प्रत्येक व्यक्ति तथा परिषद् का कोई अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी, जो ऐसे विघटन से ठीक पूर्व ऐसा कोई पद धारण किया हुआ था, वे अपने-अपने पदों को रिक्त कर देंगे और ऐसा अध्यक्ष और अन्य सदस्य, अपनी पदावधि या सेवा की किसी संविदा के समयपूर्व समापन के लिए तीन मास से अनधिक के वेतन और भत्तों के प्रतिकर का दावा करने के लिए हकदार होंगे :

परंतु ऐसा कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी, जो होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् के विघटन से ठीक पूर्व होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् में प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त था, वह ऐसे विघटन पर, यथास्थिति, अपने मूल काडर, मंत्रालय या विभाग में वापस चला जाएगा :

परंतु यह और कि ऐसा कोई अधिकारी, विशेषज्ञ, वृत्तिक या अन्य कर्मचारी, जिसे होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् के विघटन से ठीक पूर्व नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर परिषद् द्वारा नियोजित किया गया था, वह केन्द्रीय परिषद् का ऐसा अधिकारी, विशेषज्ञ, वृत्तिक या अन्य कर्मचारी नहीं रहेगा और वह अपने नियोजन के समयपूर्व समापन के लिए ऐसे प्रतिकर का हकदार होगा, जो कम से कम तीन मास का ऐसा वेतन और भत्ता होगा, जो विहित किया जाए ।

(4) पूर्वोक्त अधिनियमिति के निरसन के होते हुए भी, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 के अधीन किया गया कोई आदेश, व्यवसाय करने के लिए जारी की गई कोई अनुज्ञप्ति, किया गया कोई रजिस्ट्रीकरण, किसी नई आयुर्विज्ञान संस्था को आरंभ करने या उच्चतर अध्ययन पाठ्यक्रमों को आरंभ करने या अनुदत्त प्रवेश क्षमता में वृद्धि करने के लिए कोई अनुमति, किसी अनुदत्त चिकित्सा अर्हताओं की कोई मान्यता, जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को प्रवर्तन में हैं, उनके अवसान की तारीख तक, सभी प्रयोजनों के लिए, इस प्रकार से प्रवर्तन में बने रहेंगे, मानों उन्हें इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों के अधीन जारी या मंजूर किया गया हो ।

59. (1) आयोग, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद्, जिसके अंतर्गत उसके समनुषंगी या उसके स्वामित्वाधीन न्यास भी है, के हित में उत्तरवर्ती होगा और होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् की सभी आस्तियों और दायित्वों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे आयोग को अंतरित हो गए हैं ।

संक्रमणकालीन
उपबंध ।

1973 का 59

(2) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 का निरसन होते हुए भी, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के शिक्षा और चिकित्सा मानक, अपेक्षाएं और अन्य उपबंध तब तक प्रवर्तन और प्रचालन में रहेंगे, जब तक कि इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन नए मानक या अपेक्षाएं विनिर्दिष्ट न कर दी जाएं :

परंतु निरसनाधीन अधिनियमिति और उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन शैक्षिक और चिकित्सा मानकों तथा अपेक्षाओं के संबंध में की गई कोई बात या कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंध के अधीन की गई समझी जाएगी और वह तदनुसार, तब तक प्रवर्तन में बनी रहेंगी, जब तक उसे इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या की गई किसी कार्रवाई द्वारा अधिकांत नहीं कर दिया जाता है ।

(3) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन नए आयोग के तत्स्थानी विघटित होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् के निर्बाध संक्रमण के लिए ऐसे समुचित उपाय कर सकेगी, जो आवश्यक हो ।

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021

(2021 का अधिनियम संख्यांक 17)

[28 मार्च, 2021]

भारत में दीर्घकालिक अनावलंब वित्तपोषण अवसंरचना के विकास में सहायता करने के लिए, जिसमें अवसंरचना वित्तपोषण हेतु आवश्यक बंधपत्र और व्युत्पाद बाजारों का विकास भी सम्मिलित है और अवसंरचना वित्तपोषण का कारबार करने के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक की स्थापना करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक

विषयों के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बहतरवें वर्ष में संसद् द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 है ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारंभ ।

तारीखें नियत की जा सकेंगी तथा ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश हैं ।

परिभाषाएं ।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “संपरीक्षा समिति” से धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन गठित बोर्ड की संपरीक्षा समिति अभिप्रेत है ;

(ख) “बोर्ड” से धारा 6 के अधीन गठित निदेशक बोर्ड अभिप्रेत हैं ;

(ग) “ब्यूरो” से कोई ऐसा निकाय अभिप्रेत है जिसे केंद्रीय सरकार, धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन प्रबंध निदेशक और उप प्रबंध निदेशक की नियुक्ति के लिए और धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ii) के अधीन किसी निदेशक को हटाए जाने के लिए अभ्यर्थियों की सिफारिश करने के प्रयोजन हेतु अधिसूचित कर सकेगी ;

(घ) “अध्यक्ष” से धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन नियुक्त बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ङ) “समिति” से धारा 15 के अधीन गठित बोर्ड की कोई समिति अभिप्रेत है ;

(च) “उप प्रबंध निदेशक” से धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन नियुक्त उप प्रबंध निदेशक अभिप्रेत है ;

(छ) “निदेशक” के अंतर्गत धारा 6 के अधीन नियुक्त या नामनिर्दिष्ट बोर्ड के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, उप प्रबंध निदेशक और अन्य निदेशक आते हैं ;

(ज) “कार्यपालिका समिति” से धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन गठित बोर्ड की कार्यपालिका समिति अभिप्रेत है ;

(झ) “वित्तीय संस्था” का वही अर्थ होगा जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ड) में उसका है ;

2002 का 54

(ञ) “स्वतंत्र निदेशक” से धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन नियुक्त बोर्ड का स्वतंत्र निदेशक अभिप्रेत है ;

(ट) “अवसंरचना” से केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अवसंरचना क्षेत्र की सूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र अभिप्रेत हैं ;

(ठ) “संस्था” से धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अभिप्रेत है ;

(ड) “बीमाकर्ता” का वही अर्थ होगा जो बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2 की उपधारा (9) में है ;

1938 का 4

(ढ) “प्रबंध निदेशक” से धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन नियुक्त निदेशक अभिप्रेत है ;

(ग) “नामांकन और पारिश्रमिक समिति” से धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन गठित बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति अभिप्रेत है ;

(त) “अधिसूचना” से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और “अधिसूचित” पद का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा ;

2013 का 23

(थ) “पेंशन निधि” का वही अर्थ होगा, जो पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ठ) में उसका है ;

(द) “विहित” से केंद्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ध) “विनियम” से इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं और इसमें धारा 29 के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियम भी सम्मिलित हैं ;

1934 का 2

(न) “रिजर्व बैंक” से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अधीन स्थापित भारतीय रिजर्व बैंक अभिप्रेत है ;

(प) “जोखिम प्रबंध समिति” से धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन गठित बोर्ड की जोखिम प्रबंध समिति अभिप्रेत है ;

(फ) “अनुसूची” से इस अधिनियम से संलग्न कोई अनुसूची अभिप्रेत है ।

1872 का 9
1932 का 9
1956 का 42
1992 का 15
1993 का 51
2009 का 6
2013 का 18

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और इस अधिनियम में परिभाषित नहीं हैं किन्तु भारतीय संविदा अधिनियम, 1872, भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932, प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992, बैंक और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993, सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 और कंपनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उन अधिनियमों में हैं ।

अध्याय 2

संस्था की स्थापना और निगमन

3. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, एक वित्तीय विकास संस्था के रूप में, जिसे राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक कहा जाएगा, एक संस्था स्थापित की जाएगी ।

संस्था की
स्थापना और
निगमन ।

(2) संस्था, पूर्वोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगी, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी, जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने और संविदा करने की शक्ति होगी तथा उक्त नाम से वह वाद लाएगी और उस पर वाद लाया जाएगा ।

(3) संस्था का मुख्यालय मुम्बई में होगा ।

(4) संस्था, भारत के भीतर या भारत से बाहर किसी भी स्थान पर कार्यालय, शाखाएं या अभिकरण स्थापित कर सकेगी ।

संस्था के प्रयोजन
और उद्देश्य ।

4. (1) संस्था के, उपधारा (2) और उपधारा (3) में यथा उपवर्णित विकासात्मक और वित्तीय उद्देश्य होंगे ।

(2) संस्था का विकासात्मक उद्देश्य, भारत में दीर्घकालिक अनावलंब वित्तपोषण अवसंरचना के विकास में सहायता के लिए निर्माण को सुकर बनाने और सुसंगत संस्थाओं की अभिवृद्धि के लिए केंद्रीय और राज्य सरकारों, विनियामकों, वित्तीय संस्थाओं, संस्थागत विनिधानकर्ताओं तथा भारत के भीतर या भारत से बाहर ऐसे अन्य सुसंगत पणधारियों के बीच समन्वय बनाने का होगा ।

(3) संस्था का वित्तीय उद्देश्य, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उधार देना या निवेश करना और भारत में सतत् आर्थिक विकास का पोषण करने की दृष्टि से, भारत में या भागतः भारत में और भागतः भारत से बाहर अवस्थित अवसंरचना परियोजनाओं में प्राइवेट सेक्टर के निवेशकों और संस्थागत निवेशकों से निवेश को आकर्षित करना होगा ।

प्राधिकृत शेयर
पूंजी ।

5. (1) संस्था की प्राधिकृत शेयर पूंजी दस खरब रुपए होगी, जो प्रत्येक दस रुपए के पूर्णतः समादत्त शेयरों के दस हजार करोड़ रुपए से विभाजित की जाएगी :

परंतु बोर्ड, शेयरों का अभिहित या अंकित मूल्य बढ़ा या घटा सकेगा और ऐसे मूल्य वर्ग में से प्राधिकृत पूंजी को विभाजित कर सकेगा, जैसा वह विनिश्चय करे :

परंतु यह और कि बोर्ड, केंद्रीय सरकार के परामर्श से, पूर्णतः समादत्त शेयरों के सभी मामलों में शेयरों के अध्यक्षीन प्राधिकृत पूंजी को बढ़ा या घटा सकेगा ।

(2) संस्था की जारी की गई शेयर पूंजी, ऐसी तारीख को, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, केंद्रीय सरकार को आबंटित किया जाएगा ।

(3) संस्था के शेयर केंद्रीय सरकार, बहुपक्षीय संस्थाएं, संप्रभु स्वास्थ्य निधियों, पेंशन निधियों, बीमाकर्ताओं, वित्तीय संस्थाओं, बैंकों और ऐसी अन्य संस्थाओं द्वारा, जो विहित की जाएं, धारित किए जा सकेंगे :

परंतु केंद्रीय सरकार, सभी समयों पर संस्था के शेयरों का कम से कम छब्बीस प्रतिशत धारित करेगी ।

(4) बोर्ड, केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से अपनी शेयर पूंजी को कम कर सकेगा, जिसके अन्तर्गत शेयरों को क्रय द्वारा वापस लेना भी है ।

अध्याय 3

निदेशक बोर्ड और प्रबंधन

निदेशक बोर्ड ।

6. (1) संस्था का निदेशक बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) केंद्रीय सरकार द्वारा रिजर्व बैंक के परामर्श से नियुक्त किया जाने वाला एक अध्यक्ष;

(ख) बोर्ड द्वारा ब्यूरो की सिफारिशों पर और ऐसी प्रक्रिया के और ऐसे अभिकरणों से अनापति के अध्यक्षीन रहते हुए, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अवधारित किया जाए, नियुक्त किया जाने वाला एक प्रबंध निदेशक;

(ग) तीन से अनधिक उप प्रबंध निदेशक, जिनमें से प्रत्येक बोर्ड द्वारा ब्यूरो की सिफारिशों पर और ऐसी प्रक्रिया के और ऐसे अभिकरणों से अनापति के

अध्यधीन रहते हुए, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अवधारित किया जाए, नियुक्त किए जाएंगे;

(घ) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो निदेशक, जो केंद्रीय सरकार के पदधारी होंगे;

(ङ) तीन से अनधिक निदेशकों की ऐसी संख्या, जो शेयर धारकों द्वारा ऐसी रीति में निर्वाचित किए गए हैं, जो विहित की जाए, केंद्रीय सरकार से भिन्न ऐसा कोई शेयर धारक, जो कुल जारी की गई साधारण अंश पूंजी का दस प्रतिशत या उससे अधिक धारण करता है, एक निदेशक नामनिर्देशित कर सकेगा ;

(च) नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा नियुक्त किए जाने वाले तीन से अनधिक या बोर्ड के निदेशकों की कुल संख्या के एक तिहाई, जो भी उच्चतर हो, ऐसी संख्या में स्वतंत्र निदेशक :

परंतु यदि शेयर धारकों के साथ जारी साधारण शेयर पूंजी की धृति की प्रतिशतता तीन निदेशकों के निर्वाचन की अनुज्ञा नहीं देती है या शेयर धारकों द्वारा निर्वाचित निदेशकों द्वारा भार ग्रहण किए जाने तक, बोर्ड, नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा नियुक्त किए जाने वाले तीन से अनधिक स्वतंत्र निदेशकों की ऐसी संख्या को किसी भी समय सहयोजित कर सकेगा, जो शेयर धारकों द्वारा निर्वाचित निदेशकों द्वारा भार ग्रहण करने तक पद धारण करेंगे और ऐसे सहयोजित स्वतंत्र निदेशक किसी समान संख्या में सहयोजन के क्रम में सेवानिवृत्त होंगे:

परंतु यह और कि खंड (ड) या खंड (च) में विनिर्दिष्ट निदेशकों में कम से कम एक महिला होगी ।

(2) प्रबंध निदेशक या उप प्रबंध निदेशक, बोर्ड के पूर्णकालिक निदेशक होंगे ।

(3) कोई व्यक्ति, जो संस्था का वेतन भोगी अधिकारी या अन्य कर्मचारी है, प्रबंध निदेशक या उप प्रबंध निदेशक के पद के सिवाय, बोर्ड के निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा ।

(4) अध्यक्ष, बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेगा ।

(5) उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन बोर्ड के स्वतंत्र निदेशकों के समावेशन की निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं ।

(6) उपधारा (1) के खंड (घ) और खंड (च) के अधीन नियुक्त किए गए निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन स्वतंत्र निदेशकों को उपलब्ध उन्मुक्तियों के प्रयोजन के लिए, स्वतंत्र निदेशक समझे जाएंगे ।

7. (1) संस्था के कार्य और कारबार का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंधन बोर्ड में निहित होगा, जो उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा और वे सभी कार्य या चीजें करेगा, जिनका संस्था द्वारा प्रयोग किया जाए या जो उसके द्वारा किए जाएं ।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, बोर्ड अपने कृत्यों के निर्वहन में कारबार के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करेगा ।

शक्तियों का
प्रत्यायोजन ।

8. बोर्ड, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, किसी निदेशक या इस अधिनियम के अधीन गठित समिति या संस्था के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों और कृत्यों का प्रत्यायोजन कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे ।

बोर्ड के अध्यक्ष
और अन्य
निदेशकों की
पदावधि तथा सेवा
की अन्य निबंधन
और शर्तें ।

9. (1) अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, उप प्रबंध निदेशक या धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट निदेशकों से भिन्न बोर्ड के अन्य निदेशक, ऐसी अवधि के लिए, जो पांच वर्ष से अधिक का न हो, पद धारण करेंगे और दस वर्ष से अनधिक की संपूर्ण पदावधि के अधीन रहते हुए पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे :

परंतु प्रबंध निदेशक और उप प्रबंध निदेशक, क्रमशः पैंसठ वर्ष और बासठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् पद धारण नहीं करेंगे ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन नामनिर्दिष्ट या नियुक्त अध्यक्ष और निदेशक, उन्हें नामनिर्दिष्ट करने वाले या नियुक्त करने वाले प्राधिकारी के प्रसादपर्यंत पद धारण करेंगे ।

(3) केंद्रीय सरकार या शेयर धारकों और स्वतंत्र निदेशकों द्वारा नामनिर्दिष्ट अध्यक्ष और निदेशक, ऐसी फीस और पारिश्रमिक प्राप्त करेंगे, जो विहित की जाए:

परंतु इस उपधारा के अधीन संदेय कोई फीस या पारिश्रमिक को संस्था के अभिलाभों के साथ नहीं जोड़ा जाएगा ।

(4) प्रबंध निदेशक और उप प्रबंध निदेशक को संदेय वेतन और भत्ते बाजार मानकों द्वारा मार्गदर्शित नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिशों पर विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएंगे ।

(5) अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, उप प्रबंध निदेशक और धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट निदेशकों से भिन्न बोर्ड के अन्य निदेशकों की पदावधि और सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं ।

(6) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी निदेशक को, जो केंद्रीय सरकार का कोई अधिकारी है, कोई फीस संदेय नहीं होगी ।

निदेशकों की
निरर्हताएं और पद
से हटाया जाना ।

10. (1) केंद्रीय सरकार, किसी ऐसे निदेशक को पद से हटा सकेगी—

(क) जिसे दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाता है या किसी समय दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है; या

(ख) जो निदेशक के रूप में कार्य करने में शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है; या

(ग) जिसे किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसमें केंद्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है; या

(घ) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है, जिससे निदेशक के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(ड) जिसने केंद्रीय सरकार की राय में अपनी स्थिति का ऐसे दुरुपयोग किया है जिससे उसके पद पर बने रहने से लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; या

(च) जिसे किन्हीं कारणों से—

(i) सरकार; या

(ii) किसी बैंक, जिसके अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक भी हैं; या

(iii) किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम; या

(iv) सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी अन्य निगम, की सेवा से हटाया गया है या पदच्युत किया गया है ।

(2) किसी निदेशक को उपधारा (1) के खंड (घ) या खंड (ड) के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया गया है ।

(3) कोई निदेशक, जो संसद् या किसी राज्य विधान-मंडल में सदस्य के रूप में निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट हो जाता है, तो वह यथास्थिति, ऐसे निर्वाचन या नामनिर्देशन की तारीख से निदेशक नहीं रहेगा ।

(4) इस धारा के अधीन निरहताएं या हटाया जाना—

(क) न्यायनिर्णयन, दंडादेश या आदेश की तारीख से तीस दिन के लिए प्रभावी नहीं होगा ; या

(ख) जहां दंडादेश या आदेश के परिणामस्वरूप ऐसे न्यायनिर्णयन, दंडादेश या दोषसिद्धि के विरुद्ध तीस दिन के भीतर कोई अपील या याचिका दाखिल की जाती है वहां ऐसी तारीख से जिसको ऐसी अपील या याचिका का निपटारा किया जाता है, सात दिन की समाप्ति तक प्रभावी नहीं होगी ।

11. (1) धारा 10 में किसी बात के होते हुए भी,—

(i) केंद्रीय सरकार, रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात्, अध्यक्ष को पद से हटा सकेगी और रिक्ति को भरने के लिए उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी;

(ii) बोर्ड, ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात्, धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (च) के अधीन नियुक्त किसी निदेशक को उसके पद से हटा सकेगा और रिक्ति को भरने के लिए उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा;

(iii) केंद्रीय सरकार से भिन्न शेयर धारक, जो ऐसे सभी शेयर धारकों द्वारा धारित शेयर पूंजी के आधे से अन्यून सकल धृति रखते हैं, ऐसे शेयर धारकों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (ड) के अधीन निर्वाचित किसी निदेशक को हटाया जा सकेगा और रिक्ति को भरने के लिए उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को निर्वाचित किया जा सकेगा :

कतिपय मामलों में अध्यक्ष और अन्य निदेशकों का हटाया जाना ।

परंतु कोई व्यक्ति इस उपधारा के अधीन अपने पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे ऐसे हटाए जाने के विरुद्ध कारण दर्शाने का अवसर प्रदान नहीं किया जाता है ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार को, रिजर्व बैंक से परामर्श करके, यथास्थिति, अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, उप प्रबंध निदेशक या निदेशकों को तीन मास से अन्यून की लिखित सूचना या ऐसी सूचना के बजाय तीन मास का वेतन और भत्ता प्रदान करते हुए धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन विहित पदावधि की समाप्ति से पहले किसी भी समय, उनकी पदावधि समाप्त करने का अधिकार होगा ।

रिक्ति और
निदेशकों द्वारा
पदत्याग ।

12. (1) यदि कोई निदेशक—

(क) धारा 10 में उल्लिखित किन्हीं निरर्हताओं के अध्यक्षीन हो जाता है या धारा 11 के अधीन हटाया जाता है ; या

(ख) बोर्ड से छुट्टी के बिना लगातार तीन या अधिक उसकी बैठकों में अनुपस्थित रहता है,

तो उसका पद रिक्त हो जाएगा ।

(2) कोई निदेशक बोर्ड को लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकेगा और बोर्ड द्वारा ऐसा त्यागपत्र स्वीकार किए जाने पर या यदि ऐसा त्यागपत्र यथाशीघ्र स्वीकार नहीं किया जाता है, तो बोर्ड द्वारा उसके प्राप्त किए जाने से तीन मास के अवसान पर, ऐसा निदेशक अपने पद से रिक्त समझा जाएगा ।

बोर्ड की बैठकें ।

13. (1) बोर्ड, ऐसे समय और स्थानों पर बैठक करेगा और अपनी बैठकों के कार्य संचालन के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(2) बोर्ड की बैठक प्रत्येक कैलेंडर तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी और प्रत्येक वर्ष कम से कम ऐसी चार बैठकें आयोजित की जाएंगी ।

(3) बोर्ड का अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक, यदि किसी भी कारण से, वह बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है या अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक दोनों के बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ होने की दशा में, इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अन्य निदेशक और ऐसे नामनिर्देशन के अभाव में, बैठक में उपस्थित निदेशकों में से निर्वाचित कोई निदेशक बोर्ड के बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

(4) बोर्ड की किसी बैठक के समक्ष आने वाले सभी प्रश्न, उपस्थित और मतदान करने वाले निदेशकों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे और मत बराबर होने की दशा में, अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति निर्णायक मत देगा ।

(5) उपधारा (4) में यथा उपबंधित के सिवाय, प्रत्येक निदेशक के पास एक मत होगा ।

नियुक्ति में त्रुटि
से कार्यों, आदि
का अविधिमान्य
न होना ।

14. (1) बोर्ड या उसकी किसी समिति के किसी कार्य या कार्यवाही को केवल यथास्थिति, बोर्ड या समिति में विद्यमान किसी रिक्ति या उसके गठन में किसी त्रुटि के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

(2) बोर्ड के निदेशक के रूप में या उसकी समिति के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा सद्भावपूर्वक किया गया कोई कार्य केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं हो जाएगा कि वह निदेशक होने के लिए निरहित था या उसकी नियुक्ति में कोई अन्य त्रुटि थी ।

15. (1) बोर्ड, एक नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति, एक जोखिम प्रबंध समिति और एक संपरीक्षा समिति का गठन करेगा, जो प्रत्येक बहुमत बनाने वाले स्वतंत्र निदेशकों के साथ न्यूनतम तीन निदेशकों से मिलकर बनेगी ।

बोर्ड की समितियां।

(2) बोर्ड, एक कार्यकारी समिति का गठन करेगा जो निदेशकों की ऐसी संख्या से मिलकर बनेगी, जो आवश्यक समझा जाए ।

(3) संस्था का अध्यक्ष कार्यकारी समिति का सदस्य नहीं होगा और पहले वर्ष के पश्चात् वह संपरीक्षा समिति या नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति का अध्यक्ष नहीं रहेगा ।

(4) बोर्ड, ऐसी अन्य समितियों का गठन कर सकेगा, जैसा वह ठीक समझे ।

(5) इस धारा के अधीन गठित कार्यकारी समिति या कोई अन्य समितियां ऐसे समय और स्थानों पर बैठकें करेंगी और अपनी बैठकों के कार्य संचालन के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेंगी और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

16. (1) प्रत्येक निदेशक, बोर्ड की पहली बैठक में, जिसमें वह निदेशक के रूप में भाग लेता है और उसके पश्चात् प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बोर्ड की पहली बैठक में या जब कभी पहले से किए गए प्रकटनों में कोई परिवर्तन होता है, तो ऐसे परिवर्तन के पश्चात् आयोजित बोर्ड की पहली बैठक में, किसी निगमित निकाय में अपना सरोकार या हित, जिसके अंतर्गत शेयर धारण भी है, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रकट करेगा ।

बोर्ड या समितियों के सदस्यों द्वारा का प्रकटन ।

(2) प्रत्येक निदेशक, जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी भी तरह, संविदा या ठहराव या प्रस्तावित संविदा या ठहराव, जो संस्था द्वारा की जाती है या की जानी है, से संबद्ध या हितबद्ध है—

(क) ऐसे किसी निगमित निकाय के साथ, जिसमें ऐसा निदेशक या किसी अन्य निदेशक के साथ सहयोजन में ऐसा निदेशक, उस निगमित निकाय के दो प्रतिशत शेयर धारण से अधिक शेयर धारण करता है या उस निगमित निकाय का संप्रवर्तक, प्रबंधक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी या न्यासी है ; या

(ख) किसी फर्म या अन्य इकाई के साथ, जिसमें ऐसा निदेशक, यथास्थिति भागीदार, स्वामी या सदस्य है,

बोर्ड या उसकी समिति की किसी बैठक में भाग नहीं लेगा, जिसमें ऐसी संविदा या ठहराव पर विचार-विमर्श किया जाता है या ऐसी संविदा या ठहराव के संबंध में कोई अन्य विचार-विमर्श या चर्चा की जाती है और बोर्ड या उसकी समिति की बैठक में ऐसे विचार-विमर्श की दशा में, यथास्थिति, बोर्ड या समिति में उसके सरोकार या हित की

प्रकृति का प्रकटन होता है:

परंतु जहां कोई निदेशक, जो ऐसी संविदा या ठहराव करते समय इस प्रकार संबद्ध या हितबद्ध नहीं है, यदि वह संविदा या ठहराव किए जाने के पश्चात्, संबद्ध या हितबद्ध हो जाता है, तो उसके संबद्ध या हितबद्ध हो जाने पर अपने सरोकार या हित को तुरंत या उसके इस प्रकार संबद्ध या हितबद्ध हो जाने के पश्चात् आयोजित बोर्ड की पहली बैठक में उसे प्रकट करेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन प्रकटन के बिना संस्था द्वारा की गई कोई संविदा या ठहराव या ऐसे किसी निदेशक द्वारा, जो ऐसी संविदा या ठहराव में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी भी तरह संबद्ध या हितबद्ध है, भाग लेना, संस्था के विकल्प पर शून्यकरणीय होगा।

(4) ऐसे कर्मचारियों को, जिन्हें बोर्ड, संस्था में ज्येष्ठ प्रबंध गठित करने वाला विनिर्दिष्ट करे, बोर्ड को सभी सामग्री, वित्तीय और वाणिज्यिक संव्यवहार, जिसमें उनका वैयक्तिक हित है जिनसे संस्था के हित से मतभेद संभाव्य है, का प्रकटन करेंगे और बोर्ड, ऐसे संव्यवहारों पर उनकी किसी तात्त्विक सीमा सहित कोई नीति विनिर्मित करेगा और ऐसी नीति का प्रत्येक तीन वर्ष में कम से कम एक बार पुनर्विलोकन करेगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, हित संघर्ष, ऐसे निकाय जिनमें ज्येष्ठ प्रबंध व्यष्टि या उसके नातेदारों के पास शेयरधारण, आदि हैं, से वाणिज्यिक व्यवहार करने वाली संस्था या उसकी किसी समनुषंगियों या सहायक कंपनियों के शेयरों से व्यवहार करने से संबंधित हैं।

(5) यदि कोई व्यष्टि, जो एक निदेशक है, उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करता है या उपधारा (4) में निर्दिष्ट कोई कर्मचारी ऐसे उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो ऐसा व्यष्टि या कर्मचारी एक लाख रुपए तक की शास्ति के संदाय का दायी होगा।

(6) उपधारा (5) में अंतर्विष्ट किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यह संस्था पर निर्भर होगा कि वह ऐसे निदेशक या किसी अन्य कर्मचारी के विरुद्ध, जो इस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में ऐसी संविदा या ठहराव किया है, ऐसी संविदा या ठहराव के परिणामस्वरूप उसके द्वारा वहन की गई किसी हानि की वसूली के लिए कार्यवाही करे।

स्पष्टीकरण—इस धारा और धारा 19 के प्रयोजनों के लिए, “निगमित निकाय” पद में कोई कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (11) में यथा परिभाषित निगमित निकाय, फर्म, वित्तीय संस्था या अनुसूचित बैंक या किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित पब्लिक सेक्टर उपक्रम और व्यक्तियों का कोई अन्य निगमित संगम या व्यष्टि निकाय सम्मिलित है।

अध्याय 4

संस्था के क्रियाकलाप

17. (1) संस्था, निम्नलिखित कृत्यों को करेगी और निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगी, अर्थात् :—

संस्था के कृत्य और शक्तियां ।

(i) अपने कृत्यों का निष्पादन करने के लिए, भारत में या भारत से बाहर अवस्थित समनुषंगियों या संयुक्त उद्यमों या शाखाओं से और ऐसी समनुषंगी कंपनी या संयुक्त उद्यम या शाखा के साथ ऐसी समनुषंगी कंपनी या संयुक्त उद्यम या शाखा का वित्तपोषण करने या उनके किन्हीं दायित्वों को प्रतिभूत करने सहित कोई ठहराव करना या ऐसे अन्य ठहराव करना, जिन्हें बोर्ड वांछनीय समझे ।

(ii) अपने प्रचालन और अवसंरचना वित्त के क्षेत्र में लगी हुई विभिन्न संस्थाओं के प्रचालन में समन्वय करना और अवसंरचना वित्त से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञ कर्मचारिवृंद रखना और केंद्रीय सरकार, रिजर्व बैंक और अवसंरचना वित्त के क्षेत्र में लगी हुई अन्य संस्थाओं को परामर्श के लिए उपलब्ध रहना ;

(iii) ऐसी प्रकृति की निधियों की स्थापना के लिए, जो भारत में या भागतः भारत में और भागतः भारत से बाहर अवस्थित अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण में सहायता करेगी, भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अधीन न्यासों की स्थापना करना, जिसके अंतर्गत भू-संपदा विनिधान न्यास और अवसंरचना विनिधान न्यास भी हैं ;

(iv) अवसंरचना वित्तपोषण, जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक और बातचीत से तय की गयी बाजार अवसंरचना को सुकर बनाना, विनिधानकर्ता की सुरक्षा, अवसंरचना न्यायनिर्णयन, आदि भी हैं, के लिए बंधपत्रों, ऋणों और व्युत्पन्नों के लिए गहन और नकद बाजार के विकास में सहायता करना ;

(v) भारत में या भागतः भारत में और भागतः भारत से बाहर अवस्थित अवसंरचना परियोजनाओं को, जिसके अंतर्गत उसके प्राप्यों के निम्नांकन प्रत्यय, प्रतिभूतिकरण जिसके अंतर्गत निकासी प्रमाणपत्र या प्रत्यक्ष समनुदेशन, अंतरण या नवीयन के रूप में या परियोजना से प्राप्यों द्वारा प्रतिभूत संव्यवहार सहित नवोन्मेषी वित्तीय साधनों द्वारा उधार देना और विनिधान करना भी है ;

(vi) भारत में या भागतः भारत में और भागतः भारत से बाहर अवस्थित अवसंरचना परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए किसी अवसंरचना निधीयन कंपनी या कानूनी निगम या न्यास या किसी वित्तीय संस्था के ऋण और अधिदायों का विस्तार करना ;

(vii) भारत में या भागतः भारत में और भागतः भारत से बाहर अवस्थित अवसंरचना परियोजनाओं के लिए उधार देने वाले के द्वारा बढ़ाए गए विद्यमान ऋणों का कार्यभार लेना या उनकी पुनर्वित्तपूर्ति करना;

(viii) उसके द्वारा प्रदत्त ऋणों और अधिदायों का प्रतिफल के लिए प्रतिभूति सहित या उसके बिना न्यासों को अंतरण करना;

(ix) संस्था द्वारा धारित ऋणों या अधिदायों को अलग रखना और ऋण बाध्यता, फायदाप्रद हित का न्यास प्रमाणपत्र या अन्य लिखत के रूप में, जो चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, इस प्रकार अलग रखे गए ऐसे ऋणों या अधिदायों पर आधारित प्रतिभूतियों को जारी करना और उनका विक्रय करना तथा ऐसी प्रतिभूतियों के धारकों के लिए न्यासी के रूप में कार्य करना ;

(x) संस्था को जारी की गई प्रतिभूतियों को समनुदेशित करना ;

(xi) किसी कंपनी या न्यास या रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी या सहकारी सोसाइटी या संगम या केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या अवसंरचना वित्तपोषण करने वाली किसी वित्तीय संस्था द्वारा जारी या प्रत्याभूत, स्टॉकों, शेयरों, बंधपत्रों, डिबेंचर स्टॉकों, ऋण प्रतिभूतियों, बाध्यताओं और प्रतिभूतियों, वाणिज्यिक पत्रों, निक्षेप-प्रमाणपत्रों या डिबेंचरों को भारत में या भागतः भारत में और भागतः भारत से बाहर अवस्थित अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण को सुकर बनाने के लिए या अवसंरचना वित्तपोषण के लिए बंधपत्र बाजार को मजबूत करने को सुकर बनाने के लिए प्रतिश्रुत करना या क्रय, निम्नांकन, अर्जन, धारण या विक्रय करना ;

(xii) ऋण के माध्यम से या अन्यथा, रुपए या विदेशी मुद्रा दोनों में धन उधार लेना या समुत्थापित करना या डिबेंचरों, डिबेंचर स्टॉकों, बंधपत्रों, सभी प्रकार की बाध्यताओं, बंधकों और प्रतिभूतियों, चाहे शाश्वत या पर्यवसेय हो और चाहे विमोचनीय या अन्यथा हो, के निर्गम और विक्रय द्वारा धन का संदाय सुनिश्चित करना या उसे न्यास विलेख या अन्यथा द्वारा संस्था के वचनबंध पर, जिसके अंतर्गत उसकी प्राधिकृत और जारी की गई पूंजी भी है या संस्था या अन्यथा किसी भी तरह की वर्तमान या भविष्यवर्ती किसी विनिर्दिष्ट संपत्ति और अधिकार पर भारित या प्रतिभूत करना ;

(xiii) केंद्रीय सरकार, अनुसूचित बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, पारस्परिक निधियों, व्यक्तियों के किसी वर्ग और केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य संस्था या प्राधिकरण या संगठन से, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जिन पर सहमति हो, धन उधार लेना और केवल आस्ति दायित्व असंतुलन के प्रबंधन के लिए और न कि किसी अन्य कारबार के प्रयोजन के लिए, अल्पावधि ऋण स्वीकार करना;

(xiv) क्रय या विक्रय या ऐसे अन्य विदेशी विनिमय में व्यवहार करना, जो उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो ;

(xv) भागीदारी प्रमाणपत्र या ऋण प्रतिभूतियां जारी करना तथा अवसंरचना विकास और वित्तपोषण में लगी हुई कंपनियों और अन्य इकाईयों के ऋण संविभाग के प्रतिभूतिकरण की अभिवृद्धि करना और उसे सुकर बनाना तथा प्रत्याभूत प्राप्तियों के लिए द्वितीयक बाजार का सृजन करना और विकास करना, जिसके अंतर्गत किसी मध्यवर्ती के रूप में कार्य करना भी है ;

(xvi) प्रतिभूति पर या प्रतिभूति के बिना धन उधार देना और न्यास में धृति पर अभिदाय देना, किन्हीं प्रतिभूतियों या विनिधानों को कमीशन पर या अन्यथा जारी करना, क्रय करना, विक्रय करना या अन्यथा अर्जित करना या उनका निपटारा करना या इस प्रकार के किसी प्रयोजन के लिए अभिकर्ता के रूप में कार्य करना;

(xvii) परियोजनाओं के पूरे जीवन चक्र के अवसंरचना क्षेत्र में कार्य करने वाली कंपनियों को उधार देना या उनमें विनिधान करना या उनकी वृत्तिक या तकनीकी सेवाएं अर्जित करना;

(xviii) भारत में या भागतः भारत में और भागतः भारत से बाहर अवस्थित अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए प्रत्यय वृद्धि सुविधाओं को विस्तार रूप में सम्मिलित करते हुए अवसंरचना कंपनियों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियों से संबंधित संव्यवहारों या सेवाओं के संबंध में एक मध्यवर्ती के रूप में कार्य करना;

(xix) अवसंरचना वित्तपोषण के क्षेत्र में प्रभावी विवाद समाधान के लिए विभिन्न सरकारी प्राधिकारियों और पणधारियों के साथ बातचीत या विचार-विमर्श में सक्रिय भूमिका निभाना ;

(xx) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से, जिसके अंतर्गत विश्व बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जापान इंटरनेशनल कोआपरेशन एजेंसी, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फार इंटरनेशनल डेवलपमेंट, क्रेडिटेंटस्टेल्ट फर वाइडरराऊफब, यूरोपियन इंवेस्टमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन और अन्य संगठन तथा अभिकरण भी हैं, अनुदान, सहायता, सहायकियां, निधियां या संदान, आदि प्राप्त करने के लिए आवेदन करना, स्वीकार करना, प्रशासन करना और प्रबंध करना तथा अवसंरचना विकास परियोजनाओं में विदेशी भागीदारी को सुकर बनाना;

(xxi) भारत में या भागतः भारत में और भागतः भारत से बाहर अवस्थित अवसंरचना परियोजनाओं का निधीयन करने वाली किसी वित्तीय संस्था द्वारा ऋण या किए गए प्रत्यय ठहराव या जारी किए गए डिबेंचर या बंधपत्र के लिए प्रत्याभूति, आश्वासन पत्र या प्रत्यय पत्र जारी करना;

(xxii) रिजर्व बैंक से मांग पर या उस तारीख से, जब ऐसा धन स्टॉक, निधियों या प्रतिभूतियों (स्थावर संपत्ति से भिन्न) की, जिनमें कोई न्यासी, भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा न्यास धन का विनिधान करने के लिए प्राधिकृत है, प्रतिभूति के विरुद्ध इस प्रकार धन उधार लिया जाता है, नब्बे दिन से अनधिक की नियत अवधि की समाप्ति पर प्रतिसंदेय धन उधार लेना;

(xxiii) उधार लिए जाने की तारीख से पांच वर्ष के भीतर परिपक्व होने वाले सद्भाविक वाणिज्यिक या व्यापार संव्यवहारों से, उद्भूत विनिमयपत्र या वचनपत्र के विरुद्ध रिजर्व बैंक से धन उधार लेना;

(xxiv) किसी ऋण को, जिसे उधार लेने वाले तक विस्तृत किया गया है, साधारण शेयर में परिवर्तित करना; और

(xxv) किसी अन्य प्रकार का कारबार या किसी अन्य प्रकार के क्रियाकलाप करना, जिसे केंद्रीय सरकार रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके प्राधिकृत करे।

(2) उपधारा (1) को अग्रसर करने में, संस्था या तो स्वयं या अपनी किसी समनुषंगी या संयुक्त उद्यम के माध्यम से या किसी अन्य के सहयोजन से निम्नलिखित कृत्यों का निष्पादन कर सकेगी, अर्थात् :—

(क) भारत में या भागतः भारत में और भागतः भारत से बाहर अवस्थित अवसंरचना विकास परियोजनाओं में केंद्रीय सरकार, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और भारत या विदेश से संस्थागत विनिधानकर्ताओं की भागीदारी को संचालित करना और उसे सुकर बनाना ;

(ख) प्रशिक्षण के लिए, सूचना के प्रसार और अनुसंधान की वृद्धि करने के लिए, जिसके अंतर्गत अवसंरचना विकास के क्षेत्र में अध्ययन, अनुसंधान, तकनीकी-आर्थिक और अन्य सर्वेक्षण कराना भी है, सुविधाएं प्रदान करना और उक्त प्रयोजनों के लिए वह ऋण या अधिदाय या अनुदान, जिसके अंतर्गत अध्येतावृत्ति के लिए उपबंध के माध्यम से अनुदान भी हैं, दे सकेगा और किसी संस्था की अध्यक्षता करना;

(ग) अवसंरचना विकास क्रियाकलापों में लगे हुए किसी व्यक्ति को तकनीकी, विधिक, विपणन और प्रशासनिक सहायता प्रदान करना;

(घ) अवसंरचना विकास, परियोजना संरचना, पूंजी संरचना या प्रवर्तन के लिए पश्चातवर्ती प्रचालन और भारत में या भारत से बाहर संबंधित अन्य मामलों के क्षेत्र में परामर्शी सेवाएं प्रदान करना;

(ङ) किन्हीं डिबेंचरों, डिबेंचर स्टॉक या अन्य प्रतिभूतियों या बाध्यताओं को गठित करने वाले या उन्हें सुनिश्चित करने वाले किन्हीं विलेखों के न्यासी के रूप में कार्य करना और कोई अन्य न्यास प्रारंभ करना और उसका निष्पादन करना तथा निष्पादक, प्रशासक, प्रापक, कोषाध्यक्ष, अभिरक्षक और न्यास निगम का पद ग्रहण करना और उनकी शक्तियों का प्रयोग करना;

(च) किसी उपक्रम का अर्जन करना, जिसके अंतर्गत किसी संस्था का ऐसा कारबार, आस्तियां और दायित्व भी हैं जिनका मुख्य उद्देश्य भारत में या भागतः भारत में और भागतः भारत से बाहर अवस्थित परियोजनाओं के लिए अवसंरचना वित्तपोषण की वृद्धि करना या उसका विकास करना है;

(छ) भारत में या भागतः भारत में और भागतः भारत से बाहर अवस्थित अवसंरचना परियोजनाओं और सुविधाओं की वृद्धि, वित्तपोषण और विकास के प्रयोजन के लिए समुचित वित्तीय लिखतों के विकास और प्रसार, सभी प्रकृति के ऋणों और अधिदायों के परक्राम्य और संसाधनों के संग्रहण के लिए स्कीमें विनिर्मित करने के माध्यम से वित्तीय मध्यवर्ती के रूप में कार्य करना;

(ज) भारत में या भागतः भारत में और भागतः भारत से बाहर अवस्थित अवसंरचना परियोजनाओं के प्रस्तावकों और अवसंरचना परियोजनाओं में विनिधानकर्ताओं के साथ प्रस्तावों की संरचना करना और करारों पर बातचीत करना;

(झ) भारत में या भारत से बाहर के किसी बैंक में कोई खाता खोलना या किसी अभिकरण के साथ ठहराव करना या भारत में या भारत से बाहर के किसी बैंक या अन्य संस्था के अभिकर्ता या सम्पर्की के रूप में कार्य करना; और

(ज) ऐसे अन्य कार्य या चीजें करना जो इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उसकी शक्तियों का प्रयोग करने या उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने का आनुषंगिक या पारिणामिक हो, जिसके अंतर्गत उसकी किन्हीं आस्तियों का विक्रय या अंतरण भी है।

(3) केंद्रीय सरकार, संस्था द्वारा उससे अनुरोध किए जाने पर संस्था द्वारा जारी किए गए बंधपत्रों, डिबेंचरों और ऋणों को प्रत्याभूत कर सकेगी जिससे मूल का प्रतिदाय और ब्याज का संदाय ऐसी दर, निबंधनों और शर्तों पर किया जा सके, जिस पर केंद्रीय सरकार सहमत हो।

18. (1) संस्था, अपने स्वयं के बंधपत्रों या डिबेंचरों की प्रतिभूति पर कोई ऋण या अधिदाय नहीं देगी।

प्रतिषिद्ध
कारबार।

(2) संस्था, किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्ति-निकाय को, जिसमें संस्था का कोई निदेशक स्वत्वधारी, भागीदार, निदेशक, कर्मचारी या प्रत्याभूति-दाता है या जिसमें संस्था के एक या अधिक निदेशक कोई सारवान् हित रखते हैं, कोई ऋण या अधिदाय नहीं देगी।

(3) उपधारा (2) किसी ऐसे उधार लेने वाले पर लागू नहीं होगी यदि संस्था का कोई निदेशक, संस्था या केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसे उधार लेने वाले के बोर्ड में निदेशक के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाता है या संस्था द्वारा ऐसे उधार लेने वाले में धारित शेयरों के आधार पर ऐसे उधार लेने वाले को बोर्ड में निर्वाचित किया जाता है।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए, किसी उधार लेने वाले के संबंध में “सारवान् हित” से संस्था के एक या अधिक निदेशकों द्वारा या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (77) में यथापरिभाषित ऐसे निदेशक के किसी नातेदार द्वारा उधार लेने वाले के शेयर में या तो एकल रूप में या साथ-साथ धारित फायदाप्रद हित अभिप्रेत है और उस पर समादत्त सकल रकम या तो पचास लाख रुपए से अधिक या उधार लेने वाले की समादत्त शेयर पूंजी का दो प्रतिशत, जो भी कम हो या ऐसी अन्य सीमा है, जो विहित की जाए।

19. (1) बोर्ड की सम्मति के बिना और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, संस्था किसी संबंधित पक्षकार के साथ निम्नलिखित के संबंध में कोई संविदा या ठहराव नहीं करेगी—

संबंधित पक्षकार
संव्यवहार।

(क) किसी भी माल या सामग्रियों का विक्रय, क्रय या पूर्ति करना ;

(ख) किसी भी किस्म की संपत्ति का विक्रय या अन्यथा निपटान या क्रय करना ;

(ग) किसी भी किस्म की संपत्ति को पट्टे पर देना ;

(घ) किन्हीं सेवाओं का लेना या प्रदान करना ;

(ङ) माल, सामग्रियों, सेवाओं या संपत्ति का क्रय या विक्रय करने के लिए किसी अभिकर्ता की नियुक्ति करना ;

(च) ऐसे संबंधित पक्षकार की संस्था में, उसकी समनुषंगियों या संयुक्त उद्यमों या सहयोजित कंपनियों में किसी पद या लाभ के स्थान पर नियुक्ति करना ;

(छ) संस्था की किन्हीं प्रतिभूतियों या उसकी व्युत्पन्नियों के अभिदान की हामीदारी करना :

परंतु कोई संविदा या ठहराव, शेयरधारकों की साधारण बैठक में पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा, जिसमें ऐसी धनराशियों, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, से अधिक का संव्यवहार अंतर्वलित है :

परंतु यह और कि कोई शेयरधारक ऐसी साधारण बैठक में किसी संविदा या ठहराव, जो संस्था द्वारा किया जाए, का अनुमोदन करने के लिए मत नहीं देगा, यदि ऐसा शेयरधारक संबंधित पक्षकार है :

परंतु यह भी कि इस उपधारा की कोई बात, संस्था द्वारा संव्यवहारों से भिन्न कारबार के अपने साधारण अनुक्रम में किए गए किन्हीं संव्यवहारों, जो आसन्निकट के आधार पर नहीं हैं, को लागू नहीं होगी :

परंतु यह भी कि पहले परंतुक के अधीन अनुमोदन की आवश्यकता, ऐसे संव्यवहारों के लिए लागू नहीं होगी, जो संस्था और उसके पूर्णतया स्वामित्वाधीन समनुषंगी, यदि कोई हो, जिसके वित्तीय विवरणों को संस्था के साथ समेकित किया जाता है और अंगीकार किए जाने के लिए साधारण बैठक में शेयरधारकों के समक्ष रखा जाता है, के बीच किए जाते हैं ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में,—

(क) “पद या लाभ का स्थान” पद से कोई ऐसा पद या स्थान अभिप्रेत है—

(i) जहां ऐसा पद या स्थान किसी निदेशक द्वारा धारण किया जाता है, यदि उसे धारण करने वाला निदेशक संस्था से उस पारिश्रमिक का, जिसका वह निदेशक के रूप में हकदार है, वेतन, फीस, कमीशन, परिलब्धियां, किसी भाटक मुक्त आवास या अन्यथा से अधिक पारिश्रमिक के रूप में कुछ भी प्राप्त करता है ;

(ii) जहां ऐसा पद या स्थान निदेशक से भिन्न किसी व्यक्ति या किसी फर्म, प्राइवेट कंपनी या अन्य निगमित निकाय द्वारा धारण किया जाता है, यदि वह व्यक्ति, फर्म, प्राइवेट कंपनी या निगमित निकाय, जो उसे धारण कर रहा है, संस्था से पारिश्रमिक, वेतन, फीस, कमीशन, परिलब्धियां, भाटक मुक्त आवास या अन्यथा के रूप में कुछ भी प्राप्त करता है ;

(ख) “आसन्निकट संव्यवहार” पद से दो संबंधित पक्षकारों के बीच का ऐसा कोई संव्यवहार अभिप्रेत है, जो इस प्रकार से संचालित किया जाता है, मानो वे संबंधित नहीं थे, जिससे हित का कोई विरोध न हो ।

(2) उपधारा (1) के अधीन की गई प्रत्येक संविदा या ठहराव को, शेयरधारकों को बोर्ड द्वारा की गई रिपोर्ट में ऐसी संविदा या ठहराव करने के न्यायोचित्य के साथ निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(3) जहां कोई संविदा या ठहराव, किसी निदेशक या किसी कर्मचारी द्वारा बोर्ड की सहमति या उपधारा (1) के अधीन शेयरधारकों की साधारण बैठक में संकल्प द्वारा अनुमोदन अभिप्राप्त किए बिना किया जाता है और यदि इसका, यथास्थिति, बोर्ड या शेयरधारकों द्वारा किसी बैठक में उस तारीख से तीन मास के भीतर, जिसमें ऐसी संविदा या ठहराव किया गया था, अनुसमर्थन नहीं किया जाता है, तो ऐसी संविदा या ठहराव, यथास्थिति, बोर्ड या शेयरधारकों के विकल्प पर शून्यकरणीय होगा और यदि संविदा या ठहराव किसी निदेशक से संबंधित पक्षकार के साथ है या किसी अन्य निदेशक द्वारा प्राधिकृत किया गया है, तो संबंधित निदेशक संस्था की उसके द्वारा उपगत किसी हानि के लिए क्षतिपूर्ति करेगा।

(4) उपधारा (3) में अंतर्विष्ट किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संस्था किसी निदेशक या किसी अन्य कर्मचारी के विरुद्ध ऐसी संविदा या ठहराव के परिणामस्वरूप हुई किसी हानि की वसूली के लिए कार्यवाही करेगी, जिसने इस धारा के उपबंधों के उल्लंघन करते हुए ऐसी संविदा की थी या ठहराव किया था।

(5) संस्था का कोई निदेशक या कर्मचारी, जिसने इस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में कोई संविदा या ठहराव किया था या करने के लिए प्राधिकृत किया था, तो वह पच्चीस लाख रुपए तक की धनराशि की शास्ति का संदाय करने का दायी होगा।

20. (1) संस्था के कार्य निष्पादन का पुनर्विलोकन, केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले किसी बाह्य अभिकरण द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार किया जाएगा।

संस्था के कार्य
निष्पादन का
पुनर्विलोकन।

(2) बाह्य अभिकरण, धारा 4 में यथा उपवर्णित संस्था के प्रयोजन और उद्देश्यों के संबंध में संस्था के कार्य निष्पादन का पिछले पांच वर्ष का पुनर्विलोकन करेगा और ऐसे मुख्य कार्य निष्पादन उपदर्शकों को हिसाब में लेगा, जो विहित किए जाएं।

(3) बाह्य अभिकरण, अपने निष्कर्षों की एक रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत करेगा, जो की गई कार्रवाई, यदि कोई हो, के साथ उसकी एक प्रति ऐसी रिपोर्ट के अनुसरण में रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर केंद्रीय सरकार को भेजेगा।

अध्याय 5

सरकारी अनुदान, प्रत्याभूतियां और अन्य रियायतें

21. (1) केंद्रीय सरकार, नकद या विपणीय सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में अनुदान या अभिदाय के माध्यम से, जब कभी आवश्यक हो, संस्था की सहायता कर सकेगी।

अनुदान और
अभिदाय।

(2) पूर्वगामी की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्रीय सरकार, संस्था की स्थापना से पहले वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक, नकद या विपणीय सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में संस्था को पांच हजार करोड़ रुपए की रकम का अनुदान या अंशदान करेगी।

22. सरकार, 0.1 प्रतिशत से अनधिक फीस की रियायती दर विहित कर सकेगी, जिस पर सरकारी प्रत्याभूति का विस्तार संस्था पर, बहुपक्षीय संस्थाओं, संप्रभू संपदा

सरकारी
प्रत्याभूति की
रियायती दर।

निधियों और ऐसी अन्य विदेशी संस्थाओं से, जो विहित की जाएं, उधार लेने के लिए किया जा सकेगा।

बचाव लागत।

23. विनिमय दरों में किन्हीं उतार-चढ़ावों से संस्था को अलग करने के लिए ऋणों और अधिदायों को प्रदान करने या उसका पुनर्संदाय करने के प्रयोजनों के लिए संस्था द्वारा विदेशी मुद्रा को उधार लेने के संबंध में बचाव लागत की प्रतिपूर्ति केंद्रीय सरकार द्वारा भागतः या पूर्णतः की जा सकेगी।

अध्याय 6

लेखा, लेखापरीक्षा और रिपोर्ट

संस्था को उद्भूत होने वाले लाभों का आरक्षित निधि में व्ययन।

24. (1) संस्था, एक आरक्षित निधि की स्थापना करेगी, जिसमें संस्था को उद्भूत होने वाले वार्षिक लाभों में से ऐसी धनराशियों का अंतरण किया जा सकेगा, जिसे बोर्ड ठीक समझे :

परंतु इस उपधारा के अधीन अंतरित की जाने वाली धनराशियां, संस्था को उद्भूत होने वाले वार्षिक लाभों के बीस प्रतिशत से कम नहीं होंगी।

(2) डूबंत और शंकास्पद ऋणों, आस्तियों का अवक्षयण और अन्य सभी विषय, जिनके लिए उपबंध किया जाना आवश्यक या समीचीन है या जिनके लिए बैंककारों द्वारा प्रायः उपबंध किया जाता है और उपधारा (1) में निर्दिष्ट आरक्षित निधि के लिए उपबंध किए जाने के पश्चात् और लाभ के एक भाग को ऐसी अन्य आरक्षितियाँ या निधियों में अंतरित किए जाने के पश्चात्, जो समुचित समझी जाएं, बोर्ड अपने शुद्ध लाभ में से लाभांश का प्रस्ताव कर सकेगा।

तुलनपत्र और लेखाओं का तैयार किया जाना।

25. (1) संस्था का तुलनपत्र और लेखा ऐसे प्ररूप और रीति में तैयार किए जाएंगे, जो विहित की जाए।

(2) बोर्ड, संस्था की बहियों और लेखाओं को प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च को या ऐसी अन्य तारीख को, जो बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाए, बंद करवाएगा और तुलन करवाएगा।

लेखापरीक्षा।

26. (1) संस्था के लेखाओं की लेखापरीक्षा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141 की उपधारा (1) के अधीन लेखापरीक्षकों के रूप में कार्य करने के लिए सम्यक् रूप से अर्हित लेखापरीक्षकों द्वारा की जाएगी, जिनकी नियुक्ति संस्था द्वारा शेयरधारकों की साधारण बैठक में, रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित लेखापरीक्षकों के पैनल में से ऐसी अवधि और ऐसे पारिश्रमिक पर, जो रिजर्व बैंक नियत करे, की जाएगी।

2013 का 18

(2) लेखापरीक्षकों को संस्था के वार्षिक तुलनपत्र की एक प्रति प्रदाय की जाएगी और उनका यह कर्तव्य होगा कि वह लेखाओं और उससे संबंधित वाउचरों के साथ उसकी जांच करें और उन्हें संस्था द्वारा रखी गई सभी बहियों की एक सूची परिदत्त की जाएगी और उनकी सभी युक्तियुक्त समय पर, संस्था की बहियों, लेखाओं, वाउचरों और अन्य दस्तावेजों तक पहुंच होगी।

(3) लेखापरीक्षक ऐसे लेखाओं के संबंध में, संस्था के किसी निदेशक या किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी की जांच कर सकेंगे और वह बोर्ड या अधिकारियों या

संस्था के अन्य कर्मचारियों से ऐसी सूचना और स्पष्टीकरण की अपेक्षा करने के हकदार होंगे, जैसा वह अपने कर्तव्यों के अनुपालन के लिए आवश्यक समझे ।

(4) लेखापरीक्षक संस्था को वार्षिक तुलनपत्र और उनके द्वारा जांच किए गए लेखाओं पर एक रिपोर्ट देंगे तथा ऐसी प्रत्येक रिपोर्ट में वे यह कथन करेंगे कि क्या उनकी राय में तुलनपत्र पूर्ण है और सभी आवश्यक विशिष्टियों को अंतर्विष्ट करते हुए उचित और ठीक प्रकार से तुलनपत्र तैयार किया गया है, जिससे संस्था के कार्यों का सही और उचित दृश्य का प्रदर्शन किया जा सके और यदि उन्होंने बोर्ड या किसी अधिकारी या संस्था के अन्य कर्मचारी से किसी स्पष्टीकरण या सूचना की मांग की थी तो क्या वह दी गई है और क्या वह समाधानप्रद है ।

(5) संस्था, केंद्रीय सरकार और रिजर्व बैंक को उस तारीख से चार मास के भीतर, जिसको लेखाओं को बंद किया जाता है और उनका तुलन किया जाता है, उनके तुलनपत्र और लेखाओं की प्रति सहित लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की एक प्रति और सुसंगत वर्ष के दौरान संस्था के कार्यकरण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी तथा केंद्रीय सरकार उसकी प्राप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष उसे रखेगी ।

27. संस्था, केंद्रीय सरकार और रिजर्व बैंक को समय-समय पर ऐसी विवरणियां प्रस्तुत करेगी, जैसा केंद्रीय सरकार या रिजर्व बैंक अपेक्षा करे ।

विवरणी और रिपोर्ट ।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

28. (1) संस्था से पुनः वित्तपोषण के लिए किसी वित्तीय संस्था द्वारा प्राप्त किन्हीं धनराशि को, संस्था द्वारा अनुदत्त सौकर्य सीमा तक और बकाया शेष को संस्था के लिए न्यास के रूप में वित्तीय संस्था द्वारा प्राप्त किया गया समझा जाएगा तथा तदनुसार उनका ऐसी वित्तीय संस्था द्वारा संस्था को संदाय किया जाएगा ।

न्यास में धारित की जाने वाली प्राप्य राशियाँ ।

(2) जहां संस्था द्वारा किसी वित्तीय संस्था को कोई सौकर्य अनुदत्त किया जाता है, वहां किसी ऐसे संव्यवहार के मद्धे ऐसी वित्तीय संस्था द्वारा धारित सभी प्रतिभूतियां या जो धारित की जा सकेंगी, जिनकी बाबत ऐसा सौकर्य अनुदत्त किया गया है, ऐसी वित्तीय संस्था द्वारा न्यास के रूप में संस्था के लिए धारित की जाएंगी ।

29. (1) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन स्थापित संस्था के अतिरिक्त, किसी विकास वित्तीय संस्था की स्थापना करने की वांछा करता है, वह अनुज्ञप्ति के लिए रिजर्व बैंक को आवेदन करेगा ।

अन्य विकास वित्तीय संस्था की स्थापना ।

(2) रिजर्व बैंक, केंद्रीय सरकार के परामर्श से ऐसे मानदंड, निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विनियमों द्वारा रिजर्व बैंक विनिर्दिष्ट करें, अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगा ।

(3) कोई संस्था, जिसे उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है वह यथास्थिति, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 या बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 के उपबंधों के अध्याधीन होगी ।

अधिकारी और
कर्मचारी ।

(4) रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियम, इस अधिनियम के अधीन स्थापित संस्था को उस सीमा तक लागू होंगे, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो ।

30. (1) संस्था, अपने कृत्यों के दक्ष अनुपालन के लिए उतनी संख्या में अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगी, जो वह आवश्यक या वांछनीय समझे और सेवा में उनकी नियुक्ति की निबंधनों और शर्तों को अवधारित कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त संस्था के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के कर्तव्य और आचरण, निबंधन और सेवा की अन्य शर्तें, जिसके अंतर्गत उनके वेतन और भत्ते तथा उनके फायदे के लिए भविष्य निधि या किसी अन्य निधि की स्थापना और अनुरक्षण भी है, वे होंगे, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए :

परंतु अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्तों का अवधारण, बाजार मानकों द्वारा मार्गदर्शित नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति द्वारा किया जाएगा ।

(3) संस्था, किसी अधिकारी या अपने कर्मचारिवृंद के किसी सदस्य को ऐसी अवधि के लिए और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो अवधारित की जाए, किसी अन्य संस्था में, जिसके अंतर्गत कोई अवसंरचना वित्त या विकास संस्था भी है, तैनात कर सकेगी ।

(4) संस्था, किसी संस्था से, जिसके अंतर्गत कोई अवसंरचना वित्त या विकास संस्था भी है, किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को ऐसी अवधि के लिए और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, प्रतिनियुक्ति पर प्राप्त कर सकेगी या ले सकेगी ।

(5) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात, संस्था को किसी अधिकारी या अपने कर्मचारिवृंद के किसी सदस्य को किसी संस्था में ऐसे वेतन, परिलब्धियों या अन्य निबंधनों और शर्तों पर तैनात करने के लिए सशक्त नहीं करेगी, जो उसके लिए उससे या उनसे जिसका वह ऐसी प्रतिनियुक्ति से ठीक पूर्व हकदार है, कम अनुकूल है ।

केंद्रीय सरकार की
नियम बनाने की
शक्ति ।

31. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) वे संस्थाएं, जो धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन संस्था के शेयर को धारण कर सकेंगी ;

(ख) धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (ड) के अधीन शेयरधारकों द्वारा निदेशकों का चयन करने की रीति ;

(ग) धारा 6 की उपधारा (5) के अधीन बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों के समावेशन की निबंधन और शर्तें ;

(घ) उपधारा (3) के अधीन स्वतंत्र निदेशकों की बाबत फीस और प्रतिपूर्ति

तथा धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, उप प्रबंध निदेशक और बोर्ड के अन्य निदेशकों की पदावधि तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;

(ड) धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन बोर्ड और समिति के सदस्यों द्वारा हित का प्रकटन करने की रीति ;

(च) धारा 18 की उपधारा (3) के स्पष्टीकरण के अधीन संस्था के निदेशकों या ऐसे निदेशक के किसी नातेदार द्वारा फायदाप्रद हित का अवधारण करने की सीमा ;

(छ) धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन वे शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए संस्था कोई संविदा या ठहराव कर सकेगी ;

(ज) ऐसे मानदंड, जिनके आधार पर बाह्य अभिकरण, धारा 20 की उपधारा (2) के अधीन संस्था के कार्य निष्पादन का पुनर्विलोकन करेगा ;

(झ) धारा 22 के अधीन सरकार के लिए फीस की दर ;

(ञ) वह प्ररूप और रीति, जिसमें धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन संस्था का तुलनपत्र और लेख तैयार किए जाएंगे ;

(ट) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए ।

32. (1) बोर्ड, केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से और रिजर्व बैंक के परामर्श से सभी विषयों का उपबंध करने के लिए, जिसके लिए इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए उपबंध करना आवश्यक या समीचीन है, अधिसूचना द्वारा विनियम बना सकेगा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन प्रबंध निदेशक और उप प्रबंध निदेशक को संदेय वेतन और भत्ते ;

(ख) धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन बोर्ड के कार्य संचालन के संबंध में समय, स्थान और प्रक्रिया के नियम ;

(ग) धारा 15 की उपधारा (5) के अधीन समितियों के कार्य संचालन के संबंध में समय, स्थान और प्रक्रिया के नियम तथा उनके कृत्य ;

(घ) धारा 19 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन संव्यवहारों के लिए रकम ;

(ड) उपधारा (2) के अधीन संस्था के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की निबंधन और अन्य शर्तें तथा धारा 30 की उपधारा (4) के अधीन प्रतिनियुक्ति की निबंधन और शर्तें ;

(च) धारा 16 की उपधारा (5) और धारा 19 की उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट शास्तियों का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन तंत्र ;

बोर्ड की
विनियम बनाने
की शक्ति ।

(छ) कोई अन्य विषय, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना है या विनिर्दिष्ट किया जाए ।

नियमों और
विनियमों का
संसद् के समक्ष
रखा जाना ।

33. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और विनियम, उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, जो एक सत्र में या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के तुरंत बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियम में कोई उपांतर करने के लिए सहमत हो जाते हैं कि वह नियम या विनियम नहीं बनाए जाने चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम या विनियम, यथास्थिति, ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होंगे या निष्प्रभावी हो जाएंगे; तथापि, ऐसा उपांतरण या बातिलीकरण उस नियम या विनियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमन्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया जाएगा ।

सदभावपूर्वक की
गई कार्रवाई का
संरक्षण ।

34. इस अधिनियम के या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन सदभावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए संस्था या उसके अध्यक्ष या अन्य निदेशकों, कर्मचारियों या अधिकारियों के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां, जिसके अंतर्गत संस्था को सृजित या अन्तरित आस्तियों की बाबत भी है, नहीं की जाएगी ।

पूछताछ, जांच,
अन्वेषण और
अभियोजन के
लिए मंजूरी ।

35. (1) कोई अन्वेषण अभिकरण, जिसके अंतर्गत पुलिस, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, प्रवर्तन निदेशालय और ऐसे अन्य अभिकरण भी हैं, किंतु जो इन्हीं तक सीमित नहीं है, किसी ऐसे अपराध के बारे में कोई पूछताछ या जांच या अन्वेषण नहीं करेगा, जिसे निम्नलिखित के पूर्व अनुमोदन के बिना, संस्था के अध्यक्ष या अन्य निदेशकों, कर्मचारियों या अधिकारियों द्वारा उनके पदीय कृत्यों या कर्तव्यों के निर्वहन में की गई किसी सिफारिश या किए गए विनिश्चय के संबंध में किसी विधि के अधीन किया जाना अभिकथित किया गया है,—

(क) जहां अपराध, अध्यक्ष या अन्य निदेशकों द्वारा किया जाना अभिकथित किया गया है, वहां केंद्रीय सरकार के ; या

(ख) जहां अपराध, संस्था के किसी कर्मचारी या अधिकारी द्वारा किया जाना अभिकथित किया गया है, वहां प्रबंध निदेशक के :

परन्तु ऐसे मामलों के लिए, जिनमें किसी व्यक्ति की स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई अनुचित लाभ स्वीकार करने या स्वीकार करने का प्रयत्न करने के आरोप में मौके पर गिरफ्तारी अन्तर्वलित है, ऐसा कोई अनुमोदन आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु यह और कि, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या प्रबंध निदेशक अपने विनिश्चय को तीन मास की अवधि के भीतर सूचित करेगा और ऐसी अवधि, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या प्रबंध निदेशक द्वारा उन कारणों से, जो अभिलिखित किए जाएं, एक मास की अतिरिक्त अवधि तक बढ़ायी जा सकेगी :

परन्तु यह भी कि केंद्रीय सरकार या प्रबंध निदेशक के, दूसरे परन्तुक के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर इस उपधारा के अधीन अपने विनिश्चय को सूचित करने में

असफल रहने पर कोई पूछताछ या जांच या अन्वेषण आरंभ करने के लिए समझें गए अनुमोदन के रूप में नहीं माना जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, “अनुचित लाभ” पद का वही अर्थ होगा, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में उसका है ।

1988 का 49

(2) कोई न्यायालय, संस्था के अध्यक्ष या अन्य निदेशकों, कर्मचारियों या अधिकारियों द्वारा किसी विधि के अधीन अभिकथित किए गए किसी दंडनीय अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, जिसके लिए निम्नलिखित की पूर्व मंजूरी के बिना, उपधारा (1) के अधीन कोई पूछताछ या जांच या अन्वेषण करने की मंजूरी प्रदान की गई थी—

(क) जहां अपराध, अध्यक्ष या अन्य निदेशकों द्वारा किया जाना अभिकथित किया गया है, वहां केंद्रीय सरकार की ; या

(ख) जहां अपराध, संस्था के किसी कर्मचारी या अधिकारी द्वारा किया जाना अभिकथित किया गया है, वहां प्रबंध निदेशक की :

परंतु केंद्रीय सरकार या प्रबंध निदेशक, इस उपधारा के अधीन अभियोजन के लिए मंजूरी की अपेक्षा करने वाले प्रस्ताव प्राप्त हो जाने के पश्चात्, ऐसे प्रस्ताव पर विनिश्चय को इसकी प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर सूचित करने का भरसक प्रयास करेगी या करेगा :

परंतु यह और कि उस दशा में, जहां अभियोजन के लिए मंजूरी प्रदान करने के प्रयोजन के लिए, विधिक परामर्श की अपेक्षा की जाती है, वहां ऐसी अवधि को, ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किए जाएं, एक मास की अतिरिक्त अवधि तक बढ़ायी जा सकेगी :

परंतु यह भी कि विनिर्दिष्ट समय के भीतर इस उपधारा के अधीन अपना विनिश्चय संसूचित करने में केंद्रीय सरकार या प्रबंध निदेशक की असफलता को अभियोजन के आरंभ किए जाने के लिए समझा गया अनुमोदन के रूप में नहीं माना जाएगा ।

36. (1) जहां उधार लेने वाली किसी इकाई के साथ ऋण और अग्रिम प्रदान करते समय संस्था द्वारा किया गया कोई ठहराव, ऐसी इकाई के एक या अधिक निदेशकों की संस्था द्वारा नियुक्ति या नामनिर्देशन के लिए उपबंध करता है, वहां ऐसा उपबंध और उसके अनुसरण में की गई निदेशकों की नियुक्ति, कंपनी अधिनियम, 2013 में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या ज्ञापन और संगम के अनुच्छेदों या इकाई से संबंधित किसी अन्य लिखत में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, विधिमान्य और प्रभावी होगी, और शेयर अर्हता, आयु सीमा, निदेशक पदों की संख्या, निदेशकों का पद से हटाए जाने और ऐसी किसी विधि या पूर्वोक्त लिखत में अंतर्विष्ट ऐसी ही शर्तों के बारे में कोई उपबंध यथापूर्वोक्त ठहराव के अनुसरण में संस्था द्वारा नियुक्त किसी निदेशक को लागू नहीं होगा ।

संस्था द्वारा
निदेशकों की
नियुक्ति का
अभिभावी
होना ।

2013 का 18

(2) यथापूर्वोक्त रूप में नियुक्त कोई निदेशक—

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन स्वतंत्र निदेशकों को उपलब्ध उन्मुक्तियों के प्रयोजन के लिए स्वतंत्र निदेशक समझा जाएगा ;

2013 का 18

(ख) संस्था के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा और संस्था के लिखित आदेश द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा हटाया जा सकेगा या प्रतिस्थापित किया जा सकेगा ;

(ग) स्वयं के निदेशक होने के कारण ही या निदेशक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए लोप की गई किसी बात या उसके संबद्ध में किसी बात के लिए कोई बाध्यता या दायित्व उपगत नहीं करेगा ;

(घ) चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्ति के लिए दायी नहीं होगा और उस पर ऐसी सेवानिवृत्ति के लिए दायी निदेशकों की संख्या की संगणना करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा ।

ऋण या अग्रिम की विधिमान्यता पर प्रश्न न किया जाना ।

37. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में संस्था द्वारा मंजूर किए गए किसी ऋण या अग्रिम की विधिमान्यता को यथापूर्वोक्त ऐसी अन्य विधि या किसी संकल्प, संविदा, ज्ञापन, संगम अनुच्छेदों या अन्य लिखत की अपेक्षाओं के अननुपालन के आधार पर भी प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा की कोई बात, किसी कंपनी को कोई ऋण या अग्रिम अभिप्राप्त करने के लिए वहां समर्थ नहीं बनाएगी, जहां ऐसी कंपनी के गठन से संबंधित लिखत ऐसी कंपनी को ऐसा करने के लिए सशक्त नहीं करती है ।

विश्वसनीयता और गोपनीयता के संबंध में बाध्यताएं ।

38. (1) संस्था, इस अधिनियम के द्वारा या किसी अन्य विधि के द्वारा जैसा अपेक्षित है, उसके सिवाय, ऐसी परिस्थितियों में, के सिवाय, जिनमें विधि या बैंककारों में परिपाटी और रुढ़िजन्य प्रथा के अनुसार, संस्था के संबंध में ऐसी जानकारी प्रकट करने के लिए आवश्यक या उचित हैं, उसके संघटकों से संबंधित या उसके कार्यकलापों से संबंधित कोई जानकारी प्रकट नहीं करेगा ।

(2) प्रत्येक निदेशक, समिति का सदस्य, संस्था या रिजर्व बैंक का लेखापरीक्षक, अधिकारी या अन्य कर्मचारी जिसकी सेवाएं इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन संस्था द्वारा उपयोग की जाती हैं, अपने कर्तव्य ग्रहण करने से पूर्व, पहली अनुसूची में दिए गए प्ररूप में विश्वसनीयता और गोपनीयता की घोषणा करेगा ।

न्यायनिर्णयन ।

39. (1) बोर्ड, धारा 16 की उपधारा (5) और धारा 19 की उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट शास्तियों का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए एक तंत्र स्थापित करने हेतु विनियम बनाएगा ।

(2) विनियमों में, यथास्थिति, निदेशक या किसी कर्मचारी को, जिसके विरुद्ध धारा 16 या धारा 19 के उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए शिकायत की जाती है, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर तथा शास्ति अधिरोपित करने वाले किसी आदेश के विरुद्ध अपील करने के अधिकार के लिए उपबंध होगा ।

निदेशकों की क्षतिपूर्ति ।

40. (1) प्रत्येक निदेशक को, उसके द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में या उसके संबंध में, सिवाय ऐसे कर्तव्यों के जो उसके द्वारा जानबूझकर किए गए कार्य या व्यतिक्रम के कारण हुए हों, उपगत ऐसी सभी हानियों और व्ययों के लिए संस्था द्वारा क्षतिपूर्ति की जाएगी ।

(2) कोई निदेशक, संस्था के किसी अन्य निदेशक के प्रति या किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के प्रति या संस्था की ओर से अर्जित या ली गई किसी संपत्ति या प्रतिभूति के मूल्य या हक की किसी अपर्याप्तता या कमी या किसी ऋणी या संस्था के प्रति बाध्यता के अधीन किसी व्यक्ति के दिवालियापन या सदोष कार्य या अपने पद के कर्तव्यों के निष्पादन में या उसके संबंध में सद्भावपूर्वक की गई किसी बात के परिणामस्वरूप संस्था को होने वाली किसी हानि या व्ययों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

1891 का 18

41. बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891, संस्था के संबंध में इस प्रकार लागू होगा, मानो वह उस अधिनियम की धारा 2 में यथापरिभाषित कोई बैंक हो।

बैंककार बही
साक्ष्य
अधिनियम,
1891 का संस्था
के संबंध में
लागू होना।

1949 का 10

42. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 34क और 36कघ के उपबंध संस्था को लागू होंगे।

बैंककारी
विनियमन
अधिनियम,
1949 की धारा
34क और धारा
36कघ का
संस्था को लागू
होना।

43. कंपनियों के परिसमापन से संबंधित विधि का कोई उपबंध संस्था को लागू नहीं होगा और समापन में संस्था को, केंद्रीय सरकार के आदेश से और ऐसी रीति में ही रखा जाएगा, जैसा वह निदेश करे, अन्यथा नहीं।

संस्था का
समापन।

44. इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संस्था इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का पालन करने में, ऐसी नीति के प्रश्नों पर ऐसे निदेशों द्वारा आबद्ध होगी, जो केंद्रीय सरकार, समय-समय पर, उसे लिखित में दे।

केंद्रीय सरकार
की निदेश जारी
करने की
शक्ति।

45. इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी ऐसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाले किसी लिखत में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे।

इस अधिनियम
का अध्यारोही
प्रभाव होना।

46. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी या ऐसे निदेश दे सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

कठिनाइयों को
दूर करने की
शक्ति।

परंतु ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके बनाए जाने के शीघ्र

पश्चात्, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

1934 का
अधिनियम संख्यांक
2 का संशोधन ।

47. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 का, दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा ।

1949 का
अधिनियम संख्यांक
10 का संशोधन ।

48. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 का, तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा ।

पहली अनुसूची

[धारा 38(2) देखिए]

विश्वसनीयता और गोपनीयता की घोषणा

मैं, एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक के, यथास्थिति, निदेशक, लेखापरीक्षक, अधिकारी या अन्य कर्मचारी के रूप में मुझसे अपेक्षित कर्तव्यों का और जिनका संबंध उचित तौर से उक्त संस्था में मेरे द्वारा धारित पद या ओहदे से है, निष्ठापूर्वक, सत्यनिष्ठा से और अपनी पूर्ण कुशलता तथा योग्यता से निष्पादन और पालन करूंगा।

2. मैं यह और घोषणा करता हूँ कि मैं उक्त संस्था के कार्यों से या उक्त संस्था से व्यवहार करने वाले किसी व्यक्ति के कार्यों से संबंधित कोई जानकारी, उसके लिए किसी व्यक्ति को, जो उसका विधिक रूप से हकदार नहीं है, संसूचित नहीं करूंगा या संसूचित नहीं होने दूंगा और न किसी ऐसे व्यक्ति को उक्त संस्था का या उसके कब्जे में की तथा उक्त संस्था के कारबार या उक्त संस्था से व्यवहार करने वाले किसी व्यक्ति के कारबार से संबंधित किन्हीं बहियों या दस्तावेजों का निरीक्षण करने दूंगा और न उसकी उन तक पहुँच होने दूंगा।

मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए

(हस्ताक्षर)

दूसरी अनुसूची

[धारा 47 देखिए]

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 का संशोधन

धारा 2 का
संशोधन ।

1. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में, खंड (गगग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“(गगग) “राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक” से राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 की धारा 3 के अधीन स्थापित संस्था अभिप्रेत है ;

(गगगii) “अन्य विकास वित्तीय संस्था” से राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 की धारा 29 के अधीन अनुज्ञप्त कोई विकास वित्तीय संस्था अभिप्रेत है ;”।

धारा 17 का
संशोधन ।

2. मूल अधिनियम की धारा 17 में,—

(क) उपधारा (4छ) में, “या लघु उद्योग बैंक” शब्दों के पश्चात्, “या राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक या अन्य विकास वित्तीय संस्था” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपधारा (4झ) में, “औद्योगिक वित्त निगम” शब्दों के पश्चात् “राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक या अन्य विकास वित्तीय संस्था” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ग) उपधारा (4ट) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(4ठ) राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक या अन्य विकास वित्तीय संस्था को,—

(क) ऐसे स्टॉकों, निधियों और प्रतिभूतियों (स्थावर संपत्ति से भिन्न) के प्रतिभूति पर, जिनमें न्यास-धन विनिहित करने के लिए कोई न्यासी भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा प्राधिकृत है, ऐसा उधार या अग्रिम देना, जो मांगे जाने पर या उस उधार या अग्रिम की तारीख से नब्बे दिन से अनधिक की नियत अवधि के अवसान पर प्रतिसंदेय है ; या

(ख) ऐसे विनिमयपत्रों या वचनपत्रों की प्रतिभूति पर उधार और अग्रिम देना, जो सद्भावपूर्वक किए गए वाणिज्यिक या व्यापारिक संव्यवहारों से उद्भूत होते हैं, जिन पर दो या अधिक मान्य हस्ताक्षर हैं और जो ऐसी उधार या अग्रिम की तारीख से पांच वर्ष के भीतर परिपक्व होते हैं ;”;

(घ) उपधारा (12ख) में, “औद्योगिक वित्त निगम” शब्दों के पश्चात्, “राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक या अन्य विकास वित्तीय संस्था” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

3. मूल अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (ii) में, “अथवा लघु उद्योग बैंक से” शब्दों के पश्चात्, “या राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक से या अन्य विकास वित्तीय संस्था से” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 42 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 46ग की उपधारा (2) में,—

धारा 46ग का संशोधन ।

(क) खंड (ग) में, “या लघु उद्योग बैंक” शब्दों के पश्चात् “या राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक या अन्य विकास वित्तीय संस्था” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) खंड (घ) में, “या लघु उद्योग बैंक” शब्दों के पश्चात् “या राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक या अन्य विकास वित्तीय संस्था” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

तीसरी अनुसूची

[धारा 48 देखिए]

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 का संशोधन

धारा 5 का
संशोधन।

1. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 5 में, खंड (जक) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“(जख) “राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक” से राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 की धारा 3 के अधीन स्थापित संस्था अभिप्रेत है ;

(जग) “अन्य विकास वित्तीय संस्था” से राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 की धारा 29 के अधीन अनुज्ञप्त विकास वित्तीय संस्था अभिप्रेत है ;”।

धारा 18 का
संशोधन ।

2. मूल अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के खंड (क) के उपखंड (ii) में, “लघु उद्योग बैंक से” शब्दों के पश्चात्, “या राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक से या अन्य विकास वित्तीय संस्था से” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 34क का
संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 34क की उपधारा (3) में, “लघु उद्योग बैंक,” शब्दों के पश्चात्, “राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक या अन्य विकास वित्तीय संस्था,” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 36कघ का
संशोधन।

4. धारा 36कघ की उपधारा (3) में, “लघु उद्योग बैंक,” शब्दों के पश्चात्, “राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक या अन्य विकास वित्तीय संस्था,” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2021

(2021 का अधिनियम संख्यांक 19)

[30 जुलाई, 2021]

खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध की कतिपय संस्थाओं को राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं घोषित करने तथा खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध में शिक्षण और अनुसंधान का उपबंध करने और ऐसी शाखाओं में विद्या की अभिवृद्धि तथा ज्ञान का प्रसार करने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के बहतरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2021 है ।

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे :

परंतु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और किसी ऐसे उपबंध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है ।

कतिपय
संस्थाओं की
राष्ट्रीय महत्व
की संस्थाओं के
रूप में घोषणा ।
परिभाषाएं ।

2. अनुसूची में उल्लिखित संस्थानों के उद्देश्य ऐसे हैं जो उन्हें राष्ट्रीय महत्व की संस्था बनाते हैं । अतः, यह घोषित किया जाता है कि प्रत्येक ऐसा संस्थान एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था है ।

3. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “बोर्ड” से किसी संस्थान के सम्बन्ध में धारा 11 में निर्दिष्ट शासी बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ख) “अध्यक्ष” से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ग) “तत्स्थानी संस्थान” से अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित किसी संस्थान के सम्बन्ध में उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) में यथाविनिर्दिष्ट कोई संस्थान अभिप्रेत है ;

(घ) “परिषद्” से धारा 28 के अधीन स्थापित परिषद् अभिप्रेत है ;

(ङ) “निदेशक” से धारा 19 के अधीन नियुक्त संस्थान का निदेशक अभिप्रेत है ;

(च) “विद्यमान संस्थान” से अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित संस्थान अभिप्रेत है ;

(छ) “निधि” से धारा 33 के अधीन बनाई रखी जाने वाली संस्थान की निधि अभिप्रेत है ;

(ज) “संस्थान” से अनुसूची के स्तम्भ (3) में उल्लिखित संस्थान अभिप्रेत है ;

(झ) “सदस्य” से बोर्ड का कोई सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है ;

(ञ) “अधिसूचना” से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(ट) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ठ) “कुलसचिव” से धारा 20 के अधीन नियुक्त संस्थान का कुलसचिव अभिप्रेत है ;

(ड) “अनुसूची” से इस अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ;

(ढ) “सिनेट” से धारा 16 में निर्दिष्ट संस्थान की सिनेट अभिप्रेत है ;

(ण) “सोसाइटी” से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन सोसाइटी के रूप में रजिस्ट्रीकृत विद्यमान संस्थान अभिप्रेत है ;

(त) किसी संस्थान के सम्बन्ध में “परिनियम और अध्यादेश” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए उस संस्थान के परिनियम और अध्यादेश अभिप्रेत हैं ।

अध्याय 2

संस्थान

संस्थानों का
निगमन ।

4. इस अधिनियम प्रारम्भ के तारीख से ही, अनुसूची के स्तम्भ (3) में उल्लिखित प्रत्येक संस्थान का एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, चल और अचल दोनों ही प्रकार की संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने तथा संविदा करने की शक्ति होगी और वह उक्त नाम से वाद लाएगा या उसके विरुद्ध वाद लाया जाएगा ।

5. इस अधिनियम के प्रारम्भ के तारीख से ही,—

(क) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या किसी संविदा या अन्य लिखत में विद्यमान संस्थान के प्रति किसी निर्देश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह तत्स्थानी संस्थान के प्रति निर्देश है ;

(ख) किसी विद्यमान संस्थान की या उससे सम्बन्धित सभी चल और अचल संपत्तियां तत्स्थानी संस्थान में निहित हो जाएंगी ;

(ग) किसी विद्यमान संस्थान के सभी अधिकार और दायित्व, तत्स्थानी संस्थान को अंतरित हो जाएंगे और वे उसके अधिकार और दायित्व हो जाएंगे ;

(घ) ऐसे प्रारम्भ से ठीक पूर्व किसी विद्यमान संस्थान द्वारा नियोजित प्रत्येक व्यक्ति तत्स्थानी संस्थान में अपना पद या सेवा, उसी सेवा धृति के साथ, उसी पारिश्रमिक और उन्हीं निबंधनों तथा शर्तों पर और पेंशन, छुट्टी, उपदान, भविष्य निधि और अन्य विषयों के सम्बन्ध में उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों सहित धारण करेगा, जैसे वह उसे उस दशा में धारण करता है, यदि यह अधिनियम पारित नहीं किया गया होता और तब तक इस प्रकार धारण करता रहेगा, जब तक उसका नियोजन समाप्त नहीं कर दिया जाता या जब तक उसकी सेवाधृति, पारिश्रमिक, निबंधन और शर्तें परिणियमों द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तित नहीं कर दी जाती हैं :

परंतु यदि इस प्रकार का किया गया परिवर्तन ऐसे कर्मचारी को स्वीकार्य नहीं है तो उसका नियोजन संस्थान द्वारा उक्त कर्मचारी से की गई संविदा के निबंधनों और शर्तों के अनुसार या, यदि उसमें इस निमित्त कोई उपबंध नहीं किया गया है तो स्थायी कर्मचारी की दशा में तीन मास के पारिश्रमिक और अन्य कर्मचारी की दशा में एक मास के पारिश्रमिक के समतुल्य प्रतिकर का संस्थान द्वारा उसको संदाय करके संस्थान द्वारा समाप्त किया जा सकेगा :

परंतु यह और कि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या किसी लिखत या अन्य दस्तावेज के अधीन विद्यमान संस्थान के निदेशक या कुलपति और अन्य अधिकारियों के प्रति कोई निर्देश, चाहे किन्हीं भी शब्दों में हों, का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह तत्स्थानी संस्थान के निदेशक और अन्य अधिकारियों के प्रति निदेश है ;

(ङ) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व किसी विद्यमान संस्थान में किसी शैक्षणिक या अनुसंधान पाठ्यक्रम का अध्ययन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने उस संस्थान से, जिससे ऐसे व्यक्ति ने प्रव्रजन किया है, पाठ्यक्रम के उसी स्तर पर ऐसे प्रारम्भ पर तत्स्थानी संस्थान को प्रव्रजन कर लिया है और उसके पास रजिस्ट्रीकृत हो गया है ; और

(च) इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व किसी विद्यमान संस्थान द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित सभी वाद और अन्य विधिक कार्रवाइयां या जो उसके द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित किए जा सकते थे, तत्स्थानी संस्थान द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखी जाएंगी या संस्थित की जाएंगी ।

6. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक संस्थान निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा और निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्:—

(क) आहार विज्ञान और खाद्य प्रौद्योगिकी की ऐसी शाखाओं में और

संस्थाओं के
निगमन का
प्रभाव ।

संस्थानों की
शक्तियां और
कृत्य ।

इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रबंध की ऐसी किन्हीं अन्य शाखाओं में, जिसे संस्थान ठीक समझे, शिक्षण और अनुसंधान के लिए और ऐसी शाखाओं में विद्या के अभिवृद्धि और ज्ञान के प्रसार के लिए उपबंध करना ;

(ख) परीक्षाएं आयोजित करना और डिग्रियां, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियां या पदवियां प्रदान करना ;

(ग) मानद डिग्रियां या अन्य उपाधियां प्रदान करना ;

(घ) फीस और अन्य प्रभारों को नियत करना, उनकी मांग करना और उन्हें प्राप्त करना ;

(ङ) छात्रों के निवास के लिए छात्र निवासों और छात्रावासों की स्थापना, उनका रखरखाव और प्रबंध करना ;

(च) संस्थान के सभी प्रवर्गों के कर्मचारियों और छात्रों के अनुशासन का पर्यवेक्षण करना और नियंत्रण करना तथा उनके स्वास्थ्य, सामान्य कल्याण, सांस्कृतिक और सामूहिक जीवन के संवर्धन की व्यवस्था करना ;

(छ) छात्रों के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर की यूनिटों के रखरखाव के लिए उपबंध करना ;

(ज) शैक्षणिक और अन्य पदों को संस्थित करना और निदेशक के सिवाय उन पर नियुक्तियां करना ;

(झ) संस्थान से सम्बन्धित या उसमें निहित किसी संपत्ति के विषय में ऐसी रीति से संव्यवहार करना, जो संस्थान के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए ठीक समझे ;

(ञ) सरकार से दान, अनुदान, सदान या उपकृतियां प्राप्त करना और यथास्थिति, वसीयतकर्ताओं, दानदाताओं या अंतरकों से चल या अचल संपत्ति की वसीयत, सदान और अंतरण प्राप्त करना ;

(ट) विश्व के किसी भी भाग में ऐसी शैक्षणिक या अन्य संस्थाओं के साथ, जिनका उद्देश्य पूर्णतया या भागतः अध्यापकों और विद्वानों के आदान-प्रदान द्वारा संस्थान के उन उद्देश्यों के समरूप है और साधारणतया ऐसी रीति में, जो उनके सामान्य उद्देश्यों के सहायक हों, सहकार करना और उनका सहयोग करना ;

(ठ) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, छात्र-सहायता वृत्ति, पुरस्कार और पदक संस्थित करना और प्रदान करना ; और

(ड) ऐसी सभी बातें करना, जो संस्थान के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हो ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई संस्थान केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी अचल संपत्ति का किसी रीति में व्ययन नहीं करेगा ।

संस्थान का सभी मूलवंश, पंथ और वर्गों के लिए खुला होना ।

7. (1) प्रत्येक संस्थान सभी व्यक्तियों के लिए खुला होगा, चाहे वे किसी लिंग, मूलवंश, पंथ, जाति या वर्ग के हों और सदस्यों, छात्रों, शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों या कर्मकारों को प्रवेश देने या नियुक्त करने में या किसी भी अन्य बात के सम्बन्ध में, वह चाहे जो भी हो, धार्मिक विश्वास या मान्यता के बारे में कोई परीक्षण या शर्त अधिरोपित नहीं की जाएगी ।

(2) किसी भी संस्थान द्वारा किसी ऐसी संपत्ति की कोई वसीयत, संदान या अंतरण स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसमें परिषद् की राय में इस धारा के भाव और उद्देश्य के विरुद्ध शर्तें या बाध्यताएं अंतर्गुह्य हैं ।

(3) प्रत्येक संस्थान में प्रत्येक शैक्षणिक पाठ्यक्रम या अध्ययन के कार्यक्रम में प्रवेश, ऐसे संस्थान द्वारा प्रवेश की प्रक्रिया के प्रारंभ होने के पूर्व उसके प्रास्पेक्टस के माध्यम से प्रकटित पारदर्शी और युक्तियुक्त मानदंड के माध्यम से निर्धारित योग्यता पर आधारित होगा :

परंतु इस धारा की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह संस्थान को महिलाओं, दिव्यांगजनों या सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के और विशिष्टित या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के नियोजन या प्रवेश के लिए विशेष उपबंध करने से निवारित करती है :

परन्तु यह और कि ऐसा प्रत्येक संस्थान केन्द्रीय शिक्षा संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 के प्रयोजनों के लिए एक केन्द्रीय शिक्षा संस्था होगा ।

8. (1) प्रत्येक संस्थान एक अलाभकारी विधिक इकाई होगा और ऐसे संस्थान के राजस्व में के अधिशेष के, यदि कोई हो, किसी भाग को, इस अधिनियम के अधीन उसकी संक्रियाओं के विषय में सभी व्ययों को चुकाने के पश्चात्, ऐसे संस्थान की अभिवृद्धि और विकास अथवा उसमें अनुसंधान करने से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए विनिहित नहीं किया जाएगा ।

(2) प्रत्येक संस्थान अपनी आत्म-निर्भरता और संधारणीयता के लिए निधियां जुटाने का प्रयास करेगा ।

9. प्रत्येक संस्थान में सभी शिक्षण कार्य संस्थान द्वारा या उसके नाम से इस निमित्त बनाए गए परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार किया जाएगा ।

संस्थानों का अलाभकारी विधिक इकाई होना ।

संस्थानों में शिक्षण ।

अध्याय 3

संस्थानों के प्राधिकारी

10. संस्थान के प्राधिकारी निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :—

(क) शासी बोर्ड ;

(ख) सिनेट ; और

(ग) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जो परिनियमों द्वारा संस्थान के प्राधिकारी घोषित किए जाएं ।

संस्थानों के प्राधिकारी ।

11. (1) प्रत्येक संस्थान का शासी बोर्ड उस संस्थान का प्रधान कार्यपालक निकाय होगा ।

शासी बोर्ड ।

(2) प्रत्येक संस्थान का बोर्ड निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) खाद्य उद्योग या शिक्षा या आहार विज्ञान या खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी या प्रबंधन या ऐसे ही अन्य क्षेत्र में विशिष्ट ख्यातिप्राप्त व्यक्तियों में से केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला एक अध्यक्ष ;

(ख) संस्थान का निदेशक—सदस्य, पदेन ;

(ग) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का अध्यक्ष या उसका नामनिर्देशिती—सदस्य, पदेन ;

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का महानिदेशक या उसका नामनिर्देशिती—सदस्य, पदेन ;

(ङ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का एक प्रतिनिधि, जो निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो—सदस्य, पदेन ;

(च) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले दो प्रतिनिधि—सदस्य ;

(छ) भारतीय प्रबंध संस्थान से एक प्रतिनिधि—सदस्य, पदेन ;

(ज) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से एक प्रतिनिधि—सदस्य, पदेन ;

(झ) संस्थान का संकायाध्यक्ष, यदि कोई हो—सदस्य, पदेन ;

(ञ) भारत सरकार, उच्चतर शिक्षा विभाग का सचिव या उसका नामनिर्देशिती—सदस्य, पदेन ;

(ट) आचार्य, सह-आचार्य और सहायक आचार्य में से ज्येष्ठता के चक्रानुक्रम से संस्थान के तीन संकाय सदस्य—सदस्य, पदेन ;

(ठ) सम्बद्ध राज्य सरकार का एक नामनिर्देशिती, जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो—सदस्य, पदेन ;

(ड) संस्थान का कुलसचिव—सदस्य-सचिव, पदेन ।

(3) अध्यक्ष को किन्हीं ऐसे विशेषज्ञों को, जो बोर्ड के सदस्य न हों, बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित करने की शक्ति होगी किन्तु ऐसे आमंत्रित को बैठक में मतदान करने के हकदार नहीं होंगे ।

बोर्ड की शक्तियां
और कृत्य ।

12. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक संस्थान का बोर्ड, संस्थान के कार्यकलापों के साधारण अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होगा और संस्थान की उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा जिनका इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है और उसे सिनेट के कार्यों का पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक संस्थान का बोर्ड निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा और निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्:—

(क) संस्थान के प्रशासन और कार्यकरण से संबंधित नीति के प्रश्नों पर विनिश्चय करना ;

(ख) संस्थान के वार्षिक बजट प्राक्कलनों की परीक्षा करना और उसका अनुमोदन करना ;

(ग) संस्थान के विकास के लिए योजना की परीक्षा करना और उसका अनुमोदन करना तथा ऐसी योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्त के स्रोतों की पहचान करना ;

(घ) अध्ययन के विभागों, संकायों या विद्यालयों की स्थापना करना और संस्थान में अध्ययन कार्यक्रमों या पाठ्यक्रमों को आरंभ करना ;

(ड) केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के पश्चात् देश के भीतर खाद्य प्रसंस्करण अध्ययन और सहबद्ध क्षेत्र केन्द्रों को स्थापित करना ;

(च) डिग्रियां, डिप्लोमा और विद्या संबंधी अन्य विशेष उपाधियां या पदनाम देना और अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, पुरस्कार और पदक संस्थित और प्रदान करना ;

(छ) ऐसी रीति में मानद् उपाधियां देना, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ;

(ज) मानद् पुरस्कार और अन्य उपाधियां देना ;

(झ) शैक्षणिक, प्रशासनिक, तकनीकी और अन्य पदों को सृजित करना और विनियमों द्वारा सेवा की अर्हता, वर्गीकरण, उसके निबंधन और शर्तें तथा ऐसे पदों की नियुक्ति की पद्धति का अवधारण करना ;

(ञ) भारत से बाहर, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार और ऐसे विदेश में तत्समय प्रवृत्त विधियों के उपबंधों के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण अध्ययन और सहबद्ध क्षेत्र केंद्र स्थापित करना ;

(ट) संस्थान के निदेशक को, ऐसे उद्देश्यों के पालन के आधार पर, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, परिवर्तनीय वेतन का संदाय करना ;

(ठ) परिनियम बनाना, उनका संशोधन और निरसन करना ;

(ड) अध्यादेशों पर विचार करना और उनका उपांतरण करना या उन्हें रद्द करना ; और

(ढ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त किए जाएं या समनुदेशित किए जाएं ।

(3) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए बोर्ड, परिनियमों द्वारा, बोर्ड की ऐसी शक्तियां और कृत्यों को, निदेशक को प्रत्यायोजित कर सकेगा, जो वह उचित समझे ।

(4) बोर्ड, संस्थान के उद्देश्यों की उपलब्धियों के संदर्भ में निदेशक के कार्य का वार्षिक पुनर्विलोकन करेगा :

परन्तु ऐसे पुनर्विलोकन में, ऐसे मानदंडों के आधार पर, संस्थान के संकाय सदस्यों के कार्य का पुनर्विलोकन, नियतकालिकता और सौंपे गए कृत्य, जो बोर्ड द्वारा अवधारित किए जाएं, सम्मिलित होंगे ।

(5) बोर्ड, संस्थान के निगमन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर, और उसके पश्चात् प्रत्येक तीन वर्ष में कम से कम एक बार संस्थान के, जिसके अन्तर्गत उसका संकाय भी है, कार्य का, दीर्घकालिक रणनीति के मानदंडों और संस्थान की प्रवाही आयोजना तथा ऐसे अन्य मानदंडों के आधार पर जैसा बोर्ड विनिश्चय करे, मूल्यांकन और पुनर्विलोकन करेगा और ऐसे पुनर्विलोकन की रिपोर्ट को सार्वजनिक करेगा ।

(6) उपधारा (5) में निर्दिष्ट स्वतंत्र अभिकरण या विशेषज्ञ समूह की अर्हता, अनुभव और चयन की रीति वह होगी जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

(7) उपधारा (5) के अधीन मूल्यांकन और पुनर्विलोकन की रिपोर्ट, बोर्ड द्वारा केंद्रीय सरकार को, उस पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाएगी :

परंतु केन्द्रीय सरकार, रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, उसके द्वारा की जाने वाली अगली कार्यवाइयों के सम्बन्ध में बोर्ड को सुझाव दे सकेगी ।

(8) जहां अध्यक्ष या निदेशक की राय में, स्थिति इतनी आपातक है कि संस्थान के हित में तुरन्त विनिश्चय किया जाना आवश्यक है, वहां अध्यक्ष, निदेशक के परामर्श से, अपनी राय के आधारों को अभिलिखित करने के पश्चात्, ऐसे आदेश जारी कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे :

परन्तु ऐसे आदेश, बोर्ड द्वारा अगली बैठक में अनुसमर्थन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे ।

(9) बोर्ड, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अपने कृत्यों का निर्वहन करते हुए, केन्द्रीय सरकार के प्रति जवाबदेह होगा और केन्द्रीय सरकार नीति विषयक मामलों पर लोकहित में बोर्ड को निदेश जारी कर सकेगी ।

(10) बोर्ड को उतनी समितियां नियुक्त करने की शक्ति होगी, जितनी वह इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग के लिए और अपने कृत्यों का पालन करने के लिए आवश्यक समझे ।

बोर्ड के सदस्यों की पदावधि, रिक्तियां और उनको संदेय भते ।

13. (1) इस धारा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अध्यक्ष या पदेन सदस्य से भिन्न, किसी सदस्य की पदावधि, उसकी नियुक्ति या नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी ।

(2) किसी पदेन सदस्य की पदावधि तब तक बनी रहेगी, जब तक वह उस पद को धारण करता है, जिसके आधार पर वह बोर्ड का सदस्य है ।

(3) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पदेन सदस्य से भिन्न कोई पद छोड़ने वाला सदस्य, जब तक कि परिषद् अन्यथा निदेश न दे, उसके स्थान पर सदस्य के रूप में किसी अन्य व्यक्ति के नामनिर्देशित किए जाने तक या छह मास की समाप्ति तक, जो भी पहले हो, पद पर बना रहेगा ।

(4) पदेन सदस्य से भिन्न बोर्ड के सदस्य ऐसे भर्तों के लिए हकदार होंगे, जिनका परिनियमों द्वारा उपबंध किया जाए ।

आकस्मिक रिक्ति का भरा जाना ।

14. जब अध्यक्ष या सदस्य के पद की रिक्ति, चाहे वह हटाए जाने, त्यागपत्र, मृत्यु या अन्यथा के कारण उद्भूत होती है तो ऐसी रिक्ति धारा 11 के उपबंधों के अनुसार ऐसी रिक्ति की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर भरी जाएगी ।

सदस्यों का त्यागपत्र ।

15. अध्यक्ष या पदेन सदस्य से भिन्न, कोई सदस्य, केन्द्रीय सरकार को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित रूप में सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकेगा :

परंतु अध्यक्ष या पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य, जब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे अपना पद पहले ही छोड़ने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाता है, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से छह मास की अवधि की समाप्ति तक या उसके पद पर उसके उत्तराधिकारी के रूप में किसी व्यक्ति को सम्यक् रूप से नियुक्त किए जाने तक या उसकी पदावधि की समाप्ति तक, इसमें जो भी सबसे पहले हो, पद धारण करता रहेगा ।

सिनेट ।

16. (1) सिनेट, संस्थान का प्रधान शिक्षण निकाय होगा, जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) निदेशक — अध्यक्ष, पदेन ;

(ख) कुलसचिव — सदस्य, पदेन ;

(ग) संस्थान में शिक्षा प्रदान करने के प्रयोजन के लिए संस्थान द्वारा उस रूप में नियुक्त या मान्यताप्राप्त आचार्यों के स्तर पर सभी पूर्णकालिक संकाय — सदस्य, पदेन ;

(घ) ऐसे तीन व्यक्तियों को, जो संस्थान के कर्मचारी नहीं हैं, ख्याति प्राप्त विद्वानों में से निदेशक के परामर्श से बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएं, जिनमें से एक-एक आहार विज्ञान, प्रबंधन और खाद्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से होगा — सदस्य ; और

(ङ) कर्मचारिवृन्द के ऐसे अन्य सदस्य, जो परिनियमों में अधिकथित किए जाएं — सदस्य, पदेन ।

(2) उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन नामनिर्देशित सदस्य की पदावधि उसके नामनिर्देशन की तारीख से दो वर्ष की होगी ।

(3) किसी पदेन सदस्य की पदावधि तब तक बनी रहेगी, जब तक वह उस पद को धारण करता है, जिसके आधार पर वह सदस्य है ।

17. इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी संस्थान का सिनेट, संस्थान में शिक्षण, शिक्षा और परीक्षा के स्तरों पर नियंत्रण रखेगी और साधारण विनियमन करेगी और उसको बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगी और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगी जो परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त या समनुदेशित किए जाएं ।

सिनेट के कृत्य ।

18. (1) अध्यक्ष, बोर्ड के अधिवेशनों और संस्थान के दीक्षान्त समारोहों की साधारणतया अध्यक्षता करेगा ।

अध्यक्ष की शक्तियां और कृत्य ।

(2) अध्यक्ष का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि बोर्ड द्वारा किए गए विनिश्चय कार्यान्वित किए जाते हैं ।

(3) अध्यक्ष ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त या समनुदेशित किए जाएं ।

19. (1) निदेशक की नियुक्ति बोर्ड द्वारा की जाएगी ।

निदेशक ।

(2) निदेशक, संस्थान का मुख्य शैक्षणिक और कार्यपालक अधिकारी होगा और संस्थान के उचित प्रशासन के लिए तथा शिक्षा प्रदान करने और उसमें अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(3) निदेशक, बोर्ड के वार्षिक रिपोर्ट और लेखा को प्रस्तुत करेगा ।

(4) निदेशक ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उसे प्रदत्त या समनुदेशित किए जाएं ।

20. (1) प्रत्येक संस्थान का कुलसचिव, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर नियुक्त किया जाएगा जो परिनियमों द्वारा अधिकथित किए जाएं और वह संस्थान के अभिलेखों, सामान्य मुद्रा, निधियों और संस्थान की ऐसी अन्य संपत्तियों का अभिरक्षक होगा जिसे बोर्ड उसके भार साधन में सुपुर्द करे ।

कुलसचिव ।

(2) कुलसचिव बोर्ड, सिनेट और ऐसी समितियों के सचिव के रूप में कार्य करेगा जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(3) कुलसचिव अपने कृत्यों के उचित निर्वहन के लिए निदेशक के प्रति उत्तरदायी होगा ।

(4) कुलसचिव ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम या परिनियमों या निदेशक द्वारा उसे प्रदत्त या समनुदेशित किए जाएं ।

अन्य प्राधिकारी
और अधिकारी ।

21. ऊपर उल्लिखित वर्णित प्राधिकारियों और अधिकारियों से भिन्न अन्य प्राधिकारियों और अधिकारियों की शक्तियां और कृत्य वे होंगे जो परिनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं ।

नियुक्तियां ।

22. प्रत्येक संस्थान के कर्मचारिवृन्द की सभी नियुक्तियां, परिनियमों में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार,—

(क) यदि नियुक्ति शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द में सहायक आचार्य या उसके ऊपर के पद पर की जाती है या यदि नियुक्ति अशैक्षणिक कर्मचारिवृन्द में किसी ऐसे पद पर की जाती है जो वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 से ऊपर है तो बोर्ड द्वारा ; और

(ख) किसी अन्य दशा में, निदेशक द्वारा,
की जाएंगी ।

परिनियम ।

23. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, परिनियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) मानद उपाधियों का प्रदान किया जाना ;

(ख) शिक्षण विभागों का बनाया जाना ;

(ग) संस्थान में अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए और संस्थान की डिग्री एवं डिप्लोमा हेतु परीक्षाओं में प्रवेश के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस ;

(घ) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, छात्र-सहायता वृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों का संस्थित किया जाना ;

(ङ) अर्हताएं, वर्गीकरण, सेवा के निबंधन और शर्तें तथा शैक्षणिक, प्रशासनिक, तकनीकी और अन्य पदों पर नियुक्ति की पद्धति ;

(च) संस्थान के अधिकारियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारिवृन्द के फायदे के लिए पेंशन, बीमा और भविष्य निधियों की स्थापना करना ;

(छ) संस्थान के प्राधिकरणों का गठन, उनकी शक्तियां और कर्तव्य ;

(ज) छात्र-निवास और छात्रावासों की स्थापना और उनका रखरखाव करना ;

(झ) संस्थान के छात्रों के आवास की शर्तें और छात्र-निवासों तथा छात्रावासों में निवास के लिए फीस और अन्य प्रभारों को प्रभारित करना ;

(ञ) बोर्ड के सदस्यों की रिक्तियों को भरने की रीति ;

(ट) बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों को संदत्त किए जाने वाले भत्ते ;

(ठ) बोर्ड के आदेशों और विनिश्चयों का अधिप्रमाणन ;

(ड) संस्थान की वित्तीय जवाबदेही ;

(ढ) बोर्ड, सिनेट या किसी समिति के अधिवेशन, ऐसे अधिवेशनों में गणपूर्ति और उनके कारबार के संचालन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ; और

(ण) कोई ऐसा अन्य विषय, जो इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित है या परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

24. (1) प्रत्येक संस्थान के प्रथम परिनियम, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से परिषद् द्वारा बनाए जाएंगे और उनकी एक प्रति इसके बनाए जाने के पश्चात् संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष यथाशक्य शीघ्र रखी जाएगी ।

परिनियम कैसे बनाए जाएंगे ।

(2) बोर्ड, समय-समय पर, नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या इस धारा में इसके पश्चात् उपबंधित रीति से परिनियमों को संशोधित या निरसित कर सकेगा ।

(3) प्रत्येक नए परिनियम के लिए या परिनियमों में परिवर्धन या परिनियम के किसी संशोधन या निरसन के लिए केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा जो उसका अनुमोदन कर सकेगी या उसे बोर्ड के विचारण के लिए भेज सकेगी ।

(4) कोई नया परिनियम या विद्यमान परिनियम को संशोधित या निरसित करने वाला कोई परिनियम तब तक विधिमान्य नहीं होगा, जब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा उसका अनुमोदन नहीं हो जाता है ।

25. इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संस्थान के अध्यादेशों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात्:—

अध्यादेश ।

(क) संस्थान में छात्रों का प्रवेश ;

(ख) संस्थान की सभी डिग्रियों और डिप्लोमा के लिए अधिकथित किए जाने वाले पाठ्यक्रम ;

(ग) वे शर्तें, जिनके अधीन छात्रों को डिग्री या डिप्लोमा के पाठ्यक्रमों में और संस्थान की परीक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा और वे उन डिग्री और डिप्लोमा के लिए पात्र होंगे ;

(घ) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, छात्र-सहायता वृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों को प्रदान करने की शर्तें ;

(ङ) परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की नियुक्ति करने की शर्तें और ढंग तथा उनके कर्तव्य ;

(च) परीक्षाओं का संचालन ;

(छ) संस्थान के छात्रों के बीच अनुशासन बनाए रखना ; और

(ज) कोई अन्य विषय, जिन्हें इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किया जाना है या किए जाएं ।

26. (1) इस धारा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अध्यादेश सिनेट द्वारा बनाए जाएंगे ।

अध्यादेश कैसे बनाए जाएंगे ।

(2) सिनेट द्वारा बनाए गए सभी अध्यादेश, उस तारीख से प्रभावी होंगे जो वह निदेशित करे, किन्तु इस प्रकार बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश इसके बनाए जाने के पश्चात्,

यथाशक्य शीघ्र बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा और बोर्ड अपने आगामी अधिवेशन में उस पर विचार करेगा ।

(3) बोर्ड के पास संकल्प द्वारा किसी अध्यादेश को उपांतरित या रद्द करने की शक्ति होगी और ऐसा अध्यादेश, ऐसे संकल्प की तारीख से यथास्थिति, तदनुसार उपांतरित या रद्द हो जाएगा ।

माध्यस्थम्
अधिकरण ।

27. (1) संस्थान और उसके किसी कर्मचारी के बीच किसी संविदा से उद्भूत होने वाला कोई विवाद, संबद्ध कर्मचारी के अनुरोध पर या संस्थान की प्रेरणा पर, माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसमें संस्थान द्वारा नियुक्त एक सदस्य, संबद्ध कर्मचारी द्वारा नामनिर्देशित एक सदस्य और केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त एक अधिनिर्णायक होगा ।

(2) माध्यस्थम् अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा और उक्त अधिकरण द्वारा विनिश्चय किए गए मामलों के संबंध में कोई वाद किसी सिविल न्यायालय में नहीं लाया जाएगा :

परंतु इस उपधारा में की गई कोई बात, यथास्थिति, कर्मचारी या संस्थान को संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अधीन उपलब्ध न्यायिक उपचारों का लाभ लेने से निवारित नहीं करेगी ।

(3) माध्यस्थम् अधिकरण को स्वयं अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी ।

(4) माध्यस्थम् से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि की कोई बात, इस धारा के अधीन माध्यस्थमों को लागू नहीं होगी ।

अध्याय 4

परिषद्

परिषद् की
स्थापना ।

28. (1) ऐसी तारीख से, जिसे केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, एक केन्द्रीय निकाय की स्थापना की जाएगी, जिसे परिषद् कहा जाएगा ।

(2) परिषद्, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का भारसाधक मंत्री, केन्द्रीय सरकार — अध्यक्ष, पदेन ;

(ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का राज्य मंत्री, केन्द्रीय सरकार — सदस्य, पदेन ;

(ग) अध्यक्ष, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण — सदस्य, पदेन ;

(घ) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का, जो वित्त से सम्बन्धित हो, भारसाधक सचिव, भारत सरकार — सदस्य, पदेन ;

(ङ) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था — सदस्य, पदेन ;

(च) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का, जो उच्चतर शिक्षा से सम्बन्धित हो, भारसाधक सचिव, भारत सरकार — सदस्य, पदेन ;

(छ) परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से तीन ख्यातिप्राप्त प्रतिनिधि, — सदस्य ;

(ज) ऐसे तीन ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद्, जो खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हों, परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएं— सदस्य ;

(झ) संसद् के तीन सदस्य, जिनमें से दो लोक सभा द्वारा और एक राज्य सभा द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे —सदस्य :

परंतु परिषद् के सदस्य का पद, संसद् के किसी भी सदन का सदस्य चुने जाने या सदस्य होने के लिए, उसके धारक को निरर्हित नहीं करेगा ;

(ज) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय का, जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से सम्बन्धित हो, भारसाधक सचिव, भारत सरकार —सदस्य-सचिव, पदेन ।

(3) केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, सदस्यों में से एक सदस्य को परिषद् के उपाध्यक्ष के रूप में पदाभिहित कर सकेगी ।

29. (1) इस धारा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, पदेन सदस्य से भिन्न परिषद् के किसी सदस्य की पदावधि उसके नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी :

परंतु धारा 28 की उपधारा (2) के खंड (झ) में निर्दिष्ट सदस्य की पदावधि वैसे ही यथाशीघ्र समाप्त हो जाएगी जैसे ही सदस्य, मंत्री या राज्य मंत्री या उप मंत्री या लोक सभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या राज्य सभा का उपसभापति बन जाता है या उस सदन का, जिससे वह निर्वाचित हुआ था, सदस्य नहीं रह जाता है ।

(2) किसी पदेन सदस्य की पदावधि तब तक बनी रहेगी, जब तक वह उस पद को धारण करता है, जिसके आधार पर वह सदस्य है ।

(3) धारा 28 की उपधारा (2) के खंड (छ) और खंड (ज) में निर्दिष्ट परिषद् के सदस्य केन्द्रीय सरकार के प्रसादपर्यन्त पदधारण करेंगे ।

(4) पदेन सदस्य से भिन्न परिषद् के सदस्य की रिक्ति ऐसी रीति में भरी जाएगी, जो विहित की जाए ।

(5) किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नामनिर्देशित सदस्य की पदावधि, उस सदस्य की पदावधि के शेष भाग तक बनी रहेगी जिसके स्थान पर वह इस प्रकार नियुक्त किया गया है ।

(6) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पदेन सदस्य से भिन्न, पद छोड़ने वाला सदस्य जब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा, अन्यथा निदेश न दे, जब तक कोई अन्य व्यक्ति उसके स्थान पर सदस्य के रूप में नामनिर्देशित नहीं कर दिया जाता है या छह मास की समाप्ति तक, जो भी पहले हो, तब तक पद धारण करता रहेगा ।

(7) पदेन सदस्यों से भिन्न, परिषद् के सदस्यों को ऐसे यात्रा और अन्य भत्ते संदत्त किए जाएंगे जिन्हें परिनियमों द्वारा उपबंधित किया जाए ।

(8) पदेन सदस्य से भिन्न, परिषद् के किसी सदस्य को, केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके पद से, ऐसी परिस्थितियों और ऐसी रीति से हटाया जा सकेगा, जो विहित की जाएं ।

30. (1) परिषद् का यह साधारण कर्तव्य होगा कि वह सभी संस्थानों के क्रियाकलापों का समन्वय करे और यह संस्थानों के कार्य को बढ़ाने की दृष्टि से अनुभवों, विचारों तथा प्रसंगों को साझा करने के लिए उसे सुकर बनाएगी ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद् निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात् :—

परिषद् के सदस्यों की पदावधि, रिक्तियां और उनको संदेय भत्ते ।

परिषद् के कृत्य ।

(क) संस्थानों के कार्यकरण के लिए व्यापक नीति विषयक कार्य ढांचा अधिकथित करना ;

(ख) छात्रवृत्तियों, जिनमें नागरिकों के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के छात्रों द्वारा अनुसंधान और उनके फायदे के लिए छात्रवृत्तियां भी हैं, के संस्थान की केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करना ;

(ग) सामान्य हित के ऐसे विषयों पर संस्थानों से विचार-विमर्श करना, जो किसी संस्थान द्वारा, उसे निर्दिष्ट किए जाएं ;

(घ) संस्थानों के कार्यकरण में आवश्यक समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देना ;

(ङ) नीति विषयक उद्देश्यों की उपलब्धि का पुनर्विलोकन करना ; और

(च) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो विहित किए जाएं ।

परिषद् की बैठकें ।

31. परिषद्, ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगी और अपनी बैठकों (ऐसी बैठकों में गणपूर्ति सहित) में ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी, जो विहित की जाए ।

अध्याय 5

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान ।

32. केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन संस्थानों को अपने कृत्यों का दक्षतापूर्ण निर्वहन करने में समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए, संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात्, प्रत्येक संस्थान को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसी धनराशियों का संदाय ऐसी रीति में कर सकेगी, जो वह ठीक समझे ।

संस्थान की निधि ।

33. (1) प्रत्येक संस्थान एक निधि बनाए रखेगा, जिसमें निम्नलिखित को जमा किया जाएगा,—

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सभी धनराशियां ;

(ख) संस्थान द्वारा प्राप्त सभी फीस और अन्य प्रभार ;

(ग) संस्थान द्वारा अनुदानों, दानों, संदानों, उपकृतियों, वसीयतों या अंतरणों के रूप में प्राप्त सभी धनराशियां ; और

(घ) संस्थान द्वारा किसी अन्य रीति से या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सभी धनराशियां ।

(2) प्रत्येक संस्थान की निधि में जमा की गई सभी धनराशियां, ऐसे बैंकों में जमा की जाएंगी या ऐसी रीति में विनिहित की जाएंगी, जो संस्थान, बोर्ड के अनुमोदन से विनिश्चय करे ।

(3) प्रत्येक संस्थान की निधि, संस्थान के व्ययों को, जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अपने कृत्यों का निर्वहन करते हुए उपगत व्यय भी हैं, चुकाने के लिए उपयोजित की जाएगी ।

लेखा और संपरीक्षा ।

34. (1) प्रत्येक संस्थान उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख बनाए रखेगा तथा लेखाओं का एक वार्षिक विवरण, जिसके अन्तर्गत तुलनपत्र भी है, ऐसे प्ररूप में और रीति से तैयार करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित किया जाए ।

(2) प्रत्येक संस्थान के लेखाओं की संपरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा की जाएगी और ऐसी संपरीक्षा के सम्बन्ध में उसके द्वारा उपगत कोई व्यय संस्थान द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को संदेय होगा ।

(3) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को और संस्थान के लेखाओं की संपरीक्षा के सम्बन्ध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को ऐसी संपरीक्षा के सम्बन्ध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार प्राप्त होंगे जो भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के सम्बन्ध में प्राप्त हैं और विशिष्टतया उसे बहियां, लेखाओं, सम्बन्धित वाउचरों और अन्य दस्तावेजों तथा कागजपत्रों को प्रस्तुत किए जाने की मांग करने और संस्थान के कार्यालयों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(4) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित प्रत्येक संस्थान के लेखे, उस पर संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ, प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किए जाएंगे और वह सरकार उन्हें ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकथित की जाए, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।

35. (1) प्रत्येक संस्थान अपने कर्मचारियों, जिनमें निदेशक भी है, के फायदे के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, ऐसी पेंशन, बीमा और भविष्य निधि नियत करेगा, जो वह ठीक समझे ।

पेंशन, बीमा और भविष्य निधि ।

(2) जहां, उपधारा (1) में निर्दिष्ट भविष्य निधि नियत की गई है, वहां केन्द्रीय सरकार यह घोषणा कर सकेगी कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के उपबंध ऐसी निधि को वैसे ही लागू होंगे, मानों वे सरकारी भविष्य निधि हैं ।

1925 का 19

अध्याय 6

प्रकीर्ण

36. इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन गठित परिषद् या किसी संस्थान या बोर्ड या सिनेट या किसी अन्य समिति का कोई कार्य केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं हो जाएगा कि,—

रिक्तियों, आदि के कारण कार्य और कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना ।

(क) उसमें कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है ; या

(ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के नामनिर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि है ; या

(ग) उसकी प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है जो मामले के गुणागुण को प्रभावित नहीं करती है ।

37. इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबंधों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्यों, सिनेट या परिषद् या संस्था के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी ।

सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण ।

38. (1) केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

नियम बनाने की शक्ति ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 29 की उपधारा (4) के अधीन रिक्ति को भरने की रीति ;

(ख) वे परिस्थितियां और रीति, जिनमें परिषद् के किसी सदस्य को धारा 29 की उपधारा (8) के अधीन हटाया जा सकेगा ;

(ग) धारा 30 की उपधारा (2) के खंड (च) के अधीन परिषद् के अन्य कृत्य ;

(घ) धारा 31 के अधीन परिषद् की बैठक का समय और स्थान, उसकी गणपूर्ति तथा उसमें कारबार संचालन की प्रक्रिया ;

(ङ) धारा 34 की उपधारा (1) के अधीन वह प्ररूप और रीति, जिसमें लेखाओं का वार्षिक विवरण, जिसके अन्तर्गत तुलनपत्र भी है, तैयार किया जाएगा ; और

(च) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जाए ।

नियमों,
परिनियमों और
अध्यादेशों का
राजपत्र में
प्रकाशित किया
जाना और संसद्
के समक्ष रखा
जाना ।

39. (1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, प्रत्येक परिनियम और प्रत्येक अध्यादेश भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, प्रत्येक परिनियम और प्रत्येक अध्यादेश बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, जो एक सत्र में या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व, दोनों सदन उस नियम, परिनियम या अध्यादेश में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाते हैं कि वह नियम, परिनियम या अध्यादेश नहीं बनाया जाना चाहिए तो वह, यथास्थिति, तत्पश्चात् नियम, परिनियम या अध्यादेश ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या वह निष्प्रभावी हो जाएगा ; तथापि इस प्रकार का कोई परिवर्तन या बातिलीकरण इस नियम, परिनियम या अध्यादेश के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

कठिनाइयों को
दूर करने की
शक्ति ।

40. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परंतु इस धारा के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसे किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

संक्रमणकालीन
उपबंध ।

41. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) किसी संस्थान का शासी बोर्ड, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पहले उस रूप में कार्य कर रहा है, तब तक कार्य करता रहेगा, जब तक इस अधिनियम के अधीन उस संस्थान के लिए किसी नए बोर्ड का गठन नहीं हो जाता है, किन्तु इस अधिनियम के अधीन किसी नए बोर्ड के गठन पर विद्यमान बोर्ड के ऐसे सदस्य, जो ऐसे गठन से पहले पदधारण कर रहे हैं, पदधारण करने से प्रविरत हो जाएंगे :

(ख) जब तक कि इस अधिनियम के अधीन प्रथम परिनियम या अध्यादेश नहीं बनाए जाते हैं, तब तक इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पहले यथाप्रवृत्त विद्यमान संस्थानों के परिनियम और अध्यादेश तत्स्थानी संस्थानों को वहां तक लागू होते रहेंगे, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हैं ।

अनुसूची

[धारा 4 देखिए]

क्रम सं.	विद्यमान संस्थान का नाम	तत्स्थानी संस्थान का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंध संस्थान (एनआईएफटीईएम) कुंडली, हरियाणा ।	राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान कुंडली, हरियाणा ।
2.	भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएफपीटी) तंजावुर, तमिलनाडु ।	राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान तंजावुर, तमिलनाडु ।

सीमित दायित्व भागीदारी (संशोधन) अधिनियम, 2021

(2021 का अधिनियम संख्यांक 31)

[13 अगस्त, 2021]

सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008
का संशोधन करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के बहतरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सीमित दायित्व भागीदारी (संशोधन)
अधिनियम, 2021 है ।

संक्षिप्त नाम
और प्रारंभ ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना
द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न
तारीखें नियत की जा सकेंगी और किसी ऐसे उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के
प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के
प्रतिनिर्देश है ।

कतिपय अन्य पदों द्वारा कतिपय पदों के निर्देश का प्रतिस्थापन ।

धारा 2 का संशोधन ।

2. संपूर्ण सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) में “कंपनी अधिनियम, 1956” शब्दों और अंकों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, “कंपनी अधिनियम, 2013” शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

2009 का 6
1956 का 1
2013 का 18

3. मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) में,—

(क) खंड (ग) में, “धारा 10चद की उपधारा (1)”, शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों के स्थान पर, “धारा 410”, शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (घ) में, “धारा 3”, शब्द और अंक, जहां-जहां वे आते हैं, “धारा 2 के खंड (20)”, शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ग) खंड (ङ) में, “और उपजीविका”, शब्दों के स्थान पर, “और उपजीविका, किसी अन्य क्रियाकलाप के सिवाए, जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, अपवर्जित कर सकेगी” शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) खंड (द) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘(दक) “प्रादेशिक निदेशक” से, यथास्थिति, इस अधिनियम या कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी हैसियत से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है ;’;

2013 का 18

(ङ) खंड (ध) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

‘(ध) “रजिस्ट्रार” से, यथास्थिति, इस अधिनियम या कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रयोजनों के लिए, केन्द्रीय सरकार द्वारा, रजिस्ट्रार, अपर रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार, उप-रजिस्ट्रार या सहायक रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है ;’;

2013 का 18

(च) खंड (न) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘(नक) “लघु सीमित दायित्व भागीदारी” से ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी अभिप्रेत है—

(i) जिसका अभिदाय पच्चीस लाख रुपए से अधिक नहीं है या ऐसी उच्चतर रकम, जो विहित की जाए, पांच करोड़ रुपए से अनधिक है ; और

(ii) जिसका आवर्त, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए लेखा-विवरण और शोधन क्षमता के अनुसार, चालीस लाख रुपए से अधिक नहीं है या ऐसी उच्चतर रकम, जो विहित की जाए, पचास करोड़ रुपए से अनधिक है ; या

(iii) ऐसी अन्य अपेक्षाएं, जो विहित की जाएं, पूरी करती हैं,

और ऐसी अन्य शर्तें और निबंधन, जो विहित की जाएं, पूरी करती हैं ;’;

(छ) खंड (प) में, “धारा 10चख की उपधारा (1)” शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों के स्थान पर “धारा 408” शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

4. मूल अधिनियम की धारा 7 में,—

धारा 7 का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) के स्पष्टीकरण में, “ठीक पूर्ववर्ती एक वर्ष के दौरान एक सौ बयासी दिन” शब्दों के स्थान पर, “वित्तीय वर्ष के दौरान बीस दिन” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (6) में, “धारा 266क से धारा 266छ”, शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, “धारा 153 से धारा 159” शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

5. मूल अधिनियम की धारा 10 में,—

धारा 10 का संशोधन ।

(क) पार्श्व शीर्ष में, “धारा 8” शब्द और अंक का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (1) में, “जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा”, शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“दस हजार रुपए की शास्ति का दायी होगा और ऐसा उल्लंघन जारी रहने की दशा में, ऐसे पहले दिन के पश्चात् जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, सीमित दायित्व भागीदारी अधिकतम एक लाख रुपए और प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी के ऐसे भागीदार पचास हजार रुपए तक के अधीन रहते हुए, प्रत्येक दिन के लिए सौ रुपए अतिरिक्त शास्ति का दायी होगा ।”;

(ग) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“(2) यदि सीमित दायित्व भागीदारी, धारा 7 की उपधारा (4) के उपबंध का उल्लंघन करती है तो ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी और उसका प्रत्येक अभिहित भागीदार पांच हजार रुपए की शास्ति का दायी होगा और ऐसा उल्लंघन जारी रहने की दशा में, ऐसे पहले दिन के पश्चात् जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, सीमित दायित्व भागीदारी अधिकतम पचास हजार रुपए और उसका प्रत्येक अभिहित भागीदार पच्चीस हजार रुपए तक के अधीन रहते हुए, प्रत्येक दिन के लिए सौ रुपए अतिरिक्त शास्ति का दायी होगा ।

(3) यदि सीमित दायित्व भागीदारी, धारा 7 की उपधारा (5) या धारा 9 के उपबंधों का उल्लंघन करती है तो ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी और उसका प्रत्येक भागीदार दस हजार रुपए की शास्ति का दायी होगा और ऐसा उल्लंघन जारी रहने की दशा में, ऐसे पहले दिन के पश्चात् जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, सीमित दायित्व भागीदारी अधिकतम एक लाख रुपए और उसका प्रत्येक भागीदार पचास हजार रुपए तक के अधीन रहते हुए, प्रत्येक दिन के लिए सौ रुपए अतिरिक्त शास्ति का दायी होगा ।”।

6. मूल अधिनियम की धारा 13 में, उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

धारा 13 का संशोधन ।

“(4) यदि इस धारा की अपेक्षाओं के अनुपालन में कोई व्यतिक्रम किया जाता है तो सीमित दायित्व भागीदारी और उसका प्रत्येक भागीदार, ऐसा

व्यतिक्रम के जारी रहने के दौरान, सीमित दायित्व भागीदारी और उसका प्रत्येक भागीदार अधिकतम पचास हजार रुपए तक के अधीन रहते हुए, प्रत्येक दिन के लिए पांच सौ रुपए की शास्ति का दायी होगा।”।

धारा 15 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) में, खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(ख) किसी अन्य सीमित दायित्व भागीदारी या कंपनी या व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 के अधीन किसी अन्य व्यक्ति के रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न के समरूप है या उससे बहुत कुछ मिलता-जुलता है।”।

1999 का 47

धारा 17 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

8. मूल अधिनियम की धारा 17 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“17. (1) धारा 15 और धारा 16 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई सीमित दायित्व भागीदारी, चाहे अनवधानता से या अन्यथा, अपने पहले रजिस्ट्रीकरण पर या किसी नए नाम में उसके रजिस्ट्रीकरण पर किसी ऐसे नाम से रजिस्ट्रीकृत हो गई है, जो,—

(क) किसी अन्य सीमित दायित्व भागीदारी या कंपनी ; या

(ख) व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 के अधीन किसी स्वामित्वधारी का रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न है,

1999 का 47

के समरूप है या उससे बहुत कुछ मिलता-जुलता है, जिससे भूल होने की संभावना है, वहां केन्द्रीय सरकार, ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी या क्रमशः खंड (क) और खंड (ख) में निर्दिष्ट स्वत्वधारी या कंपनी को निदेश दे सकेगी कि ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी ऐसे निदेश जारी करने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर अपने नाम में या नए नाम में परिवर्तन करे :

परंतु यह कि रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न के स्वत्वधारी का कोई आवेदन, इस अधिनियम के अधीन निगमन या रजिस्ट्रीकरण या सीमित दायित्व भागीदारी के नाम परिवर्तन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर चलाने योग्य होगा।

(2) जहां कोई सीमित दायित्व भागीदारी, उपधारा (1) के अधीन अपना नाम परिवर्तन करती है या नया नाम अभिप्राप्त करती है, वहाँ वह ऐसे परिवर्तन की तारीख से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर, रजिस्ट्रार को केन्द्रीय सरकार के आदेश सहित परिवर्तन की सूचना देगी जो निगमन प्रमाणपत्र में आवश्यक परिवर्तन करेगा और निगमन प्रमाणपत्र में ऐसे परिवर्तन के तीस दिन के भीतर ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी अपने सीमित दायित्व भागीदारी करार में अपना नाम परिवर्तित करेगी।

(3) यदि सीमित दायित्व भागीदारी, उपधारा (1) के अधीन दिए गए किसी निदेश का अनुपालन करने में व्यतिक्रम करती है, तो केन्द्रीय सरकार, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सीमित दायित्व भागीदारी को कोई नया नाम आवंटित करेगी और रजिस्ट्रार पुराने नाम के स्थान पर सीमित दायित्व भागीदारी का नया नाम रजिस्टर में दर्ज करेगा और नए नाम के साथ नया निगमन प्रमाणपत्र जारी

करेगा जिसे सीमित दायित्व भागीदारी उसके पश्चात् उपयोग करेगी :

परंतु इस उपधारा में अन्तर्विष्ट कोई बात, सीमित दायित्व भागीदारी को धारा 16 के उपबंधों के अनुसार अपने नाम में पश्चातवर्ती परिवर्तन को नहीं रोकेगी ।”।

9. मूल अधिनियम की धारा 18 का लोप किया जाएगा ।

धारा 18 का लोप ।

10. मूल अधिनियम की धारा 21 में, उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

धारा 21 का संशोधन ।

“(2) यदि सीमित दायित्व भागीदारी, इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करती है तो सीमित दायित्व भागीदारी दस हजार रुपए की शास्ति का दायी होगी ।”।

11. मूल अधिनियम की धारा 25 में, उपधारा (4) और उपधारा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

धारा 25 का संशोधन ।

“(4) यदि सीमित दायित्व भागीदारी, उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करती है तो सीमित दायित्व भागीदारी और उसका प्रत्येक अभिहित भागीदार दस हजार रुपए की शास्ति का दायी होगा ।

(5) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट उल्लंघन सीमित दायित्व भागीदारी के किसी भागीदार द्वारा किया गया है तो ऐसा भागीदार दस हजार रुपए की शास्ति का दायी होगा ।”।

12. मूल अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (2) में, “दो वर्ष” शब्दों के स्थान पर, “पांच वर्ष” शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 30 का संशोधन ।

13. मूल अधिनियम की धारा 34 में, उपधारा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

धारा 34 का संशोधन ।

“(5) कोई सीमित दायित्व भागीदारी, जो उपधारा (3) के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहती है, तो ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी और उसका अभिहित भागीदार ऐसी असफलता के जारी रहने के दौरान, सीमित दायित्व भागीदारी अधिकतम एक लाख रुपए और उसके प्रत्येक अभिहित भागीदार पचास हजार रुपए तक के अधीन रहते हुए, प्रत्येक दिन के लिए सौ रुपए की शास्ति का दायी होगा ।

(6) कोई सीमित दायित्व भागीदारी, जो उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (4) के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहती है, तो ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी, ऐसे जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी का प्रत्येक अभिहित भागीदार ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।”।

14. मूल अधिनियम की धारा 34 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

नई धारा 34क का अंतःस्थापन ।

लेखा और संपरीक्षा
मानक ।

“34क. केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 के अधीन गठित राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के परामर्श से, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार, सीमित दायित्व भागीदारी के किसी प्रवर्ग या प्रवर्गों के लिए निम्नलिखित मानक विहित कर सकेगी,—

(क) लेखा मानक ; और

(ख) संपरीक्षा मानक ;”।

2013 का 18

1949 का 38

धारा 35 का
संशोधन ।

15. मूल अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(2) यदि कोई सीमित दायित्व भागीदारी, उपधारा (1) के अधीन अपनी वार्षिक विवरणी उसमें विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व फाइल करने में असफल रहती है, तो ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी और उसका अभिहित भागीदार ऐसी असफलता के जारी रहने के दौरान, सीमित दायित्व भागीदारी अधिकतम एक लाख रुपए और प्रत्येक अभिहित भागीदार पचास हजार रुपए तक के अधीन रहते हुए, प्रत्येक दिन के लिए सौ रुपए शास्ति का दायी होगा ।”।

धारा 39 के स्थान
पर नई धारा का
प्रतिस्थापन ।

16. मूल अधिनियम की धारा 39 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“39. (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रादेशिक निदेशक या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई ऐसे अन्य अधिकारी, जो प्रादेशिक निदेशक की पंक्ति से कम का न हो इस अधिनियम के अधीन ऐसे किसी अपराध का, जो केवल जुर्माने से दंडनीय है, ऐसे व्यक्ति से, जिसके बारे में युक्तियुक्त रूप से अपराध कारित करने का संदेह है ऐसी राशि का, जो अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माने की रकम तक की हो सकेगी, किन्तु जो अपराध के लिए उपबंधित न्यूनतम रकम से अन्यून नहीं होगी, संग्रहण करके, शमन कर सकेगा ।

1974 का 2

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सीमित दायित्व भागीदारी या उसका भागीदार या उसका अभिहित भागीदार द्वारा कारित ऐसे अपराध, जो उस तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर, जिसको उसके द्वारा वैसा ही अपराध कारित किया गया था या इस धारा के अधीन उसे शमन किया गया था, को लागू नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई दूसरा अपराध या पश्चातवर्ती अपराध, उस तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् कारित किया जाता है, जिसको पूर्ववर्ती अपराध शमन किया गया था, को प्रथम अपराध समझा जाएगा ।

(3) किसी अपराध के शमन के लिए प्रत्येक आवेदन, रजिस्ट्रार को किया जाएगा जो इसे अपनी टीका-टिप्पणी के साथ, यथास्थिति, प्रादेशिक निदेशक या ऐसे किसी अधिकारी को, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत प्रादेशिक निदेशक की पंक्ति से कम का न हो, अग्रेषित करेगा ।

अपराधों का
शमन ।

(4) जहां इस धारा के अधीन किसी अपराध का चाहे वह किसी अभियोजन को संस्थित किए जाने से पूर्व हो या पश्चात् शमन किया जाता है, तो उसकी संसूचना रजिस्ट्रार को उस तारीख से, जिसको अपराध का इस प्रकार शमन किया जाता है, सात दिन की अवधि के भीतर दी जाएगी ।

(5) जहां किसी अपराध का, किसी अभियोजन को संस्थित किए जाने से पूर्व शमन किया जाता है, वहां ऐसे अपराध के संबंध में कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जाएगा ।

(6) जहां किसी अभियोजन के संस्थित किए जाने के पश्चात्, किसी अपराध का शमन किया जाता है, वहां ऐसे शमन को रजिस्ट्रार द्वारा लिखित में उस न्यायालय को सूचना दी जाएगी जिसमें अभियोजन लंबित है और अपराध के शमन की ऐसी सूचना देने पर ऐसे अपराध के बारे में जिसका शमन किया गया है, अपराधी उन्मोचित हो जाएगा ।

(7) प्रादेशिक निदेशक या कोई अन्य अधिकारी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत प्रादेशिक निदेशक की पंक्ति से कम का न हो किसी अपराध के शमन के प्रस्ताव पर निपटारा करते समय आदेश द्वारा, सीमित दायित्व भागीदारी के किसी भी भागीदार, अभिहित भागीदार या अन्य कर्मचारी को, इस अधिनियम के अधीन संदत्त की जाने वाली यथा अपेक्षित फीस या अतिरिक्त फीस के संदाय पर या ऐसे समय के भीतर जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, ऐसी विवरणी, लेखा या अन्य दस्तावेज फाइल करने या रजिस्टर करने का निदेश दे सकेगा ।

(8) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि सीमित दायित्व भागीदारी का कोई भागीदार या अभिहित भागीदार या अन्य कर्मचारी, जो प्रादेशिक निदेशक या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत प्रादेशिक निदेशक की पंक्ति से अन्यून का किसी अन्य अधिकारी द्वारा उपधारा (7) के अधीन किए गए किसी आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है तो इस धारा के अधीन अपराध के शमन के लिए जुर्माने की अधिकतम रकम, जो प्रादेशिक निदेशक या ऐसे प्राधिकृत अधिकारी के विचाराधीन है, तत्स्थानी धारा में उपबंधित रकम की दोगुनी होगी जिसमें ऐसे अपराध के लिए दंड उपबंधित है ।”।

17. मूल अधिनियम की धारा 60 में, उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

धारा 60 का संशोधन ।

“(4) यदि उपधारा (3) के उपबंधों का अनुपालन करने में कोई व्यतिक्रम किया जाता है, तो सीमित दायित्व भागीदारी और उसका प्रत्येक अभिहित भागीदार दस हजार रुपए की शास्ति का दायी होगा और व्यतिक्रम के जारी रहने की दशा में, ऐसे प्रथम व्यतिक्रम के पश्चात् जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता हो, तो सीमित दायित्व भागीदारी एक लाख रुपए और प्रत्येक अभिहित भागीदार पचास हजार रुपए तक के अधिकतम के अधीन रहते हुए प्रत्येक दिन के लिए सौ रुपए की अतिरिक्त शास्ति का दायी होगा ।”।

18. मूल अधिनियम की धारा 62 में, उपधारा (4) और उपधारा (4) के पश्चात् आने वाले स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा और स्पष्टीकरण रखा

धारा 62 का संशोधन ।

जाएगा, अर्थात् :—

‘(4) यदि उपधारा (3) के उपबंधों का अनुपालन करने में कोई व्यतिक्रम किया जाता है, तो सीमित दायित्व भागीदारी और उसका प्रत्येक अभिहित भागीदार दस हजार रुपए की शास्ति का दायी होगा और व्यतिक्रम के जारी रहने की दशा में, ऐसे प्रथम व्यतिक्रम के पश्चात् जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता हो, तो सीमित दायित्व भागीदारी एक लाख रुपए और प्रत्येक अभिहित भागीदार पचास हजार रुपए तक के अधिकतम के अधीन रहते हुए प्रत्येक दिन के लिए सौ रुपए की अतिरिक्त शास्ति का दायी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, —

(i) “संपत्ति” के अंतर्गत प्रत्येक प्रकार की संपत्ति, अधिकार और शक्तियां भी हैं और “दायित्वों” के अंतर्गत प्रत्येक प्रकार के कर्तव्य भी हैं;

(ii) “सीमित दायित्व भागीदारी” में कंपनी का समामेलन नहीं होगा ।’।

धारा 67क, धारा
67ख और धारा
67ग का
अंतःस्थापन ।

19. मूल अधिनियम की धारा 67 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

विशेष न्यायालयों
की स्थापना ।

“67क. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन अपराधों के शीघ्र विचारण का उपबंध करने के प्रयोजन के लिए, अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए उतने विशेष न्यायालयों की स्थापना या अभिहित करेगी जितने आवश्यक हो जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए ।

(2) विशेष न्यायालय निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, —

(क) इस अधिनियम के अधीन तीन वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के मामले में सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश के रूप में पदधारण करने वाला एकल न्यायाधीश; और

(ख) अन्य अपराधों के मामले में प्रथम वर्ग महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट,

जिसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा :

परंतु उपधारा (1) के अधीन जब तक विशेष न्यायालय, अभिहित या स्थापित नहीं किए जाते हैं, तब तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 435 के निबंधनानुसार विशेष न्यायालयों के रूप में अभिहित किए गए न्यायालयों को इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराधों के विचारण के प्रयोजन के लिए विशेष न्यायालय समझा जाएगा :

2013 का 18

परंतु यह और कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई अपराध, जिसका किसी विशेष न्यायालय द्वारा विचारण किया जाता है, इस अधिनियम या कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन जब तक विशेष न्यायालय स्थापित नहीं किया जाता है तब तक उस क्षेत्र पर अधिकारिता का प्रयोग, यथास्थिति, सेशन

1974 का 2

2013 का 18

न्यायालय या महानगर मजिस्ट्रेट न्यायालय या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण किया जाएगा ।

1974 का 2

67ख. (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 67क की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट सभी अपराध केवल उस क्षेत्र के लिए स्थापित या अभिहित किए गए विशेष न्यायालय द्वारा जिसमें सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है जिसके संबंध में अपराध किया गया है या जहां ऐसे क्षेत्र के लिए एक से अधिक विशेष न्यायालय हैं जो संबद्ध उच्च न्यायालय द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए उनमें से एक के द्वारा विचारणीय होंगे ।

विशेष न्यायालय की प्रक्रिया और शक्तियां ।

1974 का 2

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करते समय एक विशेष न्यायालय इस अधिनियम के अधीन एक अपराध के अलावा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन समान विचारण के लिए अन्य अपराध पर भी विचारण कर सकेगा जिसके साथ अभियुक्त को आरोपित किया जा सकता है ।

1974 का 2

(3) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विशेष न्यायालय, यदि वह ठीक समझे, तो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का, जो तीन वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास से दंडनीय है, संक्षिप्त विचारण करेगा :

परंतु किसी संक्षिप्त विचारण में किसी दोषसिद्धि के मामले में, एक वर्ष से अनधिक की अवधि के कारावास का कोई दंडादेश पारित नहीं करेगा :

परंतु यह और कि जब किसी संक्षिप्त विचारण के प्रारंभ में या उसके दौरान विशेष न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि मामले की प्रकृति ऐसी है कि एक वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास का दंडादेश पारित किया जा सकता है या इसके किसी अन्य कारण से मामले के संक्षिप्त विचारण के लिए अवांछनीय होने पर, विशेष न्यायालय, पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात् उस प्रभाव के लिए एक आदेश अभिलिखित करने के पश्चात् किसी साक्षी को जिसकी परीक्षा की जा सकेगी पुनः बुलवाएगा और नियमित विचारण की प्रक्रिया के अनुसार मामले की सुनवाई या पुनः सुनवाई की कार्यवाई करेगा ।

1974 का 2

67ग. उच्च न्यायालय, जहां तक लागू हो, उच्च न्यायालय पर दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का अध्याय 29 और अध्याय 30 द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा, मानो एक विशेष न्यायालय, उच्च न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर मामलों के विचारण के लिए एक सेशन न्यायालय थे।”।

अपील और पुनर्विलोकन ।

20. मूल अधिनियम की धारा 68 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

नई धारा 68क का अंतःस्थापन ।

“68क. (1) केन्द्रीय सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए जिसे इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा या उसके अधीन और इस अधिनियम के अधीन सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार,

रजिस्ट्रीकृत कार्यालय ।

अधिसूचना, अपनी अधिकारिता को विनिर्दिष्ट करते हुए ऐसे स्थानों पर उतनी संख्या में, जितनी वह ठीक समझे, रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों की स्थापना करेगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार, सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकरण के लिए और इस अधिनियम के अधीन विभिन्न कृत्यों का निर्वहन करने के लिए, जो वह आवश्यक समझे, ऐसे रजिस्ट्रारों, अपर रजिस्ट्रारों, संयुक्त रजिस्ट्रारों, उप रजिस्ट्रारों और सहायक रजिस्ट्रारों की नियुक्ति कर सकेगी ।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट रजिस्ट्रारों की शक्तियां और कर्तव्य तथा उनके निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाए ।

(4) केन्द्रीय सरकार, सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकरण के लिए या उससे संबद्ध अपेक्षित दस्तावेजों के अधिप्रमाणन के लिए मुद्रा या मुद्राओं को तैयार कराने के लिए रजिस्ट्रार को निदेश दे सकेगी ।”।

धारा 69 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

अतिरिक्त फीस का संदाय ।

21. मूल अधिनियम की धारा 69 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“69. इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रीकृत या फाइल किए जाने के लिए अपेक्षित कोई दस्तावेज या विवरणी, यदि उसमें उपबंधित समय में रजिस्ट्रीकृत या फाइल नहीं की जाती है, तो उस समय के पश्चात्, जो विहित की जाए, दस्तावेज या विवरणी फाइल करने के लिए संदेय हो, अतिरिक्त फीस के संदाय पर रजिस्ट्रीकृत या फाइल की जा सकेगी :

परंतु ऐसा दस्तावेज या विवरणी, इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य कार्रवाई या दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, फाइल किए जाने की सम्यक् तारीख के पश्चात् भी फाइल की जा सकेगी :

परंतु यह और कि सीमित दायित्व भागीदारी के विभिन्न वर्गों के लिए या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन फाइल किए जाने के लिए अपेक्षित विभिन्न दस्तावेजों या विवरणियों के लिए एक अलग फीस या अतिरिक्त फीस विहित की जा सकेगी ।”।

धारा 72 का संशोधन ।

22. मूल अधिनियम की धारा 72 में उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“(2) अधिकरण के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा :

परंतु पक्षकारों की सहमति से अधिकरण द्वारा किए गए किसी आदेश से अपील अधिकरण में कोई अपील नहीं होगी ।

(3) उपधारा (2) के अधीन की गई प्रत्येक अपील, उस तारीख से, जिसको अधिकरण के आदेश की प्रति व्यथित व्यक्ति को उपलब्ध करा दी जाती है, साठ दिन की अवधि के भीतर और ऐसे प्ररूप में और ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाए, फाइल की जाएगी:

परंतु अपील अधिकरण साठ दिन की उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् किन्तु साठ दिन से अनधिक अतिरिक्त अवधि के भीतर अपील ग्रहण कर सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलकर्ता इस प्रकार

विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था ।

(4) उपधारा (2) के अधीन किसी अपील की प्राप्ति पर, अपील अधिकरण, उस पारित आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, उस पर ऐसे आदेश, जो वह ठीक समझे पुष्ट, उपांतरण या अपास्त करेगा ।

(5) अपील अधिकरण अपने द्वारा किए गए प्रत्येक आदेश की एक प्रति अधिकरण और अपील के पक्षकारों को भेजेगा ।”।

23. मूल अधिनियम की धारा 73 का लोप किया जाएगा ।

धारा 73 का लोप किया जाना ।

24. मूल अधिनियम की धारा 74 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

धारा 74 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

“74. यदि कोई सीमित दायित्व भागीदारी या कोई भागीदार या कोई अभिहित भागीदार या कोई अन्य व्यक्ति, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है या किसी शर्त, सीमा या निर्बंधन, जिसके अधीन कोई अनुमोदन, मंजूरी, सहमति, पुष्टि, मान्यता, निदेश या किसी मामले के संबंध में छूट दी गई या अनुदत्त की गई है तथा जिसके लिए इस अधिनियम में अन्यत्र किसी शास्ति या दंड का उपबंध नहीं किया गया है, सीमित दायित्व भागीदारी या कोई भागीदार या कोई अभिहित भागीदार या कोई अन्य व्यक्ति, जिसने व्यतिक्रम किया है, पांच हजार रुपए की शास्ति और उल्लंघन के जारी रहने की दशा में प्रत्येक उल्लंघन के पश्चात् जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहा हो, एक लाख रुपए के अधिकतम के अधीन रहते हुए प्रत्येक दिन के लिए सौ रुपए की अतिरिक्त शास्ति का दायी होगा ।”।

साधारण शास्तियां ।

25. मूल अधिनियम की धारा 76 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

नई धारा 76क का अंतःस्थापन ।

“76क. (1) इस अधिनियम के अधीन, शास्तियों पर न्यायनिर्णयन करने के प्रयोजनों के लिए, केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, केन्द्रीय सरकार के ऐसे अनेक अधिकारियों को, जो रजिस्ट्रार की पंक्ति से कम के न हो, न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी ।

शास्तियों का न्यायनिर्णयन ।

(2) केन्द्रीय सरकार, न्यायनिर्णायक अधिकारियों की नियुक्ति करते समय उपधारा (1) के अधीन आदेश में उनकी अधिकारिता को विनिर्दिष्ट करेगी ।

(3) न्यायनिर्णायक अधिकारी, आदेश द्वारा—

(क) इस अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अधीन उसमें किसी अननुपालन या व्यतिक्रम का कथन करते हुए, यथास्थिति, सीमित दायित्व भागीदारी या उसके भागीदारों या अभिहित भागीदारों या कोई अन्य व्यक्ति पर शास्ति अधिरोपित करेगा :

परंतु यदि व्यतिक्रम धारा 34 की उपधारा (3) या धारा 35 की उपधारा (1) के अननुपालन से संबंधित है, के मामले में और ऐसे व्यतिक्रम को या तो सूचना जारी करने के तीस दिन से पहले या इसके भीतर सुधार किया गया है, तो न्यायनिर्णायक अधिकारी इस संबंध में कोई शास्ति अधिरोपित नहीं करेगा और ऐसे व्यतिक्रम के संबंध में इस धारा के अधीन कार्यवाहियों को समाप्त माना जाएगा :

परंतु यह और कि इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि शास्ति, इस अधिनियम के किसी भी उपबंध के अननुपालन के लिए लघु सीमित दायित्व भागीदारी या स्टार्ट-अप सीमित दायित्व भागीदारी या उसके भागीदार या अभिहित भागीदार द्वारा या ऐसे सीमित दायित्व भागीदारी के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देय है तो ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी या उसका भागीदार या अभिहित भागीदार या कोई अन्य व्यक्ति, उस शास्ति के लिए सीमित दायित्व भागीदारी एक लाख रुपए तथा, यथास्थिति, प्रत्येक भागीदार या अभिहित भागीदार या कोई अन्य व्यक्ति पचास हजार रुपए तक के अधिकतम के अधीन रहते हुए दायी होगा जो ऐसे उपबंध में विनिर्दिष्ट शास्ति की आधी होगी ।

स्पष्टीकरण—इस परन्तुक के प्रयोजन के लिए “स्टार्ट-अप सीमित दायित्व भागीदारी” पद से इस अधिनियम के अधीन निगमित सीमित दायित्व भागीदारी अभिप्रेत है और इसे केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुसार मान्यताप्राप्त है ।

(ख) यथास्थिति, ऐसे सीमित दायित्व भागीदारी या उसके भागीदार या अभिहित भागीदार या कोई अन्य व्यक्ति, उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, जहां-जहां वह ठीक समझे व्यतिक्रम का सुधार करने के लिए निदेश दे ।

(4) न्यायनिर्णायक अधिकारी किसी शास्ति को अधिरोपित करने से पूर्व ऐसे सीमित दायित्व भागीदारी या उसके भागीदार या अभिहित भागीदार या किसी अन्य व्यक्ति को, जिससे व्यतिक्रम हुई है, सुनवाई का अवसर देगा ।

(5) उपधारा (3) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, मामले में अधिकारिता रखने वाले प्रादेशिक निदेशक को अपील कर सकेगा ।

(6) उपधारा (5) के अधीन की गई प्रत्येक अपील उस तारीख से जिस तारीख को न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा किए गए आदेश की प्रति व्यथित व्यक्ति द्वारा प्राप्त कर ली जाती है साठ दिन की अवधि के भीतर और ऐसे प्ररूप, रीति और ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाए, फाइल की जाएगी:

परंतु प्रादेशिक निदेशक, उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, इस उपधारा के अधीन अपील फाइल करने की अवधि को तीस दिन से अधिक नहीं बढ़ा सकेगा ।

(7) प्रादेशिक निदेशक, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसे आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्ट, उपांतरित या अपास्त करते हुए, जो वह ठीक समझे, पारित कर सकेगा ।

(8) जहां सीमित दायित्व भागीदारी, आदेश के प्रति की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर, यथास्थिति, उपधारा (3) या उपधारा (7) के अधीन किए गए आदेश के अनुपालन में असफल हो जाता है, वहां ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी, ऐसे जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(9) जहां सीमित दायित्व भागीदारी का कोई भागीदार या अभिहित भागीदार या कोई अन्य व्यक्ति, जो व्यतिक्रम किया है, आदेश के प्रति की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर, यथास्थिति, उपधारा (3) या उपधारा (7) के अधीन किए गए आदेश के अनुपालन में असफल रहता है, ऐसा भागीदार या अभिहित भागीदार या कोई अन्य व्यक्ति, ऐसे कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा।”।

26. मूल अधिनियम की धारा 77 के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

धारा 77 के स्थान पर नई धाराओं का प्रतिस्थापन।

“77. इस अधिनियम के अधीन विशेष न्यायालयों की स्थापना या अभिहित किए जाने की तारीख से ही, धारा 67क और धारा 67ख में अंतर्विष्ट उपबध्दों के अध्यधीन,—

न्यायालय की अधिकारिता।

(i) धारा 67क की उपधारा (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय को इस अधिनियम की धारा 30 के अधीन दंड अधिरोपित करने की अधिकारिता और शक्ति होगी; और

(ii) सीमित दायित्व भागीदारी या उसके भागीदारों या अभिहित भागीदारों या किसी अन्य व्यक्ति के व्यतिक्रम किए जाने के विरुद्ध ऐसे दांडिक मामले, जो इस अधिनियम के अधीन फाइल की गई हैं और जो, यथास्थिति, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, धारा 67क की उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय को अन्तर्गत किया जाएगा।

77क. धारा 67क में निर्दिष्ट विशेष न्यायालयों से भिन्न कोई भी न्यायालय, रजिस्ट्रार द्वारा या इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत रजिस्ट्रार की पंक्ति से कम के किसी अधिकारी द्वारा लिखित में शिकायत किए जाने के सिवाय इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।”।

अपराध का संज्ञान।

27. मूल अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (2) में,—

धारा 79 का संशोधन।

(i) खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“(क) धारा 2 के खंड (नक) के उपखंड (i) और उपखंड (ii) के अधीन ऐसी उच्चतर रकम का अभिदाय;

(कक) धारा 2 के खंड (नक) की दीर्घ पंक्ति के अधीन सीमित दायित्व भागीदारों के वर्ग या वर्गों द्वारा पूरा किए जाने वाले निबंधन और शर्तें;

(कख) धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन अभिहित भागीदार द्वारा दी जाने वाली पूर्व सहमति का प्ररूप और रीति ;”;

(ii) खंड (ट) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(टक) धारा 17 की उपधारा (3) के अधीन सीमित दायित्व भागीदारी के लिए नया नाम आबंटित करने की रीति;”;

(iii) खंड (न) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(नक) धारा 34क के अधीन लेखा और संपरीक्षा मानक ;”;

(iv) खंड (यच) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“(यचक) धारा 68क की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रारों द्वारा निर्वहन की जाने वाली शक्तियां और कर्तव्य तथा उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें;

(यचख) धारा 69 के अधीन दस्तावेज या विवरणी फाइल करने के लिए अतिरिक्त फीस के संदाय और विभिन्न फीस या अतिरिक्त फीस के संदाय;

(यचग) धारा 72 की उपधारा (3) के अधीन अपील फाइल करने के लिए प्ररूप और फीस;”;

(v) खंड (यछ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“(यछक) धारा 76क की उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णयन शास्ति के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारियों की नियुक्ति करने की रीति;

(यछख) धारा 76क की उपधारा (6) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा किए गए आदेश के विरुद्ध अपील फाइल करने का प्ररूप, रीति और फीस;”;

(vi) खंड (यठ) के अंत में आने वाले “और” शब्द का लोप किया जाएगा;

(vii) खंड (यड) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(यढ) कोई अन्य मामला, जिसे विहित किया गया है या विहित किया जा सकता है, या जिसके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है ।”।

धारा 80 का संशोधन ।

28. मूल अधिनियम की धारा 80 में उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(1क) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि सीमित दायित्व भागीदारी (संशोधन) अधिनियम, 2021 द्वारा यथा संशोधित इस

अधिनियम के उपबंध को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो :

परंतु इस धारा के अधीन किया गया कोई ऐसा आदेश, सीमित दायित्व भागीदारी (संशोधन) अधिनियम, 2021 के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।”।

29. मूल अधिनियम की धारा 81 का लोप किया जाएगा ।

धारा 81 का
लोप ।

बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021

(2021 का अधिनियम संख्यांक 41)

[13 दिसम्बर, 2021]

बांध विफलता संबद्ध आपदाओं के निवारण के लिए विनिर्दिष्ट बांध की
निगरानी, उसके निरीक्षण, प्रचालन और अनुरक्षण का उपबंध करने
और उनके सुरक्षित कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए
संस्थागत क्रियाविधि तथा उनसे संबंधित या
उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के बहतरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 है ।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है ।
(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारम्भ ।

संघ के नियंत्रण के
औचित्य के बारे में
घोषणा ।

लागू होना ।

परिभाषाएं ।

2. यह घोषणा की जाती है कि लोक हित में यह समीचीन है कि संघ को विनिर्दिष्ट बांध के लिए एकसमान बांध सुरक्षा प्रक्रिया का विनियमन, इसमें इसके पश्चात् उपबंधित विस्तार तक अपने नियंत्रण में लेना चाहिए ।

3. इस अधिनियम के अधीन जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, यह अधिनियम प्रत्येक विनिर्दिष्ट बांध के ऐसे स्वामी को लागू होगा, जो—

(क) यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या एक या अधिक सरकारों के संयुक्त रूप से स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कोई पब्लिक सेक्टर उपक्रम या संस्था या निकाय है; और

(ख) यथास्थिति, राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन उपक्रम या कंपनी या संस्था या निकाय से भिन्न कोई उपक्रम या कंपनी या संस्था या निकाय है ।

4. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “बांध का परिवर्तन” से ऐसे परिवर्तन या मरम्मत अभिप्रेत हैं, जो बांध या जलाशय की सुरक्षा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता हो ;

(ख) “वार्षिक रिपोर्ट” से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान प्राधिकरण और राज्य बांध सुरक्षा संगठन के क्रियाकलापों तथा उनकी अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाले विनिर्दिष्ट बांधों की सुरक्षा प्रास्थिति का उल्लेख करने वाली रिपोर्ट अभिप्रेत है ;

(ग) “अनुलग्न संरचना” से ऐसी संरचना अभिप्रेत है जो,—

(i) अधिप्लवमान मार्ग है, चाहे वे बांध में हों या उससे पृथक् हों ;

(ii) निम्न तल निकास संरचना और सुरंगें, पाइप लाइनें या निर्गम द्वार जैसी जल नालियां हैं, चाहे वे बांध के या उसके अन्त्याधारों या जलाशय किनारों के आर-पार हों ;

(iii) जल-यांत्रिक उपस्कर है, जिसके अंतर्गत द्वार, कपाट, उद्वाहक उत्पापक भी हैं ;

(iv) ऊर्जा क्षय और नदी प्रशिक्षण संरचना ; और

(v) बांध या उसके जलाशय या जलाशय के किनारे के साथ अभिन्न रूप से कार्य करने वाली अन्य सहयोजित संरचनाएं हैं ;

(घ) “प्राधिकरण” से धारा 8 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

(ङ) “बांध” से जल को अवरुद्ध करने या उसका व्यपवर्तन करने की दृष्टि से कोई ऐसा कृत्रिम अवरोधक और नदियों या उसकी सहायक नदियों के आर-पार संनिर्मित इसकी अनुलग्न संरचना अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत बैराज, बंधिका और इसी प्रकार के जल परिबंधन संरचनाएं भी हैं, किंतु इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं—

(क) नहर, जलवाही सेतु और नौपरिवहन जलसरणी और वैसी ही जलप्रवहण संरचनाएं ;

(ख) बाढ़ तटबंध, कुल्या, नियामक बंध तथा वैसी ही प्रवाह नियंत्रण संरचनाएं ;

(च) “बांध संबंधी विफलता” से किसी बांध की संरचना या संक्रिया में ऐसी कोई विफलता अभिप्रेत है, जिसके कारण रोके हुए जल का ऐसा अनियंत्रित प्रवाह होता है, जिसके परिणामस्वरूप निम्न सतह की ओर जल का भराव होता है, जिससे लोगों का जीवन और संपत्ति तथा वनस्पति, प्राणिजात और नदीय पारिस्थितिकी सहित पर्यावरण प्रभावित होता है ;

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, संक्रिया संबंधी विफलता से बांध के ऐसी दोषपूर्ण संक्रियाएं अभिप्रेत हैं, जो संक्रिया और अनुरक्षण मैनुअल से असंगत हैं ;

(छ) “बांध संबंधी घटना” से बांध को होने वाली ऐसी सभी समस्याएं अभिप्रेत हैं, जो किसी बांध संबंधी विफलता में अवक्रमित नहीं हुई हैं और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं,—

(i) बांध और उससे अनुलग्न संरचनाओं को हुआ कोई संरचनात्मक नुकसान ;

(ii) बांध में के किसी उपकरण का कोई अप्रायिक पठन ;

(iii) बांध के ढांचे में से कोई अप्रायिक प्रस्राव या रिसाव ;

(iv) प्रस्राव या रिसाव व्यवस्था में कोई अप्रायिक परिवर्तन ;

(v) बांध के नीचे अवेक्षित कोई क्वथन या उत्सृत अवस्था ;

(vi) बांध के आधार या ढांचे से या उसकी किन्हीं बीथियों में से, किसी प्रस्राव या रिसाव में कोई आकस्मिक रोक या अप्रायिक घटाव ;

(vii) फाटकों की कोई अपक्रिया या उनका अनुपयुक्त प्रचालन ;

(viii) ऐसी बाढ़ की उत्पत्ति, जिसका शिखर बांध की उपलब्ध बाढ़ निस्सार क्षमता या अनुमोदित डिजाइन बाढ़ के सत्तर प्रतिशत से अधिक है ;

(ix) किसी ऐसी बाढ़ की उत्पत्ति, जिसके परिणामस्वरूप उपलब्ध खुली जगह पर या अनुमोदित डिजाइन खुली जगह पर अधिक्रमण होता है ;

(x) अधिप्लवन-मार्ग या पक्की ढाल, आदि के अनुप्रवाह से पांच सौ मीटर तक निकट प्रतिवास में कोई अप्रायिक अपक्षरण ; और

(xi) कोई अन्य ऐसी घटना, जिसका कोई प्रजावान बांध इंजीनियर, बांध संबंधी सुरक्षा के विषयों से संबंध स्थापित कर सके;

(ज) “बांध सुरक्षा इकाई” से धारा 30 में निर्दिष्ट किसी विनिर्दिष्ट बांध की बांध सुरक्षा इकाई अभिप्रेत है ;

(झ) “संकट स्थिति” से बांध या अनुलग्न संरचना या उसके जलाशय या जलाशय के किनारे में ऐसी स्थितियों का घटना या संभावित विकास अभिप्रेत है जो, यदि उन पर कार्य न किया जाए तो, बांध को उसके आशयित फायदों के लिए सुरक्षित संक्रिया में बाधा पहुंचा सकती है या लोगों के जीवन और संपत्ति को तथा पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत वनस्पति, प्राणिजात और नदीय पारिस्थितिकी भी है, गंभीर जोखिम पहुंचा सकती हैं ;

(ञ) “प्रलेखीकरण” से बांधों के अन्वेषण, डिजाइन, संनिर्माण, प्रचालन,

निष्पादन, अनुरक्षण, मुख्य मरम्मत, परिवर्तन, विस्तार और सुरक्षा से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों सहित सभी स्थायी अभिलेख अभिप्रेत हैं और इनके अंतर्गत डिजाइन ज्ञापन, संनिर्माण रेखाचित्र, भू-गर्भीय रिपोर्टें, बांध की अनुकारक संरचना और हाइड्रोलिक प्रतिक्रिया से संबंधित विशेष अध्ययन रिपोर्टें, डिजाइन और रेखाचित्रों में किए गए परिवर्तन, क्वालिटी नियंत्रण अभिलेख, आपात कार्यवाई योजना, प्रचालन और अनुरक्षण नियमावली, यंत्रीकरण मापन, निरीक्षण और परीक्षण रिपोर्टें, प्रचालन संबंधी रिपोर्ट तथा बांध सुरक्षा पुनर्विलोकन रिपोर्टें और अन्य समान प्रकार की रिपोर्टें भी हैं ;

(ट) “बांध का विस्तार” से विद्यमान बांध या जलाशय के क्षेत्र में कोई परिवर्तन अभिप्रेत है, जिससे जल भंडारण की ऊंचाई में वृद्धि होती है या बांध द्वारा रोके गए जल की मात्रा में वृद्धि होती है ;

(ठ) “सरकार” से, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार अभिप्रेत है ;

(ड) “निरीक्षण” से बांध और उसके अनुलग्न संरचना के किसी संघटक की स्थल पर परीक्षा अभिप्रेत है ;

(ढ) “अन्वेषण” से किसी बांध और उसकी अनुलग्न या उसके किसी भाग से संबंधित किसी विनिर्दिष्ट समस्या के साक्ष्य का संग्रहण, उसकी विस्तृत परीक्षा, विश्लेषण या संवीक्षा अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत प्रयोगशाला परीक्षण, स्वस्थाने परीक्षण, भू-गर्भीय पूर्वक्षण, माडल परीक्षण और समस्या का सुनिश्चित अनुरूपण भी है ;

(ण) “राष्ट्रीय समिति” से धारा 5 के अधीन गठित राष्ट्रीय बांध सुरक्षा पर समिति अभिप्रेत है ;

(त) “अधिसूचना” से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और “अधिसूचित करना” पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(थ) “बांध की संक्रिया” से बांध के उपयोग, नियंत्रण और कार्यकरण के ऐसे तत्व अभिप्रेत हैं, जो प्राथमिक रूप से जल के संग्रहण, उसकी निकासी और बांध की ढांचागत सुरक्षा को प्रभावित कर सके ;

(द) “प्रचालन और अनुरक्षण निर्देशिका” से ऐसे लिखित अनुदेश अभिप्रेत हैं, जिनमें प्रचालन प्रक्रियाएं, अनुरक्षण प्रक्रियाएं, आपात प्रक्रियाएं और बांध के सुरक्षित प्रचालन के लिए आवश्यक कोई अन्य विशेषता उपबंधित हैं ;

(ध) “विनिर्दिष्ट बांध के स्वामी” से केन्द्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार या संयुक्त रूप से एक या अधिक सरकारें या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्थानीय प्राधिकारी या कंपनी और ऐसे कोई या सभी व्यक्ति या संगठन अभिप्रेत हैं, जिनका विनिर्दिष्ट बांध पर स्वामित्व है, नियंत्रण है, प्रचालन करते हैं, या अनुरक्षण करते हैं ;

(न) “विहित” से, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(प) “विनियमों” से इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं ;

(फ) “उपचारात्मक उपाय” से ऐसे संरचनात्मक या असंरचनात्मक उपाय

अभिप्रेत हैं जो विनिर्दिष्ट बांध की संकटकालीन स्थिति को दूर करने या कम करने के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट बांध या अनुलग्न संरचना या जलाशय या जलाशय किनारे या जलाशय के जल-ग्रहण क्षेत्र के संबंध में अपेक्षित हों ;

(ब) किसी विनिर्दिष्ट बांध के संबंध में, “जलाशय” से किसी विनिर्दिष्ट बांध द्वारा रोके गए जल का कोई विस्तार अभिप्रेत होगा ;

(भ) “विनिर्दिष्ट बांध” से इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व या उसके पश्चात् सन्निर्मित ऐसा कोई बांध अभिप्रेत है, जो—

(i) साधारण आधार क्षेत्र के निम्नतम भाग से बांध के शिखर तक मापित ऊंचाई में पन्द्रह मीटर से अधिक है ; या

(ii) ऊंचाई में दस मीटर से पन्द्रह मीटर के बीच है और निम्नलिखित में से कम से कम एक को पूरा करता है, अर्थात् :—

(अ) शिखर की लंबाई कम से कम पांच सौ मीटर है ; या

(आ) बांध द्वारा बनाए गए जलाशय की क्षमता कम से कम दस लाख घनमीटर है ;

(इ) बांध द्वारा विसर्जन किया गया अधिकतम बाढ़ निस्सारण प्रति सेकेंड कम से कम दो हजार घनमीटर है ;

(ई) बांध में विशिष्ट रूप से कठिन आधार संबंधी समस्याएं हैं ;

(उ) बांध अप्रायिक डिजाइन का है ;

(म) “राज्य समिति” से धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन गठित राज्य बांध सुरक्षा समिति अभिप्रेत है ;

(य) “राज्य बांध सुरक्षा संगठन” से धारा 14 के अधीन स्थापित राज्य बांध सुरक्षा संगठन अभिप्रेत है ; और

(यक) “भेद्यता और परिसंकट वर्गीकरण” से बांधों की स्थिति, अवस्थान, नुकसान या परिसंकट संभाव्यता के आधार पर उनके वर्गीकरण की प्रणाली या प्रणालियां अभिप्रेत हैं ।

अध्याय 2

राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति

5. (1) उस तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति नाम से ज्ञात एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया जाएगा, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग — अध्यक्ष, पदेन ;

(ख) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दस से अनधिक बांध इंजीनियरी या बांध सुरक्षा से संबंधित विषयों में कार्य करने वाले, केंद्रीय सरकार के ऐसे प्रतिनिधि, जो उस सरकार के संयुक्त सचिव या समतुल्य पंक्ति से नीचे के न हों — सदस्य, पदेन ;

(ग) केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों के मुख्य इंजीनियर या समतुल्य स्तर के चक्रानुक्रम द्वारा नामनिर्दिष्ट सात से अनधिक प्रतिनिधि — सदस्य,

राष्ट्रीय समिति
का गठन ।

पदेन ; और

(घ) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट बांध सुरक्षा के क्षेत्र में के और सहबद्ध क्षेत्रों में के तीन से अनधिक विशेषज्ञ — सदस्य ।

(2) राष्ट्रीय समिति का गठन, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा और उसके पश्चात् प्रत्येक तीन वर्ष के लिए उसका पुनर्गठन किया जाएगा ।

राष्ट्रीय समिति के
कृत्य ।

6. (1) राष्ट्रीय समिति पहली अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगी, जो आपदाओं से संबंधित बांध संबंधी विफलता का निवारण करने के लिए और बांध सुरक्षा के मानकों को बनाए रखने के लिए आवश्यक हों ।

(2) राष्ट्रीय समिति, अपने कृत्यों का निर्वहन करते हुए उतनी उपसमितियां गठित कर सकेगी, जितनी वह समिति को सहायता करने के लिए और राष्ट्रीय समिति की सचिवालयिक सहायता के लिए आवश्यक समझे और ऐसी उपसमितियां प्राधिकरण द्वारा उपबंधित की जाएंगी ।

(3) राष्ट्रीय समिति द्वारा संगृहीत या जनित जानकारी और सूचना का प्रसार प्राधिकरण द्वारा सभी पणधारियों को किया जाएगा ।

राष्ट्रीय समिति की
बैठकें ।

7. (1) राष्ट्रीय समिति की बैठक ऐसे समय और स्थानों पर होगी तथा वह अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं :

परंतु राष्ट्रीय समिति वर्ष में दो बार बैठक करेगी और एक बैठक वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने से पहले आयोजित की जाएगी ।

(2) राष्ट्रीय समिति किसी विनिर्दिष्ट बांध के स्वामी के प्रतिनिधि को और बांध सुरक्षा में ऐसे अन्य विशेषज्ञों को (जिनके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ भी हैं), जिन्हें वह अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए समुचित समझे, आमंत्रित कर सकेगी ।

(3) राष्ट्रीय समिति पर उपगत व्यय ऐसी रीति में होगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

अध्याय 3

राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण

राष्ट्रीय बांध सुरक्षा
प्राधिकरण की
स्थापना ।

8. (1) इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर, उस तारीख से, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी ।

(2) प्राधिकरण की अध्यक्षता, केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले किसी ऐसे अधिकारी द्वारा की जाएगी, जो भारत सरकार के अपर सचिव या समतुल्य की पंक्ति से नीचे का न हो और जिसके पास बांध इंजीनियरी और बांध सुरक्षा प्रबंध से संबंधित समस्याओं का निपटारा करने का ज्ञान और पर्याप्त अर्हता, अनुभव और क्षमता हो ।

(3) प्राधिकरण का मुख्यालय दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में होगा और प्राधिकरण भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालयों की स्थापना कर सकेगा ।

(4) प्राधिकरण ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा, उसे समय-समय पर दिए जाएं ।

प्राधिकरण
के
कृत्य ।

9. (1) प्राधिकरण, दूसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो विनिर्दिष्ट बांधों की उचित निगरानी, निरीक्षण और अनुरक्षण के लिए राष्ट्रीय समिति द्वारा तैयार की गई नीति, मार्गदर्शक सिद्धांतों और मानकों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हों और ऐसे प्रयोजनों के लिए, उसे किसी व्यक्ति को हाजिर करने और उससे कोई ऐसी जानकारी, जो आवश्यक हो, मांगने की शक्ति होगी ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्राधिकरण राज्यों के राज्य बांध सुरक्षा संगठनों के बीच या किसी राज्य बांध सुरक्षा संगठन और उस राज्य में के विनिर्दिष्ट बांध के स्वामी के बीच किसी मुद्दे का समाधान करने के लिए सभी प्रयास करेगा ।

(3) इस अधिनियम के अधीन विषयों के संबंध में किया गया प्राधिकरण का प्रत्येक विनिश्चय अंतिम और उस विवाद के सभी पक्षकारों पर आबद्धकर होगा ।

10. (1) केंद्रीय सरकार, प्राधिकरण को इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों का पालन करने के लिए समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए उतने अधिकारी और अन्य कर्मचारी, जितने वह आवश्यक समझे, उपलब्ध कराएगी :

प्राधिकरण के
अधिकारी और
कर्मचारी ।

परंतु ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के पास बांध सुरक्षा के क्षेत्र में, जिसके अंतर्गत बांध डिजाइन, जलीय यांत्रिकी इंजीनियरी, जल-विज्ञान, भू-तकनीकी अन्वेषण, साधन विनियोग, बांध-पुनर्वास के क्षेत्र या ऐसे अन्य क्षेत्र भी हैं, ऐसी अर्हताएं और अनुभव होगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के कृत्य, शक्तियां और उनकी सेवा के निबंधन तथा शर्तें वे होंगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

अध्याय 4

राज्य बांध सुरक्षा समिति

11. (1) उस तारीख से, जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक राज्य बांध सुरक्षा समिति का गठन किया जाएगा, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

राज्य बांध सुरक्षा
समिति का
गठन ।

(क) राज्य के बांध सुरक्षा के लिए उत्तरदायी विभाग का मुख्य इंजीनियर या समतुल्य अधिकारी — अध्यक्ष, पदेन ;

(ख) ऐसे विभागों से, जो राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किए जाएं, या ऐसे अन्य संगठनों से, जो विनिर्दिष्ट बांधों के स्वामी हैं, छह व्यक्तियों से अनधिक व्यक्तियों, मुख्य इंजीनियर की पंक्ति के तकनीकी और वैज्ञानिक अधिकारी — सदस्य ;

(ग) उन दशाओं में, जहां किसी राज्य के किसी विनिर्दिष्ट बांध के जलाशय क्षेत्र का विस्तार, किसी अन्य राज्य तक है, प्रत्येक ऐसे अनुप्रवाह राज्य का मुख्य इंजीनियर या समतुल्य स्तर का अधिकारी — सदस्य ;

(घ) उन दशाओं में, जहां किसी राज्य के किसी विनिर्दिष्ट बांध की बाढ़ निकासी का प्रवाह किसी पड़ोसी राज्य में होता है, प्रत्येक ऐसे अनुप्रवाह राज्य का मुख्य इंजीनियर या समतुल्य स्तर का अधिकारी — सदस्य ;

(ङ) अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला

केंद्रीय जल आयोग का एक प्रतिनिधि, जो निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो — सदस्य ;

(च) जल-विज्ञान या बांध डिजाइनों के क्षेत्र में, तीन से अनधिक इंजीनियरी संस्थानों के विशेषज्ञ — सदस्य ; और

(छ) अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण का एक प्रतिनिधि, जो निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो — सदस्य ।

(2) राज्य समिति का गठन इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा और उसके पश्चात् प्रत्येक तीन वर्ष के लिए उसका पुनर्गठन किया जाएगा ।

राज्य समिति के कृत्य ।

12. (1) राज्य समिति, तीसरी अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगी, जो प्राधिकरण द्वारा जारी बांध सुरक्षा संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतों, मानकों और अन्य निदेशों के अनुसार, इस अधिनियम के अधीन आपदाओं से संबंधित बांध संबंधी विफलता के निवारण के लिए आवश्यक हों ।

(2) राज्य समिति अपने कृत्यों के निर्वहन में, उतनी उपसमितियों द्वारा सहायता प्राप्त करेगी, जितनी वह आवश्यक समझे और राज्य समिति तथा उसकी उपसमितियों को सचिवालयिक सहायता संबद्ध राज्य बांध सुरक्षा संगठन द्वारा प्रदान की जाएगी ।

राज्य समिति की बैठकें ।

13. (1) राज्य समिति की बैठकें ऐसे समय और स्थानों पर होंगी तथा अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में, प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेंगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं :

परंतु राज्य समिति, एक वर्ष में दो बार बैठक करेगी और एक बैठक, वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने से पहले आयोजित की जाएगी ।

(2) राज्य समिति, किसी विनिर्दिष्ट बांध के स्वामी के प्रतिनिधि को और बांध सुरक्षा में ऐसे अन्य विशेषज्ञों को, जो वह अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए समुचित समझे, आमंत्रित कर सकेगी ।

(3) राज्य समिति की बैठकों पर उपगत व्यय ऐसी रीति में किया जाएगा, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(4) ऐसे विशेषज्ञ सदस्यों और अन्य आमंत्रित विशेषज्ञों को, जो राज्य समिति या उसकी उपसमितियों की बैठकों में उपस्थित होते हैं, ऐसी फीस और भत्ते संदत्त किए जाएंगे, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।

अध्याय 5

राज्य बांध सुरक्षा संगठन

राज्य बांध सुरक्षा संगठन की स्थापना ।

14. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के भीतर, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, बांध सुरक्षा से संबंधित विषय में कार्य करने वाले किसी विभाग में, “राज्य बांध सुरक्षा संगठन” के नाम से ज्ञात एक पृथक् संगठन की स्थापना करेगी :

परंतु ऐसे राज्यों में, जहां विनिर्दिष्ट बांधों की संख्या तीस से अधिक है, राज्य बांध सुरक्षा संगठन की अध्यक्षता किसी ऐसे अधिकारी द्वारा की जाएगी, जो मुख्य इंजीनियर या समतुल्य की पंक्ति से नीचे का न हो और सभी अन्य दशाओं में राज्य

बांध सुरक्षा संगठन की अध्यक्षता किसी ऐसे अधिकारी द्वारा की जाएगी, जो अधीक्षण इंजीनियर या समतुल्य की पंक्ति से नीचे का न हो ।

(2) राज्य बांध सुरक्षा संगठन, बांध सुरक्षा से संबंधित विषय में कार्य करने वाले विभाग के तकनीकी प्रधान के प्रति उत्तरदायी होगा और वह उसको रिपोर्ट करेगा ।

(3) राज्य बांध सुरक्षा संगठन की संगठनात्मक संरचना और कार्य प्रक्रियाएं ऐसी होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

(4) राज्य बांध सुरक्षा संगठन के प्रशासनिक और अन्य व्यय संबंध राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा ।

15. (1) राज्य सरकार, उस राज्य में विनिर्दिष्ट बांधों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, राज्य बांध सुरक्षा संगठन को उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी, जितने वह उक्त संगठन के दक्ष कार्यकरण के लिए आवश्यक समझे :

राज्य बांध सुरक्षा संगठन के अधिकारी और कर्मचारी ।

परंतु ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के पास बांध सुरक्षा के क्षेत्र में, जिसके अंतर्गत बांध डिजाइन, जलीय यांत्रिकी इंजीनियरी, जल-विज्ञान, भू-तकनीकी अन्वेषण, साधन विनियोग, बांध पुनर्वास के क्षेत्र या ऐसे अन्य क्षेत्र भी हैं, ऐसी अर्हताएं और अनुभव होगा, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों के कृत्य और शक्तियां वे होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

अध्याय 6

बांध सुरक्षा से संबंधित कर्तव्य और कृत्य

16. (1) प्रत्येक राज्य बांध सुरक्षा संगठन, ऐसे विनिर्दिष्ट बांधों की सतत् सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसकी अधिकारिता के भीतर आने वाले सभी विनिर्दिष्ट बांधों की,—

निगरानी और निरीक्षण ।

(क) शाश्वत निगरानी रखेगा ;

(ख) निरीक्षण करेगा ; और

(ग) उनकी संक्रिया और अनुरक्षण को मानिटर करेगा,

और ऐसे उपाय करेगा, जो सुरक्षा संबंधी ऐसी सरोकारों का पता लगाने के लिए आवश्यक हों, जो ऐसे बांध सुरक्षा संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतों, मानकों और अन्य निदेशों के अनुसार, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, बांध सुरक्षा आश्वासन के समाधानप्रद स्तर को प्राप्त करने की दृष्टि से जानकारी में आई हों ।

(2) राज्य बांध सुरक्षा संगठन, लोक सुरक्षा के अनुरूप विनिश्चय करने में स्वयं अपने को समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए ऐसे अन्वेषण करेगा या करवाएगा और ऐसे आंकड़े एकत्रित करेगा या एकत्रित करवाएगा, जो उसकी अधिकारिता के अधीन आने वाले बांधों, जलाशयों और अनुलग्न संरचनाओं के डिजाइन, संनिर्माण, मरम्मत और विस्तारण की विभिन्न विशेषताओं के उचित पुनर्विलोकन और अध्ययन के लिए अपेक्षित हों ।

17. राज्य बांध सुरक्षा संगठन, उसकी अधिकारिता के अधीन आने वाले प्रत्येक बांध को ऐसी भेद्यता और परिसंकट वर्गीकरण मापदंड के अनुसार वर्गीकृत करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

बांधों की भेद्यता और परिसंकट वर्गीकरण ।

लाग बुकों का
रखा जाना ।

18. (1) प्रत्येक राज्य बांध सुरक्षा संगठन उसकी अपनी अधिकारिता के अधीन आने वाले प्रत्येक विनिर्दिष्ट बांध के लिए एक लाग बुक या डाटा बेस सामग्री रखेगा, जिसमें निगरानी और निरीक्षण से संबंधित सभी क्रियाकलापों को और बांध सुरक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को ऐसे व्यौरों के साथ तथा ऐसे प्ररूप में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, को अभिलिखित किया जाएगा ।

(2) प्रत्येक राज्य बांध सुरक्षा संगठन, प्राधिकरण को, उसके द्वारा जब कभी अपेक्षा की जाए, ऐसी सभी जानकारी प्रस्तुत करेगा ।

बांध संबंधी
विफलता और बांध
संबंधी घटनाओं के
अभिलेख ।

19. (1) प्रत्येक राज्य बांध सुरक्षा संगठन, उसकी अपनी अधिकारिता के अधीन किसी बांध संबंधी विफलता की घटना की रिपोर्ट प्राधिकरण को करेगा और उसे, जब कभी उसके द्वारा अपेक्षा की जाए, सूचना देगा ।

(2) प्रत्येक राज्य बांध सुरक्षा संगठन, उसकी अधिकारिता के अधीन आने वाले प्रत्येक विनिर्दिष्ट बांध की मुख्य बांध संबंधी घटनाओं के अभिलेख रखेगा और प्राधिकरण को, जब कभी उसके द्वारा अपेक्षित हो, ऐसी सभी सूचना देगा ।

विनिर्दिष्ट बांधों
की सुरक्षा संबंधी
अनुदेश ।

20. (1) प्रत्येक राज्य बांध सुरक्षा संगठन, विनिर्दिष्ट बांध के स्वामी को किसी बांध के संबंध में किए जाने के लिए अपेक्षित सुरक्षा या उपचारात्मक उपायों पर अपने अनुदेश देगा ।

(2) विनिर्दिष्ट बांध का प्रत्येक स्वामी, राज्य बांध सुरक्षा संगठन द्वारा उसके अपने स्वामित्व वाले किसी विनिर्दिष्ट बांध के संबंध में सुरक्षा या उपचारात्मक उपायों के संबंध में जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन करेगा ।

अनुरक्षण और
मरम्मतों के लिए
निधियां ।

21. विनिर्दिष्ट बांध का प्रत्येक स्वामी, विनिर्दिष्ट बांधों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए तथा राज्य बांध सुरक्षा संगठन की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त और विनिर्दिष्ट निधियों को निश्चित करेगा ।

तकनीकी
प्रलेखीकरण ।

22. (1) विनिर्दिष्ट बांध का प्रत्येक स्वामी, जलविज्ञान, बांध के आधार, बांध की संरचनात्मक इंजीनियरी, बांध का जल विभाजक, ऊपरी प्रवाह और बांध के भूमि संबंधी निचले प्रवाह की प्रकृति या उपयोग से संबंधित सभी तकनीकी प्रलेखीकरणों को आर्थिक या संभारतंत्र या पर्यावरणीय संबंधी महत्व के ऐसे सभी संसाधनों या सुविधाओं, जिनके बांध संबंधी विफलता होने के कारण प्रभावित होने की संभावना है, संबंधी जानकारी के साथ संकलित करेगा ।

(2) विनिर्दिष्ट बांध का प्रत्येक स्वामी, राज्य बांध सुरक्षा संगठन और प्राधिकरण को, जब कभी उनके द्वारा अपेक्षा की जाए, ऐसी सभी जानकारी देगा ।

(3) विनिर्दिष्ट बांध का प्रत्येक स्वामी बांध सुरक्षा और बांध कार्य निष्पादन से संबंधित आंकड़े का भंडारण करने, पुनः प्राप्त करने और वितरित करने के लिए आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी साधनों से अपने संगठन को सुसज्जित करेगा ।

विनिर्दिष्ट बांधों
की सुरक्षा के लिए
उत्तरदायी व्यक्तियों
की अर्हताएं और
अनुभव ।

23. विनिर्दिष्ट बांधों की सुरक्षा और उनसे संबंधित सभी क्रियाकलापों के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति के पास ऐसी अर्हताएं और अनुभव होगा तथा वह ऐसा प्रशिक्षण पूरा करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

राज्य बांध सुरक्षा
संगठन और
प्राधिकरण की
अधिकारिता ।

24. (1) इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सभी विनिर्दिष्ट बांध, बांध निरीक्षण, सूचना के विश्लेषण, अन्वेषण रिपोर्टों या सुरक्षा प्रास्थिति से संबंधित सिफारिशों और बांध सुरक्षा में सुधार करने के लिए किए जाने

वाले उपचारात्मक उपायों से संबंधित विषयों में, उस राज्य के, जिसमें ऐसा बांध स्थित है, राज्य बांध सुरक्षा संगठन की अधिकारिता के अधीन होंगे ; और सभी ऐसे विषयों में विनिर्दिष्ट बांध के स्वामी द्वारा पूर्ण सहयोग दिया जाएगा :

परन्तु जहां कोई विनिर्दिष्ट बांध केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर पर उपक्रम के स्वामित्वाधीन है या जहां किसी विनिर्दिष्ट बांध का दो या अधिक राज्यों पर विस्तार किया गया है या जहां एक राज्य में कोई विनिर्दिष्ट बांध किसी अन्य राज्य के स्वामित्वाधीन है, वहां प्राधिकरण का, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए राज्य बांध सुरक्षा संगठन के रूप में अर्थ लगाया जाएगा :

परन्तु यह और कि ऐसे सभी बांधों में, जहां प्राधिकरण राज्य बांध सुरक्षा संगठन की भूमिका निभाता है, वहां राज्य सरकारों की, जिनकी अधिकारिता के भीतर ऐसे बांध अवस्थित हैं, प्राधिकरण के पास यथा उपलब्ध इन विनिर्दिष्ट बांधों से संबंधित सभी जानकारी तक पहुंच होगी ।

(2) प्राधिकरण या संबंधित राज्य बांध सुरक्षा संगठन का प्राधिकृत प्रतिनिधि इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए कोई आवश्यक निरीक्षण या अन्वेषण करने के प्रयोजनों के लिए, जब कभी अपेक्षित हो, विनिर्दिष्ट बांध के किसी भाग या उसके स्थल में प्रवेश कर सकेगा और ऐसी अन्वेषण पद्धतियों का उपयोग कर सकेगा, जो आवश्यक समझी जाएं ।

(3) उपधारा (2) के अधीन निरीक्षण या अन्वेषण करने के पश्चात्, उस उपधारा में निर्दिष्ट प्रतिनिधि की यह राय है कि कतिपय उपचारात्मक उपाय किए जाने अपेक्षित हैं तो वह ऐसे विनिर्दिष्ट बांध के भारसाधक अधिकारी को और संबंधित राज्य बांध सुरक्षा संगठन को ऐसे उपचारात्मक उपायों की रिपोर्ट करेगा ।

(4) विनिर्दिष्ट बांधों के, उनकी समय-सीमा, विकृति, अवक्रमण, संरचना संबंधी या अन्य बाधाओं के कारण संकटापन्न पाए जाने की दशा में, प्राधिकरण और संबंधित राज्य बांध सुरक्षा संगठन ऐसे प्रचालन संबंधी पैमानों के आधार पर, ऐसे उपचारात्मक उपायों का (जिसके अन्तर्गत अधिकतम जलाशय स्तर, अधिकतम उत्प्लव मार्ग निस्सारण और अन्य स्थानों के माध्यम से अधिकतम निस्सारण भी है) जो वह आवश्यक समझे, सुझाव देगा ।

(5) उपधारा (1), उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) की कोई बात, विनिर्दिष्ट बांध के स्वामी या किसी अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति को, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसे न्यस्त किए गए किन्हीं उत्तरदायित्वों या बाध्यताओं से मुक्त नहीं करेगी और उपधारा (1), उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंध इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में ।

25. प्राधिकरण या राज्य बांध सुरक्षा संगठन द्वारा किए गए किसी प्रकार के अन्वेषण पर उपगत किए जाने वाले सभी खर्चों को, जिसके अन्तर्गत किसी परामर्शी और विशेषज्ञ को दिए जाने वाले संदाय भी हैं, विनिर्दिष्ट बांध के स्वामी द्वारा वहन किया जाएगा ।

अन्वेषण
लागत । की

26. (1) किसी विनिर्दिष्ट बांध का कोई संनिर्माण या परिवर्तन कार्य, ऐसे अभिकरणों द्वारा, जो यथास्थिति, प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा प्रत्यायित हों, किए जाने वाले अन्वेषण, डिजाइन और संनिर्माण कार्य के अधीन रहते हुए किया जाएगा :

बांधों
संनिर्माण
परिवर्तन । का
या

परंतु प्राधिकरण किसी ऐसे अभिकरण को निरहित कर सकेगा, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक अभिकरण, विनिर्दिष्ट बांध की सुरक्षा का डिजाइन बनाने या मूल्यांकन करने के प्रयोजन के लिए भारतीय मानक ब्यूरो की सुसंगत मानक संहिताओं और मार्गदर्शक सिद्धांतों का उपयोग करेगा तथा यदि डिजाइन या बांध सुरक्षा मूल्यांकन में कोई विचलन किया गया है, तो उसके कारण देगा।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक अभिकरण अन्वेषण, डिजाइन और संनिर्माण के प्रयोजन के लिए ऐसे अर्हित, अनुभवी और सक्षम इंजीनियरों को नियोजित करेगा जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक अभिकरण, बांध के डिजाइन का अनुमोदन करने के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की सुसंगत संहिताओं और मार्गदर्शक सिद्धांतों के उपबंधों के अनुसार डिजाइन की सुरक्षा, प्रचालन संबंधी मानकों और नीतियों का प्रदर्शन करेगा।

(5) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक अभिकरण, बांध संनिर्माण के प्रयोजन के लिए ऐसे क्वालिटी नियंत्रणाकारी उपाय करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(6) किसी विनिर्दिष्ट बांध का संनिर्माण या किसी विद्यमान विनिर्दिष्ट बांध का परिवर्तन या विस्तारण ऐसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किया जाएगा, जो, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

जलाशयों का
आरंभिक भराव।

27. (1) किसी विनिर्दिष्ट बांध के किसी जलाशय के आरंभिक भराव से पूर्व, उसके डिजाइन के लिए जिम्मेदार अभिकरण, बांध और उसकी अनुलग्न संरचनाओं के कार्य-निष्पादन को मानिटर करने और उनका मूल्यांकन करने के लिए पर्याप्त समय रहते हुए, भराव संबंधी मापदंड बनाएगा और एक आरंभिक भराव योजना तैयार करेगा।

(2) जलाशय का आरंभिक भराव किए जाने से पूर्व, राज्य बांध सुरक्षा संगठन, विनिर्दिष्ट बांध का निरीक्षण करेगा या अपने स्वयं के इंजीनियरों द्वारा या विशेषज्ञों के स्वतंत्र पैनल द्वारा निरीक्षण करवाएगा, जो आरंभिक भराव कार्यक्रम की भी परीक्षा करेगा और भराव के लिए बांध की उपयुक्तता को सम्यक् रूप से प्रमाणित करते हुए उसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगा।

प्रचालन और
अनुरक्षण।

28. (1) विनिर्दिष्ट बांध का प्रत्येक स्वामी, विनिर्दिष्ट बांध के लिए प्रचालन और अनुरक्षण स्थापन उपलब्ध कराएगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे प्रत्येक बांध पर पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित संक्रिया और अनुरक्षण इंजीनियर या तकनीकी व्यक्ति तैनात किए जाएंगे।

(2) विनिर्दिष्ट बांध का प्रत्येक स्वामी, यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक विनिर्दिष्ट बांध पर उचित प्रलेखीकृत प्रचालन और अनुरक्षण निर्देशिका रखी जाए और सभी समयों पर उसका अनुसरण किया जाए।

विनिर्दिष्ट बांध के
स्वामी का

29. इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा

उत्तरदायित्व ।

कि किसी विनिर्दिष्ट बांध का स्वामी, बांध या जलाशय के संनिर्माण, प्रचालन, अनुरक्षण और पर्यवेक्षण के लिए अनुषंगी कर्तव्यों, बाध्यताओं या दायित्वों से मुक्त हो गया है ।

अध्याय 7

सुरक्षा, निरीक्षण और आंकड़े संग्रहण

30. प्रत्येक विनिर्दिष्ट बांध के लिए, स्वामी, उसके प्रचालन और अनुरक्षण स्थापन के भीतर ऐसे सक्षम स्तरीय इंजीनियरों से, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, से मिलकर बनी बांध सुरक्षा इकाई को उपलब्ध कराएगा ।

बांध सुरक्षा
इकाई ।

31. (1) किसी विनिर्दिष्ट बांध का प्रत्येक स्वामी, प्रत्येक वर्ष अपनी बांध सुरक्षा इकाई के माध्यम से, ऐसे प्रत्येक बांध के संबंध में वर्षा ऋतु के पहले और वर्षा ऋतु के पश्चात् निरीक्षण कराएगा ।

निरीक्षण ।

(2) उपधारा (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी विनिर्दिष्ट बांध का प्रत्येक स्वामी, प्रत्येक बाढ़ के दौरान और उसके पश्चात्, भूकंप या किन्हीं अन्य प्राकृतिक या मानव निर्मित विपत्तियों के पश्चात् या यदि बांध में कोई संकटग्रस्त या असामान्य प्रतिक्रिया का कोई संकेत देखा जाता है तो प्रत्येक विनिर्दिष्ट बांध का निरीक्षण करेगा या बांध सुरक्षा इकाई द्वारा उसका निरीक्षण कराएगा ।

(3) किसी विनिर्दिष्ट बांध का प्रत्येक स्वामी,—

(क) उपधारा (1) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट सभी निरीक्षण ऐसे मार्गदर्शक सिद्धान्तों और जांच सूचियों के अनुसार करेगा जो विनियमों द्वारा विनिश्चित की जाएं ;

(ख) संपूर्ण वर्षा ऋतु अवधि में प्रत्येक विनिर्दिष्ट बांध स्थल पर, ऐसे इंजीनियरों और अन्य तकनीकी कार्मिकों को तैनात करेगा, जिनका राज्य बांध सुरक्षा संगठन के परामर्श से विनिश्चय किया जाए ;

परंतु ऐसे इंजीनियरों और अन्य तकनीकी कार्मिकों को, ऐसी किसी अन्य प्राकृतिक या मानव निर्मित विपत्तियों के पश्चात्, जिससे बांध में संकटग्रस्त स्थितियां पैदा हो सकती हैं, संपूर्ण आपात अवधि के दौरान उनके अपने-अपने बांध स्थलों पर तैनात किया जाना अपेक्षित होगा ;

(ग) बांध सुरक्षा इकाई द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट, राज्य बांध सुरक्षा संगठन को भेजेगा, जो उस रिपोर्ट का विश्लेषण करेगा और विनिर्दिष्ट बांध के स्वामी को कमियों और उपचारात्मक उपाय, यदि कोई हों, पर टीका-टिप्पणियां प्रस्तुत करेगा ।

32. (1) किसी विनिर्दिष्ट बांध के प्रत्येक स्वामी के पास, ऐसे बांध के कार्य निष्पादन को मानीटर करने के लिए, प्रत्येक ऐसे विनिर्दिष्ट बांध पर न्यूनतम संख्या में ऐसे उपकरण होंगे और उन्हें ऐसी रीति में प्रतिष्ठापित किया जाएगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

प्रत्येक विनिर्दिष्ट
बांध में
प्रतिष्ठापित किए
जाने वाले
उपकरण ।

(2) विनिर्दिष्ट बांध का प्रत्येक स्वामी उपधारा (1) में निर्दिष्ट उपकरणों के पाठ्यांक का अभिलेख रखेगा और ऐसे पाठ्यांक का विश्लेषण राज्य बांध सुरक्षा संगठन को ऐसे प्ररूप, रीति में और ऐसे अंतरालों पर भेजेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

33. (1) विनिर्दिष्ट बांध का प्रत्येक स्वामी, प्रत्येक विनिर्दिष्ट बांध के समीप

जल-मौसम

जल-मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित करेगा, जो ऐसे आंकड़े अभिलिखित करने में समर्थ हैं, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

विज्ञान केंद्र की स्थापना।

(2) विनिर्दिष्ट बांध का प्रत्येक स्वामी, किसी उपयुक्त अवस्थान पर उपधारा (1) में निर्दिष्ट आंकड़ों का संग्रहण, संकलन, प्रक्रमण और भंडारण करेगा।

भूकंप-विज्ञानी केंद्र का प्रतिष्ठापन।

34. (1) ऐसे प्रत्येक विनिर्दिष्ट बांध की दशा में, जिसकी ऊंचाई तीस मीटर या उससे अधिक है या जो ऐसे भूकंप जोन में आता है, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, विनिर्दिष्ट बांध का स्वामी, सूक्ष्म और प्रबल गति के भूकंपों तथा ऐसे अन्य आंकड़ों को, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, अभिलिखित करने के लिए प्रत्येक ऐसे बांध के समीप एक भूकंप-विज्ञानी केंद्र स्थापित करेगा।

(2) किसी विनिर्दिष्ट बांध का प्रत्येक स्वामी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट डाटा का संग्रहण, संकलन, प्रक्रमण और भंडारण ऐसे उपयुक्त स्थान पर और ऐसी रीति में करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

अध्याय 8

आपात कार्य योजना और आपदा प्रबंधन

विनिर्दिष्ट बांध के स्वामी की बाध्यता।

35. (1) विनिर्दिष्ट बांध का प्रत्येक स्वामी, प्रत्येक विनिर्दिष्ट बांध के संबंध में,—

(क) सुअभिकल्पित जल-मौसम विज्ञान नेटवर्क और एक अंतःप्रवाही पूर्वानुमान प्रणाली स्थापित करेगा ;

(ख) बांध के अनुप्रवाह अधिसंभाव्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए आपात बाढ़ चेतावनी प्रणाली स्थापित करेगा ;

(ग) खंड (क) और खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रणालियों के कार्यकरण का आवधिक रूप से परीक्षण करेगा या करवाएगा ;

(घ) ऐसे वैज्ञानिक और तकनीकी उपकरण संस्थापित करेगा, जो बांध सुरक्षा और अनुप्रवाह क्षेत्र के लोगों के जीवन और संपत्ति को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए समय-समय पर आविष्कृत या अंगीकृत किए गए हैं ;

(ङ) संबंधित जिला प्राधिकारियों को बाढ़ संबंधी चेतावनी सहित अधिकतम पूर्वानुमानित अंतर्वाह और बहिर्वाह तथा बांध के धारा प्रतिकूल प्रवाह या अनुप्रवाह के संबंध में व्यक्तियों और संपत्ति पर उसका प्रतिकूल समाघात, यदि कोई हो, से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएगा और ऐसी जानकारी को सार्वजनिक अधिकारिता में भी उपलब्ध कराएगा ;

(च) जलाशयों की संक्रिया से संबंधित तत्काल जल-विज्ञान और मौसम विज्ञान संबंधी आंकड़ों तथा जानकारी के आदान-प्रदान के लिए आरंभिक चेतावनी प्रणाली के स्थापन और उसको चलाने में प्राधिकरण को आवश्यक सहायता देगा।

(2) किसी विनिर्दिष्ट बांध का प्रत्येक स्वामी, अपने प्रत्येक बांध के लिए ऐसे अंतराल पर, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, जोखिम निर्धारण अध्ययन करेगा और ऐसा पहला अध्ययन इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पांच वर्ष के भीतर किया जाएगा।

आपात कार्य योजना।

36. (1) किसी विनिर्दिष्ट बांध का प्रत्येक स्वामी, प्रत्येक विनिर्दिष्ट बांध के

संबंध में,—

(क) जलाशय की आरंभिक भराई की अनुज्ञा देने से पूर्व आपात कार्य योजना तैयार करेगा और तत्पश्चात् नियमित अंतरालों पर ऐसी योजनाओं को अद्यतन करेगा ;

(ख) ऐसे बांध के संबंध में, जिनका संनिर्माण और भराई इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व की गई है, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पांच वर्ष के भीतर आपात कार्य योजना तैयार करेगा और तत्पश्चात् ऐसे नियमित अंतरालों पर, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, ऐसी योजनाओं को अद्यतन करेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आपात कार्य योजना में,—

(क) किसी वास्तविक या आसन्न बांध विफलता की दशा में विनिर्दिष्ट बांध के धारा प्रतिकूल प्रवाह या अनुप्रवाह वाले व्यक्तियों और संपत्ति की संरक्षा के लिए या आपदा के प्रभावों को कम करने के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रियाएं उपवर्णित होंगी ;

(ख) उसमें,—

(i) ऐसे आपातों के प्रकार सम्मिलित होंगे, जिनके किसी जलाशय की संक्रिया में घटित होने की संभावना है ;

(ii) किसी बांध संबंधी विफलता की दशा में, जलाशय से छोड़े गए बाढ़ के पानी के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने वाले अधिसंभाव्य संभावित क्षेत्रों, जनसंख्या, संरचनाओं और संस्थापनों के साथ संभाव्य विध्वंसात्मक बाढ़ का पता लगाना सम्मिलित होगा ;

(iii) संभाव्य प्रतिकूल दशाओं से, विशेष रूप से मानव जीवन की हानि से बचने के लिए दक्ष और सर्वोत्तम संभावित रीति से निपटने के लिए, चेतावनी प्रक्रियाएं, जल प्लावन मानचित्र और अग्रिम तैयारियां सम्मिलित होंगी ;

(iv) ऐसे अन्य विषय, जो भौगोलिक दशाओं, बांध के आकार और ऐसे अन्य सुसंगत कारकों जो आवश्यक हों को ध्यान में रखते हुए सम्मिलित होंगे ।

(3) इस धारा के अधीन आपात कार्य योजना को तब कार्यान्वित किया जाएगा, जब कभी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हों, जो किसी विनिर्दिष्ट बांध के लिए परिसंकटमय हों या उसके लिए परिसंकटमय हो सकती हैं या सार्वजनिक सुरक्षा, अवसंरचना, अन्य संपत्ति के लिए या पर्यावरण के लिए संभवतः परिसंकटमय हो सकती हैं ।

(4) विनिर्दिष्ट बांध का प्रत्येक स्वामी आपात कार्य योजना को तैयार करते समय और उसे अद्यतन करते समय, सभी आपदा प्रबंधन अभिकरणों और राज्य के अन्य ऐसे विभाग, जिन्हें प्रभावित होने वाले क्षेत्र में आपदा प्रबंधन और राहत संबंधी कार्य सौंपा गया हो, और प्रभावित होने वाले निकटतम सामीप्य बांधों के स्वामियों के साथ परामर्श प्रक्रिया करेगा, जिससे बांध सुरक्षा के मुद्दों पर समन्वय और पारदर्शिता को लाया जा सके और किसी अवांछित भय का निराकरण किया जा सके ।

37. इस अधिनियम के उपबंधों पर या विशिष्ट बांध के स्वामी और अन्य संगठनों और इस अधिनियम के अधीन प्राधिकारियों के दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव

अन्य आपदा
प्रबंधन
प्राधिकारियों को

डाले बिना, प्रत्येक स्वामी, संगठन और प्राधिकारी, विनिर्दिष्ट बांधों में उद्भूत किसी आपदा या आपातस्थिति से निपटने या कम करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के किसी प्राधिकारी को, यदि उसके द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए, आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।

सहायता।

अध्याय 9

व्यापक बांध सुरक्षा मूल्यांकन

व्यापक बांध सुरक्षा मूल्यांकन।

38. (1) किसी विनिर्दिष्ट बांध का स्वामी, विनिर्दिष्ट बांध और उसके जलाशय की दशाओं के अवधारण के प्रयोजन के लिए, विनियमों के अनुसार गठित विशेषज्ञों के किसी स्वतंत्र पैनल के माध्यम से प्रत्येक विनिर्दिष्ट बांध का व्यापक बांध सुरक्षा मूल्यांकन करेगा या करवाएगा :

परंतु प्रत्येक विद्यमान विनिर्दिष्ट बांध के लिए पहला व्यापक बांध सुरक्षा मूल्यांकन इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से पांच वर्ष के भीतर किया जाएगा और तत्पश्चात् प्रत्येक ऐसे बांध का व्यापक सुरक्षा मूल्यांकन ऐसे नियमित अंतरालों पर किया जाएगा जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) व्यापक बांध सुरक्षा मूल्यांकन में निम्नलिखित सम्मिलित होगा, किन्तु यह इन तक ही सीमित नहीं होगा,—

(क) संरचना के अभिकल्प, संनिर्माण, संक्रिया, अनुरक्षण और निष्पादन पर उपलब्ध आंकड़ों का पुनर्विलोकन और विश्लेषण ;

(ख) विनियमों द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अभिकल्प बाढ़ के आजापक पुनर्विलोकन सहित जलराशिक और जल व्यवस्था संबंधी परिस्थितियों का साधारण निर्धारण ;

(ग) कतिपय दशाओं में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, आजापक स्थल विशिष्ट भूकंप पैरामीटरों के साथ विनिर्दिष्ट बांध की भूकंपीय सुरक्षा का साधारण निर्धारण ;

(घ) संक्रिया, अनुरक्षण और निरीक्षण प्रक्रियाओं का मूल्यांकन; और

(ङ) किन्हीं अन्य परिस्थितियों का मूल्यांकन जो ढांचे की अक्षतता के प्रति परिसंकटमय पैदा करता हो।

कतिपय दशाओं में अनिवार्य मूल्यांकन।

39. धारा 38 में निर्दिष्ट व्यापक बांध सुरक्षा मूल्यांकन,—

(क) मूल ढांचे या अभिकल्प संबंधी मानदंड में वृहत् उपांतरण ;

(ख) बांध या जलाशय के किनारे पर किसी अप्रायिक स्थिति का पता लगाने ; और

(ग) चरम जलीय या भूकंपीय घटना,

की दशा में अनिवार्य हो जाएगा।

व्यापक मूल्यांकन की रिपोर्टें।

40. (1) किसी विनिर्दिष्ट बांध का स्वामी, धारा 38 या धारा 39 के अधीन किए गए बांध सुरक्षा मूल्यांकन के परिणामों की रिपोर्ट राज्य बांध सुरक्षा संगठन को देगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट रिपोर्टों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, किन्तु यह उन तक ही सीमित नहीं होगी,—

(क) ढांचे के अभिकल्प, जल विज्ञान, संनिर्माण, संक्रिया, अनुरक्षण और

निष्पादन का दृष्टिक संप्रेक्षण और उससे संबंधित उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर ढांचे की स्थिति का निर्धारण ;

(ख) ढांचे की तत्काल सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए किन्हीं आपात उपायों या कार्रवाइयों की सिफारिशें, यदि अपेक्षित हों ;

(ग) ढांचे के अभिकल्प, संनिर्माण, प्रचालन, अनुरक्षण और निरीक्षण से संबंधित उपचारात्मक उपायों और कार्रवाइयों की सिफारिशें, यदि अपेक्षित हों ;

(घ) अतिरिक्त विस्तृत अध्ययन, अन्वेषण और विश्लेषण की सिफारिशें, यदि अपेक्षित हों ; और

(ङ) बांधों के नैत्यक अनुरक्षण और निरीक्षण में सुधार करने हेतु सिफारिशें, यदि अपेक्षित हों ।

(3) जहां धारा 38 या धारा 39 के अधीन किए गए सुरक्षा मूल्यांकन का परिणाम उपचारात्मक कार्रवाई की सिफारिश हैं, वहां राज्य बांध सुरक्षा संगठन, विनिर्दिष्ट बांध के स्वामी से यह सुनिश्चित करने के लिए पैरवी करेगा कि ऐसे उपचारात्मक उपाय समय पर किए जाएं, जिनके लिए स्वामी पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराएगा ।

(4) जहां धारा 38 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट विशेषज्ञों के स्वतंत्र पैनल और विनिर्दिष्ट बांध के स्वामी के बीच कोई अनिर्णीत विषय उत्पन्न होता है, वहां ऐसा विषय राज्य बांध सुरक्षा संगठन को निर्दिष्ट किया जाएगा, और कोई समझौता न हो पाने की दशा में उक्त विषय को प्राधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा, जो उस संबंध में अपनी सलाह देगा और उसके कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य सरकार को सिफारिशें करेगा ।

अध्याय 10

अपराध और शास्तियां

41. जो कोई, बिना किसी युक्तियुक्त कारण के,—

बाधा डालने, आदि के लिए दंड ।

(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी को या राष्ट्रीय समिति या प्राधिकरण या राज्य समिति या राज्य बांध सुरक्षा संगठन द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालेगा ; या

(ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या राष्ट्रीय समिति या प्राधिकरण या राज्य समिति या राज्य बांध सुरक्षा संगठन के द्वारा या उसकी ओर से इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी निदेश का पालन करने से इंकार करेगा,

वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से दंडनीय होगा और यदि ऐसी बाधा डालने या निदेशों के पालन से इंकार करने का परिणाम जीवन हानि या उसके लिए आसन्न संकट है, तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा ।

42. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है, वहां विभाग का प्रमुख, अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा, जब तक वह यह साबित नहीं कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया

सरकार के विभागों द्वारा अपराध ।

गया था या उसने ऐसे अपराध को रोकने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी सरकारी विभाग द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध, विभाग प्रमुख से भिन्न किसी अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी उपेक्षा का कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा अधिकारी उस उल्लंघन का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

कंपनियों द्वारा
अपराध ।

43. (1) जहां, इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी या निगमित निकाय द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे उल्लंघन की दोषी समझी जाएंगी और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “कंपनी” से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है ; और

(ख) फर्म के संबंध में, “निदेशक” से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

अपराध का
संज्ञान ।

44. (1) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा या राष्ट्रीय समिति या प्राधिकरण या राज्य समिति या राज्य बांध सुरक्षा संगठन द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत के सिवाय नहीं करेगा ।

(2) महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्नतर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा ।

अध्याय 11

प्रकीर्ण

विनिर्दिष्ट बांधों
की सुरक्षा

45. (1) प्रत्येक राज्य बांध सुरक्षा संगठन, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की समाप्ति के

प्रास्थिति पर
वार्षिक रिपोर्ट ।

तीन मास के भीतर अपने कार्यकलापों और राज्य में विनिर्दिष्ट बांधों की सुरक्षा प्रास्थिति की एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और ऐसी रिपोर्ट, प्राधिकरण और राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा और वह सरकार, उसे, जहां राज्य विधान-मंडल में दो सदन हैं वहां प्रत्येक सदन के समक्ष और जहां राज्य विधान-मंडल में केवल एक सदन है, वहां उस सदन के समक्ष रखवाएगी ।

(2) प्रत्येक राज्य बांध सुरक्षा संगठन और किसी विनिर्दिष्ट बांध का प्रत्येक स्वामी, प्राधिकरण को, जब कभी अपेक्षित हो, ऐसे रूपविधान में और ऐसी रीति में, जैसा प्राधिकरण द्वारा विनिश्चय किया जाए, परियोजनाओं के प्रलेखन, विफलता की जांचों की रिपोर्ट और कोई अन्य आंकड़े उपलब्ध करवाएगा ।

(3) प्राधिकरण देश में बांध सुरक्षा क्रियाकलापों की एक समेकित वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छह मास के भीतर केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा तथा वह सरकार उसे संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।

(4) प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट बांधों की सुरक्षा प्रास्थिति पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट अग्रेषित करेगा और वह ऐसी रिपोर्ट पब्लिक डोमेन पर भी उपलब्ध करवाएगा ।

(5) प्रत्येक राज्य का राज्य बांध सुरक्षा संगठन संबंधित राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को अपनी वार्षिक रिपोर्ट अग्रेषित करेगा और वह ऐसी रिपोर्ट पब्लिक डोमेन पर भी उपलब्ध करवाएगा ।

46. विनिर्दिष्ट बांधों से भिन्न बांध का प्रत्येक स्वामी, ऐसे उपाय करेगा, जो बांध की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों और ऐसे उपायों का अनुपालन करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

47. जहां कोई बांध जिसके अंतर्गत भू-स्खलन या हिमनदीय, हिमोढ़ के कारण सृजित कोई बांध भी है, भारत के राज्यक्षेत्र से बाहर अवस्थित है और प्राधिकरण की, स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति या संगठन या प्राधिकारी या स्रोत से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रथमदृष्टया यह राय है कि ऐसे बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जाने अपेक्षित हैं और जिनकी विफलता भारत में अवस्थित लोगों के जीवन और संपत्ति के लिए संकटापन्न हो सकेगी, वहां वह केन्द्रीय सरकार को, लिखित में उसकी इत्तला, उसमें ऐसे संभावित नुकसानों, जो ऐसे बांधों की विफलता के कारण उद्भूत हो सकेंगे और ऐसे बांध के संबंध में किए जाने वाले अपेक्षित सुरक्षा उपायों को उपदर्शित करते हुए करेगा और केन्द्रीय सरकार किसी संभावित आशंका को कम करने के लिए सभी यथोचित उपाय करेगी ।

48. इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे ।

49. (1) यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह अधिसूचना द्वारा, पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची का संशोधन कर सकेगी और तदुपरी, अनुसूचियां तदनुसार संशोधित की गई समझी जाएंगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना की प्रति उसके जारी किए

विनिर्दिष्ट बांधों से भिन्न बांधों के संबंध में सुरक्षा उपाय ।

भारत के राज्यक्षेत्र से बाहर अवस्थित बांधों के संबंध में सुरक्षा उपाय ।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना ।

अनुसूचियों का संशोधन करने की शक्ति ।

जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।

50. केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को, जहां वह राज्य सरकार विनिर्दिष्ट बांध की स्वामी है और किसी अन्य मामले में, किसी विनिर्दिष्ट बांध के स्वामी को ऐसे निदेश दे सकेगी, जो वह आवश्यक समझे ।

केंद्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति ।

रिक्तियों, आदि से राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति, प्राधिकरण और राज्य बांध सुरक्षा समिति की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना ।

51. राष्ट्रीय समिति, प्राधिकरण और राज्य समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि,—

(क) प्राधिकरण में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है ;

(ख) प्राधिकरण के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है ; या

(ग) प्राधिकरण की प्रक्रिया में कोई अनियमितता मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

52. (1) केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रीय समिति की बैठकों का समय और स्थान तथा ऐसी बैठकों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन राष्ट्रीय समिति की बैठकों पर उपगत व्यय ;

(ख) धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन बांध सुरक्षा के क्षेत्र में या ऐसे अन्य क्षेत्र में के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की अर्हताएं और अनुभव ;

(ग) धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन अन्य अधिकारियों और प्राधिकरण के अन्य कर्मचारियों के कृत्य, शक्तियां और सेवा के निबंधन और शर्तें ;

(घ) कोई ऐसा अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए या जिसके संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है ।

राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

53. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन राज्य समिति की बैठकों का समय और स्थान तथा ऐसी बैठकों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(ख) धारा 13 की उपधारा (3) के अधीन राज्य समिति की बैठकों पर उपगत व्यय ;

(ग) धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन राज्य समिति या उसकी उप-

समितियों के विशेषज्ञ सदस्यों या आमंत्रित विशेषज्ञों को संदत्त फीस और भत्ते ;

(घ) धारा 14 की उपधारा (3) के अधीन राज्य बांध सुरक्षा संगठन का संगठनात्मक ढांचा और कार्य प्रक्रिया ;

(ङ) धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन बांध सुरक्षा के क्षेत्र में या ऐसे अन्य क्षेत्र में के राज्य बांध सुरक्षा संगठन के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की, अर्हताएं और अनुभव ;

(च) धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन राज्य बांध सुरक्षा संगठन के कर्मचारियों के कृत्य, शक्तियां और सेवा के निबंधन और शर्तें ;

(छ) धारा 46 के अधीन विनिर्दिष्ट बांधों से भिन्न बांधों की बाबत बांध सुरक्षा उपाय ;

(ज) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए या जिसकी बाबत राज्य सरकार द्वारा, नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है ।

(3) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम यथासंभवशीघ्र इसके बनाए जाने के पश्चात् राज्य विधान-मंडल जहां वह दो सदनों से मिलकर बना है या जहां ऐसा विधान-मंडल एक सदन से मिलकर बना है, के समक्ष रखा जाएगा ।

54. (1) प्राधिकरण, राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों से संगत विनियम बना सकेगा ।

प्राधिकरण द्वारा
विनियम बनाने
की शक्ति ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन बांध सुरक्षा आश्वासन का संतोषजनक स्तर प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत, मानक और अन्य निदेश ;

(ख) धारा 17 के अधीन विनिर्दिष्ट बांधों की भेद्यता और संकट वर्गीकरण के लिए मानदंड ;

(ग) धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन लागू बुकों या डाटा बेस के अनुरक्षण से संबंधित ब्यौरे और प्ररूप ;

(घ) धारा 23 के अधीन विनिर्दिष्ट बांधों की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों की अर्हताएं, अनुभव और प्रशिक्षण ;

(ङ) धारा 26 की उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट बांधों के अन्वेषण, डिजाइन और संनिर्माण के प्रयोजन के लिए सक्षम इंजीनियरों का नियोजन तथा उनकी अर्हताएं और अनुभव ;

(च) धारा 26 की उपधारा (5) के अधीन बांध संनिर्माण के प्रयोजन के लिए क्वालिटी नियंत्रण उपाय ;

(छ) धारा 30 के अधीन बांध सुरक्षा इकाइयों के लिए सक्षम इंजीनियरों का स्तर ;

(ज) धारा 31 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन विनिर्दिष्ट बांधों के

निरीक्षण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और जांच सूचियां ;

(झ) धारा 32 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट बांधों में उपस्कर सेटों की न्यूनतम संख्या और उनके प्रतिष्ठापन की रीति ;

(ञ) धारा 32 की उपधारा (1) के अधीन राज्य बांध सुरक्षा संगठन को पाठ्यांकन का विश्लेषण अग्रेषित करने का प्ररूप, रीति और समय अंतराल ;

(ट) धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट बांधों के समीप जल मौसम विज्ञान केन्द्रों की आंकड़े अपेक्षाएं ;

(ठ) धारा 34 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट बांधों के समीप में भूकंप-विज्ञानी केन्द्रों की डाटा अपेक्षाएं ;

(ड) धारा 34 की उपधारा (2) के अधीन डाटा के संग्रहण, संकलन, प्रक्रमण और भंडारण के उपयुक्त स्थान और रीति ;

(ढ) धारा 35 की उपधारा (2) के अधीन किए जाने वाले जोखिम निर्धारण अध्ययनों का समय अंतराल ;

(ण) धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन आपात कार्य योजना को अद्यतन करने के लिए समय अंतराल ;

(त) धारा 38 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट बांधों के व्यापक सुरक्षा मूल्यांकन के लिए समय अंतराल ;

(थ) धारा 38 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन विद्यमान बांधों के बाढ़ संबंधी डिजाइन का आजापक पुनर्विलोकन ;

(द) धारा 38 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन विद्यमान बांधों का आजापक स्थल विनिर्दिष्ट भूकंप-विज्ञानी पैरामीटर अध्ययन ;

(ध) धारा 46 के अधीन विनिर्दिष्ट बांधों से भिन्न बांध के प्रत्येक स्वामी द्वारा बांध सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय ;

(न) कोई अन्य विषय, जो विनिर्दिष्ट किया जाना है या जिसकी बाबत प्राधिकरण द्वारा उपबंध किया जाना है ।

नियमों और
विनियमों का
संसद् के समक्ष
रखा जाना ।

55. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और विनियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम या विनियम निष्प्रभाव हो जाएगा । किंतु नियम या विनियम के इस प्रकार परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उस नियम या विनियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

कठिनाइयों को दूर
करने की शक्ति ।

56. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित ऐसे आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसको आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

पहली अनुसूची

[धारा 6(1) देखिए]

राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति के कृत्य

1. बांध सुरक्षा के मानकों को बनाए रखने और आपदा संबंधी बांध विफलता को रोकने के प्रयोजन के लिए, ऐसी बांध सुरक्षा नीतियां विकसित करना तथा ऐसे आवश्यक विनियमों की सिफारिश करना, जिनकी अपेक्षा की जाए ;
2. विनिर्दिष्ट बांधों और अनुलग्न संरचनाओं में दबाव संबंधी स्थितियों को हटाने हेतु उपचारात्मक उपाय के लिए अपनाई जाने वाली तकनीकों पर विचारों के आदान-प्रदान के लिए मंच के रूप में कार्य करना ;
3. प्रमुख बांध संबंधी घटनाओं और बांध असफलताओं के कारणों का विश्लेषण करना तथा ऐसी घटनाओं और असफलताओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए योजना, विनिर्देश, संनिर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण पद्धतियों में परिवर्तनों का सुझाव देना ;
4. सुरक्षा आश्वासन के वांछित स्तर के लिए बांध सुरक्षा मूल्यांकन, जोखिम निर्धारण और जोखिम प्रबंधन के एकीकरण के रूप में व्यापक बांध सुरक्षा प्रबंधन दृष्टिकोण विकसित करना ; और बांध संबंधी विफलताओं के कारण प्रभावित व्यक्तियों के लिए बीमा रक्षण के द्वारा प्रतिकारों की भी जांच करना ;
5. बांध सुरक्षा से संबंधित किसी ऐसे विनिर्दिष्ट विषय पर सलाह देना, जो, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट किया जाए ;
6. भारत के राज्यक्षेत्र से बाहर स्थित बांधों के संबंध में सुरक्षोपायों पर केन्द्रीय सरकार के अनुरोध पर सिफारिशें करना ;
7. पुराने बांधों की पुनरुद्धार संबंधी अपेक्षाओं पर सिफारिशें करना ;
8. ऐसे बांध पुनरुद्धार कार्यक्रमों पर, राज्यों में जिनका निष्पादन केन्द्रीय या बाहरी वित्तपोषण के माध्यम से किया जा रहा है, अनुकूल पर्यवेक्षण का उपबंध करना ;
9. बांध सुरक्षा के लिए अनुसंधान और विकास के क्षेत्रों की पहचान करना और निधियों के उपबंध की सिफारिश करना ;
10. जलप्रपातीय बांधों के लिए समन्वित जलाशय प्रचालन के संबंध में सिफारिशें करना ; और
11. बांध सुरक्षा से संबंधित कोई अन्य विनिर्दिष्ट विषय, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट किया जाए ।

दूसरी अनुसूची

[धारा 9(1) देखिए]

राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण के कृत्य

1. बांध सुरक्षा मानकों को बनाए रखने और आपदा संबंधी बांध विफलताओं को रोकने के प्रयोजन के लिए ऐसे कृत्यों का निर्वहन करना, जो राष्ट्रीय समिति द्वारा बनाई गई नीतियों के कार्यान्वयन से संबंधित हैं, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर विनियम बनाना भी है ;
2. राज्यों के राज्य बांध सुरक्षा संगठनों के बीच या किसी राज्य बांध सुरक्षा संगठन और उस राज्य में किसी विनिर्दिष्ट बांध के किसी स्वामी के बीच किसी मुद्दे का समाधान करना ;
3. राज्य बांध सुरक्षा संगठनों को अद्यतन तकनीकी और प्रबंधकीय सहायता उपलब्ध कराना ;
4. देश में सभी विनिर्दिष्ट बांधों के लिए राष्ट्रीय स्तर के डाटा बेस का अनुरक्षण करना, जिसके अंतर्गत उसमें अपेक्षित गंभीर दबाव की स्थितियां, यदि कोई हों, भी हैं ;
5. राज्य बांध सुरक्षा संगठनों और विनिर्दिष्ट बांध के स्वामियों के साथ बांध सुरक्षा से संबंधित डाटा और पद्धतियों तथा तकनीकी या प्रबंधकीय सहायता संबंधी मानकीकरण के लिए संपर्क बनाए रखना ;
6. विनिर्दिष्ट बांधों और अनुलग्न संरचनाओं के नेमी निरीक्षण और विस्तृत अन्वेषण के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त और जांच सूचियां अधिकथित करना ;
7. देश में प्रमुख बांध संबंधी विफलताओं के अभिलेखों का अनुरक्षण करना ;
8. किसी प्रमुख बांध विफलता के कारण की, अपने स्वयं के इंजीनियरों के माध्यम से या विशेषज्ञों के पैनल के माध्यम से, जहां कहीं आवश्यक हो, परीक्षा कराना और राष्ट्रीय समिति को उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करना ;
9. किसी विनिर्दिष्ट बांध के संबंध में किसी प्रमुख लोक सुरक्षा चिंता के कारण का अपने स्वयं के इंजीनियरों के माध्यम से या विशेषज्ञों के पैनल के माध्यम से, जब कभी अपेक्षित हो, परीक्षा करना तथा आगे और अन्वेषणों, प्रचालन संबंधी पैरामीटरों या उपचारात्मक उपायों के संबंध में समुचित अनुदेश जारी करना ;
10. देश में के विनिर्दिष्ट बांधों की भेद्यता और संकट के वर्गीकरण के लिए एक समान मानदंड अधिकथित करना और जब भी आवश्यक हो, ऐसे मानदंड का पुनर्विलोकन करना ;
11. लागू बुक या डाटा बेस को बनाए रखने के संबंध में निदेश देना ;
12. विनिर्दिष्ट बांधों की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों की अपेक्षित अर्हताओं और अनुभव के संबंध में निदेश देना ;
13. ऐसे अभिकरणों को प्रत्यायन प्रदान करना, जिन्हें विनिर्दिष्ट बांधों का अन्वेषण, डिजाइन या संनिर्माण सौंपा जा सकेगा ;
14. किसी ऐसे अभिकरण को विनिर्दिष्ट बांधों के अन्वेषण, डिजाइन,

संनिर्माण या परिवर्तन करने से निरहित करना, यदि वह इस अधिनियम के अधीन किसी विनियम का उल्लंघन करता है ;

15. विनिर्दिष्ट बांधों के अन्वेषण, विन्यास या संनिर्माण के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों की अपेक्षित अर्हताओं और अनुभव के संबंध में निदेश देना ;

16. विनिर्दिष्ट बांधों के संनिर्माण के दौरान किए जाने वाले क्वालिटी नियंत्रण उपायों के संबंध में निदेश देना ;

17. सन्निर्माणाधीन किसी विनिर्दिष्ट बांध के समीप भू-स्खलनों से असुरक्षित क्षेत्रों में निवारक उपायों के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित करना ;

18. ऐसे बांधों की भेद्यता और संकट के वर्गीकरण के आधार पर विनिर्दिष्ट बांधों के बांध सुरक्षा एककों में इंजीनियरों की सक्षमता स्तरों के संबंध में निदेश देना ;

19. विनिर्दिष्ट बांधों में उपस्करों की आवश्यकता और उनके कार्यनिष्पादन को मानीटर करने के लिए उनके लिए प्रतिष्ठापन की रीति के संबंध में निदेश देना ;

20. विनिर्दिष्ट बांधों के आसपास जल-मौसम विज्ञान केन्द्रों की आंकड़े अपेक्षाओं के संबंध में निदेश देना ;

21. विनिर्दिष्ट बांधों के आस-पास भूकंप-विज्ञानी स्टेशनों के डाटा अपेक्षाओं के संबंध में निदेश देना ;

22. विनिर्दिष्ट बांधों की भेद्यता और संकट वर्गीकरण के आधार पर ऐसे बांधों के जोखिम निर्धारण अध्ययनों के लिए समय अंतराल के संबंध में निदेश देना ;

23. विनिर्दिष्ट बांधों की भेद्यता और संकट वर्गीकरण के आधार पर ऐसे बांधों की आपातस्थिति कार्य योजनाओं को अद्यतन करने के लिए समय अंतराल के संबंध में निदेश देना ;

24. विनिर्दिष्ट बांधों के व्यापक बांध सुरक्षा मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञों के स्वतंत्र पैनल के गठन के संबंध में निदेश देना ;

25. विनिर्दिष्ट बांधों की भेद्यता और संकट वर्गीकरण के आधार पर ऐसे बांधों के व्यापक सुरक्षा मूल्यांकन के लिए समय अंतराल के संबंध में निदेश देना ;

26. विद्यमान विनिर्दिष्ट बांधों के बाढ़ विन्यास के पुनर्विलोकन के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित करना ;

27. विनिर्दिष्ट बांधों के स्थल विनिर्दिष्ट भूकंपी पैरामीटर अध्ययनों के पुनर्विलोकन के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित करना ;

28. जल विज्ञान और मौसम विज्ञान और सूचना से संबंधित वास्तविक डाटा के आदान-प्रदान के लिए किसी बांध के स्वामी द्वारा जलाशयों के प्रचालन से संबंधित समुचित ढांचे को सम्मिलित करते हुए किसी आरंभिक चेतावनी प्रणाली की स्थापना करना ;

29. बांध सुरक्षा के संबंध में सामान्य शिक्षा और जागरूकता का संवर्धन करना ;

30. राष्ट्रीय समिति और उसकी उपसमितियों को सचिवालयिक सहायता

उपलब्ध कराना ;

31. ऐसे बांध पुनर्वास कार्यक्रमों के, जो राज्यों, केंद्रीय या बाह्य वित्तपोषण के माध्यम से निष्पादित किए जाते हैं, समन्वयन और संपूर्ण पर्यवेक्षण का उपबंध करना ; और

32. बांध सुरक्षा से संबंधित कोई अन्य विनिर्दिष्ट विषय, जो उसको केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाए ।

तीसरी अनुसूची

[धारा 12(1) देखिए]

राज्य बांध सुरक्षा समिति के कृत्य

1. बांध सुरक्षा के मानकों को बनाए रखने तथा आपदा संबंधी बांध विफलता को रोकने के प्रयोजन के लिए ऐसे कृत्यों का निर्वहन करना जो प्राधिकरण द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, मानकों और अन्य निदेशों के अनुसार आवश्यक हों ;
2. राज्य बांध सुरक्षा संगठन द्वारा किए गए कार्य का पुनर्विलोकन ;
3. संकटग्रस्त दशाओं के अधीन विनिर्दिष्ट बांधों की दशा में अन्वेषणों के लिए पूर्विकताएं स्थापित करना ;
4. ऐसे मामलों में, जहां राज्य में किसी विनिर्दिष्ट बांध की सुरक्षा के संबंध में पहले से ही अन्वेषण किए जा रहे हैं, वहां ऐसे विनिर्दिष्ट बांध की सुरक्षा के संबंध में आगे और अन्वेषणों के लिए आदेश देना और निष्पादन हेतु उत्तरदायित्व सौंपना, जिसके अंतर्गत गैर-विभागीय संसाधनों और स्वतंत्र विशेषज्ञों के संगम का उपयोग भी है, जहां आवश्यक हो ;
5. ऐसे किसी विनिर्दिष्ट बांध की, जो किसी संकटग्रस्त स्थिति में है, सुरक्षा के संबंध में किए जाने हेतु समुचित उपायों की सिफारिश करना ;
6. ऐसी परियोजनाओं के बीच, जिनमें उपचारात्मक सुरक्षा संकर्म अपेक्षित हैं, पूर्विकताएं स्थापित करना ;
7. बांध सुरक्षा के संबंध में सिफारिश किए गए उपायों की प्रगति का पुनर्विलोकन करना ;
8. किसी प्रतिस्रोत राज्य के संबंध में राज्य में विनिर्दिष्ट बांध के जलाशय को भरने की संभावित विवक्षा का निर्धारण करना और ऐसे प्रतिस्रोत राज्यों के साथ न्यूनीकरण उपायों के संबंध में समन्वय करना ;
9. किसी अनुस्रोत राज्य के संबंध में राज्य में विनिर्दिष्ट बांध की विफलता की संभावित विवक्षा का निर्धारण करना और ऐसे अनुस्रोत राज्यों के साथ न्यूनीकरण उपायों के संबंध में समन्वय करना ;
10. जल प्रपातीय बांध विफलता की संभावना का निर्धारण करना और सीमावर्ती राज्यों सहित सभी संबद्ध व्यक्तियों के साथ न्यूनीकरण उपायों के संबंध में समन्वय करना ;
11. राज्य में पुराने हो रहे बांधों के योजनाबद्ध और उपयुक्त रूप से चरणबद्ध पुनर्वास के प्रयोजन के लिए निधियों के उपबंध की सिफारिश करना ;
12. ऐसे बांध सुधार तथा पुनर्वास कार्यक्रमों के लिए, जिन्हें राज्य वित्त पोषण के माध्यम से निष्पादित किया जाता है, रणनीतिक पर्यवेक्षण का उपबंध करना ;
13. बांधों की सुरक्षा से संबंधित ऐसा कोई अन्य विनिर्दिष्ट विषय, जो उसे राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाए ।

चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत और संकर्म लेखापाल और कंपनी सचिव (संशोधन) अधिनियम, 2022

(2022 का अधिनियम संख्यांक 12)

[18 अप्रैल, 2022]

चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949, लागत और
संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 और
कंपनी सचिव अधिनियम, 1980
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत और संकर्म
लेखापाल और कंपनी सचिव (संशोधन) अधिनियम, 2022 है ।

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना
द्वारा, नियत करे, और इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें
नियत की जा सकेंगी तथा किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति निर्देश का

यह अर्थ लगाया जाएगा कि यह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है ।

अध्याय 2

चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 का संशोधन

वृहत् नाम और
उद्देशिका का
संशोधन ।

2. चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) के दीर्घ शीर्षक और उद्देशिका में, “विनियम” शब्द के स्थान पर, “विनियम और विकास” शब्द रखे जाएंगे ।

1949 का 38

धारा 2 का
संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) में,—

(i) खंड (कक) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘(कख) “अनुशासन बोर्ड” से धारा 21क की उपधारा (1) के अधीन गठित अनुशासन बोर्ड अभिप्रेत है ;’;

(ii) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

‘(खक) “समन्वय समिति” से धारा 9क के अधीन गठित समन्वय समिति अभिप्रेत है ;

(खख) “कंपनी अधिनियम” से कंपनी अधिनियम, 2013 या उक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (67) में यथापरिभाषित कोई अन्य पूर्व कंपनी विधि अभिप्रेत है ;’;

2013 का 18

(iii) खंड (ग) में “संस्थान की परिषद्” शब्दों से पूर्व, “धारा 9 के अधीन गठित” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(iv) खंड (गक) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

‘(गख) “निदेशक (अनुशासन)” से धारा 21 में निर्दिष्ट निदेशक (अनुशासन) अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत संयुक्त निदेशक (अनुशासन) सम्मिलित है ;

(गग) “अनुशासन समिति” से धारा 21ख की उपधारा (1) के अधीन गठित अनुशासन समिति अभिप्रेत है ;

(गघ) “अनुशासन निदेशालय” से धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अनुशासन निदेशालय अभिप्रेत है ;

(गङ) “अध्येता” से संस्थान का अध्यक्ष सदस्य अभिप्रेत है ;’;

(v) खंड (डक) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

‘(डक) “अधिसूचना” से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और “अधिसूचित” पद का तदनुसार अर्थान्वयन किया जाएगा ;’;

(vi) खंड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

‘(छ) “रजिस्टर” से, यथास्थिति, धारा 19 के अधीन रखा गया संस्थान के सदस्यों का रजिस्टर या धारा 20ख के अधीन रखा गया संस्थान की फर्मों

का रजिस्टर अभिप्रेत है ;;

(vii) खंड (जकक) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘(जककक) “स्थायी समिति” से धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन गठित स्थायी समिति अभिप्रेत है ;’।

4. मूल अधिनियम की धारा 4 में,—

धारा 4 का संशोधन ।

(i) “रजिस्टर” शब्द के स्थान पर, जहां-कहीं भी वह आता है, “सदस्यों का रजिस्टर” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (1) में खंड (v) और खंड (vi) में हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है ;

(iii) उपधारा (3) में,—

(क) “जो तीन हजार रुपए से अधिक की नहीं होगी” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) परंतुक का लोप किया जाएगा ।

5. मूल अधिनियम की धारा 5 में,—

धारा 5 का संशोधन ।

(i) दोनों स्थानों पर आने वाले “रजिस्टर” शब्द के स्थान पर, “सदस्यों का रजिस्टर” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (3) में,—

(क) “जो पांच हजार रुपए से अधिक की नहीं होगी” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) परंतुक का लोप किया जाएगा ।

6. मूल अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

धारा 6 का संशोधन ।

“(2) प्रत्येक सदस्य प्रमाणपत्र के लिए वार्षिक फीस जो परिषद् द्वारा अधिसूचना द्वारा अवधारित की जाए, का संदाय करेगा और ऐसी फीस प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को या उससे पूर्व संदेय होगी ।”।

7. मूल अधिनियम की धारा 8 में,—

धारा 8 का संशोधन ।

(i) “रजिस्टर” शब्द के स्थान पर, जहां-कहीं वह आता है, “सदस्यों का रजिस्टर” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (iii) में “अनुन्मुक्त दिवालिया” शब्दों के पश्चात्, “या कोई अनुन्मुक्त शोधन अक्षम” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(iii) खंड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(iii)क) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन शोधन अक्षम घोषित किया गया है ; या” ;

(iv) खंड (v) में,—

(क) हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है ;

(ख) “निर्वासन, या” शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 9 का
संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 9 में,—

(i) उपधारा (2) में,—

(क) दोनों स्थानों पर आने वाले “रजिस्टर” शब्द के स्थान पर, “सदस्यों का रजिस्टर” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) “तीन वर्ष” शब्दों के स्थान पर, “चार वर्ष” शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) “छह वर्ष” शब्दों के स्थान पर, “आठ वर्ष” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (4) में,—

(क) “व्यक्ति” शब्द के स्थान पर, “संस्थान का सदस्य या फर्म का कोई भागीदार” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) “तीन वर्ष” शब्दों के स्थान पर, “चार वर्ष” शब्द रखे जाएंगे ।

नई धारा 9क का
अंतःस्थापन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 9 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

समन्वय
समिति ।

“9क. (1) चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत और संकर्म लेखापाल तथा कंपनी सचिव की वृत्तियों के विकास और सुमेलन के लिए एक समन्वय समिति होगी, जो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान, भारतीय लागत और संकर्म लेखापाल संस्थान तथा भारतीय कंपनी सचिव संस्थान, हर एक संस्थान में से परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव से मिलकर बनेगी ।

(2) समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा की जाएगी ।

(3) समन्वय समिति की बैठक वर्ष की प्रत्येक तिमाही में एक बार की जाएगी ।

(4) समिति, प्रत्येक संस्थान को सौंपे गए कृत्यों के प्रभावी समन्वय के लिए उत्तरदायी होगी और,—

(i) संस्थान की विद्या, अवसंरचना, अनुसंधान और उसके सभी संबंधित कार्यों में क्वालिटी सुधार को सुनिश्चित करेगी ;

(ii) वृत्ति को अधिक प्रभावी और सुदृढ़ बनाने के लिए वृत्तियों के बीच समन्वय और सहयोग पर ध्यान केन्द्रित करेगी ;

(iii) अंतःवृत्तिक विकास के लिए अन्तर अनुशासनिक विनियामक तंत्रों को समरूप करेगी ;

(iv) वृत्तियों के लिए विनियामक नीतियों से संबंधित विषयों पर सिफारिशें करेगी ;

(v) पूर्वोक्त खंडों (i) से खंड (iv) तक के आनुषंगिक ऐसे अन्य कृत्य करेगी ।”।

धारा 10 का
संशोधन ।

10. मूल अधिनियम की धारा 10 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और,—

(i) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) के पहले परंतुक में “तीन से अधिक आनुक्रमिक अवधियों” शब्दों के स्थान पर, “दो आनुक्रमिक अवधियों” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित और संशोधित उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, परिषद् का कोई सदस्य, जिसने चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत और संकर्म लेखापाल तथा कंपनी सचिव (संशोधन) अधिनियम, 2022 के ठीक प्रारंभ होने पर ऐसे सदस्य के रूप में दो पदावधियों के लिए पद धारण किया है या तीन वर्ष की दूसरी पदावधि के लिए पदधारण कर रहा है, चार वर्ष की एक और अवधि के लिए लड़ने के लिए पात्र होगा तथा कोई सदस्य, जिसने एक पदावधि के लिए पद धारण किया है या तीन वर्ष की पहली पदावधि के लिए पद धारण कर रहा है, दो और आनुक्रमिक अवधियों के लिए लड़ने हेतु पात्र होगा ।”।

11. मूल अधिनियम की धारा 12 में,—

धारा 12 का
संशोधन ।

(i) उपधारा (1) में परंतुक का लोप किया जाएगा ;

(ii) उपधारा (2) में, “मुख्य कार्यपालक प्राधिकारी” शब्दों के स्थान पर, “प्रधान” शब्द रखा जाएगा ;

(iii) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“(2क) अध्यक्ष, परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करेगा ।

(2ख) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ऐसे कर्तव्यों और कृत्यों का पालन करेंगे, जो विहित किए जाएं ।

(2ग) परिषद् द्वारा किए गए विनिश्चयों को कार्यान्वित करने का सुनिश्चय करना अध्यक्ष का कर्तव्य होगा ।

(2घ) यदि, किसी भी कारण से अध्यक्ष का पद रिक्त होता है या यदि अध्यक्ष अनुपस्थित है या किसी अन्य कारण से शक्तियों का प्रयोग करने में या उसे सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, तो उपाध्यक्ष उसके स्थान पर कार्य करेगा और अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा उसके कर्तव्यों का पालन करेगा ।”।

12. मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) में, “रजिस्टर” शब्द के स्थान पर, “सदस्यों का रजिस्टर” शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 13 का
संशोधन ।

13. मूल अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) में, “तीन वर्ष” शब्दों के स्थान पर, “चार वर्ष” शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 14 का
संशोधन ।

14. मूल अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) में,—

धारा 15 का
संशोधन ।

(i) खंड (ख) और खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“(ख) अभ्यावेशन हेतु अभ्यर्थियों की परीक्षा के लिए फीस विहित करना ;

(ग) किसी फर्म को रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करना या इंकार करना ;”;

(ii) खंड (घ) में, “रजिस्टर” शब्द के स्थान पर, “सदस्यों का रजिस्टर” शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) खंड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“(च) इस अधिनियम के अधीन व्यवसाय का प्रमाणपत्र अनुदत्त करने या उससे इंकार करने के लिए दिशा-निर्देश विहित करना ;

(चक) इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के प्रयोजन के लिए दिशा-निर्देश जारी करना ;”;

(iv) खंड (छ) का लोप किया जाएगा ;

(v) खंड (ज) में, “और संग्रहण” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(vi) खंड (झ) का लोप किया जाएगा ;

(vii) खंड (ठ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“(ठ) विनिधानकर्ता शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम संचालित करना ;

(ठक) इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का निष्पादन करने के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से किसी अभिकरण या दूसरे देश के साथ कोई ज्ञापन या ठहराव करना ;”।

नई धारा 15ख
का अंतःस्थापन ।

15. मूल अधिनियम की धारा 15क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

संस्थान के
कृत्य ।

“15ख. संस्थान के कृत्यों में, निम्नलिखित सम्मिलित होंगे,—

(क) अभ्यावेशन के लिए अभ्यर्थियों की परीक्षा ;

(ख) आबद्ध सहायक और संपरीक्षा सहायकों के विनियोजन और प्रशिक्षण के लिए विनियमन करना ;

(ग) चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में व्यवसाय करने के लिए अर्हित व्यक्तियों का रजिस्टर रखा जाना और उसका प्रकाशन करना ;

(घ) फर्मों के रजिस्टर का अनुरक्षण करना और उसका प्रकाशन करना ;

(ङ) सदस्यों, परीक्षार्थियों और अन्य व्यक्तियों से फीस का संग्रहण करना ;

(च) इस अधिनियम के अधीन समुचित प्राधिकारियों के आदेशों के अधीन रहते हुए, सदस्यों और फर्मों के रजिस्टर से नामों को हटाना तथा सदस्यों और फर्मों के रजिस्टर में ऐसे नामों को पुनःदर्ज करना, जिनको काट दिया गया है ;

(छ) किसी पुस्तकालय का अनुरक्षण और लेखाकर्म से तथा सहबद्ध विषयों से संबंधित पुस्तकों और नियतकालिक पत्रिकाओं का प्रकाशन ;

(ज) संस्थान की परिषद् के निर्वाचनों का संचालन ; और

(झ) परिषद् द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार व्यवसाय प्रमाणपत्र अनुदत्त करना या इंकार करना ।”।

16. मूल अधिनियम की धारा 16 में,—

धारा 16 का संशोधन ।

(i) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(1) परिषद् अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिए—

(क) एक सचिव की नियुक्ति करेगी, जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में संस्थान के प्रशासनिक कृत्य भी करेगा ;

(ख) निदेशक (अनुशासन) और संयुक्त निदेशक (अनुशासन) जो संस्थान के उप सचिव की पंक्ति से अन्यून पंक्ति का न हो की नियुक्ति ऐसे कृत्यों का निष्पादन करने के लिए करेगी, जो उन्हें इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन समुद्देशित किए जाएं :

परंतु किसी निदेशक (अनुशासन) या संयुक्त निदेशक (अनुशासन) की कोई नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति या नियुक्ति की समाप्ति तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक ऐसी नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति या नियुक्ति की समाप्ति को केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से न किया जाए ।”;

(ii) उपधारा (2) के खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(ग) सचिव और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति, शक्तियों, कर्तव्यों और कृत्यों, उनके वेतन, फीस, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तों को विहित करना ;”।

17. मूल अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

धारा 18 का संशोधन ।

“(5) परिषद् के वार्षिक लेखे ऐसी रीति में तैयार किए जाएंगे, जो विहित की जाए और वह परिषद् द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा रखे गए लेखापरीक्षकों के पैनल से नियुक्त की जाने वाली चार्टर्ड अकाउन्टेंटों की फर्म द्वारा वार्षिक रूप से की जाने वाली लेखापरीक्षा के अधीन होंगे :

परंतु कोई फर्म इस उपधारा के अधीन लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र नहीं होगी यदि उसका कोई भागीदार परिषद् का सदस्य है या पिछले चार वर्ष के दौरान सदस्य रहा है :

परंतु यह और कि परिषद् की जानकारी में यह लाए जाने पर कि परिषद् के लेखे उसके वित्त का सही और उचित दृश्य प्रस्तुत नहीं करते हैं तब परिषद् स्वयं एक विशेष लेखापरीक्षा का संचालन कर सकेगी :

परंतु यह भी कि केन्द्रीय सरकार द्वारा परिषद् को ऐसी सूचना भेजी जाती है कि परिषद् के लेखें उसके वित्त का सही और उचित दृश्य उत्पन्न नहीं करते हैं, तो जहां समुचित हो, परिषद् एक विशेष लेखा परीक्षा करवाएगी या ऐसी अन्य कार्रवाई करेगी, जो वह आवश्यक समझे और उस पर की गई कार्रवाई की एक रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगी।”।

धारा 19 का
संशोधन।

18. मूल अधिनियम की धारा 19 में,—

(i) “रजिस्टर” शब्द के स्थान पर, जहां-कहीं वह आता है, “सदस्यों का रजिस्टर” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(1) परिषद् संस्थान के सदस्यों का एक रजिस्टर ऐसी रीति में रखेगी, जो विहित की जाए।”;

(iii) उपधारा (2) में, खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(गक) अध्याय 5 के अधीन उसके विरुद्ध क्या कोई अनुयोज्य सूचना या शिकायत लंबित है या कोई शास्ति अधिरोपित की गई है, जिसके अंतर्गत उसके ब्यौरे भी हैं, यदि कोई हों ;”;

(iv) उपधारा (4) में,—

(क) “जो पांच हजार रुपए से अधिक नहीं होगी” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) परंतुक का लोप किया जाएगा।”।

धारा 20 का
संशोधन।

19. मूल अधिनियम की धारा 20 में,—

(i) “रजिस्टर” शब्द, जहां-कहीं वह आता है, के स्थान पर, “सदस्यों का रजिस्टर” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (3) में,—

(क) “जो दो हजार रुपए से अधिक नहीं होगी” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) परंतुक का लोप किया जाएगा।

नए अध्याय 4क
का अंतःस्थापन।

20. मूल अधिनियम के अध्याय 4 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“अध्याय 4क

फर्मों का रजिस्ट्रीकरण और रजिस्टर

फर्मों का
रजिस्ट्रीकरण।

20क. किसी फर्म के किसी भागीदार या स्वामी द्वारा परिषद् को उसके नाम के अनुमोदन तथा रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने के लिए किए गए आवेदन पर प्रत्येक फर्म को संस्थान के पास ऐसी रीति में और ऐसे निबंधन और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, रजिस्टर किया जाएगा :

परंतु परिषद् किसी फर्म को रजिस्टर करने से इंकार कर सकेगी यदि ऐसी फर्म का नाम पहले से ही रजिस्ट्रीकृत किसी फर्म या भारत में या भारत से बाहर किसी फर्म द्वारा उपयोग किए गए नाम से मिलता-जुलता है या उसके समान है या परिषद् की राय में फर्म का रजिस्ट्रीकरण अवांछनीय है ।

फर्मों का
रजिस्टर ।

20ख. (1) परिषद्, फर्मों का एक रजिस्टर, ऐसी रीति में रखेगी, जो विहित की जाए ।

(2) फर्मों के रजिस्टर में, फर्म के संबंध में, ऐसी विशिष्टियां सम्मिलित होंगी, जिनके अंतर्गत ऐसे प्ररूप और ऐसे अंतरालों पर, जो विहित किया जाए, अध्याय 5 के अधीन उसके विरुद्ध किसी अनुयोज्य सूचना या शिकायत या उस पर अधिरोपित किसी शास्ति के ब्यौरे हैं ।

(3) परिषद्, प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को या ऐसे अंतराल पर, जिसका परिषद् द्वारा विनिश्चय किया जाए, संस्थान के साथ रजिस्ट्रीकृत फर्मों की सूची ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रकाशित करवाएगी और ऐसे व्यक्तियों की सूची को ऐसे प्ररूप में और ऐसी रकम का संदाय करने पर, जो विहित की जाए, उपलब्ध कराएगी ।

20ग. परिषद् फर्मों के रजिस्टर से किसी फर्म के नाम को हटाएगी,—

फर्मों के रजिस्टर
से हटाया जाना ।

(क) जिसका विघटन या परिसमापन हो गया है ; या

(ख) जिससे इस निमित्त कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ; या

(ग) जिसे दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के उपबंधों के अधीन दिवाला या शोधन अक्षम घोषित किया गया है और जो अनुन्मोचित रहती है ; या

(घ) जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंट की वृत्ति से संबंधित किसी कार्यकलाप या कार्यकलापों को करने से विवर्जित किया गया है ; या

(ङ) जिसके संबंध में, हटाए जाने के लिए इस अधिनियम के अधीन कोई आदेश पारित किया गया है ।

20घ. (1) रजिस्ट्रीकरण से इंकार करने के किसी विनिश्चय से व्यथित कोई फर्म परिषद् के समक्ष पुनर्विलोकन करने के लिए ऐसे इंकार की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर आवेदन कर सकेगी ।

परिषद् के समक्ष
पुनर्विलोकन ।

(2) परिषद्, पुनर्विलोकन आवेदन पर विचार करने के पश्चात् इस प्रकार किए गए विनिश्चय की पुष्टि कर सकेगी या उसे अपास्त कर सकेगी या ऐसा आदेश पारित कर सकेगी, जो वह समुचित समझे ।”।

21. मूल अधिनियम की धारा 21 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

धारा 21 का
प्रतिस्थापन ।

“21. (1) परिषद्, ऐसे प्ररूप में ऐसी फीस के साथ जो विनिर्दिष्ट की जाए, जांच करने के लिए या तो स्व:प्रेरणा से या किसी सूचना या किसी शिकायत की प्राप्ति पर जांच करने के लिए अधिसूचना द्वारा एक अनुशासनिक निदेशालय की

अनुशासनिक
निदेशालय ।

स्थापना करेगी, जो संस्थान के निदेशक (अनुशासन), उप सचिव के रैंक से अन्यून कम से कम दो संयुक्त निदेशक (अनुशासन) और धारा 16 के अधीन नियुक्त अन्य कर्मचारियों से मिलकर बनेगा ।

(2) किसी सूचना या शिकायत की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर, निदेशक (अनुशासन) ऐसी रीति में जो विनिर्दिष्ट की जाए, विनिश्चय करेगा कि क्या शिकायत या सूचना कार्रवाई किए जाने योग्य है या कार्रवाई नहीं किए जा सकने के लिए बन्द की जा सकती है :

परंतु निदेशक (अनुशासन) यह विनिश्चय करने से पूर्व पन्द्रह दिन का समय से कि क्या कोई मामला कार्रवाई किए जाने योग्य है या कार्रवाई किए जाने योग्य नहीं है, यथास्थिति, शिकायतकर्ता या इतिला देने वाले से अतिरिक्त सूचना की मांग कर सकेगा :

परंतु यह और कि निदेशक (अनुशासन) कार्रवाई न किए जाने योग्य शिकायतों या सूचना की सिफारिश को अनुशासन बोर्ड को उनकी प्राप्ति के साठ दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा तथा अनुशासन बोर्ड गुणागुण पर विचार करने के पश्चात् ऐसी किसी शिकायत या सूचना को आगे अन्वेषण करने हेतु निदेशक (अनुशासन) को निर्दिष्ट कर सकेगा ।

(3) मामले का अन्वेषण करते समय जिसे कार्रवाई करने योग्य पाया जाता है, निदेशक (अनुशासन), यथास्थिति, सदस्य या फर्म को, इक्कीस दिन के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करने का अवसर देगा, जिसका कारणों को लेखबद्ध करते हुए इक्कीस दिन के लिए और विस्तार किया जा सकेगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन लिखित कथन, यदि कोई हो, की प्राप्ति पर निदेशक (अनुशासन), उसकी एक प्रति शिकायतकर्ता या इतिला देने वाले को भेजेगा और शिकायतकर्ता और इतिला देने वाले को ऐसा लिखित कथन प्राप्त होने के इक्कीस दिन के भीतर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करेगा ।

(5) उपधारा (3) के अधीन लिखित कथन और उपधारा (4) के अधीन प्रत्युत्तर की प्राप्ति पर, निदेशक (अनुशासन) यदि प्रथमदृष्टया, यथास्थिति, सदस्य या फर्म के विरुद्ध कोई मामला बनता है तो तीस दिन के भीतर प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

(6) पहली अनुसूची में अधिकथित किसी वृत्तिक या अन्य अवचार का यदि प्रथमदृष्टया मामला बनता है तो निदेशक (अनुशासन), निदेशक बोर्ड को एक प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा तथा जहां दूसरी अनुसूची में या पहली और दूसरी अनुसूची, दोनों में, अधिकथित वृत्तिक या अन्य अवचार का प्रथमदृष्टया मामला बनता है तो वह प्रारंभिक जांच रिपोर्ट अनुशासनिक समिति को प्रस्तुत करेगा :

परंतु केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी कानूनी प्राधिकरण के किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा फाइल की गई किसी शिकायत या सूचना को, जो जांच रिपोर्ट या समर्थनकारी साक्ष्य के साथ जांच रिपोर्ट के सुसंगत सार द्वारा सम्यक् रूप से समर्थित है, को प्रारंभिक जांच रिपोर्ट माना जाएगा :

परंतु यह और कि जहां प्रथमदृष्ट्या, यथास्थिति, सदस्य या फर्म के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनता है तो निदेशक (अनुशासन) सुसंगत दस्तावेजों के साथ ऐसी सूचना या शिकायत को अनुशासन बोर्ड को भेजेगा और अनुशासन बोर्ड, यदि निदेशक (अनुशासन) के निष्कर्षों से सहमत होता है तो मामले को समाप्त कर देगा या असहमति की दशा में, स्वयं अग्रसर हो सकेगा या अनुशासनिक समिति को निर्दिष्ट कर सकेगा या निदेशक (अनुशासन) को मामले की और जांच करने के लिए परामर्श देगा ।

(7) इस अधिनियम के अधीन जांच के प्रयोजनों के लिए अनुशासनिक निदेशालय ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जो विनिर्दिष्ट की जाए ।

(8) अनुशासनिक निदेशालय के पास फाइल की गई शिकायत को किसी भी स्थिति में वापस नहीं लिया जाएगा ।

(9) अनुशासन निदेशालय, अनुशासन बोर्ड और अनुशासनिक समिति के समक्ष लंबित कार्यवाई की जा सकने वाली सूचना और शिकायतें तथा धारा 21क के अधीन अनुशासन बोर्ड द्वारा और धारा 21ख के अधीन अनुशासनिक समिति द्वारा पारित आदेशों को अनुशासन निदेशालय द्वारा पब्लिक डोमेन में ऐसी रीति में उपलब्ध कराया जाएगा, जो विहित की जाए ।”।

22. मूल अधिनियम की धारा 21क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी,
अर्थात् :—

धारा 21क का
प्रतिस्थापन ।

“21क. (1) परिषद्, अधिसूचना द्वारा एक या अधिक अनुशासन बोर्डों का गठन करेगी, प्रत्येक बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा,—

अनुशासन बोर्ड ।

(क) विधि का अनुभव और अनुशासनिक विषयों तथा व्यवसाय की जानकारी रखने वाला एक व्यक्ति जो संस्थान का सदस्य न हों, जिसको परिषद् द्वारा तैयार किए गए और उपलब्ध कराए गए पैनल में से पीठासीन अधिकारी के रूप में ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ;

(ख) एक सदस्य, जो विधि, अर्थशास्त्र, कारबार, वित्त या लेखांकन के क्षेत्र में अनुभव रखने वाला विख्यात व्यक्ति है और जो संस्थान का सदस्य न हों, जिसको परिषद् द्वारा तैयार किए गए और उपलब्ध कराए गए पैनल में से पीठासीन अधिकारी के रूप में, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ;

(ग) एक सदस्य, जिसको परिषद् द्वारा तैयार किए गए संस्थान के सदस्यों के पैनल में से, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ;

(घ) उप सचिव की पंक्ति से अन्यून पंक्ति का संस्थान का कोई अधिकारी अनुशासन बोर्ड के सचिव के रूप में कार्य करेगा :

परंतु खंड (क) के अधीन नामनिर्दिष्ट पीठासीन अधिकारी और खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य इस उपधारा के अधीन गठित भिन्न-भिन्न अनुशासन बोर्डों के लिए वही रहेंगे ।

(2) अनुशासन बोर्ड, उसके समक्ष रखे गए मामलों पर विचार करते समय ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जिसके अंतर्गत फेसलेस कार्यवाहियां और आभासी सुनवाईयां जो विनिर्दिष्ट की जाएं, भी हैं।

(3) अनुशासन बोर्ड, निदेशक (अनुशासन) से प्रारंभिक जांच रिपोर्ट की प्राप्ति पर, यथास्थिति, सदस्य या फर्म जिसके विरुद्ध ऐसी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट फाइल की गई है से इक्कीस दिन, जिसका आपवादिक परिस्थितियों में कारणों को लेखबद्ध करते हुए, इक्कीस दिन की और अवधि तक विस्तार किया जा सकेगा, के भीतर एक लिखित विवरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा।

(4) अनुशासन बोर्ड, निदेशक (अनुशासन) से प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के नब्बे दिन के भीतर, अपनी जांच पूरी करेगा।

(5) जांच करने पर, यदि अनुशासन बोर्ड यह पाता है कि ऐसा सदस्य पहली अनुसूची में वर्णित वृत्तिक या अन्य अवचार का दोषी है, तो वह सदस्य को ऐसे निष्कर्ष के तीस दिन के भीतर सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् निम्नलिखित कार्यवाइयों में से कोई एक या अधिक कार्यवाई करने का आदेश पारित कर सकेगा, अर्थात् :—

(क) सदस्यों को धिग्दंडित करने और सदस्यों के रजिस्टर में इसे अभिलिखित करने ;

(ख) सदस्य के नाम को सदस्यों के रजिस्टर में से छह मास की कालावधि तक के लिए हटाने ;

(ग) ऐसा जुर्माना अधिरोपित करने, जो वह ठीक समझे, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा।

(6) जहां, किसी सदस्य के संबंध में या किसी अभिलेख पर रखे गए साक्ष्य के आधार पर, अनुशासन बोर्ड की यह राय है कि ऐसा कोई सदस्य जो किसी फर्म का भागीदार या स्वामी है, पहली अनुसूची में उल्लिखित अवचार का पिछले पांच वर्ष के दौरान बार-बार दोषी पाया गया है, तो ऐसी फर्म के विरुद्ध निम्नलिखित कार्यवाई की जा सकेगी, अर्थात् :—

(क) फर्म को व्यवसायरत चार्टर्ड एकाउंटेंट की वृत्ति से संबंधित कोई कार्यकलाप या कार्यकलापों को करने से एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए प्रतिषिद्ध कर सकेगा ; या

(ख) ऐसा जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे, जो पच्चीस लाख रुपए तक का हो सकेगा।

(7) जब कोई सदस्य या फर्म, उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन अधिरोपित जुर्माने का विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संदाय करने में असफल रहता है तो परिषद् ऐसे सदस्य या फर्म का नाम, यथास्थिति, सदस्यों के रजिस्टर या फर्म के रजिस्टर से ऐसी अवधि के लिए, जो वह ठीक समझे, हटा देगी।

(8) अनुशासन बोर्ड के पीठासीन अधिकारी और सदस्यों को ऐसे भत्तों का संदाय किया जाएगा, जो विहित किए जाएं।”।

प्रतिस्थापन ।

अनुशासन
समिति ।

अर्थात् :—

“21ख. (1) परिषद्, अधिसूचना द्वारा एक या अधिक अनुशासनिक समितियों का गठन करेगी, जिसमें निम्नलिखित प्रत्येक में होंगे—

(क) कोई ऐसा व्यक्ति जो संस्थान का सदस्य न हो और जिसके पास विधि का अनुभव और अनुशासनिक मामलों तथा वृत्ति का ज्ञान हो, केन्द्रीय सरकार द्वारा पीठासीन अधिकारी के रूप में परिषद् द्वारा, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, तैयार किए गए और उपलब्ध कराए गए व्यक्तियों के पैनल में से नामनिर्दिष्ट किया जाए ;

(ख) ऐसे दो सदस्य जो संस्थान के सदस्य न हो और जो विधि, अर्थशास्त्र, कारबार, वित्त या लेखांकन के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले प्रख्यात व्यक्ति हों, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा, परिषद् द्वारा ऐसी रीति में जो विहित की जाए, तैयार किए गए और उपलब्ध कराए गए व्यक्तियों के पैनल में से नामनिर्दिष्ट किया जाए ;

(ग) ऐसे दो सदस्य जो परिषद् द्वारा ऐसी रीति में जो विहित की जाए, तैयार किए जाने वाले संस्थान के सदस्यों के पैनल में से नामनिर्दिष्ट किए जाएं :

परंतु खंड (क) के अधीन नामनिर्दिष्ट पीठासीन अधिकारी और खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य, इस धारा के अधीन गठित भिन्न-भिन्न अनुशासनिक समितियों के लिए वही हो सकेंगे ।

(2) अनुशासनिक समिति, उसके समक्ष रखे गए मामलों पर विचार करते समय, ऐसी प्रक्रिया जो विनिर्दिष्ट की जाएं का अनुसरण करेगी जिसके अंतर्गत फेसलेस कार्यवाहियां और वर्चुअल सुनवाईयां भी हैं ।

(3) अनुशासनिक समिति, निदेशक (अनुशासन) से प्रारंभिक परीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति पर, यथास्थिति, ऐसे सदस्य या फर्म, जिसके विरुद्ध ऐसी प्रारंभिक परीक्षा रिपोर्ट फाइल की गई है, 21 दिन के भीतर जिसे आपवादिक परिस्थितियों में, कारणों को लेखबद्ध करके अतिरिक्त 21 दिनों तक बढ़ाया जा सकेगा, लिखित कथन प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगी ।

(4) अनुशासन समिति, निदेशक (अनुशासन) से प्रारंभिक परीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति से एक सौ अस्सी दिनों के भीतर उसकी जांच पूरी करेगी ।

(5) जांच करने पर यदि अनुशासन समिति का यह निष्कर्ष है कि कोई सदस्य दूसरी अनुसूची में या पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची, दोनों में वर्णित वृत्तिक या अन्य अवचार का दोषी है, तो वह ऐसे निष्कर्ष से तीस दिन के भीतर, उस सदस्य को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, निम्नलिखित कोई एक या अधिक कार्रवाई करने का आदेश पारित कर सकेगी, अर्थात् :—

(क) सदस्य को धिगदंड देना और उसे सदस्यों के रजिस्टर में अभिलिखित करना ; या

(ख) सदस्य के नाम को स्थायी रूप से या ऐसी अवधि के लिए, जो वह ठीक समझे, सदस्यों के रजिस्टर से हटाना ; या

(ग) ऐसा जुर्माना अधिरोपित करना जो वह ठीक समझे, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा ।

(6) जहां किसी सदस्य से संबंधित जांच के क्रम के दौरान या अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य के आधार पर अनुशासन समिति की, यह राय है कि कोई ऐसा सदस्य, जो फर्म का भागीदार या स्वामी है, पिछले पांच वर्ष के दौरान दूसरी अनुसूची या पहली और दूसरी अनुसूची, दोनों में वर्णित अवचार का बार-बार दोषी पाया गया है, वहां फर्म के विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाई भी की जा सकेगी, अर्थात्:—

(क) फर्म को दो वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट व्यवसाय की वृत्ति से संबंधित किसी क्रियाकलाप या क्रियाकलापों को करने से प्रतिषिद्ध करना ; या

(ख) फर्म के रजिस्ट्रीकरण को निलंबित या रद्द करना और फर्म के रजिस्टर से उसका नाम स्थायी रूप से या ऐसी अवधि के लिए जो वह ठीक समझे, हटाना ; या

(ग) ऐसा जुर्माना अधिरोपित करना, जो वह ठीक समझे, जो पचास लाख रुपए तक का हो सकेगा ।

(7) जहां कोई सदस्य या फर्म विनिर्दिष्ट समय के भीतर, उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन अधिरोपित जुर्माने का संदाय करने में विफल रहता है वहां परिषद् ऐसे सदस्य या फर्म का नाम ऐसी अवधि के लिए, यथास्थिति, सदस्यों के रजिस्टर या फर्म के रजिस्टर से हटा देगी ।

(8) अनुशासनिक समिति के पीठासीन अधिकारी और सदस्यों को ऐसे भत्तों का संदाय किया जाएगा जो विहित किए जाएं ।”।

धारा 21ग का
संशोधन ।

24. मूल अधिनियम की धारा 21ग में स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा ।

धारा 21घ का
प्रतिस्थापन ।

25. मूल अधिनियम की धारा 21घ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

संक्रमणकालीन
उपबंध ।

“21घ. चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत और संकर्म लेखापाल तथा कंपनी सचिव (संशोधन) अधिनियम, 2022 के प्रारंभ से पूर्व, अनुशासन बोर्ड या अनुशासन समिति के समक्ष लंबित सभी शिकायतें या कोई जांच या अपील प्राधिकारी या उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल की गई कोई अपील या कोई निर्देश इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा शासित होना जारी रहेगा, मानो यह अधिनियम, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत और संकर्म लेखापाल तथा कंपनी सचिव (संशोधन) अधिनियम, 2022 द्वारा संशोधित नहीं किया गया हो ।”।

धारा 22 का
प्रतिस्थापन ।

26. मूल अधिनियम की धारा 22 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

परिभाषित वृत्तिक
और अन्य
अवचार।

‘22. इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, “वृत्तिक या अन्य अवचार” पद में संस्थान के किसी सदस्य की ओर से किसी अनुसूची में यथा उल्लिखित या तो उसकी व्यक्तिगत क्षमता या फर्म के भागीदार या स्वामी के रूप में कोई कार्य या लोप सम्मिलित समझा जाएगा, परन्तु इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन निदेशक (अनुशासन) को किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन ऐसे सदस्यों या फर्म के आचरण की जांच करने के लिए प्रदत्त शक्ति या निक्षेपित कर्तव्य किसी रूप में सीमित या न्यून करती हैं ।’।

धारा 22छ का
संशोधन ।

27. मूल अधिनियम की धारा 22छ में,—

(i) उपधारा (1) में,—

(क) “संस्थान का कोई सदस्य” शब्दों के पश्चात्, “या कोई फर्म” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) “उस पर अधिरोपित करने” शब्दों के स्थान पर, “ऐसे सदस्य या फर्म पर अधिरोपित करने” शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) “धारा 21क की उपधारा (3) और धारा 21ख की उपधारा (3)” शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर “धारा 21क की उपधारा (5) या उपधारा (6) या धारा 21ख की उपधारा (5) या उपधारा (6)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(घ) “उसे आदेश संसूचित किया जाता है” शब्दों के स्थान पर, “ऐसे सदस्य या फर्म को आदेश संसूचित किया जाता है” शब्द रखे जाएंगे ।

(ii) उपधारा (2) में, “धारा 21क की उपधारा (3) और धारा 21ख की उपधारा (3)” शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर “धारा 21क की उपधारा (5) या उपधारा (6) अथवा धारा 21ख की उपधारा (5) या उपधारा (6)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(iii) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा और स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

‘(3) प्राधिकरण के किसी आदेश या कार्य या कार्यवाही को प्राधिकरण के गठन में केवल किसी त्रुटि या आकस्मिक रिक्ति या एक अथवा दो सदस्यों की अनुपस्थिति के आधार पर, किसी भी रीति में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण 1—इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए,—

(अ) “संस्थान के सदस्य” में ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है जो अभिकथित अवचार की तारीख को संस्थान का सदस्य था, तथापि वह जांच के समय संस्थान का सदस्य नहीं रह गया हो ;

(आ) संस्थान के साथ रजिस्ट्रीकृत “फर्म” भी ऐसे सदस्य के अवचार के लिए दायी होगी जो अभिकथित अवचार की तारीख को उसका भागीदार या स्वामी था के तथापि जांच के समय वह ऐसा

भागीदार या स्वामी नहीं रह गया हो ।

स्पष्टीकरण 2—इस अध्याय के अधीन की गई कोई कार्रवाई, केन्द्रीय सरकार के विभाग या राज्य सरकार या किसी कानूनी प्राधिकारी या विनियामक निकाय द्वारा संस्थान के साथ रजिस्ट्रीकृत किसी सदस्य या फर्म के विरुद्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कार्रवाई करने का वर्जन नहीं करेगी ।।

28. मूल अधिनियम की धारा 24 में,—

धारा 24 का संशोधन ।

(क) “एक हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर, “एक लाख रुपए” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) “पांच हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर, “पांच लाख रुपए” शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 24क का संशोधन ।

29. मूल अधिनियम की धारा 24क की उपधारा (2) में,—

(i) “जुर्माने से, जो प्रथम दोषसिद्धि पर एक हजार रुपए तक का हो सकेगा” शब्दों के स्थान पर, “कारावास से, जो प्रथम दोषसिद्धि पर छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) “जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा” शब्दों के स्थान पर, “जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो दो लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु दस लाख रुपए तक का हो सकेगा” शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 25 का संशोधन ।

30. मूल अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (2) में,—

(क) “जुर्माने से, जो प्रथम दोषसिद्धि पर एक हजार रुपए तक का हो सकेगा” शब्दों के स्थान पर, “जुर्माने से, जो प्रथम दोषसिद्धि पर दो लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु दस लाख रुपए तक का हो सकेगा” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) “एक हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर, “दस लाख रुपए” शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) “पांच हजार रुपए तक हो सकेगा” शब्दों के स्थान पर, “जुर्माने से, जो चार लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु बीस लाख रुपए तक का हो सकेगा” शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 26 का संशोधन ।

31. मूल अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (2) में,—

(क) “पांच हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर, “एक लाख रुपए” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) “एक लाख रुपए” शब्दों के स्थान पर, “पांच लाख रुपए” शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) “दस हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर, “दो लाख रुपए” शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) जो “दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा” शब्दों के स्थान पर, “जो दो लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा” शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 28ख का संशोधन ।

32. मूल अधिनियम की धारा 28ख के खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(घ) संस्थान या फर्मों के सदस्यों द्वारा विभिन्न कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं के अननुपालन के मामलों को, जो उसके द्वारा उनके पुनर्विलोकन के दौरान ध्यान में आए हों, अनुशासन निदेशालय को उनकी परीक्षा के लिए अग्रेषित करना ।”।

33. मूल अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) में, “रजिस्टर” शब्दों के स्थान पर, “सदस्यों के रजिस्टर” शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 29 का संशोधन ।

34. मूल अधिनियम की धारा 29क की उपधारा (2) में,—

धारा 29क का संशोधन ।

(i) खंड (ग) और खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“(ग) धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन कोई सूचना या शिकायत फाइल करने के लिए प्ररूप और फीस, किसी शिकायत या सूचना का या गैर-अनुयोज्य रूप में होने संबंधी उपधारा (2) के अधीन अनुयोज्य विनिश्चय करने की रीति और उपधारा (7) के अधीन अन्वेषण की प्रक्रिया ;

(घ) धारा 21क की उपधारा (2) के अधीन अनुशासन बोर्ड द्वारा मामलों पर विचार करते समय प्रक्रिया और उपधारा (7) के अधीन जुर्माने के संदाय के लिए समय—सीमा ;

(घक) धारा 21ख की उपधारा (2) के अधीन अनुशासन समिति द्वारा मामलों पर विचार करते समय प्रक्रिया और उपधारा (7) के अधीन जुर्माने के संदाय के लिए समय—सीमा ;”।

35. मूल अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (2) में,—

धारा 30 का संशोधन ।

(i) खंड (ख), खंड (ड) और खंड (ज) में, “रजिस्टर” शब्दों के स्थान पर, जहां वह आता है, “सदस्यों का रजिस्टर” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (छ) और खंड (झ) का लोप किया जाएगा ;

(iii) खंड (द) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“(द) धारा 5 की उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित अर्हता ;

(दक) ऐसी परिस्थितियां जिनके अधीन धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन व्यवसाय प्रमाणपत्र रद्द किए जा सकेंगे ;

(दख) धारा 15 की उपधारा (2) के खंड (च) के अधीन व्यवसाय

प्रमाणपत्र प्रदान करने या खारिज करने के मार्गदर्शक सिद्धांत;

(दग) धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन परिषद् के सचिव और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति, शक्तियां, कर्तव्य, कृत्य, वेतन, फीस, भत्ते और सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें;

(दघ) धारा 18 की उपधारा (4) के अधीन वार्षिक वित्तीय विवरण और उपधारा (5) के अधीन वार्षिक लेखे तैयार करने की रीति;

(दड़) धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन संस्थान के सदस्यों के रजिस्टर को बनाए रखने की रीति और वह रीति जिसमें संस्थान के साथ रजिस्ट्रीकृत सदस्यों की वार्षिक सूची, उपधारा (3) के अधीन प्रकाशित की जाएगी;

(दच) धारा 20क के अधीन किसी फर्म का रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए आवेदन करने की रीति और ऐसे रजिस्ट्रीकरण के निबंधन और शर्तें ;

(दछ) धारा 20ख के अधीन फर्मों के रजिस्टर और अन्य विशिष्टियों के अनुरक्षण की रीति, जिसके अंतर्गत उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन किसी फर्म के विरुद्ध किसी अनुयोज्य सूचना या लंबित शिकायत अथवा अधिरोपित शास्ति के ब्यौरे भी हैं और वह रीति जिसमें संस्थान के साथ रजिस्ट्रीकृत फर्म की वार्षिक सूची, उपधारा (3) के अधीन प्रकाशित की जाएगी ;

(दज) धारा 21 की उपधारा (9) के अधीन अनुयोज्य सूचना और शिकायतों तथा पारित आदेशों की प्रास्थिति उपलब्ध कराने की रीति;

(दझ) धारा 21क की उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन व्यक्तियों के पैनल तैयार करने की रीति और उपधारा (8) के अधीन अनुशासन बोर्ड के पीठासीन अधिकारियों और सदस्यों को संदेय भत्ते;

(दञ) धारा 21ख की उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन व्यक्तियों के पैनल तैयार करने की रीति और उपधारा (8) के अधीन अनुशासन समिति के पीठासीन अधिकारियों और सदस्यों को संदेय भत्ते ;

(दट) धारा 22ड की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृन्द के वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की शर्तें ;

(दठ) वह रीति जिसमें क्षेत्रीय परिषद् धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन गठित की जा सकेगी और उसके कृत्य ; और ।”।

पहली अनुसूची
का संशोधन ।

36. मूल अधिनियम की पहली अनुसूची में,—

(i) शीर्षक में, “धारा 21(3), धारा 21क(3)” शब्दों, अंकों, अक्षर और कोष्ठकों के स्थान पर “धारा 21(6), धारा 21क(5) और (6), धारा 21ख(5) और (6)” शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ii) भाग 1 की मद (9) में “कंपनी अधिनियम, 1956” शब्दों और अंकों के पश्चात् “या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 और धारा 141 अथवा लेखा परीक्षकों की नियुक्ति से संबंधित तत्समय प्रवृत्त कोई अन्य विधि” शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

1956 का 1

2013 का 18

दूसरी अनुसूची
का संशोधन ।

37. मूल अधिनियम की दूसरी अनुसूची में,—

(i) शीर्षक में, “धारा 21(3), धारा 21ख(3)” शब्दों, अंकों, अक्षर और कोष्ठकों के स्थान पर “धारा 21(6), धारा 21ख(5) और (6)” शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ii) भाग 1 की मद (3) में “ऐसी रीति से जिससे यह विश्वास हो जाए कि वह” शब्दों के स्थान “ऐसी रीति से जिससे यह विश्वास हो जाए कि वह या उसकी फर्म” शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) भाग 2 में, मद (4) के पश्चात् निम्नलिखित मद को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

2013 का 18

“(5) कंपनी अधिनियम 2013 के उपबंधों के उल्लंघन में कंपनी के लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है ।”।

अध्याय 3

लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 का संशोधन

1959 का 23

38. लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) के वृहत नाम में “लागत और संकर्म लेखापालों की वृत्ति के विनियमन” शब्दों के स्थान पर “लागत लेखापालों की वृत्ति के विनियमन और विकास” शब्द रखे जाएंगे ।

वृहत नाम का
संशोधन ।

39. मूल अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (1) में “लागत और संकर्म लेखापाल” के स्थान पर “लागत लेखापाल” शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 1 का
संशोधन ।

40. मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) में,—

(i) खंड (ककक) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

धारा 2 का
संशोधन ।

“(कख) “अनुशासन बोर्ड” से धारा 21क की उपधारा (1) के अधीन गठित अनुशासन बोर्ड अभिप्रेत है;

2013 का 18

(कग) “कंपनी अधिनियम” से कंपनी अधिनियम, 2013 या उक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (67) में यथा परिभाषित कोई अन्य पूर्व कंपनी विधि अभिप्रेत है;”;

(ii) खंड (ग) में, “संस्थान की परिषद्” शब्दों के पूर्व “धारा 9 के अधीन गठित” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(iii) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे,

अर्थात् :—

‘(गक) “निदेशक (अनुशासन)” से धारा 21 में निर्दिष्ट निदेशक (अनुशासन) अभिप्रेत है और उसमें संयुक्त निदेशक (अनुशासन) सम्मिलित है;

(गख) “अनुशासन समिति” से धारा 21ख की उपधारा (1) के अधीन गठित अनुशासन समिति अभिप्रेत है ;

(गग) “अनुशासन निदेशालय” से धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अनुशासन निदेशालय अभिप्रेत है;’;

(iv) खंड (घ) में “1956” अंकों का लोप किया जाएगा ;

(v) खंड (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

‘(ङ) “अध्येता” से संस्थान का अध्येता सदस्य अभिप्रेत है ;’;

(vi) खंड (चक) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

‘(चक) “अधिसूचना” से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और पद “अधिसूचित” का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ; ’;

(vii) खंड (झ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

‘(झ) “रजिस्टर” से यथास्थिति, धारा 19 के अधीन अनुरक्षित संस्थान के सदस्यों का रजिस्टर या धारा 20ख के अधीन अनुरक्षित संस्थान की फर्मों का रजिस्टर अभिप्रेत है;’;

(viii) खंड (झकक) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘(झककक) “स्थायी समिति” से धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन गठित स्थायी समिति अभिप्रेत है ;’।

अध्याय 2 के
शीर्षक का
संशोधन ।

41. मूल अधिनियम के अध्याय 2 के शीर्षक में “और संकर्म” शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 4 का
संशोधन ।

42. मूल अधिनियम की धारा 4 में,—

(i) “रजिस्टर” शब्द के स्थान पर, जहां-कहीं वह आता है “सदस्यों के रजिस्टर” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) हिन्दी पाठ में संशोधन आवश्यक नहीं है;

(iii) उपधारा (3) में,—

(क) “जो तीन हजार रुपए से अधिक की नहीं होगी” शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) परन्तुक का लोप किया जाएगा ।

धारा 5 का
संशोधन ।

43. मूल अधिनियम की धारा 5 में,—

(i) “रजिस्टर” शब्द के स्थान पर, जहां-कहीं वह आता है, “सदस्यों के

रजिस्टर" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (4) में, "जो पांच हजार रुपए से अधिक नहीं होगी" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(iii) परन्तुक का लोप किया जाएगा ।

धारा 6 का
संशोधन ।

44. मूल अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) में,—

(i) "जो तीन हजार रुपए से अधिक नहीं होगी" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) पहले परन्तुक का लोप किया जाएगा;

(iii) दूसरे परन्तुक में, "परन्तु यह और कि" शब्दों के स्थान पर "परन्तु" शब्द रखा जाएगा ।

धारा 8 का
संशोधन ।

45. मूल अधिनियम की धारा 8 में,—

(i) "रजिस्टर" शब्द के स्थान पर, जहां-कहीं वह आता है, "सदस्यों के रजिस्टर" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (iii) में, "अनुन्मोचित दिवालिया" शब्दों के पश्चात् "या अनुन्मोचित शोधन अक्षम" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(iii) खंड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

2016 का 31

"(iii)क) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन शोधन अक्षम घोषित किया गया है ;";

(iv) खंड (v) में संशोधन आवश्यक नहीं है ।

46. मूल अधिनियम की धारा 9 में,—

धारा 9 का
संशोधन ।

(i) उपधारा (2) में,—

(क) "रजिस्टर" शब्द के स्थान पर, जहां-कहीं वह आता है, "सदस्यों के रजिस्टर" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) "तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर "चार वर्ष" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) "छह वर्ष" शब्दों के स्थान पर "आठ वर्ष" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (4) में,—

(क) "कोई व्यक्ति" शब्दों के स्थान पर "संस्थान का कोई सदस्य या फर्म का कोई भागीदार" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) "तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर "चार वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

47. मूल अधिनियम की धारा 12 में,—

धारा 12 का
संशोधन ।

(i) उपधारा (1) में, पहले परन्तुक का लोप किया जाएगा;

(ii) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(2क) अध्यक्ष, परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करेगा ।

(2ख) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ऐसे

कर्तव्यों या कृत्यों का निर्वहन करेंगे, जो विहित किए जाएं ।

(2ग) यह सुनिश्चित करना अध्यक्ष का कर्तव्य होगा कि परिषद् द्वारा लिए गए विनिश्चयों को क्रियान्वित किया जाए ।

(2घ) यदि किसी कारण से अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है या यदि अध्यक्ष अनुपस्थित है अथवा किसी अन्य कारण से, उसे समनुदेशित शक्तियों का प्रयोग करने या कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तो उपाध्यक्ष उसके स्थान पर कार्य करेगा और अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग और उसके कर्तव्यों का पालन करेगा ।”।

48. मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) में, “रजिस्टर” शब्द के स्थान पर “सदस्यों के रजिस्टर” शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 13 का संशोधन ।

49. मूल अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) में,—

धारा 15 का संशोधन ।

(i) खंड (ग) में, “रजिस्टर” शब्द के स्थान पर “सदस्यों के रजिस्टर” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ड) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(डक) किसी फर्म का रजिस्ट्रीकरण प्रदान करना या नामंजूर करना ;”;

(iii) खंड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“(जक) इस अधिनियम के प्रयोजन को पूरा करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करना;

(जख) विनिधानकर्ता शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना;

(जग) इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों का पालन करने के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से किसी विदेशी अभिकरण के साथ कोई जापन या ठहराव करना ;”;

(iv) खंड (ट) में, “और उस पर केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट के साथ तीन मास के भीतर कार्रवाई करना और उनको वार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित करना” शब्दों के स्थान पर “और उसकी वार्षिक रिपोर्ट में उस पर की गई कार्रवाई के ब्यौरे रखना” शब्द रखे जाएंगे ।

50. मूल अधिनियम की धारा 15क में,—

(i) खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(गक) फर्मों के रजिस्टर का अनुरक्षण और प्रकाशन ;”;

(ii) खंड (ड) में, “रजिस्टर से नामों का हटाया जाना और रजिस्टर” शब्दों के स्थान पर “ सदस्यों के रजिस्टर और फर्मों से नामों का हटाया जाना और सदस्यों के रजिस्टर और फर्मों” शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 15क का संशोधन ।

धारा 16 का
संशोधन ।

51. मूल अधिनियम की धारा 16 में,—

(i) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(1) परिषद्, अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिए—

(क) एक सचिव की नियुक्ति करेगी, जो संस्थान के प्रशासनिक कृत्यों का उसके मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में पालन करेगा;

(ख) एक निदेशक (अनुशासन) और संस्थान के उप सचिव से अन्यून पंक्ति के दो संयुक्त निदेशक (अनुशासन), इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के अधीन ऐसे कृत्यों का पालन करने के लिए, जो उन्हें समनुदेशित किए जाएं, नियुक्त करेगी:

परंतु निदेशक (अनुशासन) अथवा संयुक्त निदेशक (अनुशासन) की कोई नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति अथवा नियुक्ति का पर्यवसान तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि ऐसी नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति अथवा नियुक्ति का पर्यवसान केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से न किया गया हो ।”;

(ii) उपधारा (2) के खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(ग) सचिव और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की शक्तियां, नियुक्ति की रीति, कर्तव्यों और कृत्यों को, उनके वेतन, फीस, भत्ते और सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें, विहित कर सकेगी ;”।

52. मूल अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

धारा 18 का
संशोधन ।

“(5) परिषद् के वार्षिक लेखे ऐसी रीति में तैयार किए जाएंगे जो विहित की जाएं और वे परिषद् द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा अनुरक्षित संपरीक्षकों के पैनल से हर वर्ष नियुक्त किए जाने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म द्वारा संपरीक्षित किए जाएंगे :

परंतु फर्म इस उपधारा के अधीन संपरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी यदि उसका कोई भागीदार परिषद् का सदस्य है या पिछले चार वर्षों के दौरान भागीदार रहा है :

परंतु यह और कि यदि यह सूचना कि परिषद् के लेखे उसकी वित्तीय स्थिति का सही और उचित चित्र प्रस्तुत नहीं करते, केंद्रीय सरकार द्वारा परिषद् को भेजी जाती है तो परिषद्, जहां भी उपयुक्त हो उसकी विशेष संपरीक्षा करा सकेगी और ऐसे अन्य कार्य कर सकेगी जिन्हें वह आवश्यक समझे तथा केंद्रीय सरकार को उस पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट देगी :

परंतु यह भी कि यदि केंद्रीय सरकार द्वारा परिषद् को ऐसी सूचना भेजी जाती है कि परिषद् के लेखे उसकी वित्तीय स्थिति का सही और उचित चित्र प्रस्तुत नहीं करते, तो परिषद्, जहां समुचित समझे, विशेष संपरीक्षा करा सकेगी या ऐसी

अन्य कार्रवाई करा सकेगी, जो वह उचित समझे और उस पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगी ।”।

53. मूल अधिनियम की धारा 19 में,—

धारा 19 का संशोधन ।

(i) “रजिस्टर” शब्द के स्थान पर, जहां-कहीं वह आता है, “सदस्यों के रजिस्टर” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(1) परिषद्, संस्थान के सदस्यों का रजिस्टर ऐसी रीति में अनुरक्षित करेगी जो विहित की जाए ।”;

(iii) उपधारा (2) के खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(गक) क्या उसके विरुद्ध अध्याय 5 के अधीन कोई अनुयोज्य सूचना या शिकायत लंबित है अथवा कोई शास्ति अधिरोपित की गई है, यदि कोई हो, जिसके अंतर्गत उसके ब्यौरे भी है ;”;

(iv) उपधारा (4) में,—

(क) “और पांच हजार रुपए से अधिक नहीं होगी” शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) परंतुक का लोप किया जाएगा ।

धारा 20 का संशोधन ।

54. मूल अधिनियम की धारा 20 में,—

(i) “रजिस्टर” शब्द के स्थान पर, जहां-कहीं वह आता है, “सदस्यों के रजिस्टर” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (3) में,—

(क) “दो हजार रुपए से अधिक नहीं होगी” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) परंतुक का लोप किया जाएगा ।

नए अध्याय 4क का अंतःस्थापन ।

55. मूल अधिनियम के अध्याय 4 के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“अध्याय 4क

फर्मों का रजिस्ट्रीकरण और रजिस्टर

फर्मों का रजिस्ट्रीकरण ।

20क. (1) प्रत्येक फर्म, फर्म के किसी भागीदार या स्वामी द्वारा, ऐसी रीति में और ऐसे निबंधनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, परिषद् को किए गए आवेदन पर संस्थान के पास रजिस्ट्रीकृत की जाएगी :

परंतु परिषद्, किसी फर्म को रजिस्टर करना नामंजूर कर सकेगी, यदि ऐसी फर्म का नाम, किसी अन्य फर्म के नाम के समरूप या समान है, जो पहले से ही

रजिस्ट्रीकृत है अथवा भारत के भीतर या बाहर किसी फर्म द्वारा नाम उपयोग में है या परिषद् की राय में फर्म का रजिस्ट्रीकरण अवांछनीय है ।

फर्मों का
रजिस्टर।

20ख. (1) परिषद्, फर्मों का रजिस्टर, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, अनुरक्षित करेगी ।

(2) फर्मों के रजिस्टर में, फर्म के बारे में ऐसी विशिष्टियां, जिसके अंतर्गत अध्याय 5 के अधीन अनुयोज्य सूचना या परिषद् के लंबित अथवा इसके विरुद्ध किसी अधिरोपित शास्ति के ब्यौरे भी हैं, ऐसी रीति में और ऐसे अंतरालों पर होगी, जो विहित किए जाए ।

(3) परिषद्, प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रैल को या ऐसे अंतरालों पर, जो परिषद् द्वारा विनिश्चित किए जाएं, संस्थान के साथ रजिस्ट्रीकृत फर्मों की सूची, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रकाशित कराएगी और ऐसे प्ररूप में और ऐसी रकम के संदाय पर, जो विहित की जाए, ऐसे व्यक्तियों को यह सूची, उपलब्ध कराएगी ।

फर्मों के रजिस्टर
से हटाया जाना ।

20ग. (1) परिषद्, फर्मों के रजिस्टर से ऐसी किसी फर्म के नाम को हटाएगी,—

(क) जिसका विघटन या परिसमापन हो गया है ; या

(ख) जिससे इस निमित्त कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ; या

(ग) जिसे दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के उपबंधों के अधीन दिवाला या शोधन अक्षम घोषित किया गया है और जो अननुमोचित रहती है ; या

2016 का 31

(घ) जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन या किसी अन्य सक्षम न्यायालय द्वारा व्यवसायरत लागत लेखापाल के व्यवसाय से संबंधित किसी कार्यकलाप या किन्हीं कार्यकलापों को करने से वर्जित किया गया है ; या

(ङ) जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन हटाए जाने का आदेश पारित किया गया है ।

20घ. (1) रजिस्ट्रीकरण से इंकार करने के किसी विनिश्चय से व्यथित कोई फर्म, ऐसे इंकार की तारीख के एक मास के भीतर, परिषद् के समक्ष पुनर्विलोकन के लिए आवेदन कर सकेगी ।

परिषद् के समक्ष
पुनर्विलोकन ।

(2) परिषद्, पुनर्विलोकन आवेदन पर विचार करने के पश्चात्, इस प्रकार किए गए विनिश्चय की पुष्टि कर सकेगी या उसे अपास्त कर सकेगी या ऐसा आदेश पारित कर सकेगी, जो वह समुचित समझे ।”।

56. मूल अधिनियम की धारा 21 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

धारा 21 का
प्रतिस्थापन ।

“21. (1) परिषद्, अन्वेषण करने के लिए, या तो स्वःप्रेरणा से या किसी सूचना या शिकायत की प्राप्ति पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी रीति में, ऐसी फीस के साथ विनिर्दिष्ट की जाए, जो अधिसूचना द्वारा एक अनुशासनिक निदेशालय की स्थापना करेगी, जो निदेशक (अनुशासन), संस्थान के उप सचिव की पंक्ति से अन्यून के कम से कम दो संयुक्त निदेशक (अनुशासन) और धारा 16 के अधीन

अनुशासनिक
निदेशालय ।

नियुक्त ऐसे अन्य कर्मचारियों से मिलकर बनेगा ।

(2) किसी सूचना या शिकायत की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर, निदेशक (अनुशासन) ऐसी रीति में विनिश्चय करेगा जो विनिर्दिष्ट की जाए, क्या शिकायत या सूचना अनुयोज्य है या गैर-अनुयोज्य रूप में बंद किए जाने के लिए दायी है :

परंतु निदेशक (अनुशासन), यथास्थिति, शिकायतकर्ता या सूचनादाता से, यह विनिश्चय करने से पूर्व कि क्या मामला अनुयोज्य है या गैर-अनुयोज्य है, पन्द्रह दिन का समय देकर अतिरिक्त सूचना मांग सकेगा :

परंतु यह और कि गैर-अनुयोज्य शिकायत या सूचना के संबंध में निदेशक (अनुशासन) की सिफारिशों को अनुशासनिक बोर्ड को उनकी प्राप्ति के साठ दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा तथा अनुशासनिक बोर्ड, उनके गुणागुण की जांच करने के पश्चात्, ऐसी शिकायत या सूचना को, उसका और अन्वेषण करने के लिए निदेशक (अनुशासन) को निर्दिष्ट कर सकेगा ।

(3) किसी ऐसे मामले, जो अनुयोज्य पाया जाता है, का अन्वेषण करते समय, निदेशक (अनुशासन), यथास्थिति, सदस्य या फर्म को इक्कीस दिन के भीतर एक लिखित कथन प्रस्तुत करने का अवसर देगा, जिसको अन्य इक्कीस दिन तक, अतिरिक्त विस्तार मांगने के कारणों को लेखबद्ध करते हुए और बढ़ाया जा सकेगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन लिखित कथन, यदि कोई हो, की प्राप्ति पर, निदेशक (अनुशासन), यथास्थिति, शिकायतकर्ता या सूचना देने वाले को उसकी एक प्रति भेजेगा और शिकायतकर्ता या सूचना देने वाला व्यक्ति ऐसे लिखित कथन की प्राप्ति के इक्कीस दिन के भीतर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करेगा ।

(5) उपधारा (3) के अधीन लिखित कथन और उपधारा (4) के अधीन प्रत्युत्तर के प्राप्त हो जाने पर, निदेशक (अनुशासन), यदि, यथास्थिति, किसी सदस्य या फर्म के विरुद्ध प्रथमदृष्टया मामला बनता है, तो तीस दिन के भीतर एक प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

(6) यदि पहली अनुसूची में उल्लिखित किसी वृत्तिक या अन्य अवचार के लिए प्रथमदृष्टया मामला बनता है तो निदेशक (अनुशासन), प्रारंभिक जांच रिपोर्ट अनुशासनिक बोर्ड को प्रस्तुत करेगा और जहां दूसरी अनुसूची में या पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची, दोनों में, उल्लिखित किसी वृत्तिक या अन्य अवचार का प्रथमदृष्टया मामला बनता है, तो वहां वह प्रारंभिक जांच रिपोर्ट अनुशासनिक समिति को प्रस्तुत करेगा :

परंतु केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी कानूनी प्राधिकारी के किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा फाइल की गई शिकायत या सूचना, जो अन्वेषण रिपोर्ट या समर्थनकारी साक्ष्य के साथ अन्वेषण रिपोर्ट के सुसंगत उद्धरण द्वारा सम्यक्त समर्थित है, प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के रूप में समझा जाएगा :

परंतु यह और कि जहां, यथास्थिति, सदस्य या फर्म के विरुद्ध प्रथमदृष्टया कोई मामला नहीं बनता है, वहां निदेशक (अनुशासन), अनुशासनिक बोर्ड को सुसंगत दस्तावेजों के साथ, ऐसी सूचना या शिकायत प्रस्तुत करेगा और

अनुशासनिक बोर्ड, यदि वह निदेशक (अनुशासन) के निष्कर्षों से सहमत हो जाता है, मामले को बंद कर सकेगा या असहमति की दशा में, स्वयं आगे कार्यवाही कर सकेगा या मामले को अनुशासनिक समिति को निर्दिष्ट कर सकेगा या मामले का और आगे अन्वेषण करने के लिए निदेशक (अनुशासन) को सलाह दे सकेगा ।

(7) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अन्वेषणों के प्रयोजनों के लिए, अनुशासनिक निदेशालय ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जो विनिर्दिष्ट की जाए।

(8) अनुशासनिक निदेशालय के पास फाइल की गई शिकायत किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं ली जाएगी ।

(9) अनुशासनिक निदेशालय, अनुशासनिक बोर्डों और अनुशासनिक समितियों के समक्ष लंबित शिकायतों और अनुयोज्य सूचना की प्रास्थिति और धारा 21क के अधीन अनुशासनिक बोर्ड तथा धारा 21ख के अधीन अनुशासनिक समिति द्वारा पारित आदेश, अनुशासनिक निदेशालय द्वारा, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, लोक अधिकारिता में उपलब्ध कराई जाएगी ।”।

धारा 21क का
प्रतिस्थापन ।

57. मूल अधिनियम की धारा 21क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी,
अर्थात् :—

अनुशासन बोर्ड ।

“21क. (1) परिषद् अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनने वाले एक या अधिक अनुशासन बोर्डों का गठन करेगी—

(क) कोई व्यक्ति जो संस्थान का सदस्य नहीं हो, जिसके पास विधि का अनुभव हो तथा अनुशासनात्मक मामलों का और वृत्ति का ज्ञान हो, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, परिषद् द्वारा तैयार किए गए और प्रदत्त व्यक्तियों के पैनल से इसके पीठासीन अधिकारी के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए ;

(ख) एक सदस्य जो विधि, अर्थशास्त्र, कारबार, वित्त या लेखांकन के क्षेत्र में ख्यातिप्राप्त व्यक्ति हो, और संस्थान का सदस्य न हो, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, परिषद् द्वारा तैयार किए गए और प्रदत्त व्यक्तियों के पैनल से केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए ;

(ग) एक सदस्य जो ऐसी रीति में जो विहित की जाए, परिषद् द्वारा तैयार किए सदस्यों के पैनल से परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए ;

(घ) उप सचिव से अन्यून पंक्ति का, संस्थान का एक अधिकारी अनुशासन बोर्ड के सचिव के रूप में कार्य करेगा :

परन्तु खंड (क) के अधीन नामनिर्दिष्ट पीठासीन अधिकारी तथा खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य, इस उपधारा के अधीन गठित प्रत्येक अनुशासन बोर्ड के लिए समान होगा ।

(2) अनुशासन बोर्ड उसके समक्ष रखे गए मामलों पर विचार करते समय ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जो विनिर्दिष्ट की जाए जिसके अन्तर्गत फेसलेस कार्यवाहियां तथा आभासी सुनवाईयां भी हैं ।

(3) अनुशासन बोर्ड, निदेशक (अनुशासन) से प्रारंभिक परीक्षा रिपोर्ट की

प्राप्ति पर, यथास्थिति, सदस्य या फर्म से, जिसके विरुद्ध ऐसी प्रारंभिक परीक्षा रिपोर्ट फाइल की गई है, इक्कीस दिन के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा, जिसे आपवादिक परिस्थितियों में लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से इक्कीस दिन के लिए और बढ़ाया जा सकेगा ।

(4) अनुशासन बोर्ड, निदेशक (अनुशासन) से प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के नब्बे दिन के भीतर अपनी जांच पूरी करेगा ।

(5) जांच करने पर यदि अनुशासन बोर्ड यह पाता है कि ऐसा सदस्य पहली अनुसूची में वर्णित व्यवसायिक या अन्य अवचार का दोषी है तो वह सदस्य को ऐसे निष्कर्ष से तीस दिन के भीतर सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् निम्नलिखित कार्रवाइयों में से कोई एक या अधिक कार्रवाई किए जाने का आदेश पारित कर सकेगा, अर्थात् :—

(क) सदस्यों को धिगदंडित और सदस्यों के रजिस्टर में इसे अभिलिखित करने का ;

(ख) सदस्य के नाम को सदस्यों के रजिस्टर से छह मास की कालावधि तक के लिए हटाने का ;

(ग) ऐसा जुर्माना अधिरोपित करने का, जो वह ठीक समझे, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा ।

(6) जहां अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य के आधार पर या किसी सदस्य से संबंधित जांच के अनुक्रम के दौरान, अनुशासन बोर्ड यह राय बनाता है कि ऐसा कोई सदस्य, जो किसी फर्म का भागीदार या स्वामी है, पिछले पांच वर्ष के दौरान पहली अनुसूची के अधीन अवचार का लगातार दोषी पाया गया है तो ऐसी फर्म के विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाई भी की जा सकेगी, अर्थात् :—

(क) एक वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए व्यवसायरत किसी कम्पनी सचिव की वृत्ति से संबंधित किसी क्रियाकलाप या क्रियाकलापों को करने से फर्म को प्रतिषिद्ध करना, या

(ख) ऐसा जुर्माना अधिरोपित करना जो पच्चीस लाख रुपए तक हो सकेगा ।

(7) जहां कोई सदस्य उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन अधिरोपित जुर्माने को ऐसे समय के भीतर जो विनिर्दिष्ट किया जाए, संदाय करने में असफल रहता है तो परिषद् ऐसी अवधि के लिए, जो वह ठीक समझे, यथास्थिति, सदस्यों के रजिस्टर या फर्मों के रजिस्टर से ऐसे सदस्य या फर्म का नाम हटा देगी ।

(8) पीठासीन अधिकारी और अनुशासन बोर्ड के सदस्यों को ऐसे भत्तों का संदाय किया जाएगा, जो विहित किए जाएं ।”।

58. मूल अधिनियम की धारा 21ख के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“21ख. (1) परिषद्, अधिसूचना द्वारा, एक या अधिक अनुशासनिक समितियों का गठन करेगी, प्रत्येक समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी—

धारा 21ख का
प्रतिस्थापन ।

अनुशासनिक
समिति ।

(क) परिषद् द्वारा, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, तैयार किए गए और उपलब्ध कराए गए व्यक्तियों के पैनल में से, केंद्रीय सरकार द्वारा उसके पीठासीन अधिकारी के रूप में नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला, विधि का अनुभव रखने वाला ऐसा व्यक्ति, जो संस्थान का सदस्य नहीं है और जिसके पास अनुशासनिक विषयों और व्यवसाय का ज्ञान हो ;

(ख) परिषद् द्वारा, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, तैयार किए गए और उपलब्ध कराए गए व्यक्तियों के पैनल में से, केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो सदस्य, जो ऐसे विख्यात व्यक्ति हों, जिनके पास विधि, अर्थशास्त्र, कारबार, वित्त या लेखांकन के क्षेत्र में अनुभव हो और जो संस्थान का सदस्य नहीं हैं ;

(ग) परिषद् द्वारा, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, तैयार किए जाने वाले संस्थान के सदस्यों के पैनल में से परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो सदस्य :

परंतु खंड (क) के अधीन नामनिर्दिष्ट पीठासीन अधिकारी और खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य, इस उपधारा के अधीन गठित भिन्न-भिन्न अनुशासनिक बोर्डों के लिए समान हो सकेंगे ।

(2) अनुशासनिक बोर्ड, उसके समक्ष रखे गए मामलों पर विचार करते समय, ऐसी प्रक्रिया, जो विनिर्दिष्ट की जाए जिसमें फेसलेस कार्यवाहियां और वर्चुअल सुनवाईयां भी हैं, का अनुसरण करेगा ।

(3) अनुशासनिक समिति, निदेशक (अनुशासन) से प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यथास्थिति, सदस्य या फर्म से, जिसके विरुद्ध ऐसी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट फाइल की गई है, से अपेक्षा करेगा कि वह इक्कीस दिन के भीतर, लिखित कथन प्रस्तुत करे, जिसे आपवादिक परिस्थितियों में, ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, अन्य इक्कीस दिनों तक और बढ़ाया जा सकेगा ।

(4) अनुशासनिक समिति, निदेशक (अनुशासन) से प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के एक सौ अस्सी दिन के भीतर अपनी जांच समाप्त करेगी ।

(5) जांच करने पर यदि अनुशासनिक समिति यह पाती है कि ऐसा कोई सदस्य दूसरी अनुसूची में या पहली और दूसरी अनुसूची, दोनों में वर्णित वृत्तिक या अन्य अवचार का दोषी है तो वह सदस्य को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, ऐसे निष्कर्ष के तीस दिन के भीतर, निम्नलिखित कार्यवाहियों में से कोई एक या अधिक कार्यवाहियां किए जाने का आदेश पारित कर सकेगी, अर्थात् :—

(क) सदस्यों को धिगदंडित देने का और सदस्यों के रजिस्टर में इसे अभिलिखित करने ; या

(ख) सदस्य के नाम को, सदस्यों के रजिस्टर में से, स्थायी रूप से हटाने या छह मास की कालावधि तक के लिए हटाने, जैसा वह ठीक समझे ; या

(ग) ऐसा जुर्माना अधिरोपित करने, जो वह ठीक समझे, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा ।

(6) जहां अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य के आधार पर या किसी सदस्य से संबंधित जांच के दौरान, अनुशासनिक समिति की यह राय बनती है कि ऐसा कोई सदस्य, जो फर्म का भागीदार या स्वामी है, गत पांच वर्षों के दौरान दूसरी अनुसूची में या पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची, दोनों में वर्णित अवचार का बारम्बार दोषी पाया गया है, वहां ऐसी फर्म के विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाई भी की जा सकेगी, अर्थात् :—

(क) दो वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए व्यवसायरत लागत लेखापाल के व्यवसाय से संबंधित किसी क्रियाकलाप या क्रियाकलापों को करने से फर्म को प्रतिषिद्ध करना ; या

(ख) फर्म के रजिस्ट्रीकरण को निलंबित करना या रद्द करना और उसके नाम को फर्मों के रजिस्टर से स्थायी रूप से या ऐसी अवधि के लिए, जो वह ठीक समझे, हटाना ; या

(ग) ऐसा जुर्माना अधिरोपित करना, जो वह ठीक समझे, जो पचास लाख रुपए तक का हो सकेगा ।

(7) जहां कोई सदस्य या फर्म उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन ऐसे समय के भीतर, अधिरोपित जुर्माने का संदाय करने में असफल रहता है या रहती है, वहां परिषद्, यथास्थिति, ऐसे सदस्य या फर्म का नाम, सदस्यों के रजिस्टर या फर्मों के रजिस्टर से, ऐसी अवधि के लिए, जो वह ठीक समझे, हटाएगी ।

(8) अनुशासनिक समिति के पीठासीन अधिकारी और सदस्यों को ऐसे भर्त्ता का संदाय किया जाएगा, जो विहित किए जाएं ।”।

59. मूल अधिनियम की धारा 21ग में, स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा ।

धारा 21ग का संशोधन ।

धारा 21घ का प्रतिस्थापन ।

60. मूल अधिनियम की धारा 21घ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

संक्रमणकालीन उपबंध ।

“21घ. चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत और संकर्म लेखापाल तथा कंपनी सचिव (संशोधन) अधिनियम, 2021 के आरंभ से पूर्व, अनुशासनिक बोर्ड या अनुशासनिक समिति के समक्ष लंबित सभी शिकायतें या कोई जांच या अपील प्राधिकारी अथवा किसी उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल कोई निर्देश या अपील, इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा उसी प्रकार शासित होते रहेंगे, मानो इस अधिनियम का चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत और संकर्म लेखापाल तथा कंपनी सचिव (संशोधन) अधिनियम, 2021 द्वारा संशोधन नहीं किया गया हो ।”।

धारा 22 का प्रतिस्थापन ।

61. मूल अधिनियम की धारा 22 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

परिभाषित वृत्तिक
या अन्य
अवचार ।

‘22. इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, “वृत्तिक या अन्य अवचार” पद के अन्तर्गत संस्थान के किसी सदस्य की ओर से या तो अपनी व्यक्तिगत हैसियत में या किन्हीं अनुसूचियों में यथाउल्लिखित फर्म के भागीदार या स्वामी के रूप में कोई कृत्य या लोप भी सम्मिलित समझा जाएगा, किन्तु इस धारा की किसी बात का अर्थान्वयन किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन ऐसे सदस्य या फर्म के आचरण की जांच करने के लिए धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन निदेशक (अनुशासन) को प्रदत्त कोई शक्ति या अधिरोपित कर्तव्य को सीमित या न्यून करने वाला नहीं होगा ।’।

धारा 22ड का
संशोधन ।

62. मूल अधिनियम की धारा 22ड में,—

(i) उपधारा (1) में,—

(क) “संस्थान का कोई सदस्य” शब्दों के पश्चात्, “या कोई फर्म” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) “कोई शास्ति उस पर” शब्दों के स्थान पर, “कोई शास्ति ऐसे सदस्य या फर्म पर” शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) “धारा 21क की उपधारा (3) और धारा 21ख की उपधारा (3)” शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों के स्थान पर, “, यथास्थिति, धारा 21क की उपधारा (5) या उपधारा (6) या धारा 21ख की उपधारा (5) या उपधारा (6)” शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(घ) “उसे आदेश संसूचित किया जाता है” शब्दों के स्थान पर, “ऐसे सदस्य या फर्म को आदेश संसूचित किया जाता है” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (2) में “धारा 21क की उपधारा (3) और धारा 21ख की उपधारा (3)” शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर “यथास्थिति, धारा 21क की उपधारा (5) या उपधारा (6) या धारा 21ख की उपधारा (5) या उपधारा (6)” शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(iii) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा और स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

‘(3) प्राधिकरण के किसी आदेश या कार्य या कार्यवाही को, प्राधिकरण के, गठन में केवल मात्र किसी त्रुटि के, या आकस्मिक रिक्ति होने या एक अथवा दो सदस्यों की अनुपस्थिति के आधार पर, किसी भी रीति में, प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण 1—इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए,—

(अ) “संस्थान का सदस्य” के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति सम्मिलित है, जो अभिकथित अवचार की तारीख को संस्थान का सदस्य था, यद्यपि जांच के समय वह संस्थान का सदस्य नहीं रह गया है ;

(आ) संस्थान के पास रजिस्ट्रीकृत “फर्म” किसी ऐसे सदस्य के अवचार के लिए भी दायी ठहराई जाएगी, जो अभिकथित अवचार की तारीख को इसका भागीदार या स्वामी था, यद्यपि जांच के समय वह

ऐसा भागीदार या स्वामी नहीं रह गया है ।

स्पष्टीकरण 2—इस अध्याय के उपबंधों के अधीन की गई कोई कार्रवाई, केंद्रीय सरकार के विभाग या राज्य सरकार या किसी कानूनी प्राधिकरण या विनियामक निकाय को, संस्थान के पास रजिस्ट्रीकृत किसी सदस्य या फर्म के विरुद्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कार्रवाई करने से वर्जित नहीं करेगी ।’।

63. मूल अधिनियम की धारा 24 में,—

धारा 24 का संशोधन ।

(क) “एक हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर, “एक लाख रुपए” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) “पांच हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर, “पांच लाख रुपए” शब्द रखे जाएंगे ।

64. मूल अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (2) में,—

धारा 25 का संशोधन ।

(i) “जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा” शब्दों के स्थान पर, “कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) “जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा” शब्दों के स्थान पर, “जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो दो लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु दस लाख रुपए तक का हो सकेगा” शब्द रखे जाएंगे ।

65. मूल अधिनियम की धारा 26 में, उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

धारा 26 का संशोधन ।

“(2) यदि कोई कंपनी उपधारा (1) के अधीन उपबंधों का उल्लंघन करती है, तो प्रत्येक निदेशक, प्रबंधक, सचिव और कोई अन्य ऐसा अधिकारी जो जानबुझकर ऐसे उल्लंघन का पक्षकार है, पहले दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से, दो लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा और किसी पश्चातवर्ती दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने से, जो चार लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो बीस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा ।”।

66. मूल अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (2) में,—

धारा 27 का संशोधन ।

(क) “पांच हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर, “एक लाख रुपए” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) “एक लाख रुपए” शब्दों के स्थान पर, “पांच लाख रुपए” शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) “दस हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर, “दो लाख रुपए” शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) “दो लाख रुपए” शब्दों के स्थान पर, “दस लाख रुपए” शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 29ख का
संशोधन ।

67. मूल अधिनियम की धारा 29ख के खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(घ) संस्थान या फर्मों के सदस्यों द्वारा विभिन्न कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं के अननुपालन के मामलों को, जो उसके द्वारा उनके पुनर्विलोकन के दौरान ध्यान में आए हों, उनकी परीक्षा के लिए अनुशासनिक निदेशालय को अग्रेषित करना ।”।

धारा 34 का
प्रतिस्थापन ।

68. मूल अधिनियम की धारा 34 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

समन्वय
समिति ।

“34. चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 9क के अधीन गठित समन्वय समिति, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए समन्वय समिति समझी जाएगी ।”।

1949 का 38

धारा 38 का
संशोधन ।

69. मूल अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) में, “रजिस्टर” शब्द के स्थान पर, “सदस्यों का रजिस्टर” शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 38क का
संशोधन ।

70. मूल अधिनियम की धारा 38क की उपधारा (2) में, खंड (ग) और खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“(ग) धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन कोई सूचना या शिकायत फाइल करने के लिए प्ररूप, रीति और फीस तथा इसकी उपधारा (2) के अधीन अनुयोज्य या गैर-अनुयोज्य के रूप में शिकायत या सूचना का विनिश्चय करने की रीति और उपधारा (7) के अधीन अन्वेषण की प्रक्रिया ;

(घ) धारा 21क की, उपधारा (2) के अधीन अनुशासनिक बोर्ड द्वारा मामलों पर विचार करते समय प्रक्रिया और उपधारा (7) के अधीन जुर्माने के संदाय के लिए समय-सीमा ;

(घक) धारा 21ख की, उपधारा (2) के अधीन अनुशासनिक समिति द्वारा मामलों पर विचार करते समय प्रक्रिया और उपधारा (7) के अधीन जुर्माने के संदाय के लिए समय-सीमा ;”।

धारा 39 का
संशोधन ।

71. मूल अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (ख), खंड (च) और खंड (झ) में, “रजिस्टर” शब्द के स्थान पर, “सदस्यों का रजिस्टर” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ज) और खंड (ञ) का लोप किया जाएगा ;

(iii) खंड (त) में, “के सदस्य” शब्दों के स्थान पर, “के पास रजिस्ट्रीकृत सदस्य और फर्म” शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) खंड (ध) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“(ध) वे परिस्थितियां, जिनके अधीन धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन व्यवसाय प्रमाणपत्र रद्द किया जा सकेगा ;

(धक) धारा 15 की उपधारा (2) के खंड (ङ) के अधीन व्यवसाय

प्रमाणपत्र प्रदान करने या उसके लिए इंकार करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत ;

(धख) धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन परिषद् के सचिव और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति, शक्तियां, कर्तव्य, कृत्य, वेतन, फीस, भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;

(धग) धारा 18 की उपधारा (4) के अधीन वार्षिक वित्तीय विवरण और उपधारा (5) के अधीन वार्षिक लेखा तैयार करने की रीति ;

(धघ) धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन संस्थान के सदस्यों के रजिस्टर को बनाए रखने की रीति ;

(धड) धारा 20क के अधीन फर्म का रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए आवेदन करने की रीति और ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए निबंधन और शर्तें ;

(धच) धारा 20ख की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन फर्म के रजिस्टर और अन्य विशिष्टियों, जिसमें फर्म के विरुद्ध लंबित शिकायतों या अनुयोज्य सूचनाओं या किसी शास्ति के अधिरोपण के ब्यौरे भी हैं, के रख-रखाव की रीति, और वह रीति, जिसमें उपधारा (3) के अधीन संस्थान के पास रजिस्ट्रीकृत फर्मों की वार्षिक सूची प्रकाशित की जाएगी ;

(धछ) धारा 21 की उपधारा (9) के अधीन अनुयोज्य सूचना तथा शिकायतों और पारित आदेशों की प्रास्थिति उपलब्ध कराने की रीति ;

(धज) धारा 21क की उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन व्यक्तियों का पैनल तैयार करने की रीति और उपधारा (8) के अधीन अनुशासनिक समितियों के पीठासीन अधिकारियों और सदस्यों को संदेय भत्ते ;

(धझ) धारा 21क की उपधारा (8) के अधीन अनुशासनिक बोर्ड के तथा धारा 21ख की उपधारा (4) के अधीन अनुशासनिक समिति के पीठासीन अधिकारी और सदस्यों को संदेय भत्ते ;

(धञ) धारा 22घ की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृन्द के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें ;

(धट) वह रीति जिसमें धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन क्षेत्रीय परिषद् का गठन किया जा सकेगा और उसके कृत्य ।”।

पहली अनुसूची
का संशोधन ।

72. मूल अधिनियम की पहली अनुसूची के शीर्षक में, “धारा 21(3), धारा 21क(3)” शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर, “धारा 21(6), धारा 21क(5) और (6), धारा 21ख(5) और (6)” शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ।

दूसरी अनुसूची
का संशोधन ।

73. मूल अधिनियम की दूसरी अनुसूची में,—

(i) “धारा 21(3), धारा 21ख(3)” शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर, “धारा 21(6), धारा 21ख(5) और (6)” शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे

जाएंगे ;

(ii) भाग 1 की मद (3) में, “जिससे यह विश्वास हो जाए कि वह” शब्दों के स्थान पर, “जिससे यह विश्वास हो जाए कि वह या उसकी फर्म” शब्द रखे जाएंगे ।

अध्याय 4

कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 का संशोधन

धारा 2 का
संशोधन ।

74. कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,—

1980 का 56

(क) उपधारा (1) में,—

(i) खंड (ककक) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘(कख) “अनुशासन बोर्ड” से धारा 21क की उपधारा (1) के अधीन गठित अनुशासन बोर्ड अभिप्रेत है;’;

(ii) खंड (ख) में “कंपनी अधिनियम, 1956” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “कंपनी अधिनियम, 2013 या उक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (67) में यथा परिभाषित कोई अन्य पूर्व कंपनी विधि” शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

1956 का 1

2013 का 18

(iii) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

‘(घक) “निदेशक (अनुशासन)” से धारा 21 में निर्दिष्ट निदेशक (अनुशासन) अभिप्रेत है और उसमें संयुक्त निदेशक (अनुशासन) भी सम्मिलित है ;

(घख) “अनुशासनिक समिति” से धारा 21ख की उपधारा (1) के अधीन गठित अनुशासनिक समिति अभिप्रेत है ;

(घग) “अनुशासनिक निदेशालय” से धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अनुशासनिक निदेशालय अभिप्रेत है ;’;

(iv) खंड (छक) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

‘(छक) “अधिसूचना” से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और “अधिसूचित” पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;’;

(v) खंड (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

‘(ज) “रजिस्टर” से, यथास्थिति, धारा 19 के अधीन बनाए रखा गया संस्थान के सदस्यों का रजिस्टर या धारा 20ख के अधीन बनाए रखा गया संस्थान की फर्मों का रजिस्टर अभिप्रेत है ;’;

(vi) खंड (जक) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘(जकक) “स्थायी समिति” से धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन गठित स्थायी समिति अभिप्रेत है ;’;

(ख) उपधारा (2) के खंड (ग) के उपखंड (vi) में,—

1947 का 29

(अ) “पूँजी निर्गमन (नियंत्रण) अधिनियम, 1947” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों का लोप किया जाएगा ;

1969 का 54

1973 का 46

1992 का 15

1999 का 42

2003 का 12

(आ) “एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002” शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

75. मूल अधिनियम की धारा 4 में,—

धारा 4 का संशोधन ।

(i) “रजिस्टर” शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वह आता है, “सदस्यों का रजिस्टर” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) हिंदी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है ;

(iii) उपधारा (3) में,—

(क) “जो तीन हजार रुपए से अधिक की नहीं होगी” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) परंतुक का लोप किया जाएगा ।

76. मूल अधिनियम की धारा 5 में,—

धारा 5 का संशोधन ।

(i) “रजिस्टर” शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वह आता है, “सदस्यों का रजिस्टर” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (3) में, “जो पांच हजार रुपए से अधिक नहीं होगी” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(iii) परन्तुक का लोप किया जाएगा ।

77. मूल अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) में,—

धारा 6 का संशोधन ।

(i) “जो तीन हजार रुपए से अधिक की नहीं होगी” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ii) परंतुक का लोप किया जाएगा ।

धारा 8 का संशोधन ।

78. मूल अधिनियम की धारा 8 में,—

(i) “रजिस्टर” शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वह आता है, “सदस्यों का रजिस्टर” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ग) में, “अननुमोचित दिवालिया” शब्दों के पश्चात्, “या अननुमोचित शोधन अक्षम” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(iii) खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(गक) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के उपबंधों के अधीन शोधन अक्षम घोषित किया गया है ;”;

(iv) खंड (ड) में संशोधन आवश्यक नहीं है ।

धारा 9 का
संशोधन ।

79. मूल अधिनियम की धारा 9 में,—

(i) उपधारा (2) में,—

(क) “रजिस्टर” शब्द के स्थान पर, दोनों स्थान पर, जहां वह आता है, “सदस्यों का रजिस्टर” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) “तीन वर्ष” शब्दों के स्थान पर, “चार वर्ष” शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) “छह वर्ष” शब्दों के स्थान पर, “आठ वर्ष” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (4) में,—

(क) “व्यक्ति” शब्द के स्थान पर, “संस्थान का सदस्य या फर्म का कोई भागीदार” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) “तीन वर्ष” शब्दों के स्थान पर, “चार वर्ष” शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 12 का
संशोधन ।

80. मूल अधिनियम की धारा 12 में,—

(i) उपधारा (1) में, पहले परंतुक का लोप किया जाएगा ;

(ii) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“(2क) अध्यक्ष परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करेगा ।

(2ख) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों तथा कृत्यों का पालन करेंगे, जो विहित किए जाएं ।

(2ग) अध्यक्ष का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि परिषद् द्वारा किए गए विनिश्चय कार्यान्वित किए जाते हैं ।”।

धारा 13 का
संशोधन ।

81. मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) में “रजिस्टर” शब्द के स्थान पर, “सदस्यों का रजिस्टर” शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 15 का
संशोधन ।

82. मूल अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (ग) में, “रजिस्टर” शब्द के स्थान पर, “सदस्यों के रजिस्टर” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(डक) फर्म के रजिस्ट्रीकरण को अनुदत्त करना या अस्वीकृत करना ;”;

(iii) खंड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे,

“(जक) इस अधिनियम के उद्देश्यों के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करना ;

(जख) विनिधानकर्ता शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम संचालित करना;

(अग) इस अधिनियम के अधीन इसके कृत्यों के पालन के प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से किसी अन्य बाहरी देश के किसी अभिकरण के साथ कोई जापन या ठहराव करना ।”।

83. मूल अधिनियम की धारा 15क में,—

धारा 15क का संशोधन ।

(i) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(गक) फर्मों के रजिस्टर का अनुरक्षण और प्रकाशन ;”;

(ii) खंड (ड) में, “रजिस्टर से नामों को हटाया जाना और रजिस्टर में ऐसे नामों का प्रत्यावर्तन” शब्दों के स्थान पर, “सदस्यों और फर्मों के रजिस्टर से नामों को हटाया जाना और सदस्यों और फर्मों के रजिस्टर में ऐसे नामों का प्रत्यावर्तन” शब्द रखे जाएंगे ।

84. मूल अधिनियम की धारा 16 में,—

धारा 16 का संशोधन ।

(i) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(1) परिषद् अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिए—

(क) एक सचिव की नियुक्ति करेगी जो संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में प्रशासनिक कृत्यों का भी कार्यान्वयन करेगा;

(ख) इस अधिनियम और उसके अधीन विरचित नियमों और विनियमों के अधीन उन्हें समनुदेशित ऐसे कृत्यों के पालन के लिए संस्थान के एक निदेशक (अनुशासन) और उप सचिव से अन्यून पंक्ति वाले संयुक्त निदेशकों (अनुशासन) को नियुक्त करेगी :

परन्तु सचिव या निदेशक (अनुशासन) या संयुक्त निदेशक (अनुशासन) की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति या नियुक्ति की समाप्ति नहीं की जाएगी यदि ऐसी नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति या नियुक्ति की समाप्ति केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से नहीं की जाती है ।”;

(ii) उपधारा (2) में खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(ग) सचिव और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति, शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य, उनके वेतन, फीस, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें विहित कर सकेगी ;”।

धारा 18 का संशोधन ।

85. मूल अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(5) परिषद् के वार्षिक लेखे ऐसी रीति में तैयार किए जाएंगे जो विहित की जाए तथा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा अनुरक्षित संपरीक्षकों के पैनल से परिषद् द्वारा वार्षिक रूप से नियुक्त की जाने वाली चार्टर्ड अकाउन्टेन्टों की फर्म द्वारा संपरीक्षा के अधीन होंगे :

परन्तु इस उपधारा के अधीन संपरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए कोई फर्म पात्र नहीं होगी यदि इसका कोई भागीदार पिछले चार वर्षों के दौरान परिषद् का सदस्य हो या रहा हो :

परन्तु यह और कि यदि परिषद् की जानकारी में यह लाया जाता है कि परिषद् के लेखे इसके वित्त का सत्य और ऋजु दृश्य प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो परिषद् स्वयं ही एक विशेष संपरीक्षा करवाएगी :

परन्तु यह भी कि यदि ऐसी सूचना, परिषद् के लेखे इसके वित्त का सत्य और ऋजु दृश्य प्रस्तुत नहीं करते हैं, केन्द्रीय सरकार द्वारा परिषद् को भेजी जाती है, तो परिषद्, जहां-कहीं उचित हो, विशेष संपरीक्षा करवाएगी या ऐसी अन्य कार्रवाई करेगी जो वह आवश्यक समझे तथा इस पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगी ।” ।

धारा 19 का
संशोधन ।

86. मूल अधिनियम की धारा 19 में,—

(i) “रजिस्टर” शब्द के स्थान पर, जहां-कहीं वह आता है, “सदस्यों के रजिस्टर” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(1) परिषद्, संस्थान के सदस्यों का रजिस्टर ऐसी रीति में रखेगी, जो विहित की जाए ।”;

(iii) उपधारा (2) में, खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(गक) क्या अध्याय 5 के अधीन उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई योग्य सूचना या परिवाद लंबित है या कोई शास्ति अधिरोपित की गई है, जिसके अंतर्गत उसके ब्यौरे भी हैं, यदि कोई हों ;”;

(iv) उपधारा (4) में,—

(क) “जो पांच हजार रुपए से अधिक नहीं होगी”, शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) परन्तुक का लोप किया जाएगा ।

धारा 20 का
संशोधन ।

87. मूल अधिनियम की धारा 20 में,—

(i) “रजिस्टर” शब्द के स्थान पर, जहां-कहीं वह आता है, “सदस्यों के रजिस्टर” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (3) में,—

(क) जो “दो हजार रुपए से अधिक नहीं होगा”, शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) परन्तुक का लोप किया जाएगा ।

88. मूल अधिनियम के अध्याय 4 के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित

नए अध्याय 4क

किया जाएगा, अर्थात् :—

का अंतःस्थापन ।

“अध्याय 4क

फर्मों का रजिस्ट्रीकरण और रजिस्टर

20क. प्रत्येक फर्म, फर्म के किसी भागीदार या स्वामी द्वारा ऐसी रीति में, और ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाएं, परिषद् को किए गए आवेदन पर संस्थान के पास रजिस्ट्रीकृत करेगी :

फर्मों का रजिस्ट्रीकरण ।

परन्तु परिषद् किसी फर्म को रजिस्टर करने से इंकार कर सकेगी यदि ऐसी फर्म का नाम पहले से ही रजिस्ट्रीकृत किसी अन्य फर्म के नाम जैसा ही या समान है या भारत के भीतर या बाहर किसी फर्म द्वारा नाम उपयोग में है अथवा परिषद् की राय में फर्म का रजिस्ट्रीकरण अवांछनीय है ।

20ख (1) परिषद्, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, फर्मों का रजिस्टर रखेगी ।

फर्मों का रजिस्टर ।

(2) फर्मों के रजिस्टर में फर्म के बारे में ऐसी विशिष्टियां, जिसके अन्तर्गत अध्याय 5 के अधीन अनुयोज्य सूचना या परिवाद या इसके विरुद्ध किसी शास्ति के अधिरोपण के ब्यौरे भी हैं, ऐसे प्ररूप में और ऐसे अंतरालों पर होंगी, जो विहित किए जाएं ।

(3) परिषद्, प्रत्येक वर्ष के 1 अप्रैल को या ऐसे अंतरालों पर जो परिषद् द्वारा विनिश्चित किए जाएं, संस्थान में रजिस्ट्रीकृत फर्मों की एक सूची, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, प्रकाशित करवाएगी, और ऐसे प्ररूप में और ऐसी रकम के संदाय पर जो विहित की जाए ऐसे व्यक्तियों को सूची उपलब्ध करवाएगी ।

20ग. परिषद्, फर्मों के रजिस्टर से किसी फर्म का नाम हटाएगी,—

फर्मों के रजिस्टर से निकाला जाना ।

(क) जिसका विघटन या परिसमापन हो गया है ; या

(ख) जिससे उस आशय का अनुरोध प्राप्त हुआ है ; या

(ग) जिसे दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन दिवालिया और शोधन अक्षम घोषित किया गया है तथा जो अननुमोचित रहती है ; या

(घ) जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा व्यवसायरत कंपनी सचिव की वृत्ति से संबंधित किसी क्रियाकलाप या क्रियाकलापों को करने से वर्जित किया है; या

(ङ) जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन हटाए जाने का आदेश पारित किया गया है ।

20घ. (1) रजिस्ट्रीकरण को अस्वीकृत करने के विनिश्चय से व्यथित कोई फर्म, ऐसे अस्वीकार करने की तारीख से एक मास के भीतर परिषद् के समक्ष पुनर्विलोकन के लिए आवेदन कर सकेगी ।

परिषद् के समक्ष पुनर्विलोकन ।

(2) परिषद्, पुनर्विलोकन आवेदन पर विचार करने के पश्चात् इस प्रकार किए गए विनिश्चय की पुष्टि कर सकेगी या अपास्त कर सकेगी या ऐसा आदेश पारित कर सकेगी, जो वह उचित समझे ।”।

धारा 21 का
प्रतिस्थापन ।

अनुशासनिक
निदेशालय ।

89. मूल अधिनियम की धारा 21 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी,
अर्थात् :—

“21. (1) परिषद्, अधिसूचना द्वारा, स्वप्रेरणा से या ऐसे प्ररूप में ऐसे फीस के साथ जो विहित की जाए, किसी सूचना या शिकायत की प्राप्ति पर अन्वेषण करने के लिए संस्थान के निदेशक (अनुशासन), कम से कम दो संयुक्त निदेशकों (अनुशासन) जो संस्थान के उप सचिव की पंक्ति के नीचे के न हों और धारा 16 के अधीन नियुक्त ऐसे अन्य कर्मचारियों से मिलकर बने अनुशासनिक निदेशालय की स्थापना करेगी ।

(2) किसी सूचना या परिवाद की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर, निदेशक (अनुशासन) चाहे परिवाद या सूचना अनुयोज्य है या गैर-अनुयोज्य के रूप में बन्द किए जाने के लिए दायी है, ऐसी रीति में विनिश्चय करेगा जो विनिर्दिष्ट की जाए :

परंतु निदेशक (अनुशासन), यथास्थिति, परिवादी या सूचनाकर्ता से विनिश्चय करने के पूर्व पंद्रह दिन का समय देकर कि क्या मामला अनुयोज्य है या गैर-अनुयोज्य है, अतिरिक्त सूचना मांग सकेगा :

परन्तु यह और कि अनुयोज्य परिवाद या सूचना पर निदेशक (अनुशासन) की सिफारिशें इसकी प्राप्ति के साठ दिन के भीतर अनुशासन बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी और अनुशासन बोर्ड इसके गुणागुण को देखने के पश्चात् ऐसे परिवाद या सूचना को और अन्वेषण करने के लिए निदेशक (अनुशासन) को निर्दिष्ट करेगा ।

(3) किसी मामले में अन्वेषण करते समय, जो अनुयोज्य पाया जाता है, निदेशक (अनुशासन) यथास्थिति, सदस्य या फर्म को इक्कीस दिन के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा, उसके लिए कारण लेखबद्ध करते हुए अतिरिक्त इक्कीस दिन के लिए विस्तारित किया जा सकेगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन लिखित कथन की प्राप्ति पर, यदि कोई हो, निदेशक (अनुशासन) उसकी एक प्रति शिकायतकर्ता या सूचनाकर्ता को भेजेगा तथा, यथास्थिति, शिकायतकर्ता या सूचनाकर्ता ऐसे लिखित कथन की प्राप्ति के इक्कीस दिन के भीतर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करेगा ।

(5) उपधारा (3) के अधीन लिखित कथन तथा उपधारा (4) के अधीन प्रत्युत्तर की प्राप्ति पर निदेशक (अनुशासन), यदि यथास्थिति, किसी सदस्य या फर्म के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है तो तीस दिन के भीतर प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

(6) पहली अनुसूची में उल्लिखित किसी व्यवसायिक या अन्य अवचार का यदि प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है तो निदेशक (अनुशासन), निदेशक बोर्ड को एक आरंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा तथा जहां दूसरी अनुसूची में या पहली और दूसरी अनुसूची, दोनों में, उल्लिखित व्यवसायिक या अन्य अवचार का प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है तो वह एक प्रारंभिक जांच रिपोर्ट अनुशासनिक समिति को प्रस्तुत करेगा :

परंतु केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी प्राधिकृत अधिकारी या किसी कानूनी प्राधिकारी द्वारा समर्थनकारी साक्ष्य के साथ जांच रिपोर्ट या जांच रिपोर्ट का सुसंगत सार द्वारा समर्थित किसी शिकायत या सूचना को फाइल किए जाने पर उसे प्रारंभिक जांच रिपोर्ट समझा जाएगा :

परंतु यह और कि, जहां सदस्य या फर्म के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या मामला नहीं बनता, निदेशक (अनुशासन) सुसंगत दस्तावेजों के साथ ऐसी सूचना या परिवाद को अनुशासन बोर्ड को प्रस्तुत करेगा और अनुशासन बोर्ड, यदि वह निदेशक (अनुशासन) के निष्कर्षों से सहमत है, मामले को बन्द कर देगा या असहमति की स्थिति में, स्वयं आगे कार्यवाही करेगा या मामले को अनुशासनिक समिति को निर्दिष्ट करेगा अथवा निदेशक (अनुशासन) को मामले का और अन्वेषण करने की सलाह देगा ।

(7) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अन्वेषणों के प्रयोजनों के लिए, अनुशासनात्मक निदेशालय ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो विनिर्दिष्ट की जाए ।

(8) अनुशासनात्मक निदेशालय के समक्ष फाइल किया गया परिवाद किन्हीं भी परिस्थितियों में वापस नहीं लिया जाएगा ।

(9) अनुशासनात्मक निदेशालय, अनुशासन बोर्ड और अनुशासनिक समितियों के साथ संबंधित कार्यवाई योग्य सूचना और परिवादों की प्राप्ति तथा धारा 21क के अधीन अनुशासन बोर्ड द्वारा तथा धारा 21ख के अधीन अनुशासनिक समितियों द्वारा पारित आदेश, ऐसी रीति में जो विहित की जाए अनुशासनात्मक निदेशालय द्वारा पब्लिक डोमेन में उपलब्ध करवाए जाएंगे ।”।

90. मूल अधिनियम की धारा 21क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी,
अर्थात् :—

धारा 21क का
प्रतिस्थापन ।

“21क. (1) परिषद् अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनने वाले एक या अधिक अनुशासन बोर्डों का गठन करेगी—

अनुशासन बोर्ड ।

(क) कोई व्यक्ति जो संस्थान का सदस्य नहीं हो, जिसके पास विधि का अनुभव हो तथा अनुशासनात्मक मामलों का और वृत्ति का ज्ञान हो, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, परिषद् द्वारा तैयार किए गए और प्रदत्त व्यक्तियों के पैनल से इसके पीठासीन अधिकारी के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए ;

(ख) एक सदस्य जो विधि, अर्थशास्त्र, कारबार, वित्त या लेखांकन के क्षेत्र में ख्यातिप्राप्त व्यक्ति हो, और संस्थान का सदस्य न हो, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, परिषद् द्वारा तैयार किए गए और प्रदत्त व्यक्तियों के पैनल से केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए ;

(ग) एक सदस्य जो ऐसी रीति में जो विहित की जाए, परिषद् द्वारा तैयार किए सदस्यों के पैनल से परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए ;

(घ) उप सचिव से अन्यून पंक्ति का, संस्थान का एक अधिकारी

अनुशासन बोर्ड के सचिव के रूप में कार्य करेगा :

परन्तु खंड (क) के अधीन नामनिर्दिष्ट पीठासीन अधिकारी तथा खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य, इस उपधारा के अधीन गठित प्रत्येक अनुशासन बोर्ड के लिए समान होगा ।

(2) अनुशासन बोर्ड उसके समक्ष रखे गए मामलों पर विचार करते समय ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जो विनिर्दिष्ट की जाए जिसके अन्तर्गत फेस लेस कार्यवाहियां तथा आभासी सुनवाईयां भी हैं ।

(3) अनुशासन बोर्ड, निदेशक (अनुशासन) से प्रारंभिक परीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति पर, यथास्थिति, सदस्य या फर्म से, जिसके विरुद्ध ऐसी प्रारंभिक परीक्षा रिपोर्ट फाइल की गई है, इक्कीस दिन के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा, जिसे आपवादिक परिस्थितियों में लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से इक्कीस दिन के लिए और बढ़ाया जा सकेगा ।

(4) अनुशासन बोर्ड, निदेशक (अनुशासन) से प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के नब्बे दिन के भीतर अपनी जांच पूरी करेगा ।

(5) जांच करने पर यदि अनुशासन बोर्ड यह पाता है कि ऐसा सदस्य पहली अनुसूची में वर्णित व्यवसायिक या अन्य अवचार का दोषी है तो वह सदस्य को ऐसे निष्कर्ष से तीस दिन के भीतर सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् निम्नलिखित कार्रवाईयों में से कोई एक या अधिक कार्रवाई किए जाने का आदेश पारित कर सकेगा, अर्थात् :—

(क) सदस्यों को धिगंदित और सदस्यों के रजिस्टर में इसे अभिलिखित करने का ;

(ख) सदस्य के नाम को सदस्यों के रजिस्टर से छह मास की कालावधि तक के लिए हटाने का ;

(ग) ऐसा जुर्माना अधिरोपित करने का, जो वह ठीक समझे, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा ।

(6) जहां अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य के आधार पर या किसी सदस्य से संबंधित जांच के अनुक्रम के दौरान, अनुशासन बोर्ड यह राय बनाता है कि ऐसा कोई सदस्य, जो किसी फर्म का भागीदार या स्वामी है, पिछले पांच वर्ष के दौरान पहली अनुसूची के अधीन अवचार का लगातार दोषी पाया गया है तो ऐसी फर्म के विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाई भी की जा सकेगी, अर्थात् :—

(क) एक वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए व्यवसायरत किसी कम्पनी सचिव की वृत्ति से संबंधित किसी क्रियाकलाप या क्रियाकलापों को करने से फर्म को प्रतिषिद्ध करना, या

(ख) ऐसा जुर्माना अधिरोपित करना जो पच्चीस लाख रुपए तक हो सकेगा ।

(7) जहां कोई सदस्य उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन अधिरोपित जुर्माने को ऐसे समय के भीतर जो विनिर्दिष्ट किया जाए, संदाय करने में असफल

रहता है तो परिषद् ऐसी अवधि के लिए, जो वह ठीक समझे, यथास्थिति, सदस्यों के रजिस्टर या फर्मों के रजिस्टर से ऐसे सदस्य या फर्म का नाम हटा देगी।

(8) पीठासीन अधिकारी और अनुशासन बोर्ड के सदस्यों को ऐसे भत्तों का संदाय किया जाएगा, जो विहित किए जाएं।”।

91. मूल अधिनियम की धारा 21ख के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“21ख. (1) परिषद्, अधिसूचना द्वारा, एक या अधिक अनुशासन समितियों का गठन करेगी, जिनमें से प्रत्येक निम्नलिखित से मिलकर बनेगी—

धारा 21ख का संशोधन।

अनुशासनिक समिति।

(क) कोई व्यक्ति जो संस्थान का सदस्य नहीं हो, जिसके पास विधि का अनुभव हो तथा अनुशासनात्मक मामलों का और वृत्ति का ज्ञान हो, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, परिषद् द्वारा तैयार किए गए और प्रदत्त व्यक्तियों के पैनल से इसके पीठासीन अधिकारी के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाए ;

(ख) दो सदस्य जो अर्थशास्त्र, कारबार, वित्त या लेखांकन के क्षेत्र में ख्यातिप्राप्त व्यक्ति हों और जो संस्थान का सदस्य नहीं है परिषद् द्वारा तैयार किए गए और उपलब्ध कराए गए व्यक्तियों के पैनल से केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी रीति में जो विहित की जाए नामनिर्दिष्ट किए जाएं ;

(ग) दो सदस्य जो ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, परिषद् द्वारा तैयार किए गए सदस्यों के पैनल से परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएं :

परन्तु खंड (क) के अधीन नामनिर्दिष्ट पीठासीन अधिकारी तथा खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य, इस उपधारा के अधीन गठित प्रत्येक अनुशासन समिति के लिए एक समान होंगे।

(2) अनुशासनिक समिति, उसके समक्ष रखे गए मामलों पर विचार करते समय ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी, जो विनिर्दिष्ट की जाए, जिसके अन्तर्गत फेस लेस कार्यवाहियां तथा आभासी सुनवाईयां भी हैं।”।

(3). अनुशासनिक समिति, निदेशक (अनुशासन) से प्रारंभिक परीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति पर, यथास्थिति, सदस्य या फर्म से, जिसके विरुद्ध ऐसी प्रारंभिक परीक्षा रिपोर्ट फाइल की गई है, इक्कीस दिन के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगी, जिसे आपवादिक परिस्थितियों में लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से इक्कीस दिन के लिए और बढ़ाया जा सकेगा।

(4) अनुशासनिक समिति, निदेशक (अनुशासन) से प्रारम्भिक परीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति के एक सौ अस्सी दिनों के भीतर अपनी जांच समाप्त करेगी।

(5) जांच करने पर, यदि अनुशासनिक समिति द्वारा यह पाया जाता है कि कोई सदस्य दूसरी अनुसूची या पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची दोनों में उल्लिखित वृत्तिक या अन्य अवचार का दोषी है, तो वह निम्नलिखित एक या अधिक कार्यवाहियां करते हुए, सदस्य को सुनवाई का एक अवसर देने के पश्चात्,

ऐसे निष्कर्ष के तीस दिन के भीतर एक आदेश पारित कर सकेंगी, अर्थात् :—

(क) सदस्य को धिगदंड देगी और इसे सदस्यों के रजिस्टर में अभिलिखित करेगी ; या

(ख) सदस्य के नाम को स्थायी रूप से या ऐसी अवधि के लिए, जो वह ठीक समझे, रजिस्टर से हटाना ; या

(ग) ऐसा जुर्माना अधिरोपित करना जो वह ठीक समझे, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा ।

(6) जहां अनुशासनिक समिति, अभिलेख पर लाए गए या संस्थान के सदस्य से संबंधित जांच के क्रम के दौरान, साक्ष्य के आधार पर यह राय बनाती है कि कोई सदस्य, जो फर्म का भागीदार या स्वामी हैं, पिछले पांच वर्ष के दौरान दूसरी अनुसूची या पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची दोनों में उल्लिखित अवचार का बारम्बार दोषी पाया गया है, तो ऐसी फर्म के विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाइयां भी की जा सकेंगी, अर्थात् :—

(क) फर्म को दो वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट व्यवसाय की वृत्ति से संबंधित किसी क्रियाकलाप या क्रियाकलापों को करने से प्रतिषिद्ध करना ; या

(ख) फर्म के रजिस्ट्रीकरण को निलंबित या रद्द करना और इसका नाम फर्म के रजिस्टर से स्थायी रूप से या ऐसी अवधि के लिए, जैसा वह उचित समझे, हटाना ; या

(ग) ऐसा जुर्माना अधिरोपित करना, जैसा वह उचित समझे, जो पचास लाख रुपए तक का हो सकेगा ।

(7) जहां कोई सदस्य या फर्म उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए, अधिरोपित किए गए जुर्माने का संदाय करने में विफल रहता है तो परिषद् ऐसे सदस्य या फर्म का नाम ऐसी अवधि या ऐसी और अवधि, जो वह उचित समझे, के लिए, यथास्थिति, सदस्यों के रजिस्टर या फर्म का रजिस्टर से हटा देगी ।

(8) पीठासीन अधिकारी तथा अनुशासनिक समिति के सदस्यों को ऐसे भत्तों का संदाय किया जाएगा, जो विहित किए जाएं ।”।

92. मूल अधिनियम की धारा 21ग में, स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा ।

93. मूल अधिनियम की धारा 21घ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“21घ. चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत और संकर्म लेखापाल, कंपनी सचिव (संशोधन) अधिनियम, 2021 के प्रारम्भ के पूर्व अनुशासन बोर्ड या अनुशासनिक समिति के समक्ष लम्बित सभी शिकायतें या कोई जांच अथवा अपील प्राधिकरण

धारा 21ग का संशोधन ।

धारा 21घ का प्रतिस्थापन ।

संक्रमणकालीन उपबंध ।

या उच्च न्यायालय के समक्ष कोई निदेश या फाइल की गई अपील, इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा शासित किए जाते रहेगें, मानो यह अधिनियम चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत और संकर्म लेखापाल और कंपनी सचिव (संशोधन) अधिनियम, 2021 द्वारा संशोधित नहीं किया गया हो ।'।

94. मूल अधिनियम की धारा 22 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी,
अर्थात् :—

‘22. इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, “वृत्तिक या अन्य अवचार” पद के अन्तर्गत संस्थान के किसी सदस्य की ओर से या तो अपनी व्यक्तिगत हैसियत में या किन्हीं अनुसूचियों में यथाउल्लिखित फर्म के भागीदार या स्वामी के रूप में कोई कृत्य या लोप भी सम्मिलित समझा जाएगा, किन्तु इस धारा की किसी बात का अर्थान्वयन किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन ऐसे सदस्य या फर्म के आचरण की जांच करने के लिए धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन निदेशक (अनुशासन) को प्रदत्त कोई शक्ति या अधिरोपित कर्तव्य को सीमित या न्यून करने वाला नहीं होगा ।’।

धारा 22 का
प्रतिस्थापन ।

परिभाषित किया
गया वृत्तिक
या अन्य
कदाचरण ।

95. मूल अधिनियम की धारा 22ड में,—

(i) उपधारा (1) में,—

(क) “संस्थान का कोई सदस्य” शब्दों के पश्चात्, “या कोई फर्म” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) “कोई शास्ति उस पर” शब्दों के स्थान पर, “कोई शास्ति ऐसे सदस्य या फर्म पर” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ग) “धारा 21क की उपधारा (3) और धारा 21ख की उपधारा (3)” शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों के स्थान पर, “यथास्थिति, धारा 21क की उपधारा (5) या उपधारा (6) तथा धारा 21ख की उपधारा (5) या उपधारा (6)” शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(घ) “उसे संसूचित” शब्दों के स्थान पर, “ऐसे सदस्य या फर्म को संसूचित” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) “धारा 21क की उपधारा (3) और धारा 21ख की उपधारा (3)” शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों के स्थान पर, “धारा 21क की उपधारा (5) या उपधारा (6) तथा धारा 21ख की उपधारा (3क) या उपधारा (3ख)” शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(iii) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा और स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

‘(3) प्राधिकरण के किसी आदेश या कार्य या कार्यवाही को प्राधिकरण के गठन में केवल मात्र किसी त्रुटि या आकस्मिक रिक्ति या एक या दो सदस्यों की अनुपस्थिति के आधार पर किसी रीति में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

धारा 22ड का
संशोधन ।

स्पष्टीकरण 1—इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए,—

(अ) “संस्थान का सदस्य” के अन्तर्गत वह व्यक्ति है जो अभिकथित अवचार की तारीख को संस्थान का सदस्य था, यद्यपि वह जांच के समय संस्थान का सदस्य नहीं था;

(आ) संस्थान में रजिस्ट्रीकृत “फर्म” भी किसी सदस्य के अवचार के लिए दायी ठहरायी जाएगी जो अभिकथित अवचार की तारीख को इसका भागीदार या स्वामी था, यद्यपि वह जांच के समय ऐसा भागीदार या स्वामी नहीं था ।

स्पष्टीकरण 2—इस अध्याय के उपबंधों के अधीन की गई कोई कार्रवाई किसी केन्द्रीय सरकार के विभाग या राज्य सरकार या किसी कानूनी प्राधिकारी अथवा विनियामक निकाय को तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन संस्थान में रजिस्ट्रीकृत किसी सदस्य या फर्म के विरुद्ध कार्रवाई करने से नहीं रोकेगी ।’।

धारा 24 का
संशोधन ।

96. मूल अधिनियम की धारा 24 में,—

(क) “एक हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर, “एक लाख रुपए” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) “पांच हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर, “पांच लाख रुपए” शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 25 का
संशोधन ।

97. मूल अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (2) में,—

(i) “जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा” शब्दों के स्थान पर, “कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम नहीं होगा किंतु पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) “जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा” शब्दों के स्थान पर, “जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो दो लाख रुपए से कम नहीं होगा किंतु दस लाख रुपए तक का हो सकेगा” शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 26 का
संशोधन ।

98. मूल अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी,—

“(2) उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करने वाली कोई कम्पनी पहले उल्लंघन पर जुर्माने से दंडनीय होगी जो दो लाख रुपए से कम नहीं होगा किन्तु जो दस लाख रुपए तक हो सकेगा, तथा किसी पश्चातवर्ती उल्लंघन पर जुर्माने से दंडनीय होगी जो चार लाख रुपए से कम नहीं होगा किन्तु जो बीस लाख रुपए तक हो सकेगा ।”।

धारा 27 का
संशोधन ।

99. मूल अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (2) में,—

(क) “पांच हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर, “एक लाख रुपए” शब्द रखे

जाएंगे ;

(ख) “एक लाख रुपए” शब्दों के स्थान पर, “पांच लाख रुपए” शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) “दस हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर, “दो लाख रुपए” शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) “दो लाख रुपए” शब्दों के स्थान पर, “दस लाख रुपए” शब्द रखे जाएंगे ।

100. मूल अधिनियम की धारा 29ख में, खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

धारा 29ख का संशोधन ।

“(घ) संस्थान या फर्मों के सदस्यों द्वारा विभिन्न कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं के अननुपालन के मामलों, जो उसके द्वारा उनके पुनर्विलोकन के दौरान ध्यान में आए हों, को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उनकी परीक्षा के लिए अनुशासन निदेशालय को अग्रेषित करना ।”।

101. मूल अधिनियम की धारा 34 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

धारा 34 का संशोधन ।

1949 का 38

“34. चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 9क के अधीन गठित समन्वयन समिति इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए समन्वयन समिति समझी जाएगी ।”।

समन्वयन समिति।

102. मूल अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) में, “रजिस्टर” शब्द के स्थान पर, “सदस्यों के रजिस्टर” शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 38 का संशोधन ।

103. मूल अधिनियम की धारा 38क की उपधारा (2) में, खंड (ग) और खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

धारा 38क का संशोधन ।

“(ग) धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन कोई सूचना या परिवाद फाइल करने का प्ररूप, रीति और फीस उपधारा (2) के अधीन किसी जानकारी या शिकायत या कार्रवाई योग्य के होने या कार्रवाई योग्य न होने के रूप में विनिश्चय करने की रीति और उपधारा (7) के अधीन अन्वेषण की प्रक्रिया ;

(घ) धारा 21क की उपधारा (2) के अधीन अनुशासन बोर्ड द्वारा मामलों पर विचार करते समय प्रक्रिया, उपधारा (7) के अधीन शास्ति के संदाय की समयसीमा ;

(घक) धारा 21ख की उपधारा (2) के अधीन अनुशासन समिति द्वारा मामलों पर विचार करते समय प्रक्रिया, उपधारा (7) के अधीन शास्ति के संदाय की समयसीमा ;”।

104. मूल अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (2) में,—

धारा 39 का संशोधन ।

(i) “रजिस्टर”, शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वह आता है, “सदस्यों के रजिस्टर”, शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(चक) धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन वे परिस्थितियां जिनके अधीन व्यवसाय प्रमाणपत्र रद्द किए जा सकेंगे ;

(चख) धारा 12 की उपधारा (2ख) के अधीन परिषद् के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य ;”;

(iii) खंड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(जक) धारा 15 की उपधारा (2) के खंड (ड) के अधीन व्यवसाय प्रमाणपत्र अनुदत्त या अस्वीकृत करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त ;”;

(iv) खंड (ट) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(टक) धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन परिषद् के सचिव और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति, शक्तियां, कर्तव्य, कृत्य, वेतन, फीस, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;”;

(v) खंड (ड) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(डक) धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन लेखों का अनुरक्षण, उपधारा (4) के अधीन वार्षिक विवरण तैयार करने की रीति और उपधारा (5) के अधीन परिषद् के वार्षिक लेखों को तैयार करने की रीति ;”;

(vi) खंड (त) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

(त) धारा 20क के अधीन किसी फर्म को रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने के लिए आवेदन करने की रीति और ऐसे रजिस्ट्रीकरण के निबंधन और शर्तें ;

(तक) फर्मों के रजिस्टर और अन्य विशिष्टियां अनुरक्षित करने की रीति जिसके अन्तर्गत धारा 20ख की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन कार्रवाई योग्य सूचना या परिवाद या किसी फर्म के विरुद्ध अधिरोपित किसी शास्ति के अधिरोपण के ब्यौरे, और वह रीति जिसमें उपधारा (3) के अधीन संस्थान में रजिस्ट्रीकृत फर्मों की वार्षिक सूची प्रकाशित की जाएगी ;

(तख) धारा 21 की उपधारा (9) के अधीन अनुयोज्य सूचना तथा परिवादों की प्रास्थिति और पारित आदेश उपलब्ध करवाने की रीति ;

(तग) धारा 21क की उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन व्यक्तियों का पैनल तैयार करने की रीति और धारा 21क की उपधारा (8) के अधीन अनुशासन बोर्ड के पीठासीन अधिकारियों और सदस्यों को संदेय भत्ते ;

(तघ) धारा 21ख की उपधारा (1) के खंड (क) खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन व्यक्तियों का पैनल तैयार करने की रीति और उपधारा (8) के अधीन अनुशासन बोर्ड के तथा धारा 21ख की उपधारा (4) के अधीन अनुशासनिक समितियों के पीठासीन अधिकारियों तथा सदस्यों को संदेय भत्ते ।”।

(तड) धारा 22 घ की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारिवृंद के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें ;

105. मूल अधिनियम की पहली अनुसूची के शीर्ष में, “धारा 21(3), धारा 21क(3)”, शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर, “धारा 21(6), धारा 21क(5) और (6), धारा 21ख (5) और (6)”, शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ।

पहली अनुसूची
का संशोधन ।

106. मूल अधिनियम की दूसरी अनुसूची में,—

दूसरी अनुसूची
का संशोधन ।

(i) “धारा 21(3), धारा 21क(3)”, शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर, “धारा 21(6), धारा 21ख (5) और (6)”, शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) भाग 1 के मद (3) में, “यह विश्वास हो जाए कि वह” शब्दों के स्थान पर, “यह विश्वास हो जाए कि वह या उसकी फर्म” शब्द रखे जाएंगे ।

संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2022

(2022 का अधिनियम संख्यांक 20)

[24 दिसम्बर, 2022]

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 और संविधान
(अनुसूचित जनजातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहतरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित
जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2022 है ।

संक्षिप्त नाम ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

परिभाषाएं ।

(क) “अनुसूचित जातियां आदेश” से संविधान (अनुसूचित जातियां)
आदेश, 1950 अभिप्रेत है;

(ख) “अनुसूचित जनजातियां आदेश” से संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (उत्तर
प्रदेश) आदेश, 1967 अभिप्रेत है ।

अनुसूचित जातियां
आदेश का
संशोधन ।

3. अनुसूचित जातियां आदेश का पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में और परिमाण तक संशोधन किया जाता है ।

अनुसूचित
जनजातियां आदेश
का संशोधन ।

4. अनुसूचित जनजातियां आदेश का दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में और परिमाण तक संशोधन किया जाता है ।

पहली अनुसूची

(धारा 3 देखिए)

संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश, 1950 (सं.आ.19) की अनुसूची के भाग 18—
उत्तर प्रदेश की प्रविष्टि 36 में, “मिर्जापुर और सोनभद्र” शब्दों के स्थान पर “मिर्जापुर,
सोनभद्र, संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली और भदोही” शब्द रखे जाएंगे ।

दूसरी अनुसूची

(धारा 4 देखिए)

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 (सं.आ. 78) की अनुसूची की प्रविष्टि 6 में, “मिर्जापुर और सोनभद्र” शब्दों के स्थान पर “मिर्जापुर, सोनभद्र, संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली और भदोही” शब्द रखे जाएंगे ।

नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र (संशोधन) अधिनियम, 2022

(2022 का अधिनियम संख्यांक 23)

[30 दिसम्बर, 2022]

नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र
अधिनियम, 2019 का संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र (संशोधन) अधिनियम, 2022 है ।

संक्षिप्त नाम और
प्रारम्भ ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

वृहत् नाम का संशोधन ।	2. नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अधिनियम, 2019 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) के वृहत् नाम में, “नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र” शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, “भारत अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र” शब्द रखे जाएंगे ।	2019 का 17
उद्देशिका का संशोधन ।	3. मूल अधिनियम की उद्देशिका में, “नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र” शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, “भारत अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र” शब्द रखे जाएंगे ।	
धारा 1 का संशोधन ।	4. मूल अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (1) में, “नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र” शब्दों के स्थान पर, “भारत अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र” शब्द रखे जाएंगे ।	
धारा 2 का संशोधन ।	5. मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (क) में, “नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र” शब्दों के स्थान पर, “भारत अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र” शब्द रखे जाएंगे ।	
अध्याय शीर्ष का संशोधन ।	6. मूल अधिनियम के अध्याय 2 के अध्याय शीर्ष में, “नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र” शब्दों के स्थान पर, “भारत अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र” शब्द रखे जाएंगे ।	
धारा 3 का संशोधन ।	7. मूल अधिनियम की धारा 3 में,— (i) पार्श्व शीर्ष में, “नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र” शब्दों के स्थान पर, “भारत अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र” शब्द रखे जाएंगे ; (ii) उपधारा (1) में, “नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र” शब्दों के स्थान पर, “भारत अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र” शब्द रखे जाएंगे ।	
धारा 4 का संशोधन ।	8. मूल अधिनियम की धारा 4 में,— (i) पार्श्व शीर्ष में, “नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र” शब्दों के स्थान पर, “भारत अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र” शब्द रखे जाएंगे ; (ii) उपधारा (1) में, “नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र” शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, “भारत अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र” शब्द रखे जाएंगे ।	
धारा 15 का संशोधन ।	9. मूल अधिनियम की धारा 15 में, खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :— “(क) अंतरराष्ट्रीय और घरेलू दोनों, माध्यस्थम् और अन्य प्रकार के विकल्पी विवाद समाधान तंत्रों के संचालन ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, को सुकर बनाने ;”।	
धारा 20 का संशोधन ।	10. मूल अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (5) के परन्तुक में, “आवेदन” शब्द, दोनों स्थानों पर, जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर “प्रश्न” शब्द रखा जाएगा ।	
धारा 23 का संशोधन ।	11. मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) के खंड (क) में, “केन्द्र” शब्द के स्थान पर “सचिवालय” शब्द रखा जाएगा ।	

12. मूल अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (3) में, “निधि का उपयोग सदस्यों” शब्दों के पश्चात्, “, रजिस्ट्रार, परामर्शी और केंद्रीय सरकार के अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे । धारा 25 का संशोधन ।
13. मूल अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (1) में, “केंद्र एक माध्यस्थम् चैंबर की स्थापना करेगा, जो मध्यस्थों के एक स्थायी पैनल को बनाए रखने के लिए मध्यस्थों को पैनलबद्ध करेगा और साथ ही विख्यात मध्यस्थों के पैनल में प्रविष्टि हेतु आवेदनों की संवीक्षा करेगा ।” शब्दों के स्थान पर, “केंद्र, मध्यस्थों के एक स्थायी पैनल को बनाए रखने के लिए मध्यस्थों का पैनल बनाने और साथ ही विख्यात मध्यस्थों के पैनल में प्रविष्टि हेतु आवेदनों की संवीक्षा करने के लिए एक माध्यस्थम् चैंबर की स्थापना करेगा ।” शब्द रखे जाएंगे । धारा 28 का संशोधन ।
14. मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (2) में, खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :— धारा 31 का संशोधन ।
- “(क) धारा 15 के खंड (क) के अधीन, माध्यस्थम् और अन्य प्रकार के विकल्पी विवाद समाधान तंत्र के संचालन की रीति ;
- (कक) समय और स्थान तथा बैठकों में समिति के कार्य संचालन के संबंध में अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया के नियम जिसके अन्तर्गत धारा 19 की उपधारा (3) के अधीन गणपूर्ति भी है ;”।
15. मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (1) के परंतुक में, “दो वर्ष” शब्दों के स्थान पर, “पांच वर्ष” शब्द रखे जाएंगे । धारा 34 का संशोधन ।

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2022 (2023 का अधिनियम संख्यांक 1)

[2 जनवरी, 2023]

तमिलनाडु राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची को उपांतरित
करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां)
आदेश, 1950 का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश
(दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2022 है ।

संक्षिप्त नाम ।

2. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची के भाग 14—
तमिलनाडु में, प्रविष्टि 36 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी,
अर्थात् :—

संविधान
(अनुसूचित
जनजातियां)
आदेश, 1950 का
संशोधन ।

“37. नरिकुरवन, कुरुविकारन ।”

संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश (चौथा संशोधन) अधिनियम, 2022

(2023 का अधिनियम संख्यांक 2)

[2 जनवरी, 2023]

कर्नाटक राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची को
उपांतरित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ)
आदेश, 1950 का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश
(चौथा संशोधन) अधिनियम, 2022 है ।

संक्षिप्त नाम।

2. संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश, 1950 की अनुसूची के भाग 6—
कर्नाटक में, प्रविष्टि 16 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

संविधान
(अनुसूचित
जनजातियाँ)
आदेश, 1950
का संशोधन ।

“16. काडू कुरुबा, बेट्टा-कुरुबा ।”

वित्त अधिनियम, 2023

(2023 का अधिनियम संख्यांक 8)

[31 मार्च, 2023]

वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए केन्द्रीय सरकार
की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वित्त अधिनियम, 2023 है ।

(2) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय,—

(क) धारा 2 से धारा 127, 1 अप्रैल, 2023 को प्रवृत्त होंगी ;

(ख) धारा 128 से धारा 163, उस तारीख को प्रवृत्त होंगी, जो केंद्रीय सरकार
राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

संक्षिप्त नाम
और प्रारंभ ।

अध्याय 2

आय-कर की दरें

आय-कर ।

2. (1) उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, 1 अप्रैल, 2023 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए आय-कर, पहली अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट दरों से प्रभारित किया जाएगा और ऐसे कर में, प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

(2) उन दशाओं में, जिनमें पहली अनुसूची के भाग 1 का पैरा क लागू होता है, जहां निर्धारित की, पूर्ववर्ष में, कुल आय के अतिरिक्त, पांच हजार रुपए से अधिक कोई शुद्ध कृषि-आय है, और कुल आय दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक हो जाती है वहां,—

(क) शुद्ध कृषि-आय को, कुल आय के संबंध में केवल आय-कर प्रभारित करने के प्रयोजन के लिए, खंड (ख) में उपबंधित रीति से हिसाब में लिया जाएगा, (अर्थात् मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय के प्रथम दो लाख पचास हजार रुपए के पश्चात् कुल आय में समाविष्ट हो, किंतु कर के दायित्वाधीन न हो) ; और

(ख) प्रभार्य आय-कर निम्नानुसार संगणित किया जाएगा, अर्थात् :—

(i) कुल आय और शुद्ध कृषि-आय संकलित की जाएगी और आय-कर की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दर पर संकलित आय के संबंध में ऐसे अवधारित की जाएगी मानो ऐसी संकलित आय कुल आय थी ;

(ii) शुद्ध कृषि-आय में दो लाख पचास हजार रुपए की राशि बढ़ा दी जाएगी और इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय के संबंध में आय-कर की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी, मानो इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय कुल आय हो ;

(iii) उपखंड (i) के अनुसार अवधारित आय-कर की रकम में से उपखंड (ii) के अनुसार अवधारित आय-कर की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय के संबंध में आय-कर होगी :

परन्तु पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क की मद (ii) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष का या उससे अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है, इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो “दो लाख पचास हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर, “तीन लाख रुपए” शब्द रखे गए हों :

परन्तु यह और कि पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क की मद (iii) में निर्दिष्ट, प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है, इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो “दो लाख पचास हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर, “पांच लाख रुपए” शब्द रखे गए हों ।

(3) उन दशाओं में, जिनमें आय-कर अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् आय-कर अधिनियम कहा गया है) के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115अख या धारा 115अग या अध्याय 12चक या अध्याय 12चख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के उपबंध लागू होते हैं, प्रभार्य कर का अवधारण, उस अध्याय या उस धारा में यथाउपबंधित रीति से, और, यथास्थिति, उपधारा (1) द्वारा अधिरोपित दरों के या उस अध्याय या उस धारा में विनिर्दिष्ट दरों के प्रति निर्देश से किया जाएगा :

1961 का 43

परन्तु आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, पहली अनुसूची के भाग 1 के, यथास्थिति, पैरा क, पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ और पैरा ङ में यथाउपबंधित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा, सिवाय उस देशी कंपनी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है या उस सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकघ के अधीन कर से प्रभार्य है :

परन्तु यह और कि किसी ऐसी आय के संबंध में, जो आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा 115कख, धारा 115कग, धारा 115कगक, धारा 115कघ, धारा 115ख, धारा 115खक, धारा 115खख, धारा 115खखक, धारा 115खखग, धारा 115खखच, धारा 115खखछ, धारा 115खखज, धारा 115खखझ, धारा 115ङ, धारा 115ञख या धारा 115ञग के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम में,—

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों का संगम, ऐसे व्यक्तियों के संगम के मामले के सिवाय जो उसके सदस्य के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बना है या व्यष्टि निकाय, चाहे निगमित हो या न हो, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ के अधीन कोई आय नहीं है, की दशा में, जहां,—

(i) कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(iii) कुल आय दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ; और

(iv) कुल आय पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से ;

(ख) प्रत्येक व्यष्टि या व्यक्तियों का संगम, ऐसे व्यक्तियों का संगम के मामले के सिवाय, जो उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बना है या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या न हो, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ के अधीन आय है,—

(i) कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(iii) कुल आय (लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय को छोड़कर) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ; और

(iv) कुल आय (लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय को छोड़कर) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से ; और

(v) कुल आय (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय सम्मिलित है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु जो उपखंड (iii) और उपखंड (iv) के अधीन नहीं आती है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से,

संगणित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु उस दशा में, जहां कुल आय में, जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रभार्य आय सम्मिलित है, आय के उस भाग के संबंध में संगणित आय-कर की रकम पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ;

(ग) व्यक्तियों का संगम जो इसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बना है, की दशा में,—

(i) जहां कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अनधिक है, वहां ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से;

(ii) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, वहां ऐसी आय के पन्द्रह प्रतिशत की दर से, संगणित किया जाएगा;

(घ) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, सिवाय ऐसी सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकघ के अधीन कर से प्रभार्य है,—

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है किंतु दस करोड़ रुपए से अनधिक है, वहां ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है वहां ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से;

(ङ) प्रत्येक फर्म या स्थानीय प्राधिकारी की दशा में जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है वहां ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से;

(च) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, सिवाय ऐसी देशी कंपनी के, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है,—

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अनधिक है, ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(छ) देशी कंपनी से भिन्न, प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए

से अनधिक है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

संगणित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु यह भी कि उपरोक्त (क) और (ख) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिसकी कुल आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय,—

(i) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, पचास लाख रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो पचास लाख रुपए से अधिक है ;

(ii) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है ;

(iii) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दो करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो दो करोड़ रुपए से अधिक है ;

(iv) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम पांच करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो पांच करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु यह भी कि उपरोक्त (ग) में वर्णित व्यक्तियों के संगम की दशा में, जिनकी कुल आय आय-कर अधिनियम की धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य है,—

(i) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम पचास लाख रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो पचास लाख रुपए से अधिक है ;

(ii) एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु यह भी कि उपरोक्त (घ) में वर्णित सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय,—

(i) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय या आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है ;

(ii) दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो दस करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु यह भी कि उपरोक्त (ड) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिसकी कुल आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय, एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु यह भी कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय आय-कर अधिनियम की धारा 115जख के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु यह भी कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115जख के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो दस करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115खखड की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम को ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु यह भी कि ऐसी प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम को ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु यह भी कि ऐसे प्रत्येक व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम को, पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क में यथा उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु यह भी कि ऐसी प्रत्येक निवासी सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकघ के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम को ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

(4) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 92गड की उपधारा (2क) या धारा 115थक या धारा 115नघ के अधीन प्रभारित और संदत्त किया जाना है, कर उन धाराओं में यथा विनिर्दिष्ट दर से प्रभारित और संदत्त किया जाएगा और उसमें ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

(5) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 193, धारा 194क,

धारा 194ख, धारा 194खक, धारा 194खख, धारा 194घ, धारा 194ठखक, धारा 194ठखख, धारा 194ठखग और धारा 195 के अधीन, प्रवृत्त दरों से काटा जाना है, उनमें कटौतियां पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट दरों से की जाएगी और उन मामलों में, जहां कहीं विहित किया गया हो, उसमें उपबंधित रीति से परिकल्पित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा।

(6) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 192क, धारा 194, धारा 194ग, धारा 194घक, धारा 194ङ, धारा 194ङङ, धारा 194च, धारा 194छ, धारा 194ज, धारा 194झ, धारा 194झक, धारा 194झख, धारा 194झग, धारा 194ज, धारा 194ठक, धारा 194ठख, धारा 194ठखक, धारा 194ठखख, धारा 194ठखग, धारा 194ठग, धारा 194ठघ, धारा 194ट, धारा 194ड, धारा 194ढ, धारा 194ण, धारा 194थ, धारा 194द, धारा 194ध, धारा 196क, धारा 196ख, धारा 196ग और धारा 196घ के अधीन काटा जाना है, कटौतियां उन धाराओं में विनिर्दिष्ट दरों से की जाएगी और उसमें,—

(क) प्रत्येक व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम, इसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनी से मिलकर बने व्यक्तियों के संगम की दशा के सिवाय, या व्यक्ति-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो अनिवासी है, इस अधिनियम की धारा 196घ के अधीन लाभान्श के रूप में आय की कटौती की दशा के सिवाय,—

(i) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से ;

(iii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

(iv) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से :

परंतु जहां ऐसे व्यक्ति की आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है, वहां अधिभार की दर पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ;

(ख) प्रत्येक व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम, उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बने व्यक्तियों के संगम की दशा के सिवाय, या व्यक्ति-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो अनिवासी है, आय-कर अधिनियम की धारा 196घ के अधीन लाभान्श के रूप में आय की कटौती की दशा में,—

(i) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से ;

(ग) उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बने व्यक्तियों के संगम की दशा में, जो अनिवासी है,—

(i) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से ;

(घ) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, जो अनिवासी है, की दशा में,—

(i) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के सात प्रतिशत की दर से;

(ii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए दस करोड़ रुपए से अधिक है, वहां ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ङ) प्रत्येक फर्म की दशा में, जो अनिवासी है, जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, वहां ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित की जाएगी ;

(च) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(i) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(7) उन दशाओं में, जिनमें कर का संग्रहण, आय-कर अधिनियम की धारा 194ख के परन्तुक के अधीन किया जाना है, ऐसा संग्रहण, पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट दरों से किया जाएगा और उन दशाओं में, जहां कहीं विहित किया गया हो, उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(8) उन दशाओं में, जिनमें कर का संग्रहण, आय-कर अधिनियम की धारा 206ग के अधीन किया जाना है, ऐसा संग्रहण, उस धारा में विनिर्दिष्ट दरों से किया जाएगा और उसमें,—

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बने व्यक्तियों के संगम की दशा के सिवाय व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो अनिवासी है, जहां,—

(i) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संगृहीत किया गया है या जिनके संगृहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संगृहीत किया गया है या जिनके संगृहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से ;

(iii) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संगृहीत किया गया है या जिनके संगृहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

(iv) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संगृहीत किया गया है या जिनके संगृहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से :

परंतु जहां ऐसे व्यक्ति की आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है, वहां अधिभार की दर पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ;

(ख) व्यक्तियों के संगम जो उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बना है, संगम की दशा में, जो अनिवासी है,—

(i) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संगृहीत किया गया है या जिनके संगृहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संगृहीत किया गया है या जिनके संगृहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(ग) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, जो अनिवासी है, की दशा में,—

(i) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संगृहीत किया गया है या जिनके संगृहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के सात प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संगृहीत किया गया है या जिनके संगृहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(घ) प्रत्येक फर्म की दशा में, जो अनिवासी है, जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों

का योग, जिन्हें संगृहीत किया गया है या जिनके संगृहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ड) देशी कंपनी से भिन्न, प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(i) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संगृहीत किया गया है या जिनके संगृहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संगृहीत किया गया है या जिनके संगृहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(9) उपधारा (10) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उन दशाओं में, जिनमें आय-कर, प्रवृत्त दर या दरों से, आय-कर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) या धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित किया जाना है या उक्त अधिनियम की धारा 192 के अधीन "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय में से काटा जाना है, या उस पर संदत्त किया जाना है या उक्त अधिनियम की धारा 194त के अधीन कटौती की जानी है अथवा उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की संगणना की जानी है, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर", पहली अनुसूची के भाग 3 में विनिर्दिष्ट दर या दरों से इस प्रकार प्रभारित किया जाएगा, काटा जाएगा या संगणित किया जाएगा और ऐसे कर में, प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु उन दशाओं में, जिनमें आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115अख या धारा 115अग या अध्याय 12चक या अध्याय 12चख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के उपबंध लागू होते हैं, "अग्रिम कर" की संगणना, यथास्थिति, इस उपधारा द्वारा अधिरोपित दरों के या उस अध्याय या धारा में विनिर्दिष्ट दरों के प्रति निर्देश से की जाएगी :

परन्तु यह और कि आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित "अग्रिम कर" की रकम में, पहली अनुसूची के भाग 3 के, यथास्थिति, पैरा क, पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ और पैरा ड में यथा उपबंधित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा, सिवाय किसी देशी कंपनी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है, किसी व्यक्ति या अविभक्त हिंदू कुटुंब या व्यक्तियों के संगम या व्यष्टियों के निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जिसकी आय आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है, या किसी निवासी सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकघ के अधीन या धारा 115खकड के अधीन कर से प्रभार्य है :

परन्तु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा 115कख,

धारा 115कग, धारा 115कगक, धारा 115कघ, धारा 115ख, धारा 115खक, धारा 115खख, धारा 115खखक, धारा 115खखग, धारा 115खखच, धारा 115खखछ, धारा 115खखज, धारा 115खखझ, 115खखज, धारा 115ङ, धारा 115जख या धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में पहले परन्तुक के अधीन संगणित “अग्रिम कर” में,—

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बने व्यक्तियों के संगम की दशा में, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जिसकी आय आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ के अधीन कोई आय नहीं है और जिसकी कोई ऐसी आय नहीं है जो धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है, जहां,—

(i) जहां कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे “अग्रिम कर” के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे “अग्रिम कर” के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(iii) जहां कुल आय दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे “अग्रिम कर” के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

(iv) जहां कुल आय पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे “अग्रिम कर” के सैंतीस प्रतिशत की दर से ;

(ख) प्रत्येक व्यष्टि या उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बने व्यक्तियों के संगम की दशा में के सिवाय, या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ के अधीन कोई आय है और जिसकी कोई ऐसी आय नहीं है जो धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है, जहां,—

(i) जहां कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे “अग्रिम कर” के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे “अग्रिम कर” के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(iii) जहां कुल आय (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय सम्मिलित नहीं है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे “अग्रिम कर” के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

(iv) जहां कुल आय (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय सम्मिलित नहीं है) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे “अग्रिम कर” के सैंतीस प्रतिशत की दर से ;

(v) जहां कुल आय (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय सम्मिलित है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु जो उपखंड (iii) और

उपखंड (iv) के अंतर्गत नहीं आती है, ऐसे “अग्रिम कर” के पन्द्रह प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु उस दशा में, जहां कुल आय में लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय सम्मिलित है, वहां आय के उस भाग पर संगणित अग्रिम कर पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह और कि किसी व्यक्ति की कुल आय जो आय-कर अधिनियम की धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट निधि है, जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन कोई आय सम्मिलित है, आय के उस भाग पर संगणित अग्रिम कर को किसी अधिभार द्वारा नहीं बढ़ाया जाएगा ;

(ग) उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बने व्यक्तियों के संगम की दशा में,—

(i) जहां कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे “अग्रिम कर” के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे “अग्रिम कर” के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(घ) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, ऐसी सहकारी सोसाइटी के सिवाय, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकघ और धारा 115खकड के अधीन कर से प्रभार्य है, की दशा में,—

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे “अग्रिम कर” के सात प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे “अग्रिम कर” के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ङ) प्रत्येक फर्म या स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे “अग्रिम कर” के बारह प्रतिशत की दर से ;

(च) प्रत्येक देशी कंपनी, ऐसी देशी कंपनी के सिवाय, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है, की दशा में,—

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे “अग्रिम कर” के सात प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे “अग्रिम कर” के बारह प्रतिशत की दर से ;

(छ) देशी कंपनी से भिन्न, प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे “अग्रिम कर” के दो प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे “अग्रिम कर” के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु यह भी कि उपरोक्त (क) और (ख) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115अग के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय,—

(क) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम पचास लाख रुपए की कुल आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो पचास लाख रुपए से अधिक है ;

(ख) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है ;

(ग) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम दो करोड़ रुपए की कुल आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो दो करोड़ रुपए से अधिक है ;

(घ) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम पांच करोड़ रुपए की कुल आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो पांच करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु उपरोक्त (ग) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115अग के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय,—

(क) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम पचास लाख रुपए की कुल आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो पचास लाख रुपए से अधिक है ;

(ख) एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु उपरोक्त (घ) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी आय-कर अधिनियम की धारा 115अग के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय,—

(क) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है ;

(ख) दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम दस करोड़ रुपए की कुल आय पर

“अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो दस करोड़ रुपए से अधिक है ;

परन्तु उपरोक्त (ड) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115अग के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु यह भी कि ऐसी प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115अख के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु यह भी कि ऐसी प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115अख के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम दस करोड़ रुपए की कुल आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो दस करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115खखड की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन कर से प्रभार्य पहले परन्तुक के अधीन संगणित “अग्रिम कर” को ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु यह भी कि ऐसी प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है, पहले परन्तुक के अधीन संगणित “अग्रिम कर को” ऐसे “अग्रिम कर” के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य आय के संबंध में, पहले परन्तुक के अनुसार संगणित “अग्रिम कर”, संघ के प्रयोजनों के लिए व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों के संगम या व्यष्टियों के निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में संगणित अधिभार द्वारा बढ़ा दिया जाएगा,—

(i) पांच लाख रुपए से अधिक किंतु एक करोड़ रुपए से अनधिक कुल आय वाले, (आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय सहित), “ऐसे अग्रिम कर के दस प्रतिशत की दर पर” ;

(ii) एक करोड़ रुपए से अधिक किंतु दो करोड़ रुपए से अनधिक कुल आय वाले, (आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय सहित), “ऐसे अग्रिम कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर पर” ;

(iii) दो करोड़ रुपए से अधिक कुल आय वाले, (आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय को छोड़कर), “ऐसे अग्रिम कर के बीस प्रतिशत की दर पर” ; और

(iv) दो करोड़ रुपए से अधिक कुल आय वाले, किंतु ऊपर खंड (iii) के अंतर्गत नहीं आने वाले (आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय सहित), “ऐसे अग्रिम कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर पर” :

परंतु यह भी कि जहां धारा 115खकग की उपधारा (1क) के उपबंध लागू होने की दशा में तथा कुल आय के अंतर्गत आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन प्रभार्य लाभांश या आय के माध्यम से कोई आय भी है, आय के उस भाग के संबंध में “अग्रिम कर” पर अधिभार की दर है, पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगा :

परंतु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी विनिर्दिष्ट निधि की दशा में, जिसकी आय, धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है और जहां ऐसी आय में आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन कोई आय सम्मिलित है, आय के उस भाग पर संगणित अग्रिम कर को किसी अधिभार द्वारा नहीं बढ़ाया जाएगा :

परंतु यह भी कि केवल कंपनियों के इसके सदस्यों से मिलकर बने व्यक्तियों के संगम की दशा में तथा धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन प्रभार्य आय पर, “अग्रिम कर” पर अधिभार की दर भी है, पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगा :

परन्तु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट ऐसे प्रत्येक व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों के संगम या व्यष्टियों के निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, या प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय निम्नलिखित से अधिक है,—

(क) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम पचास लाख रुपए की कुल आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो पचास लाख रुपए से अधिक है ;

(ख) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है ;

(ग) दो करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम दो करोड़ रुपए की कुल आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो दो करोड़ रुपए से अधिक है ;

परन्तु यह भी कि ऐसी प्रत्येक निवासी सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकघ या धारा 115खकड के अधीन कर से प्रभार्य है, पहले परंतुक के अनुसार संगणित आय-कर की रकम को ऐसे “अग्रिम कर” के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

(10) उन दशाओं में, जिनमें पहली अनुसूची के भाग 3 का पैरा ‘क’ लागू होता है या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति या

हिंदू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों के संगम या व्यष्टियों के निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं या प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जो एक निवासी है, की दशा में, जिसकी आय आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है, जहां निर्धारिती ने पूर्ववर्ष में या, यदि आय-कर अधिनियम के किसी उपबंध के आधार पर आय-कर पूर्ववर्ष से भिन्न किसी अवधि की आय के संबंध में प्रभारित किया जाना है, ऐसी अन्य अवधि में कुल आय के अतिरिक्त पांच हजार रुपए से अधिक कोई शुद्ध कृषि-आय भी है और कुल आय दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक है, वहां प्रवृत्त दर या दरों से, उक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन आय-कर प्रभारित करने में अथवा उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय “अग्रिम कर” की संगणना करने में,—

(क) शुद्ध कृषि-आय को, कुल आय के संबंध में, केवल यथास्थिति, ऐसा आय-कर या “अग्रिम कर” प्रभारित या संगणित करने के प्रयोजन के लिए, खंड (ख) में उपबंधित रीति से हिसाब में लिया जाएगा, मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय के प्रथम दो लाख पचास हजार रुपए के पश्चात् कुल आय में समाविष्ट हो, किंतु कर के दायित्वाधीन न हो ; और

(ख) यथास्थिति, ऐसा आय-कर या “अग्रिम कर” निम्नलिखित रीति से प्रभारित या संगणित किया जाएगा, अर्थात् :-

(i) कुल आय और शुद्ध कृषि-आय को संकलित किया जाएगा और संकलित आय के संबंध में आय-कर या “अग्रिम कर” की रकम, उक्त पैरा क या धारा 115खकग की उपधारा (1क) में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो ऐसी संकलित आय कुल आय हो ;

(ii) शुद्ध कृषि-आय में दो लाख पचास हजार रुपए की राशि बढ़ा दी जाएगी और इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय के संबंध में आय-कर या “अग्रिम कर” की रकम, उक्त पैरा क या धारा 115खकग की उपधारा (1क) में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी, मानो शुद्ध कृषि-आय, कुल आय हो ;

(iii) उपखंड (i) के अनुसार अवधारित आय-कर या “अग्रिम कर” की रकम में से उपखंड (ii) के अनुसार अवधारित, यथास्थिति, आय-कर या “अग्रिम कर” की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय के संबंध में, यथास्थिति, आय-कर या “अग्रिम कर” होगी :

परन्तु ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा क की मद (II) में निर्दिष्ट भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या उससे अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम की आयु का है, इस उपधारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो “दो लाख पचास हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर, “तीन लाख रुपए” शब्द रखे गए हों :

परन्तु यह और कि ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा क की मद (III) में निर्दिष्ट भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक की आयु का है, इस उपधारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो “दो लाख पचास हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर, “पांच लाख रुपए” शब्द रखे गए हों :

परन्तु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में

निर्दिष्ट प्रत्येक व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों के संगम या व्यष्टियों के निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं या प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति, की दशा में जो निवासी है, जिसकी आय आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के उपबंधों का वैसे ही प्रभाव होगा मानो “दो लाख पचास हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर, “तीन लाख रुपए” शब्द रख दिए गए हों :

परंतु यह भी कि इस प्रकार संकलित आय-कर या “अग्रिम कर” की रकम पर, प्रत्येक दशा में परिकलित अधिभार इस धारा में उपबंधित रीति में, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ;

(11) उपधारा (1) से उपधारा (3) में यथा विनिर्दिष्ट और उसमें उपबंधित रीति से परिकलित, संघ के प्रयोजनों के लिए, अधिभार द्वारा बढ़ाई गई आय-कर की रकम को, ऐसे आय-कर और अधिभार पर चार प्रतिशत की दर से परिकलित “आय-कर पर स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर” नाम से ज्ञात, अतिरिक्त अधिभार द्वारा संघ के प्रयोजनों के लिए और बढ़ा दिया जाएगा, जिससे सार्वत्रिक स्तर की क्वालिटी की स्वास्थ्य सेवाओं तथा बुनियादी शिक्षा और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपलब्ध और उसका वित्तपोषण करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके ।

(12) उपधारा (4) से उपधारा (10) में यथा विनिर्दिष्ट और उसमें उपबंधित रीति से परिकलित, संघ के प्रयोजनों के लिए, अधिभार द्वारा बढ़ाई गई आय-कर की रकम को, ऐसे आय-कर और अधिभार पर चार प्रतिशत की दर से परिकलित “आय-कर पर स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर” नाम से ज्ञात, अतिरिक्त अधिभार द्वारा संघ के प्रयोजनों के लिए और बढ़ा दिया जाएगा, जिससे सार्वत्रिक स्तर की क्वालिटी की स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी शिक्षा और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपलब्ध कराने और उसका वित्तपोषण करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात, उन दशाओं में लागू नहीं होगी, जिनमें उपधारा (5), उपधारा (6), उपधारा (7) और उपधारा (8) में उल्लिखित आय-कर अधिनियम की धाराओं के अधीन कर की कटौती या संग्रहण किया जाना है, यदि स्रोत पर कर की कटौती या स्रोत पर कर के संग्रहण के अधीन रहते हुए आय को देशी कंपनी और किसी अन्य व्यक्ति को, जो भारत में निवासी है, संदत्त किया जाता है :

परंतु यह और कि इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात, आय-कर अधिनियम की धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी विनिर्दिष्ट निधि के आय-कर की बाबत जैसा कि उपधारा (9) में विनिर्दिष्ट किया गया है, जिसकी संगणना आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट आय पर की गई है, लागू नहीं होगी ।

(13) इस धारा और पहली अनुसूची के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “देशी कंपनी” से कोई भारतीय कंपनी या कोई अन्य ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, जिसने 1 अप्रैल, 2023 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए, आय-कर अधिनियम के अधीन आय-कर के दायित्वाधीन अपनी आय के संबंध में ऐसी आय में से संदेय लाभांशों (जिनके अंतर्गत अधिमानी शेयरों पर लाभांश भी हैं) की घोषणा और भारत में उनके संदाय के लिए इंतजाम कर लिए हैं ;

(ख) “बीमा कमीशन” से बीमा कारबार (जिसके अन्तर्गत बीमा पालिसियों को जारी रखने, उनका नवीकरण या उन्हें पुनरुज्जीवित करने से संबंधित कारबार है) की

याचना करने या उसे उपाप्त करने के लिए कमीशन के रूप में या अन्यथा कोई पारिश्रमिक या इनाम अभिप्रेत है ;

(ग) किसी व्यक्ति के संबंध में, “शुद्ध कृषि-आय” से, पहली अनुसूची के भाग 4 में अंतर्विष्ट नियमों के अनुसार संगणित, उस व्यक्ति की किसी भी स्रोत से व्युत्पन्न कृषि-आय की कुल रकम अभिप्रेत है ;

(घ) अन्य सभी शब्दों या पदों के, जो इस धारा में या पहली अनुसूची में प्रयुक्त हैं, किन्तु इस उपधारा में परिभाषित नहीं हैं और आय-कर अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उनके उस अधिनियम में हैं ।

अध्याय 3

प्रत्यक्ष कर

आय-कर

धारा 2 का
संशोधन ।

3. आय-कर अधिनियम की धारा 2 में,—

(क) खंड (19ख) में “या आय-कर अपर आयुक्त (अपील)” शब्दों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा ;

(ख) खंड (24) में, उपखंड (xviiख) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड 1 अप्रैल, 2024 से अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“(xviiग) धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (xii) में निर्दिष्ट कोई राशि ;

“(xviiघ) धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (xiii) में निर्दिष्ट कोई राशि ;”;

(ग) उपधारा (28ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(28गक) “संयुक्त आयुक्त (अपील)” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन आय-कर संयुक्त आयुक्त (अपील) या आय-कर अपर आयुक्त (अपील) के रूप में नियुक्त किया गया है ;”;

(घ) खंड (37क) के उपखंड (ii) में, “194ख” अंकों और अक्षर के पश्चात् “194खक” अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ङ) खंड (42क) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (i) में, उपखंड (जज) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड, 1 अप्रैल, 2024 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(जझ) किसी ऐसी पूंजी आस्ति की दशा में,—

(क) जो धारा 47 के खंड (viiघ) में यथानिर्दिष्ट जमा किए गए स्वर्ण के संबंध में जारी कोई इलैक्ट्रानिक स्वर्ण प्राप्ति है, उसमें उस अवधि को सम्मिलित किया जाएगा, जिसके लिए ऐसे स्वर्ण को निर्धारिती द्वारा उसके इलैक्ट्रानिक स्वर्ण प्राप्ति के रूप में संपरिवर्तन से पूर्व धारित किया गया था ;

(ख) जो धारा 47 के खंड (viiघ) में यथानिर्दिष्ट इलैक्ट्रानिक स्वर्ण प्राप्ति के संबंध में जारी किया गया स्वर्ण है, उसमें उस अवधि को सम्मिलित किया जाएगा, जिसके लिए ऐसी इलैक्ट्रानिक स्वर्ण प्राप्ति को निर्धारिती द्वारा उसके स्वर्ण में संपरिवर्तन से पूर्व धारित किया गया था ।”।

धारा 9 का
संशोधन ।

4. आय-कर अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (viii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2024 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(viii) भारत से बाहर उद्भूत होने वाली कोई आय, जो धारा 2 के खंड (24) के उपखंड (xvii) में निर्दिष्ट कोई धनराशि है, जिसे भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा,—

(क) 5 जुलाई, 2019 को या उसके पश्चात् किसी अनिवासी को, जो कंपनी नहीं है या किसी विदेशी कंपनी को ; या

(ख) जिसे 1 अप्रैल, 2023 को या उसके पश्चात् किसी ऐसे व्यक्ति को, जो धारा 6 के खंड (6) के अर्थात्गत भारत में मामूली तौर पर निवासी नहीं है,

संदत्त किया गया है ।”।

5. आय-कर अधिनियम की धारा 10 में,—

धारा 10 का
संशोधन ।

1992 का 15

2019 का 50

1992 का 15

2019 का 50

(क) खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (i) की मद (I) में, “जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (वैकल्पिक विनिधान निधि) विनियम, 2012 के अधीन” शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, “जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (वैकल्पिक विनिधान निधि) विनियम, 2012 या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अधीन बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंध) विनियम, 2022 के अधीन विनियमित” शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (4ड) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड, 1 अप्रैल, 2024 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(4ड) निम्नलिखित के परिणामस्वरूप किसी अनिवासी भारतीय को उद्भूत हुई या प्राप्त कोई आय,—

(i) अपरिदेय अग्रिम संविदाओं या अपतटीय व्युत्पन्न लिखतों या ओवर-द-काउंटर व्युत्पन्नीय के अंतरण ; या

(ii) अपतटीय व्युत्पन्न लिखतों के वितरण,

जो किसी धारा 80ठक की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की अपतटीय बैंककारी यूनिट के साथ किया गया है, जो यथाविहित शर्तों को पूरा करता है ;

(ग) खंड (4छ) के स्थान पर, 1 अप्रैल, 2024 से निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“(4छ) किसी अनिवासी द्वारा निम्नलिखित से प्राप्त कोई आय,—

(i) प्रतिभूति पोर्टफोलियो या वित्तीय उत्पाद या ऐसे अनिवासी के निमित्त किसी पोर्टफोलियो प्रबंधक द्वारा प्रबंध की गई या प्रशासित निधियों ; या

(ii) ऐसे व्यक्ति द्वारा किए जा रहे ऐसे कार्यकलापों, जो केंद्रीय

सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किए जाएं,

के किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, जैसा कि धारा 80ठक की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट है, द्वारा किसी अपतटीय बैंककारी इकाई के पास रखे गए लेखे, उस सीमा तक, जिस तक ऐसी आय भारत से बाहर उद्भूत या उत्पन्न होती है और जिसे भारत में उद्भूत या उत्पन्न हुई नहीं समझा गया है।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, “पोर्टफोलियो प्रबंधक” का वही अर्थ होगा, जो उसका अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अधीन बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (पूँजी बाजार मध्यवर्ती) विनियम, 2021 के विनियम 2 के उपविनियम (1) के खंड (य) में है ;

2019 का 50

(4ज) किसी अनिवासी या धारा 80ठक की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, जो किसी वायुयान को पट्टे पर देने के मुख्य कारबार में लगा हुआ है, जो धारा 80ठक की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की किसी इकाई की देशी कंपनी है, जो मुख्यतः किसी वायुयान को पट्टे पर देने के कारबार में लगी हुई है, जिसने 31 मार्च, 2026 को या उससे पूर्व अपने प्रचालन प्रारंभ किए हैं, के साम्य शेरों के अंतरण से उद्भूत पूँजी लाभ के माध्यम से कोई आय :

परंतु इस खंड के उपबंध ऐसी देशी कंपनी के निम्नलिखित के भीतर आने वाले किसी निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्व वर्ष में साम्य शेरों के अंतरण से उद्भूत पूँजी अभिलाभ को लागू होंगे,—

(क) उस पूर्व वर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष से प्रारंभ होने वाले दस निर्धारण वर्ष की अवधि, जिसमें देशी कंपनी ने अपने प्रचालन आरंभ किए हैं ; या

(ख) 1 अप्रैल, 2024 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से आरंभ होने वाले दस निर्धारण वर्ष, जहां खंड (क) में निर्दिष्ट अवधि 1 अप्रैल, 2034 से पूर्व समाप्त हो जाती है।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, “वायुयान” से कोई वायुयान या हेलीकाप्टर या किसी वायुयान या हेलीकाप्टर का कोई इंजन या उसका कोई भाग, अभिप्रेत है ;’।

(घ) खंड (10घ) में,—

(i) दूसरे परंतुक में, “यथास्थिति, धारा 80ग की उपधारा (3क) या धारा 88 की उपधारा (2क) के स्पष्टीकरण” शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों के स्थान पर, “धारा 80ग की उपधारा (3क)” शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ii) छठवें परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2024 से, अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“परंतु यह भी कि इस खंड में अंतर्विष्ट कोई बात, 1 अप्रैल, 2023 को या उसके पश्चात् जारी किसी यूनिट संबद्ध बीमा पालिसी से भिन्न किसी जीवन बीमा पालिसी के संबंध में लागू नहीं होगी, यदि ऐसी पालिसी की अवधि के दौरान किसी पूर्ववर्ष के लिए संदेय प्रीमियम की

रकम पांच लाख रुपए से अधिक है :

परंतु यह भी कि यदि 1 अप्रैल, 2023 को या उसके पश्चात् जारी यूनिट संबद्ध बीमा पालिसी से भिन्न एक से अधिक जीवन बीमा पालिसी के लिए किसी व्यक्ति द्वारा प्रीमियम संदेय है, तो इस खंड के उपबंध यूनिट संबद्ध बीमा पालिसियों से भिन्न केवल उन जीवन बीमा पालिसियों के संबंध में लागू होंगे, जहां प्रीमियम की समग्र रकम उन पालिसियों में से किसी की अवधि के दौरान किन्हीं पूर्ववर्षों में छठवें परंतुक में निर्दिष्ट रकम से अधिक नहीं होती है :

परंतु यह भी कि चौथे, पांचवें, छठवें और सातवें परंतुकों के उपबंध किसी व्यक्ति की मृत्यु पर प्राप्त किसी राशि को लागू नहीं होंगे ;”;

(ड) खंड (12ख) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘(12ग) अग्निपथ स्कीम के अधीन अभ्यावेशित किसी व्यक्ति या उसके नामनिर्देशिती को अग्निवीर समग्र निधि से कोई संदाय ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, “अग्निवीर समग्र निधि” और “अग्निपथ स्कीम” का वही अर्थ होगा, जो धारा 80गगज में क्रमशः उनका है ;”;

(च) खंड (22ख) में, तीसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2024 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह भी कि इस खंड में अंतर्विष्ट कोई बात, 1 अप्रैल, 2024 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष की समाचार एजेंसी की किसी आय को लागू नहीं होगी ;”;

(छ) खंड (23खखच) का लोप किया जाएगा ;

(ज) खंड (23ग) में,—

(I) 1 अक्टूबर, 2023 से,—

(i) पहले परंतुक में, खंड (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(iv) किसी अन्य दशा में, जहां किसी निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था अथवा अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था के क्रियाकलाप,—

(अ) ऐसे निर्धारण वर्ष से, जिसमें उक्त अनुमोदन की ईप्सा की गई है, सुसंगत पूर्ववर्ष के प्रारंभ के कम से कम एक मास पूर्व आरंभ नहीं हुए है ;

(आ) आरंभ हो गए हैं और ऐसे क्रियाकलापों के प्रारंभ के पश्चात् किसी भी समय ऐसे लागू होने की तारीख को या उसके पूर्व समाप्त होने वाले किसी पूर्ववर्ष के लिए उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) अथवा उपखंड (vi)क) या धारा 11 या धारा 12 के लागू होने के कारण कुल आय से उक्त निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था अथवा अस्पताल या

अन्य आयुर्विज्ञान संस्था की कोई आय या उसका भाग अपवर्जित नहीं किया गया है,;

(ii) दूसरे परंतुक में,—

(क) खंड (ii) में,—

(अ) आरंभिक भाग में, “खंड (iii)”, शब्द, कोष्ठकों और अंकों के पश्चात्, “या खंड (iv) का उपखंड (आ)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(आ) उपखंड (ख) में, मद (आ) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(आ) यदि उसका समाधान नहीं होता है तो वह,—

(I) पहले परंतुक के खंड (ii) या खंड (iii) में निर्दिष्ट दशा में ऐसे आवेदन को नामंजूर करते हुए तथा अपना अनुमोदन भी रद्द करते हुए ;

(II) पहले परंतुक के खंड (iv) के उपखंड (आ) में निर्दिष्ट दशा में, ऐसा आवेदन नामंजूर करते हुए,

उसे सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् लिखित में आदेश पारित करेगा ;”;

(ख) खंड (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(iii) जहां आवेदन उक्त परंतुक के खंड (iv) के उपखंड (अ) या आवेदन उक्त परंतुक के खंड (iv) के अधीन, जैसा वह वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा इसके संशोधन के पूर्व था, किया जाता है, तो वह उस निर्धारण वर्ष के, जिससे अनुमोदन की ईप्सा की गई है, तीन वर्ष की अवधि के लिए अनंतिम रूप से इसका अनुमोदन करते हुए लिखित में आदेश पारित करेगा, और ऐसे आदेश की एक प्रति निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था अथवा अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था को भेजेगा :”;

(II) तीसरे परंतुक में,—

(i) स्पष्टीकरण 2 में,—

(क) खंड (i) में,—

(अ) परंतुक में, “और”, शब्द का लोप किया जाएगा ;

(आ) परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“परंतु यह और कि पहले परंतुक के उपबंध केवल तभी लागू होंगे, यदि समग्र निधि से उपयोजन के समय इस खंड के बारहवें, तेरहवें और इक्कीसवें

परंतुकों तथा स्पष्टीकरण 2 और स्पष्टीकरण 3 में विनिर्दिष्ट शर्तों का कोई अतिक्रमण न हुआ हो :

परंतु यह भी कि पहले परंतुक के अधीन विनिधान की गई या वापस जमा की गई रकम को पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोजन नहीं माना जाएगा जब तक ऐसा विनिधान या जमा, ऐसे पूर्ववर्ष के अंत से, जिसके दौरान समग्र निधि से ऐसे उपयोजन के रूप में किया गया था, पांच वर्ष की अवधि के भीतर नहीं किया जाता :

परंतु यह भी कि पहले परंतुक में अंतर्विष्ट कोई बात लागू नहीं होगी जहां 31 मार्च, 2021 को या उसके पूर्व समग्र निधि से उपयोजन किया जाता है ;”;

(ख) खंड (ii) में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“परंतु यह और कि पहले परंतुक के उपबंध केवल तभी लागू होंगे यदि ऋण या उधार से ऐसे उपयोजन के दौरान इस खंड के बारहवें, तेरहवें और इक्कीसवें परंतुकों तथा स्पष्टीकरण 2 और स्पष्टीकरण 3 में विनिर्दिष्ट शर्तों का कोई अतिक्रमण न हुआ हो :

परंतु यह भी कि पहले परंतुक के अधीन पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए पुनः संदत्त रकम को उपयोजन नहीं माना जाएगा जब तक ऐसा पुनः संदाय ऐसे पूर्ववर्ष के अंत से, जिसके दौरान ऐसा उपयोजन ऋण या उधार से किया गया था, पांच वर्ष की अवधि के भीतर नहीं किया जाता :

परंतु यह भी कि पहले परंतुक में अंतर्विष्ट कोई बात वहां लागू नहीं होगी, जहां समग्र निधि से उपयोजन 31 मार्च, 2021 को या उसके पूर्व किया जाता है ; और”;

(ग) खंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2024 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(iii) यथास्थिति, उपखंड (iv), उपखंड (v) या उपखंड (vi) अथवा उपखंड (vi) में निर्दिष्ट निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था अथवा अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था अथवा धारा 12कख के अधीन रजिस्ट्रीकृत न्यास या संस्था को, बारहवें परंतुक में निर्दिष्ट रकम से भिन्न, उपखंड (iv), उपखंड (v) या उपखंड (vi) अथवा उपखंड (vi) में निर्दिष्ट निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था अथवा अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था की आय से प्रत्यय की गई या संदत्त कोई रकम, ऐसी प्रत्यय की गई या संदत्त रकम के केवल पचासी प्रतिशत की सीमा तक केवल पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोजन मानी जाएगी ।”;

(ii) स्पष्टीकरण 3 में, खंड (ग) में, “को या उसके पूर्व” शब्दों के स्थान पर, “से कम से कम दो मास पूर्व” शब्द रखे जाएंगे ;

(III) पंद्रहवें परंतुक के स्पष्टीकरण 2 में,—

(अ) खंड (घ) में, “अंतिम रूप प्रदान कर दिया गया है ;” शब्दों के स्थान पर, “अंतिम रूप प्रदान कर दिया गया है ; या” शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(ड) इस खंड के पहले परंतुक में निर्दिष्ट आवेदन पूर्ण नहीं है या इसमें मिथ्या या गलत सूचना अंतर्विष्ट है ।”;

(IV) उन्नीसवें परंतुक के स्पष्टीकरण में, 1 अप्रैल, 2024 से,—

(क) “खंड (46) के अधीन अधिसूचित” शब्दों, कोष्ठक और अंकों के स्थान पर, “खंड (46) या खंड (46क) के अधीन अधिसूचित” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) “खंड (46) के अधीन” शब्दों, कोष्ठक और अंकों के स्थान पर, “यथास्थिति, खंड (46) या खंड (46क) के अधीन” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(V) बीसवें परंतुक में, “उस धारा के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर” शब्दों के स्थान पर, “उस धारा की उपधारा (1) या उपधारा (4) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(झ) खंड (23डख) का लोप किया जाएगा ;

(ज) खंड (23चड) में प्रारंभिक पैरा में, “ब्याज” शब्द के स्थान पर 1 अप्रैल, 2024 से, “ब्याज, धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (xii) में निर्दिष्ट कोई राशि” शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ट) खंड (26क) का लोप किया जाएगा ;

(ठ) खंड (26ककक) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे और 1 अप्रैल, 1990 से रखे गए समझे जाएंगे, अर्थात् :—

‘(26ककक) किसी व्यष्टि की दशा में, जो सिक्किमी है,—

(क) जिसे सिक्किम राज्य में किसी स्रोत से ; या

(ख) प्रतिभूतियों पर लाभांश या ब्याज के माध्यम से,

कोई आय उद्भूत या उत्पन्न होती है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, “सिक्किमी” से—

(i) कोई व्यष्टि, जिसके नाम को 26 अप्रैल, 1975 के तुरंत पूर्व सिक्किम प्रजा नियम, 1961 के साथ पठित सिक्किम प्रजा विनियम, 1961 के अधीन रखे गए रजिस्टर (जिसे इसमें इसके पश्चात् “सिक्किम प्रजा रजिस्टर” कहा गया है) में अभिलिखित किया गया है ; या

(ii) कोई व्यष्टि, जिसके नाम को तारीख 7 अगस्त, 1990 के भारत सरकार के आदेश सं. 26030/36/90-आई.सी.आई. और तारीख

8 अप्रैल, 1991 के समसंख्यक आदेश के आधार पर सिक्किम प्रजा के रजिस्टर में सम्मिलित किया गया है ; या

(iii) कोई अन्य व्यष्टि, जिसका नाम सिक्किम प्रजा के रजिस्टर में नहीं है किंतु यह संदेह से परे साबित कर दिया गया है कि ऐसे व्यष्टि के पिता या पति या पितामह या उसी पिता से भाई का नाम उस रजिस्टर में अभिलिखित किया गया है ; या

(iv) कोई अन्य व्यष्टि, जिसका नाम सिक्किम प्रजा के रजिस्टर में नहीं है किंतु यह साबित कर दिया जाता है कि ऐसा व्यष्टि 26 अप्रैल, 1975 को या उससे पूर्व सिक्किम में अधिवास कर रहा था ; या

(v) कोई अन्य व्यष्टि, जो 26 अप्रैल, 1975 को या उससे पूर्व सिक्किम में अधिवास नहीं कर रहा था किंतु यह संदेह से परे साबित कर दिया गया है कि ऐसे व्यष्टि के पिता या पति या पितामह या उसी पिता से भाई 26 अप्रैल, 1975 को या उससे पूर्व सिक्किम में अधिवास कर रहा था,

अभिप्रेत होगा ;

(ड) खंड (34क) के पश्चात्, 1 अप्रैल, 2024 से निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(34ख) किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की कोई इकाई, जो मुख्यतः किसी वायुयान को पट्टे पर देने के कारबार में लगी हुई है, की किसी कंपनी की, जो किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की कोई इकाई है, जो मुख्यतः किसी वायुयान को पट्टे पर देने के कारबार में लगी हुई है, की लाभांश के माध्यम से कोई आय ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए “अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र” का वही अर्थ होगा, जो उसका विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (थ) में है ;”।

(ढ) खंड (41) का लोप किया जाएगा ;

(ण) खंड (46) में, “या उसके किसी वर्ग” दोनों स्थानों पर, जहां-जहां वे आते हैं, शब्दों के स्थान पर, “खंड (46क) के अधीन आने वालों से भिन्न या उसके किसी वर्ग” कोष्ठक, शब्द, अंक और अक्षर 1 अप्रैल, 2024 से रखे जाएंगे ;

(त) खंड (46) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2024 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(46क) किसी निकाय या प्राधिकरण या बोर्ड या न्यास या आयोग जो कंपनी नहीं है, जिसे—

(क) निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजनों के लिए किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित या गठित किया गया है, अर्थात् :—

(i) जो गृह आवासन की आवश्यकता से संबंधित है और उसको पूरा करना ;

(ii) शहरों, नगरों और ग्रामों की योजना, विकास या सुधार ;

(iii) जन साधारण के फायदे के लिए किसी कार्यकलाप का विनियमन या विनियमन और विकास ; या

(iv) उस उद्देश्य, जिसके लिए उसका सृजन किया गया है, के कारण उद्भूत होने वाले जन साधारण के फायदे के लिए किसी मामले का विनियमन,

को प्रोद्भूत होने वाली कोई आय ; और

(ख) जिसे इस खंड के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया गया है ;

(46ख) निम्नलिखित को उद्भूत या उत्पन्न कोई आय,—

(i) राष्ट्रीय प्रत्यय प्रतिभूति न्यासी कंपनी लिमिटेड, जो केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित और पूर्णतया वित्तपोषित प्रत्यय प्रतिभूति निधियों के प्रचालन के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित और पूर्णतया वित्तपोषित कंपनी है ; या

(ii) केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित और पूर्णतया वित्तपोषित और कोई प्रत्यय प्रतिभूति निधि, जिनका प्रबंधन राष्ट्रीय प्रत्यय प्रतिभूति न्यासी कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाता है ; या

(iii) सूक्ष्म और लघु उपक्रमों के लिए प्रत्यय प्रतिभूति निधि न्यास, जो भारत सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा सृजित न्यास है ;”;

1989 का 39

(थ) खंड (49) का लोप किया जाएगा ।

धारा 10कक का संशोधन ।

6. आय-कर अधिनियम की धारा 10कक में, 1 अप्रैल, 2024 से,—

(क) उपधारा (1) में, खंड (ii) के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पहले निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु ऐसी कोई कटौती किसी निर्धारिती को अनुज्ञात नहीं की जाएगी, जो धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उसके पूर्व आय की विवरणी प्रस्तुत नहीं करता है ।”;

(ख) उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(4क) यह धारा ऐसी किसी इकाई को लागू होती है, यदि माल के विक्रय या सेवाओं के उपबंध से प्राप्त आगम निर्धारिती द्वारा भारत में संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में, पूर्ववर्ष के अंत से छह मास की अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर, जो सक्षम प्राधिकारी इस निमित्त अनुज्ञात करे, प्राप्त होते हैं या लाए जाते हैं ।

स्पष्टीकरण 1—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए “सक्षम प्राधिकारी” पद से भारतीय रिजर्व बैंक या ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है, जो विदेशी मुद्रा में संदायों और व्यौहारों का विनियमन करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्राधिकृत है ।

स्पष्टीकरण 2—माल का विक्रय या सेवाओं का उपबंध उस समय भारत में प्राप्त किया गया समझा जाएगा, जहां ऐसी निर्यात आवर्त भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से भारत के बाहर किसी बैंक में निर्धारिती द्वारा इस प्रयोजन के लिए रखे गए किसी पृथक् खाते में जमा की जाती है ।’;

(ग) स्पष्टीकरण 1 के खंड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

‘(i) “संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा” का वही अर्थ होगा, जो धारा 10क के स्पष्टीकरण 2 के खंड (ii) में उसका है ;

(ik) “निर्यात आवर्त” से निर्धारिती द्वारा उपधारा (4क) के उपबंधों के अनुसार संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में भारत में प्राप्त की गई या लाई गई वस्तुओं या चीजों या सेवाओं के उपक्रम द्वारा, जो यूनिट है, निर्यात के संबंध में प्रतिफल अभिप्रेत है, किंतु इसके अंतर्गत भारत से बाहर वस्तुओं या चीजों के परिदान के कारण माने जा सकने वाले भाड़ा, दूर-संचार प्रभार या बीमा या भारत से बाहर सेवाएं (जिसमें कंप्यूटर साफ्टवेयर भी है) प्रदान करने में विदेशी मुद्रा में उपगत व्यय, यदि कोई हो, सम्मिलित नहीं है ;’।

7. आय-कर अधिनियम की धारा 11 में,—

धारा 11 का संशोधन ।

(अ) उपधारा (1) में,—

(क) स्पष्टीकरण 1 के खंड (2) के उपखंड (ii) की दीर्घ पंक्ति में, “अनुज्ञात समय की समाप्ति के पूर्व” शब्दों के स्थान पर, “नियत विनिर्दिष्ट तारीख से कम से कम दो मास पूर्व” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) स्पष्टीकरण 4 में,—

(i) खंड (i) में,—

(क) परंतुक में, “माना जाएगा ; और” शब्दों के स्थान पर, “माना जाएगा :” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“परंतु यह और कि पहले परंतुक के उपबंध केवल तभी लागू होंगे,—

(क) जब इस उपधारा के, खंड (ग) में ;

(ख) इस उपधारा के स्पष्टीकरण 2, स्पष्टीकरण 3 और स्पष्टीकरण 5 में ;

(ग) इस धारा के स्पष्टीकरण में ; और

(घ) धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ग) में, समग्र निधि से उपयोजन किए जाने के समय यदि विनिर्दिष्ट शर्तों का कोई अतिक्रमण नहीं किया गया था :

परंतु यह भी कि विनिधान की गई या पुनः जमा की गई रकम को पहले परंतुक के अधीन पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोजन के रूप में तब तक नहीं माना जाएगा जब तक ऐसा विनिधान या जमा उस पूर्ववर्ष, जिसमें

समग्र निधि से ऐसा उपयोजन किया गया था, के अंत से पांच वर्ष की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है :

परंतु यह भी कि पहले परंतुक में अंतर्विष्ट कोई बात वहां लागू नहीं होगी, जहां समग्र निधि से उपयोजन 31 मार्च, 2021 को या उससे पूर्व किया जाता है :”;

(II) खंड (ii) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“परंतु यह और कि पहले परंतुक के उपबंध केवल तभी लागू होंगे,—

(क) जब इस उपधारा के खंड (ग) में ;

(ख) इस उपधारा के स्पष्टीकरण 2, स्पष्टीकरण 3 और स्पष्टीकरण 5 में ;

(ग) इस धारा के स्पष्टीकरण में ; और

(घ) धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ग) में,

ऋण या उधार से उपयोजन किए जाने के समय यदि विनिर्दिष्ट शर्तों का कोई अतिक्रमण नहीं किया गया था :

परंतु यह भी कि प्रतिसंदत रकम को पहले परंतुक के अधीन पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोजन के रूप में तब तक नहीं माना जाएगा, जब तक ऐसा प्रतिसंदाय उस पूर्ववर्ष, जिसमें ऋण या उधार से ऐसा उपयोजन किया गया था, के अंत से पांच वर्ष की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है :

परंतु यह भी कि पहले परंतुक में अंतर्विष्ट कोई बात वहां लागू नहीं होगी, जहां कोई ऋण या उधार से उपयोजन 31 मार्च, 2021 को या उससे पूर्व किया जाता है ; और”;

(III) खंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2024 से, अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(iii) यथास्थिति, धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट किसी निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था या धारा 12कख के अधीन रजिस्ट्रीकृत अन्य न्यास या संस्था में, स्पष्टीकरण 2 में निर्दिष्ट रकम से भिन्न, जमा या संदत किसी रकम को ऐसी जमा की गई या संदत रकम के पचासी प्रतिशत की सीमा तक ही पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोजन के रूप में माना जाएगा।”;

(आ) उपधारा (2) के खंड (ग) में, “को या उससे पहले” शब्दों के स्थान पर, “से कम से कम दो मास पूर्व” शब्द रखे जाएंगे ;

(इ) उपधारा (7) में, 1 अप्रैल, 2024 से,—

(क) “और खंड (46) से भिन्न” शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, “खंड (23डग), खंड (46) और खंड (46क) से भिन्न” शब्द, कोष्ठक,

अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) पहले परंतुक में, “खंड (46) के अधीन” शब्दों, कोष्ठक और अंकों के स्थान पर, “खंड (23डग) या खंड (46) या खंड (46क) के अधीन” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(ग) दूसरे परंतुक में, “खंड (46) के अधीन” शब्दों, कोष्ठक और अंकों के स्थान पर, “खंड (23डग) या खंड (46) या खंड (46क) के अधीन” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ।

8. आय-कर अधिनियम की धारा 12क में,—

धारा 12क का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) में,—

(I) खंड (कग) के उपखंड (vi) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड 1 अक्टूबर, 2023 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(vi) किसी अन्य दशा में, जहां न्यास या संस्था के क्रियाकलाप,—

(अ) ऐसे निर्धारण वर्ष से, जिसमें उक्त रजिस्ट्रीकरण की ईप्सा की गई है, सुसंगत पूर्ववर्ष के प्रारंभ के कम से कम एक मास पूर्व आरंभ नहीं हुए हैं ;

(आ) आरंभ हो गए हैं और ऐसे क्रियाकलापों के प्रारंभ के पश्चात् किसी भी समय ऐसे लागू होने की तारीख को या उसके पूर्व समाप्त होने वाले किसी पूर्ववर्ष के लिए धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) अथवा उपखंड (vi)क) या धारा 11 या धारा 12 के लागू होने के कारण कुल आय से उक्त न्यास या संस्था की कोई आय या उसका भाग अपवर्जित नहीं किया गया है,”;

(II) खंड (खक) में, “उस धारा के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर”, शब्दों के स्थान पर, “उस धारा की उपधारा (1) या उपधारा (4) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर”, शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) में, दूसरे, तीसरे और चौथे परंतुकों का लोप किया जाएगा ।

9. आय-कर अधिनियम की धारा 12कख में,—

धारा 12कख का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) में, 1 अक्टूबर, 2023 से,—

(अ) खंड (ख) में,—

(क) आरंभिक भाग में, “उपखंड (v)” शब्द, कोष्ठकों और अंक के पश्चात्, “उपखंड (vi) की मद (आ)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) उपखंड (ii) में, मद (आ) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(आ) यदि उसका इस प्रकार समाधान नहीं होता है तो वह सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्,—

(I) धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (कग) के उपखंड (ii) या उपखंड (iii) या उपखंड (v) में निर्दिष्ट किसी मामले में ऐसे आवेदन को नामंजूर करते हुए और साथ ही

उसके रजिस्ट्रीकरण को रद्द करते हुए लिखित आदेश पारित करेगा ;

(II) धारा 12क की उपधारा (1) के उपखंड (iv) या उपखंड (vi) की मद (आ) में निर्दिष्ट किसी मामले में ऐसे आवेदन को नामंजूर करते हुए लिखित आदेश पारित करेगा ;”;

(आ) खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(ग) जहां कोई आवेदन उक्त खंड के उपखंड (vi) की मद (अ) के अधीन किया जाता है या आवेदन उक्त खंड के उपखंड (vi) के अधीन, जैसा कि वह वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा उसके संशोधन से ठीक पूर्व विद्यमान था, किया जाता है तो वह उस निर्धारण वर्ष से, जिससे रजिस्ट्रीकरण की ईप्सा की गई है, तीन वर्ष की अवधि के लिए न्यास या संस्था को अनन्तिम रूप से रजिस्ट्रीकृत करते हुए लिखित आदेश पारित करेगा,”;

(ख) उपधारा (4) में, स्पष्टीकरण के खंड (च) में, “या उसे अंतिम रूप दिया गया है ।” शब्दों के स्थान पर, “या उसे अंतिम रूप दिया गया है ; या” शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(छ) धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (कग) में निर्दिष्ट आवेदन पूर्ण नहीं है, या उसमें कोई मिथ्या या गलत सूचना अंतर्विष्ट है ।”।

धारा 17 का
संशोधन ।

10. आय-कर अधिनियम की धारा 17 में,—

(i) खंड (1) में, उपखंड (viii) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(ix) केंद्रीय सरकार द्वारा पूर्ववर्ष में धारा 80गगज में निर्दिष्ट अग्निपथ स्कीम में अभ्यावेशित किसी व्यष्टि के अग्निवीर समग्र निधि खाते में किया गया अभिदाय ;”;

(ii) खंड (2) में, 1 अप्रैल, 2024 से,—

(क) उपखंड (i) में, “वास-सुविधा का” शब्दों के पश्चात्, “ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संगणित” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपखंड (ii) और उसके स्पष्टीकरण 1 से स्पष्टीकरण 4 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(ii) निर्धारिती को उसके नियोजक द्वारा रियायती दर पर प्रदान की गई किसी वास-सुविधा का मूल्य ।

स्पष्टीकरण—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि वास-सुविधा रियायती दर पर प्रदान की गई समझी जाएगी, यदि वास-सुविधा का संगणित मूल्य, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, निर्धारिती से वसूलनीय या उसके द्वारा संदेय किराए से अधिक है ;”।

धारा 28 का

11. आय-कर अधिनियम की धारा 28 के खंड (iv) के स्थान पर, 1 अप्रैल, 2024 से

संशोधन ।

निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(iv) किसी कारबार या किसी वृत्ति के प्रयोग से उदभूत होने वाले किसी फायदे या परिलब्धि का मूल्य, चाहे—

(क) वह धन में संपरिवर्तनीय हो या न हो ; या

(ख) नकद रूप में या वस्तु रूप में या भागतः नकद रूप में और भागतः वस्तु रूप में हो ;”।

12. आय-कर अधिनियम की धारा 35घ की उपधारा (2) के खंड (क) में, परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2024 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

धारा 35घ का संशोधन ।

“परंतु निर्धारिती, ऐसे आय-कर प्राधिकारी को ऐसी अवधि के भीतर ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, इस खंड में विनिर्दिष्ट व्यय की विशिष्टियां अंतर्विष्ट करने वाला एक विवरण प्रस्तुत करेगा ।”।

13. आय-कर अधिनियम की धारा 43ख में, 1 अप्रैल, 2024 से,—

धारा 43ख का संशोधन ।

(i) खंड (घक) में, “किसी निक्षेप लेने वाली गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी या किसी सुव्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण निक्षेप न लेने वाली गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी” शब्दों के स्थान पर, “गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों का ऐसा वर्ग, जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचित किया जाए,” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (छ) में, “राशि,” शब्दों के स्थान पर, “राशि या” शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) खंड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

2006 का 27

“(ज) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 15 में विनिर्दिष्ट समय-सीमा से परे किसी सूक्ष्म या लघु उद्यम को निर्धारिती द्वारा संदेय कोई राशि ।”;

(iv) परंतुक में, “इस धारा की कोई बात” शब्दों के पश्चात्, “[खंड (ज) के उपबंधों के सिवाय]” कोष्ठक, शब्द और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(v) स्पष्टीकरण 4 में,—

(I) खंड (ड) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

2006 का 27

‘(ड) “सूक्ष्म उद्यम” का वही अर्थ होगा, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 2 के खंड (ज) में उसका है ;’;

(II) खंड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

2006 का 27

‘(छ) “लघु उद्यम” का वही अर्थ होगा, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 2 के खंड (ड) में उसका है ।’।

14. आय-कर अधिनियम की धारा 43घ में, 1 अप्रैल, 2024 से,—

धारा 43घ का संशोधन ।

(i) खंड (क) में, “निक्षेप लेने वाली गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी या सुव्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण निक्षेप न लेने वाली गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी” शब्दों के स्थान पर, “गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों का ऐसा वर्ग, जो केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में इस निमित्त अधिसूचित किया जाए” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) दीर्घ पंक्ति में, “निक्षेप लेने वाली गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी या

सुव्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण निक्षेप न लेने वाली गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी” शब्दों के स्थान पर, “गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों का ऐसा वर्ग, जो केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में इस निमित्त अधिसूचित किया जाए” शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) स्पष्टीकरण के खंड (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(ज) “गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी” पद का वही अर्थ होगा, जो उसका धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (vii) के स्पष्टीकरण के खंड (vii) में है ।”।

धारा 44कख का संशोधन ।

15. आय-कर अधिनियम की धारा 44कख में, पहले परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2024 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह धारा ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी, जो धारा 44कघ की उपधारा (1) या धारा 44कघक की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार पूर्ववर्ष के लिए लाभों और अभिलाभों की घोषणा करता है :”।

धारा 44कघ का संशोधन ।

16. आय-कर अधिनियम की धारा 44कघ के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के उपखंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2024 से अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

‘परंतु जहां पूर्ववर्ष के दौरान नकद रूप में प्राप्त की गई रकम या रकमों का योग, ऐसे पूर्ववर्ष के कुल आवर्त या सकल प्राप्तियों का पांच प्रतिशत से अधिक नहीं है, वहां इस उपखंड का इस प्रकार प्रभाव होगा, मानो “दो करोड़ रुपए” शब्दों के स्थान पर, “तीन करोड़ रुपए” शब्द रखे गए हों :

परंतु यह और कि पहले परंतुक के प्रयोजनों के लिए किसी बैंक के नाम देय चेक या बैंक ड्राफ्ट द्वारा रकम या रकमों के योग की प्राप्ति, जो पाने वाले के खाते में देय नहीं है, नकद प्राप्ति के रूप में समझी जाएगी ।’।

धारा 44कघक का संशोधन ।

17. आय-कर अधिनियम की धारा 44कघक की उपधारा (1) के पश्चात्, 1 अप्रैल, 2024 से निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘परंतु किसी ऐसे निर्धारिती के मामले में, जहां पूर्ववर्ष के दौरान प्राप्त की गई रकम या रकम का योग, नकद रूप में ऐसे पूर्ववर्ष की सकल प्राप्तियों के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं है, वहां इस उपधारा का इस प्रकार प्रभाव होगा, मानो “पचास लाख रुपए” शब्दों के स्थान पर, “पचहत्तर लाख रुपए” रखे गए हों :

परंतु यह और कि पहले परंतुक के प्रयोजनों के लिए, किसी बैंक के नाम देय चेक या बैंक ड्राफ्ट द्वारा रकम या रकमों के योग की प्राप्ति, जो पाने वाले के खाते में देय नहीं है, नकद प्राप्ति के रूप में समझी जाएगी ।’।

धारा 44खख का संशोधन ।

18. आय-कर अधिनियम की धारा 44खख की उपधारा (3) के पश्चात् और स्पष्टीकरण के पूर्व, निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2024 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(4) धारा 32 की उपधारा (2) और धारा 72 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई निर्धारिती उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार किसी पूर्ववर्ष के लिए कारबार के लाभों और अभिलाभों की घोषणा करता है, तो शेष अवक्षयण और अग्रसरित हानि का कोई मुजरा ऐसे पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।”।

धारा 44खखख का संशोधन ।

19. आय-कर अधिनियम की धारा 44खखख की उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2024 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(3) धारा 32 की उपधारा (2) और धारा 72 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट

किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई निर्धारित उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार किसी पूर्ववर्ष के लिए कारबार के लाभों और अभिलाभों की घोषणा करता है, वहां शेष अवक्षयण और अग्रणीत हानि का कोई मुजरा ऐसे पूर्ववर्ष के लिए निर्धारित को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।”।

20. आय-कर अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (5क) में, “नकद रूप में प्रतिफल, यदि कोई हो,” शब्दों के स्थान पर, “नकद रूप में या किसी चैक या ड्राफ्ट या किसी अन्य पद्धति से प्राप्त प्रतिफल, यदि कोई हो,” शब्द 1 अप्रैल, 2024 से रखे जाएंगे।

धारा 45 का संशोधन।

21. आय-कर अधिनियम की धारा 47 में,—

धारा 47 का संशोधन।

(क) खंड (viiकघ) के स्पष्टीकरण में,—

“(i) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

‘(क) “मूल निधि” से—

(अ) भारत से बाहर स्थापित या निगमित या रजिस्ट्रीकृत कोई निधि अभिप्रेत है, जो अपने सदस्यों से उनके फायदे के लिए, विनिधान करने के लिए, निधियां एकत्रित करती है और जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है, अर्थात् :—

(i) निधि, भारत में निवासी कोई व्यक्ति नहीं है ;

(ii) निधि, किसी देश या किसी विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र की निवासी है, जिसके साथ धारा 90 की उपधारा (1) या धारा 90क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट करार किया गया है ; या जिसे इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में स्थापित या निगमित या रजिस्ट्रीकृत किया गया है ;

(iii) निधि और उसके कार्यकलाप देश में या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र, जहां उसकी स्थापना या निगमन किया गया है या जहां की वह निवासी है, को लागू विनिधान संरक्षण विनियमों के अधीन है ; और

(iv) ऐसी अन्य शर्तों को पूरा करती है, जो विहित की जाएं ;

(आ) कोई विनिधान यान, जिसमें आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथारिटी प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः शेयर धारक या यूनिट धारक या फायदाग्राही या हितधारक है और ऐसा विनिधान यान पूर्णतया आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथारिटीया आबू धाबी सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन है ; या

(इ) केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए राजपत्र में अधिसूचित कोई निधि ;।”।

(ii) खंड (ख) में, “2023” अंकों के स्थान पर, “2025” अंक रखे जाएंगे ;

(iii) खंड (ग) के उपखंड (i) में, “जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम,

2019 का 50

1992 का 15

2019 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (वैकल्पिक विनिधान निधि) विनियम, 2012 के अधीन" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (वैकल्पिक विनिधान निधि) विनियम, 2012 या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अधीन बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंध) विनियम, 2022 के अधीन विनियमित" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

2019 का 50

(ख) खंड (viiग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2024 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘(viiघ) किसी पूंजी आस्ति का, जो किसी वाल्ट प्रबंधक द्वारा जारी स्वर्ण का इलेक्ट्रॉनिक स्वर्ण प्राप्ति में संपरिवर्तन या इलेक्ट्रॉनिक स्वर्ण प्राप्ति का स्वर्ण में संपरिवर्तन है, का कोई अंतरण ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, “इलेक्ट्रिक स्वर्ण प्राप्ति” और “वाल्ड प्रबंधक” पद के वही अर्थ होंगे, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (वाल्ड प्रबंधक) विनियम, 2021 के विनियम 2 के उपविनियम (1) के खंड (ज) और खंड (ठ) में क्रमशः उनके हैं ।’;

1992 का 15

(ग) खंड (xix) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘(xx) उस दूसरे देश की विधियों के अनुसार, दूसरे देश की सरकार द्वारा भारत के बाहर निगमित, किसी कंपनी के शेयरों के विनियम में, किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी द्वारा धारित पूंजी आस्ति का कोई अंतरण, जो संयुक्त उपक्रम में कोई हित है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, “संयुक्त उपक्रम” से वह कारबार अस्तित्व अभिप्रेत होगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जाए ।’।

धारा 48 का
संशोधन ।

22. आय-कर अधिनियम की धारा 48 में, खंड (ii) में, 1 अप्रैल, 2024 से निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु आस्ति के अर्जन की लागत या उसके सुधार की लागत में धारा 24 के खंड (ख) के अधीन या अध्याय 6क के उपबंधों के अधीन ब्याज की रकम पर कटौती किए दावे शामिल नहीं होंगे ।

स्पष्टीकरण 1—संदेह को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी कारबार न्यास की यूनिट के अर्जन की लागत कम कर दी जाएगी और सदैव के लिए ऐसी रकम से कम कर दी गई समझी जाएगी जो ऐसी यूनिट के संबंध में कारबार न्यास से यूनिट धारक द्वारा प्राप्त की जाती है, जो धारा 10 के खंड (23चग) या खंड (23चगक) में यथानिर्दिष्ट आय की प्रकृति की नहीं है और जो धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (xii)के अधीन और धारा 115पक की उपधारा (2) के अधीन कर से प्रभार्य नहीं है ।

स्पष्टीकरण 2—स्पष्टीकरण 1 के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है

कि जहां धारा 47 के अधीन किसी यूनिट के अंतरण के संव्यवहार को अंतरण के रूप में नहीं माना जाता और धारा 49 के अधीन ऐसी यूनिट के अर्जन की लागत अवधारित की जाती है, ऐसे अंतरण के पूर्व के साथ-साथ ऐसे अंतरण के पश्चात् ऐसी यूनिट के संबंध में प्राप्त राशि उक्त स्पष्टीकरण के अधीन अर्जन की लागत से घटा दी जाएगी।”।

23. आय-कर अधिनियम की धारा 49 में,—

धारा 49 का संशोधन ।

(क) उपधारा (2कज) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(2कझ) जहां पूंजी आस्ति, जो धारा 47 के खंड (xx) में यथानिर्दिष्ट शेयर है, निर्धारित की संपत्ति हो जाती है, ऐसी आस्ति के अर्जन की लागत उक्त खंड में निर्दिष्ट संयुक्त उपक्रम में हित के अर्जन की लागत समझी जाएगी।”;

(ख) उपधारा (9) के पश्चात् 1 अप्रैल, 2024 से निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(10) जहां पूंजी आस्ति, जो,—

(i) धारा 47 के खंड (viiघ) में निर्दिष्ट किसी वाल्ट प्रबंधक द्वारा जारी कोई इलैक्ट्रॉनिक स्वर्ण प्राप्ति है, वहां उक्त अंतरण के प्रयोजन के लिए आस्ति के अर्जन की लागत को, उस व्यक्ति के पास, जिसके नाम पर इलैक्ट्रॉनिक स्वर्ण प्राप्ति जारी की गई है, ऐसे स्वर्ण की लागत के रूप में माना जाएगा ;

(ii) इलैक्ट्रॉनिक स्वर्ण प्राप्ति के लिए जारी स्वर्ण है और धारा 47 के खंड (viiघ) में निर्दिष्ट अंतरण के लिए प्रतिफल के रूप में उस व्यक्ति की संपत्ति हो जाती है, वहां उक्त अंतरण के प्रयोजन के लिए आस्ति के अर्जन की लागत को, उस व्यक्ति के पास, जिसके नाम पर इलैक्ट्रॉनिक स्वर्ण प्राप्ति जारी की गई है, ऐसे स्वर्ण की लागत के रूप में माना जाएगा ।”।

24. आय-कर अधिनियम की धारा 50क के पश्चात् 1 अप्रैल, 2024 से निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

नई धारा 50क का अंतःस्थापन ।

‘50कक. धारा 2 के खंड (42क) या धारा 48 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां पूंजी आस्ति, 1 अप्रैल, 2023 को या उसके पश्चात् अर्जित किसी विनिर्दिष्ट पारस्परिक निधि की यूनिट या बाजार संबद्ध डिबेंचर है, ऐसे डिबेंचर या यूनिट के अंतरण या मोचन या परिपक्वता के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोदभूत प्रतिफल के पूर्ण मूल्य को,—

बाजार संबद्ध डिबेंचरों की दशा में पूंजी अभिलाभ की संगणना के लिए विशेष उपबंध ।

(i) डिबेंचर या यूनिट के अर्जन की लागत ;

(ii) ऐसे अंतरण या मोचन या परिपक्वता के संबंध में पूर्णतया और विशिष्टतया उपगत व्यय से,

घटा दिया जाएगा, उसे अल्पकालिक पूंजी आस्ति के अंतरण से उदभूत पूंजी अभिलाभ समझा जाएगा :

परंतु वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 के अध्याय 7 के उपबंधों के अधीन प्रतिभूति संव्यवहार कर के मददे संदत्त किसी राशि के संबंध में “पूंजी अभिलाभ” शीर्ष

के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) “बाजार संबद्ध डिबेंचर” से किसी भी नाम से ज्ञात कोई प्रतिभूति अभिप्रेत है, जो ऋण सुरक्षा के रूप में अंतर्निहित मूल घटक रखती है और जहां रिटर्न अन्य अंतर्निहित प्रतिभूतियों पर बाजार रिटर्न या सूचकों से संबद्ध हैं तथा इसके अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा बाजार संबद्ध डिबेंचर के रूप में वर्गीकृत या विनियमित कोई प्रतिभूति भी है ;

(ii) “विनिर्दिष्ट पारस्परिक निधि” से किसी भी नाम से ज्ञात कोई पारस्परिक निधि अभिप्रेत है, जहां इसके कुल आगमों का पैंतीस प्रतिशत से अनधिक घरेलू कंपनियों के साम्या शेयरों में विनिधान किया जाता है :

परंतु यह कि विनिर्दिष्ट पारस्परिक निधि के संबंध में धृत साम्या शेयर धृति की प्रतिशतता की संगणना दैनिक बंद होने वाली संख्या के औसत को निर्दिष्ट करते हुए की जाएगी ।’।

धारा 54 का
संशोधन ।

25. आय-कर अधिनियम की धारा 54 में, 1 अप्रैल, 2024 से,—

(क) उपधारा (1) में, दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह भी कि जहां नई आस्ति की लागत दस करोड़ रुपए से अधिक हो जाती है, वहां दस करोड़ रुपए से अधिक की रकम, इस उपधारा के प्रयोजन के लिए हिसाब में नहीं ली जाएगी ।”;

(ख) उपधारा (2) में,—

(i) “इस प्रकार निक्षिप्त रकम सहित नई आस्ति”, शब्दों के पश्चात्, “उपधारा (1) के तीसरे परंतुक के अधीन रहते हुए,” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह और कि इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए दस करोड़ रुपए से अधिक पूंजीगत लाभ हिसाब में नहीं लिए जाएंगे ।”।

धारा 54डक का
संशोधन ।

26. आय-कर अधिनियम की धारा 54डक की उपधारा (3) का लोप किया जाएगा ।

धारा 54डख का
संशोधन ।

27. आय-कर अधिनियम की धारा 54डख की उपधारा (3) का लोप किया जाएगा ।

धारा 54डग का
संशोधन ।

28. आय-कर अधिनियम की धारा 54डग की उपधारा (3) के खंड (क) का लोप किया जाएगा ।

धारा 54डघ का
संशोधन ।

29. आय-कर अधिनियम की धारा 54डघ की उपधारा (3) के खंड (क) का लोप किया जाएगा ।

धारा 54च का
संशोधन ।

30. आय-कर अधिनियम की धारा 54च में, 1 अप्रैल, 2024 से,—

(क) उपधारा (1) में, पहले परंतुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह और कि जहां नई आस्ति की लागत दस करोड़ रुपए से

अधिक हो जाती है, वहां दस करोड़ रुपए से अधिक की रकम को इस उपधारा के प्रयोजन के लिए हिसाब में नहीं लिया जाएगा।”;

(ख) उपधारा (4) में,—

(i) “इस प्रकार निक्षिप्त रकम सहित नई आस्ति” शब्दों के पश्चात्, “उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के अधीन रहते हुए” शब्द, कोष्ठक और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह और कि इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए दस करोड़ रुपए से अधिक शुद्ध प्रतिफल को हिसाब में नहीं लिया जाएगा।”।

31. आय-कर अधिनियम की धारा 55 में, 1 अप्रैल, 2024 से,—

धारा 55 का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (1) में,—

(i) “गुडविल”, शब्दों के पश्चात्, “या कोई अन्य अमूर्त आस्ति” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) “प्रक्रिया का अधिकार”, शब्दों के पश्चात्, “या कोई अन्य अधिकार” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) के खंड (क) में,—

(i) “किसी कारबार या वृत्ति”, शब्दों के पश्चात्, “या किसी अन्य अमूर्त आस्ति” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) “करघा घंटे”, शब्दों के पश्चात्, “या कोई अन्य अधिकार” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

32. आय-कर अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) में,—

धारा 56 का संशोधन ।

(क) खंड (viiख) में,—

(i) “जो निवासी है” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ii) स्पष्टीकरण में, खंड (कक) में, “भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 द्वारा विनियमित” शब्दों, कोष्ठक और अंकों के पश्चात् “अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अधीन बनाए गए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण, (निधि प्रबंधन) विनियम, 2022 द्वारा विनियमित” शब्द, अंक और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) खंड (xi) के पश्चात् 1 अप्रैल, 2024 से निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“(xii) पूर्ववर्ष के दौरान किसी भी समय किसी यूनिट धारक द्वारा धारित यूनिट के संबंध में पूर्ववर्ष के दौरान कारबार निधि से उसके द्वारा प्राप्त कोई विनिर्दिष्ट राशि ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, “विनिर्दिष्ट राशि” की संगणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जाएगी, अर्थात् :—

विनिर्दिष्ट राशि = क-ख-ग (जिसे शून्य समझा जाएगा, यदि ख और ग राशियां क से अधिक हैं), जहां—

क = पूर्ववर्ष के दौरान या किसी पूर्ववर्ती पूर्व वर्ष या वर्षों के दौरान ऐसे

यूनिट धारक को ऐसी यूनिट के संबंध में कारबार न्यास द्वारा वितरित राशि या कुल योग है, जो राशि के वितरण की तारीख को ऐसी यूनिट धारण करता है या किसी अन्य यूनिट धारक को, राशि का कुल योग है, जो ऐसे वितरण की तारीख से पूर्व किसी भी समय ऐसी यूनिट को धारण करता था, जो,—

(क) धारा 10 के खंड (23चग) या खंड (23चगक) में निर्दिष्ट आय की प्रकृति की नहीं है ; और

(ख) धारा 115पक की उपधारा (2) के अधीन कर से प्रभार्य नहीं है;

ख = रकम, जिस पर ऐसी यूनिट, कारबार न्यास द्वारा जारी की गई ; और

ग = किसी पूर्ववर्ती पूर्व वर्ष में इस खंड के अधीन कर से प्रभारित रकम ; '।'।

(xiii) जहां किसी पूर्ववर्ष के दौरान किसी भी समय किसी जीवन बीमा पालिसी के अधीन बोनस के माध्यम से आबंटित रकम सहित कोई राशि प्राप्त की जाती है, जो—

(क) किसी यूनिट संबद्ध बीमा पालिसी के अधीन प्राप्त राशि ; या

(ख) खंड (iv) में निर्दिष्ट आय,

से भिन्न राशि है, जो धारा 10 के खंड (10घ) के उपबंधों के अनुसार पूर्ववर्ष की कुल आय से अपवर्जित नहीं की जानी है, तो इस प्रकार प्राप्त राशि को, जो ऐसी जीवन बीमा पालिसी की अवधि के दौरान संदत्त प्रीमियम के समग्र से अधिक है तथा जिसका इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन कटौती के रूप में दावा नहीं किया जाता है, ऐसी रीति में संगणित किया जाएगा, जो विहित की जाए ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, “यूनिट संबद्ध बीमा पालिसी” का वही अर्थ होगा, जो धारा 10 के खंड (10घ) के स्पष्टीकरण 3 में उसका है।’।

धारा 72क का संशोधन ।

33. आय-कर अधिनियम की धारा 72क की उपधारा (1) के खंड (घ) के स्पष्टीकरण में, खंड (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

‘(iii) “सामरिक विनिवेश” से केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी द्वारा किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी या किसी कंपनी में उसकी शेयर धृति का ऐसा विक्रय अभिप्रेत है, जिसके परिणामस्वरूप—

(क) उसकी शेयर धृति इक्यावन प्रतिशत से कम रह जाती है ; और

(ख) नियंत्रण क्रेता को अंतरित हो जाता है :

परंतु उपखंड (क) में अधिकथित शर्त केवल ऐसी दशा में लागू होगी, जहां केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर की शेयर धृति, ऐसी शेयर धृति के ऐसे विक्रय से पूर्व इक्यावन प्रतिशत से अधिक थी :

परंतु यह और कि उपखंड (ख) में निर्दिष्ट नियंत्रण के अंतरण संबंधी अपेक्षा केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर कंपनी या उनमें से किन्हीं दो या सभी द्वारा पूरी की जा सकेगी ।’।

धारा 72कक का संशोधन ।

34. आय-कर अधिनियम की धारा 72कक में,—

(क) खंड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(i) निम्नलिखित के साथ एक या अधिक बैंककारी कंपनी,—

(क) केंद्रीय सरकार द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 की उपधारा (7) के अधीन मंजूर की गई और प्रवर्तन में लाई गई किसी स्कीम के अधीन किसी अन्य बैंककारी संस्था ; या

1949 का 10

(ख) किसी सामरिक विनिवेश के परिणामस्वरूप किसी अन्य बैंककारी संस्था या किसी कंपनी, जिसमें उस पूर्व वर्ष, जिसके दौरान सामरिक विनिवेश किया जाता है, के अंत से पांच वर्ष की अवधि के भीतर समामेलन किया जाता है ; या” ;

(ख) दीर्घ पंक्ति में, “ऐसी बैंककारी संस्था या” शब्दों के पश्चात् “कंपनी या” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ग) स्पष्टीकरण में, खंड (vi) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(vi) “सामरिक विनिवेश” पद का वही अर्थ होगा, जो धारा 72क की उपधारा (1) के खंड (घ) के स्पष्टीकरण के खंड (iii) में उसका है ;”।

35. आय-कर अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (1) के परंतुक में, “सात” शब्द के स्थान पर, “दस” शब्द रखा जाएगा ।

धारा 79 का संशोधन ।

36. आय-कर अधिनियम की धारा 80ग की उपधारा (7) का लोप किया जाएगा ।

धारा 80ग का संशोधन ।

37. आय-कर अधिनियम की धारा 80गग की उपधारा (3) के खंड (क) का लोप किया जाएगा ।

धारा 80गग का संशोधन ।

38. आय-कर अधिनियम की धारा 80गगघ की उपधारा (4) के खंड (क) का लोप किया जाएगा ।

धारा 80गगघ का संशोधन ।

39. आय-कर अधिनियम की धारा 80गगछ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

नई धारा 80गगज का अंतःस्थापन ।

“80गगज. (1) जहां किसी निर्धारिती ने, जो अग्निपथ स्कीम में अभ्यावेशित व्यक्ति है और 1 नवंबर, 2022 को या उसके पश्चात् अग्निवीर समग्र निधि में अभिदाय कर रहा है, उक्त निधि में अपने खाते में पूर्ववर्ष में कोई रकम संदत्त की है या जमा की है, वहां उसे इस प्रकार संदत्त या जमा की गई संपूर्ण रकम को उसकी कुल आय की संगणना में कटौती के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ।

अग्निपथ स्कीम में अभिदाय के संबंध में कटौती ।

(2) जहां केंद्रीय सरकार, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अग्निवीर समग्र निधि में निर्धारिती के खाते में कोई अभिदाय करती है, वहां निर्धारिती को इस प्रकार अभिदाय की गई संपूर्ण रकम को उसकी कुल आय की संगणना में कटौती के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) “अग्निपथ स्कीम” से रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0 1(23)2022/डी(वेतन/सेवा), तारीख 29 दिसंबर, 2022 के द्वारा आरंभ की गई भारतीय सशस्त्र बलों में अभ्यावेशन के लिए स्कीम अभिप्रेत है ;

(ख) “अग्निवीर समग्र निधि” से ऐसी कोई निधि अभिप्रेत है, जिसमें सभी अग्निवीरों के अभिदाय और केंद्रीय सरकार के समरूप अभिदाय इन दोनों

अभिदायों पर ब्याज सहित समेकित हैं।”।

धारा 80छ का
संशोधन।

40. आय-कर अधिनियम की धारा 80छ में,—

(I) उपधारा (2) के खंड (क) में उपखंड (ii), उपखंड (iiiग) और उपखंड (iiiघ) का 1 अप्रैल, 2024 से लोप किया जाएगा ;

(II) उपधारा (5) में,—

(अ) 1 अक्टूबर, 2023 से,—

(i) पहले परंतुक में, खंड (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(iv) किसी अन्य दशा में, जहां संस्था या निधि ने,—

(अ) उस निर्धारण वर्ष, जिससे उक्त अनुमोदन की ईप्सा की गई है, से सुसंगत पूर्व वर्ष के आरंभ से कम से कम एक मास पूर्व कार्यकलाप आरंभ नहीं किया है ;

(आ) कार्यकलाप आरंभ कर दिया है और जहां उक्त संस्था या निधि की किसी आय या उसके किसी भाग को, ऐसे कार्यकलाप आरंभ करने के पश्चात् किसी समय ऐसे आवेदन की तारीख को या उससे पूर्व समाप्त होने वाले किसी पूर्व वर्ष के लिए धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) या धारा 11 या धारा 12 के लागू होने के कारण कुल आय से अपवर्जित किया गया है :”;

(ii) दूसरे परंतुक में,—

(क) खंड (ii) में,—

(1) प्रारंभिक भाग में “खंड (iii)” शब्द, कोष्ठक और अक्षरों के पश्चात्, “या खंड (iv) का उपखंड (ख)” शब्द, कोष्ठक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(2) उपखंड (ख) में, मद (आ) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(आ) यदि उसका समाधान नहीं होता है तो वह सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात्,—

(I) पहले परंतुक के खंड (ii) या खंड (iii) में निर्दिष्ट किसी मामले में ऐसे आवेदन को नामंजूर करते हुए और साथ ही उसके अनुमोदन को रद्द करते हुए लिखित आदेश पारित करेगा ; या

(II) पहले परंतुक के खंड (iv) के उपखंड (आ) में निर्दिष्ट किसी मामले में ऐसे आवेदन को नामंजूर करते हुए लिखित आदेश पारित करेगा ;”;

(ख) खंड (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा,

अर्थात् :—

“(iii) जहां आवेदन उक्त परंतुक के खंड (iv) के उपखंड (अ) के अधीन किया गया है या आवेदन उक्त परंतुक के खंड (iv), जैसा कि वह वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा उसके संशोधन से ठीक पूर्व यथाविद्यमान था, के अधीन किया गया है, वहां वह उस निर्धारण वर्ष, जिससे अनुमोदन की ईप्सा की गई है, से तीन वर्ष की अवधि के लिए अनंतिम रूप से अनुमोदन मंजूर करते हुए लिखित आदेश पारित करेगा,”;

(आ) तीसरे परंतुक में, “पहले परंतुक” शब्दों के स्थान पर, “दूसरे परंतुक” शब्द रखे जाएंगे ।

41. आय-कर अधिनियम की धारा 80झकग के स्पष्टीकरण के खंड (ii) के उपखंड (क) में, “2023” अंकों के स्थान पर, “2024” अंक रखे जाएंगे ।

धारा 80झकग का संशोधन ।

42. आय-कर अधिनियम की धारा 80ठक की उपधारा (1) में, खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

धारा 80ठक का संशोधन ।

“परंतु 1 अप्रैल, 2023 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए, इस खंड के अधीन कटौती ऐसी आय की एक सौ प्रतिशत होगी ।”।

43. आय-कर अधिनियम की धारा 87 में,—

धारा 87 का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) में, “या धारा 88 या धारा 88क या धारा 88ख या धारा 88ग या धारा 88घ” शब्दों, अंकों और अक्षरों का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (2) में, “या धारा 88 या धारा 88क या धारा 88ख या धारा 88ग या धारा 88घ” शब्दों, अंकों और अक्षरों का लोप किया जाएगा ।

44. आय-कर अधिनियम की धारा 87क में, निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2024 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

धारा 87क का संशोधन ।

“परंतु जहां निर्धारिती की कुल आय धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है, और कुल आय—

(क) सात लाख रुपए से अधिक नहीं है, तो निर्धारिती (इस अध्याय के अधीन कटौतियों के लिए अनुज्ञात करने के पूर्व यथासंगणित) उसकी कुल आय पर आय-कर की रकम से कटौती का हकदार होगा जिसके लिए वह किसी निर्धारण वर्ष के लिए ऐसे आय-कर के सौ प्रतिशत के बराबर रकम या पच्चीस हजार रुपए की रकम, जो भी कम हों, से प्रभार्य है ;

(ख) सात लाख रुपए से अधिक है तथा ऐसी कुल आय पर संदेय आय-कर ऐसी रकम से अधिक है जिसके द्वारा कुल आय सात लाख रुपए से अधिक है, तो निर्धारिती (इस अध्याय के अधीन कटौतियों के लिए अनुज्ञात करने के पूर्व यथासंगणित) उसकी कुल आय पर उस रकम के बराबर रकम पर कटौती का हकदार होगा जिसके द्वारा ऐसी कुल आय पर संदेय आय-कर उस रकम से अधिक है जिसके द्वारा कुल आय सात लाख रुपए से अधिक होती है ।”।

45. आय-कर अधिनियम की धारा 88 का लोप किया जाएगा ।

धारा 88 का लोप ।

धारा 92खक का संशोधन ।

46. आय-कर अधिनियम की धारा 92खक में, खंड (vक) के पश्चात् निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2024 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,—

“(vख) धारा 115खकड की उपधारा (4) में यथानिर्दिष्ट निर्धारिती और अन्य व्यक्ति के बीच संव्यवहार किया गया कोई कारबार”;

धारा 92घ का संशोधन ।

47. आय-कर अधिनियम की धारा 92घ की उपधारा (3) में “तीस दिन की अवधि” शब्दों के स्थान पर, “दस दिन की अवधि” दोनों स्थानों पर, जहां-जहां वे आते हैं, शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 94ख का संशोधन ।

48. आय-कर अधिनियम की धारा 94ख में, 1 अप्रैल, 2024 से,—

(i) उपधारा (3) में, “भारतीय कंपनी या विदेशी कंपनी के स्थायी” शब्दों के स्थान पर, “भारतीय कंपनी या विदेशी कंपनी या गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों के ऐसे वर्ग, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचित किया जाए, के स्थायी” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (5) में, खंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘(iik) “गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी” का वही अर्थ होगा, जो धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (viiक) के स्पष्टीकरण के खंड (vii) में उसका है ;’।

धारा 111क का संशोधन ।

49. आय-कर अधिनियम की धारा 111क की उपधारा (3) का लोप किया जाएगा ।

धारा 112 का संशोधन ।

50. आय-कर अधिनियम की धारा 112 की उपधारा (3) का लोप किया जाएगा ।

धारा 115क का संशोधन ।

51. आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1) में 1 अप्रैल, 2024 से,—

(i) खंड (क) के उपखंड (अ) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु धारा 80ठक की उपधारा (1क) में यथानिर्दिष्ट किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में किसी यूनिट से प्राप्त लाभान्श के माध्यम से आय की रकम पर संगणित आय-कर की रकम, दस प्रतिशत होगी ;”;

(ii) खंड (ख) के उपखंड (अ) और उपखंड (आ) में, “दस” शब्द के स्थान पर “बीस” शब्द रखा जाएगा ।’।

धारा 115खकग का संशोधन ।

52. आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग में,—

(अ) 1 अप्रैल, 2024 से—

(क) पार्श्व शीर्ष में “हिन्दू अविभक्त कुटुंब” शब्दों के स्थान पर, “हिन्दू अविभक्त कुटुंब और अन्य” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (1) में, “1 अप्रैल, 2021” अंकों और शब्द के स्थान पर, “1 अप्रैल, 2021 किंतु 1 अप्रैल, 2024 से पूर्व” अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की

जाएगी, अर्थात् :—

“(1क) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किंतु अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति संगम (किसी सहकारी सोसाइटी से भिन्न) या व्यक्ति निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं या धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति से भिन्न, जो उपधारा (6) के अधीन किसी विकल्प का प्रयोग करता है, किसी कृत्रिम विधिक व्यक्ति की कुल आय के संबंध में 1 अप्रैल, 2024 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कुल आय के संबंध में संदेय आय-कर की संगणना निम्नलिखित सारणी में दी गई दर पर की जाएगी, अर्थात् :—

सारणी

क्रम सं.	कुल आय	कर की दर
(1)	(2)	(3)
1.	3,00,000 रुपए तक	शून्य
2.	3,00,001 रुपए से 6,00,000 रुपए तक	5 प्रतिशत
3.	6,00,001 रुपए से 9,00,000 रुपए तक	10 प्रतिशत
4.	9,00,001 रुपए से 12,00,000 रुपए तक	15 प्रतिशत
5.	12,00,001 रुपए से 15,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
6.	15,00,001 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत”;

(आ) 1 अप्रैल, 2023 से, उपधारा (2) के खंड (i) में, “धारा 80गगघ की उपधारा (2) या” शब्दों, अंकों और अक्षरों के पश्चात्, “धारा 80गगज की उपधारा (2) या” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(इ) 1 अप्रैल, 2024 से,—

(क) उपधारा (2) में, प्रारंभिक पंक्ति और खंड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(2) उपधारा (1क) के प्रयोजनों के लिए, इसमें निर्दिष्ट व्यक्ति की कुल आय की संगणना,—

(i) धारा 10 के खंड (5) या खंड (13क) के अधीन या खंड (14) (ऐसे प्रयोजन से भिन्न, जो इस प्रयोजन के लिए विहित किए जाएं) या खंड (17) या खंड (32) या धारा 10कक या धारा 16 के खंड (ii) या खंड (iii) या धारा 24 के खंड (ख) [धारा 23 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट संपत्ति की बाबत] या धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (ii)क या धारा 32कख या धारा 32कघ या धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) या खंड (ii)क या खंड (iii) या उपधारा (2कक) या

धारा 35कघ या धारा 35गगग या धारा 80गगघ की उपधारा (2) या धारा 80गगज की उपधारा (2) या धारा 80अनकक के उपबंधों से भिन्न अध्याय 7क के किसी भी उपबंध के अधीन किसी छूट या कटौती के बिना की जाएगी ;”;

(ख) उपधारा (3) के परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह और कि—

(i) ऐसी दशा में, जहां निर्धारिती ने 1 अप्रैल, 2023 को या उससे पूर्व प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष के लिए उपधारा (5) के अधीन किसी विकल्प का उपयोग नहीं किया है ;

(ii) निर्धारिती की कुल आय पर आय-कर की संगणना उपधारा (1क) के अधीन की गई है ; और

(iii) आस्तियों के किसी खंड की बाबत अवक्षयण मोक है, जिसको 1 अप्रैल, 2024 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से पूर्व पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं किया गया है,

तत्स्थानी समायोजन ऐसी आस्ति खंड के अवलिखित मूल्य पर, 1 अप्रैल, 2023 की स्थिति के अनुसार यथाविहित रीति में किया जाएगा ।”;

(ग) उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

‘(4) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जिसके पास धारा 80ठक की उपधारा (1क) में यथानिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की कोई यूनिट है,—

(i) जिसने 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष से सुसंगत, पूर्ववर्ष के लिए किंतु 1 अप्रैल, 2024 से पूर्व उपधारा (5) के अधीन विकल्प का उपयोग किया है;

(ii) जिसकी कुल आय की संगणना उपधारा (1क) के अधीन की गई है,

उपधारा (2) में अंतर्विष्ट शर्तों को उस परिमाण तक उपांतरित किया जाएगा कि धारा 80ठक के अधीन कटौती ऐसी यूनिट को उक्त धारा में अंतर्विष्ट शर्तों के पूरा होने के अधीन रहते हुए उपलब्ध होगी ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, “यूनिट” पद का वही अर्थ होगा, जो उसका विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (यग) में है”;

(घ) उपधारा (5) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह और कि इस उपधारा के उपबंध 1 अप्रैल, 2024 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष को लागू नहीं होंगे ।”;

(ङ) उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की

जाएगी, अर्थात् :—

“(6) उपधारा (1क) में अंतर्विष्ट कोई बात, उस व्यक्ति को लागू नहीं होगी जहां किसी निर्धारण वर्ष के लिए यथाविहित रीति में, ऐसे व्यक्ति द्वारा विकल्प का प्रयोग किया जाता है और ऐसा विकल्प,—

(i) कारबार या वृत्ति से आय वाले व्यक्ति की दशा में ऐसे निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उसके पूर्व प्रयोग किया जाएगा, और एक बार प्रयोग करने पर ऐसा विकल्प पश्चात्तर्वर्ती निर्धारण वर्षों के लिए लागू होगा ; या

(ii) खंड (i) में निर्दिष्ट आय न रखने वाले व्यक्ति की दशा में, ऐसे निर्धारण वर्ष के लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली आय की विवरणी के साथ प्रयोग किया जाएगा :

परंतु खंड (i) के अधीन विकल्प किसी पूर्ववर्ष के लिए एक बार प्रयोग होने पर उस वर्ष से भिन्न जिसमें इसे प्रयोग किया गया था, एक पूर्ववर्ष के लिए केवल एक बार वापस लिया जा सकेगा और तत्पश्चात्, सिवाय जहां ऐसा व्यक्ति कारबार या वृत्ति से कोई आय नहीं रखता है, इस उपधारा के अधीन विकल्प के प्रयोग के लिए कभी भी पात्र नहीं होगा, उस दशा में खंड (ii) के अधीन विकल्प उपलब्ध रहेगा ।’।

53. आय-कर अधिनियम की धारा 115खकघ की उपधारा (1) में, “किंतु” शब्द के पश्चात्, “धारा 115खकड के अधीन उल्लिखित उपबंधों से भिन्न” शब्द 1 अप्रैल, 2024 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा
115खकघ का
संशोधन ।

54. आय-कर अधिनियम की धारा 115खकघ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2024 से, अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

नई धारा
115खकड का
अंतःस्थापन ।

“115खकड (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किंतु धारा 115खकघ के अधीन उल्लिखित उपबंधों से भिन्न इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, 1 अप्रैल, 2024 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती, जो भारत में निवासी सहकारी सोसाइटी है, की कुल आय के संबंध में संदेय आय-कर, ऐसे निर्धारिती के विकल्प पर पंद्रह प्रतिशत की दर पर संगणित किया जाएगा, यदि उपधारा (2) में अंतर्विष्ट शर्तों को पूरा किया जाता है :

नई धारा
115खकड का
अंतःस्थापन ।
कतिपय नई
विनिर्माता
सहकारी
सोसाइटियों की
आय पर कर ।

परंतु जहां निर्धारिती की कुल आय के अंतर्गत कोई ऐसी आय सम्मिलित है जो किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन से न तो व्युत्पन्न है न ही उसके आनुषंगिक है तथा जिसके संबंध में इस अध्याय के अधीन पृथक् रूप से कर की किसी विनिर्दिष्ट दर का उपबंध नहीं किया गया है, तो ऐसी आय बाईस प्रतिशत की दर पर कर योग्य होगी तथा ऐसी आय की संगणना में किए गए किसी व्यय या भत्ते के संबंध में कोई कटौती या मोक नहीं किया जाएगा :

परंतु यह और कि उपधारा (4) के दूसरे परंतुक के अधीन ऐसी समझी गयी निर्धारिती की आय के संबंध में संदेय आय-कर, तीस प्रतिशत की दर पर संगणित किया जाएगा :

परंतु यह भी कि पूंजी आस्ति के अंतरण से व्युत्पन्न अल्प अवधि पूंजी अभिलाषों से आय, जिस पर अधिनियम के अधीन कोई अवक्षयण अनुज्ञेय नहीं है, के संबंध में संदेय आय-कर बाईस प्रतिशत की दर पर संगणित किया जाएगा :

परंतु यह भी कि जहां किसी पूर्ववर्ष में उपधारा (2) में अंतर्विष्ट शर्तों को पूरा करने में निर्धारिती असफल रहता है तो उस पूर्व वर्ष तथा पश्चात्पूर्वी निर्धारण वर्षों से सुसंगत निर्धारण वर्ष के संबंध में विकल्प अविधिमान्य हो जाएगा तथा निर्धारिती को अधिनियम के अन्य उपबंध लागू होंगे मानो उस पूर्व वर्ष तथा पश्चात्पूर्वी निर्धारण वर्षों से सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया था ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी, अर्थात् :—

(क) सहकारी सोसाइटी का गठन और रजिस्ट्रीकरण 1 अप्रैल, 2023 को या उसके पश्चात् किया गया है तथा उसमें 31 मार्च, 2024 को या उसके पूर्व किसी वस्तु या चीज का विनिर्माण या उत्पादन आरंभ कर दिया है तथा,—

(i) कारबार, पहले से ही विद्यमान कारबार को बांटकर या पुनः निर्मित करके नहीं किया गया है ;

(ii) किसी प्रयोजन के लिए पहले से ही प्रयुक्त मशीनरी या संयंत्र का उपयोग नहीं करता है ।

स्पष्टीकरण 1—उपखंड (ii) के प्रयोजनों के लिए, कोई मशीनरी या संयंत्र, जिसका उपयोग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किया गया था, किसी प्रयोजन के लिए पहले से प्रयुक्त मशीनरी या संयंत्र नहीं माना जाएगा यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाती हैं, अर्थात् :—

(अ) ऐसी मशीनरी या संयंत्र संस्थापित करने की तारीख से पहले किसी भी समय भारत में प्रयुक्त नहीं हुई थी ;

(आ) ऐसी मशीनरी या संयंत्र भारत के बाहर किसी देश से भारत में आयातित की गई थी ; और

(इ) व्यक्ति द्वारा मशीनरी या संयंत्र को संस्थापित करने की तारीख से पूर्व किसी भी अवधि के लिए किसी व्यक्ति की कुल आय की संगणना करने में इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन ऐसी मशीनरी या संयंत्र के संबंध में अवक्षयण के मददे कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की गई है या अनुज्ञेय नहीं है ।

स्पष्टीकरण 2—जहां किसी प्रयोजन के लिए पूर्व में प्रयुक्त कोई मशीनरी या संयंत्र या उसका कोई भाग, निर्धारिती द्वारा प्रयोग के लिए रखा जाता है और ऐसी मशीनरी या संयंत्र या उसके भाग का कोई मूल्य निर्धारिती द्वारा प्रयुक्त मशीनरी या संयंत्र के कुल मूल्य के बीस प्रतिशत से अनधिक है, तो उपखंड (ii) के प्रयोजनों के लिए उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन किया गया समझा जाएगा ;

(ख) निर्धारिती किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन के कारबार और इसके द्वारा विनिर्मित या उत्पादित ऐसी वस्तु या चीज के संबंध में अनुसंधान या उसके वितरण से भिन्न किसी अन्य कारबार में नहीं लगा है।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है

कि किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन के कारबार के अंतर्गत विद्युत के उत्पादन का कारबार भी सम्मिलित होगा, किंतु निम्नलिखित का कारबार सम्मिलित नहीं होगा,—

- (i) किसी भी रूप में या किसी माध्यम में कंप्यूटर साफ्टवेयर का विकास ;
 - (ii) खनन ;
 - (iii) संगमरमर खंडों या वैसी ही चीजों को पट्टियों में परिवर्तित करना ;
 - (iv) सिलेंडर में गैस भरना ;
 - (v) पुस्तकों का मुद्रण या सिनेमेटोग्राफ फिल्म का निर्माण ; या
 - (vi) कोई अन्य कारबार, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाए ;
- (ग) निर्धारिती की कुल आय,—

(i) धारा 10कक या धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (iiक) या धारा 33कख अथवा धारा 33कखक या धारा 35 की उपधारा (1) के उपखंड (ii), उपखंड (iiक) या उपखंड (iii) या उपधारा (2कक) या धारा 35कघ अथवा धारा 35गगग के उपबंधों के अधीन या धारा 80त्रकक के उपबंधों से भिन्न अध्याय 6क के किन्हीं उपबंधों के अधीन किसी कटौती के बिना ;

(ii) अग्रणीत किसी हानि के मुजरा या किसी पूर्ववर्ती निर्धारण वर्ष से अवक्षयण के बिना, यदि ऐसी हानि या अवक्षयण खंड (i) में निर्दिष्ट किन्हीं कटौतियों के कारण हुआ माना जा सकता है ; और

(iii) उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (iiक) से भिन्न, धारा 32 के अधीन ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अवधारित अवक्षयण का दावा करके, यदि कोई हों,

की संगणना की गई है ।

(3) उपधारा (2) के खंड (ग) के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट हानि और अवक्षयण पूर्ण रूप से प्रभावी किया गया समझा जाएगा तथा ऐसी हानि के लिए कोई और कटौती किसी पश्चात्त्वर्ती वर्ष के लिए अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(4) जहां निर्धारण अधिकारी को ऐसा प्रतीत होता है कि निर्धारिती जिसको यह धारा लागू होती है तथा किसी अन्य व्यक्ति के बीच कोई निकट संबंध होने के कारण या किसी अन्य कारण से उनके बीच कारबार का अनुक्रम इस प्रकार व्यवस्थित है कि उनके बीच संव्यवहार किया गया कारबार निर्धारिती को साधारण लाभों, जिनकी ऐसे कारबार में उद्भूत होने की प्रत्याशा है, से अधिक लाभ प्रदान करता है, तो निर्धारण अधिकारी इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे कारबार से लाभों और अभिलाभों की गणना करने में लाभों की ऐसी रकम संगणना में लेगा, जो व्यक्तियुक्त रूप से उससे व्युत्पन्न प्रतीत हों :

परंतु उस दशा में, जहां धारा 92खक में निर्दिष्ट किसी विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार पूर्वोक्त ठहराव में अंतर्वलित है, तो ऐसे संव्यवहार से लाभ की रकम धारा 92च के खंड (ii) में यथा परिभाषित सन्निकट कीमत का ध्यान रखते हुए अवधारित की जाएगी :

परंतु यह और भी कि निर्धारण अधिकारी द्वारा अवधारित लाभ की रकम से अधिक लाभ की रकम, निर्धारिती की आय समझी जाएगी ।

(5) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात लागू नहीं होगी, यदि 1 अप्रैल, 2024 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्व वर्ष के लिए आय की पहली विवरणी प्रस्तुत करने के लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उसके पूर्व विहित रीति में, व्यक्ति द्वारा विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता है :

परंतु किसी पूर्ववर्ष के लिए विकल्प का प्रयोग हो जाने पर, इसे उसी या किसी अन्य पूर्ववर्ष के लिए तत्पश्चात् वापस नहीं लिया जा सकता ।”।

55. आय-कर अधिनियम की धारा 115खख में, स्पष्टीकरण के स्थान पर, 1 अप्रैल, 2024 से, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

‘परंतु इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात, 1 अप्रैल, 2024 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए किसी आनलाइन खेल से जीत के माध्यम से आय पर लागू नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) “घुड़दौड़” का वही अर्थ होगा, जो धारा 74क में उसका है ;

(ii) “आनलाइन खेल” का वही अर्थ होगा, जो धारा 115खख में उसका है ।”।

56. आय-कर अधिनियम की धारा 115खख के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2024 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

‘115खख. (1) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी निर्धारिती की कुल आय के अंतर्गत किसी आनलाइन खेल से जीत के माध्यम से आय भी है, संदेय आय-कर निम्नलिखित का कुल योग होगा—

(i) पूर्ववर्ष के दौरान ऐसे आनलाइन खेलों से शुद्ध जीतों पर संगणित आय-कर की रकम, उस रीति में, जो विहित की जाए, संगणित तीस प्रतिशत की दर पर होगी ; और

(ii) आय-कर की रकम, जो निर्धारिती पर प्रभार्य होती यदि उसकी कुल आय, खंड (i) में निर्दिष्ट शुद्ध जीतों से घटा दी गई होती ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) “कंप्यूटर संसाधन” का वही अर्थ होगा, जो धारा 144ख के स्पष्टीकरण के खंड (ड) में उसका है ;

(ii) “इंटरनेट” से अंतर-संबंधित विश्वव्यापी कंप्यूटर नेटवर्क से मिलकर बनी कंप्यूटर सुविधाओं और इलेक्ट्रो-मैग्नेटिक पारेषण मीडिया तथा संबंधित उपस्कर और साफ्टवेयर का संयोजन अभिप्रेत है, जो ऐसे पारेषण का नियंत्रण करने के लिए प्रोटोकाल के आधार पर सूचना का पारेषण करता है ;

(iii) “आनलाइन खेल” से वह खेल अभिप्रेत है, जिसे इंटरनेट पर प्रस्तावित किया जाता है और वह किसी उपयोक्ता द्वारा कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से पहुंच योग्य है, जिसके अंतर्गत कोई दूरसंचार युक्ति भी है ।”।

धारा 115खख
का संशोधन ।

नई धारा
115खख का
अंतःस्थापन ।
आनलाइन खेल
से जीत पर
कर ।

धारा 115अग का
संशोधन ।

57. आय-कर अधिनियम की धारा 115अग में, उपधारा (5) के स्थान पर, 1 अप्रैल, 2024 से, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(5) इस धारा के उपबंध ऐसे किसी व्यक्ति को लागू नहीं होंगे, जहां,—

(i) ऐसे व्यक्ति ने धारा 115खकग की उपधारा (5) या धारा 115खकघ की उपधारा (5) या धारा 115खकड की उपधारा (5) में निर्दिष्ट विकल्प का प्रयोग किया है ; या

(ii) ऐसे व्यक्ति की कुल आय के संबंध में संदेय आय-कर, धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन संगणित किया जाता है ।”।

58. आय-कर अधिनियम की धारा 115अघ में, उपधारा (7) के स्थान पर, 1 अप्रैल, 2024 से, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

धारा 115अघ
का संशोधन ।

“(7) इस धारा के उपबंध ऐसे किसी व्यक्ति को लागू नहीं होंगे, जहां,—

(i) ऐसे व्यक्ति ने धारा 115खकग की उपधारा (5) या धारा 115खकघ की उपधारा (5) या धारा 115खकड की उपधारा (5) में निर्दिष्ट विकल्प का प्रयोग किया है ; या

(ii) ऐसे व्यक्ति की कुल आय के संबंध में संदेय आय-कर, धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन संगणित किया जाता है ।”।

59. आय-कर अधिनियम की धारा 115नघ में,—

धारा 115नघ
का संशोधन ।

(i) उपधारा (3) में,—

(क) खंड (ii) के उपखंड (ख) में, “अस्वीकार कर दिया गया है ।” शब्दों के स्थान पर, “अस्वीकार कर दिया गया है ; या” रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(iii) वह, धारा 10 के खंड (23ग) के पहले परंतुक के खंड (i) या खंड (ii) या खंड (iii) या धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (कग) के उपखंड (i) या उपखंड (ii) या उपखंड (iii) के उपबंधों के अनुसार, यथास्थिति, उक्त खंडों या उपखंडों में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, जो उक्त पूर्ववर्ष में समाप्त हो गई है, आवेदन करने में असफल रहता है ।”;

(ii) उपधारा (5) के खंड (ii) में, “खंड (ii) के उपखंड (क)” शब्द, कोष्ठकों और अंकों के पश्चात्, “खंड (ii) या खंड (iii)” शब्द, कोष्ठक और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(iii) स्पष्टीकरण के खंड (i) में,—

(क) उपखंड (ख) में, “उपांतरित करने की तारीख ;” शब्दों के स्थान पर, “उपांतरित करने की तारीख ; या” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपखंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(ग) उपधारा (3) के खंड (iii) में निर्दिष्ट किसी मामले में, यथास्थिति, धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (कग) के उपखंड (i) या उपखंड (ii) या उपखंड (iii) के अधीन रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन करने या धारा 10 के खंड (23ग) के पहले परंतुक के खंड (i) या खंड (ii) या

खंड (iii) के अधीन अनुमोदन हेतु आवेदन करने की अंतिम तारीख ;”।

60. आय-कर अधिनियम की धारा 115पक में, उपधारा (3) के पश्चात् 1 अप्रैल, 2024 से निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

धारा 115पक
का संशोधन ।

“(3क) उपधारा (1) के उपबंध किसी कारबार न्यास से किसी यूनिट धारक द्वारा प्राप्त की गई ऐसी किसी राशि के संबंध में लागू नहीं होंगे, जिसे धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (xii) में निर्दिष्ट किया गया है ।”।

धारा 115पख का
संशोधन ।

61. आय-कर अधिनियम की धारा 115पख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (क) में, “जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (आनुकल्पिक विनिधान निधि) विनियम, 2012 के अधीन” शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, “जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (आनुकल्पिक विनिधान निधि) विनियम, 2012 या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अधीन बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंध) विनियम, 2022 के अधीन विनियमित” शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

1992 का 15

2019 का 50

1992 का 15

2019 का 50

धारा 115फत का
संशोधन ।

62. आय-कर अधिनियम की धारा 115फत में,—

(i) उपधारा (2) में परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह और कि किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र की कोई यूनिट, जिसने धारा 80ठक के अधीन कटौती प्राप्त की है, उस तारीख से जिसको ऐसी कटौती रुक जाती है, तीन मास के भीतर आवेदन कर सकेगी ।”;

(ii) उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र” का वही अर्थ होगा, जो उसका विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (थ) में है ।’।

2005 का 28

धारा 116 का
संशोधन ।

63. आय-कर अधिनियम की धारा 116 के खंड (गगक) में, “आय-कर संयुक्त आयुक्त” शब्दों के पश्चात्, “या आय-कर संयुक्त आयुक्त (अपील)” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 119 का
संशोधन ।

64. आय-कर अधिनियम की धारा 119 में, “आयुक्त (अपील)” शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, “संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

धारा 131 का
संशोधन ।

65. आय-कर अधिनियम की धारा 131 में, “आयुक्त (अपील)” शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, “संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

धारा 132 का
संशोधन ।

66. आय-कर अधिनियम की धारा 132 में,—

(क) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(2) प्राधिकृत अधिकारी, उपधारा (1) या उपधारा (1क) में विनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं प्रयोजनों में अपनी सहायता के लिए, निम्नलिखित की सेवाओं की अध्यपेक्षा कर सकेगा—

(i) किसी पुलिस अधिकारी या केंद्रीय सरकार के किसी अधिकारी, या दोनों ; या

(ii) किसी अन्य व्यक्ति या इकाई, जैसा इस संबंध में ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जो विहित की जाए, प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त, प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा अनुमोदित किया जाए,

और ऐसे प्रत्येक अधिकारी या व्यक्ति या इकाई का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी अध्यपेक्षा का अनुपालन करे।”;

(ख) उपधारा (9घ) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(9घ) प्राधिकृत अधिकारी, तलाशी या अभिग्रहण के दौरान या उस तारीख से, जिसको तलाशी के लिए अंतिम प्राधिकारों का निष्पादन किया गया था, साठ दिन की अवधि के भीतर,—

(i) धारा 142क में निर्दिष्ट मूल्यांकन अधिकारी को, या

(ii) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा या अधीन किसी अन्य व्यक्ति या इकाई या किसी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक को जैसा कि प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा इस संबंध में ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जो विहित की जाए, अनुमोदित किया जाए,

निर्देश कर सकेगा, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संपत्ति के उचित बाजार मूल्य का प्राक्कलन करेगा तथा, यथास्थिति, प्राधिकृत अधिकारी या निर्धारण अधिकारी को प्राक्कलन की रिपोर्ट ऐसे निर्देश की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा।”।

(ग) स्पष्टीकरण 1 के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा और 1 अप्रैल, 2022 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

‘स्पष्टीकरण 1—उपधारा (9क), उपधारा (9ख) और उपधारा (9घ) के प्रयोजनों के लिए, “तलाशी के लिए अंतिम प्राधिकार” को,—

(क) तलाशी के मामले में, ऐसे किसी व्यक्ति के संबंध में, जिसके मामले में प्राधिकार का वारंट जारी किया जा चुका है, तैयार अंतिम पंचनामे में यथा अभिलिखित तलाशी के पूर्ण होने पर ; या

(ख) धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा के मामले में, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों या आस्तियों की वास्तविक प्राप्ति पर,

निष्पादित किया गया समझा जाएगा।”।

67. आय-कर अधिनियम की धारा 133 में, “आयुक्त (अपील)” शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, “संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

धारा 133 का संशोधन।

68. आय-कर अधिनियम की धारा 134 में, “आयुक्त (अपील)” शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां कहीं वे आते हैं, “संयुक्त आयुक्त (अपील) या

धारा 134 का संशोधन।

आयुक्त (अपील)” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

69. आय-कर अधिनियम की धारा 135क की उपधारा (2) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2022 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

धारा 135क
का संशोधन ।

“परंतु यह और कि केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस उपधारा के अधीन 31 मार्च, 2022 को या उसके पूर्व जारी किसी निदेश का संशोधन कर सकेगी।”।

धारा 140ख का
संशोधन ।

70. आय-कर अधिनियम की धारा 140ख की उपधारा (4) में, 1 अप्रैल, 2022 से,—

(i) प्रारंभिक भाग में, “यथास्थिति, जो निर्धारित कर के बराबर है, रकम पर की जाएगी या उतनी रकम पर, जितनी से संदत्त अग्रिम कर निर्धारिती कर से कम पड़ जाता है” शब्दों के स्थान पर, “जो निर्धारित कर के बराबर है, रकम पर की जाएगी” शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे ;

(ii) खंड (क) के उपखंड (i) में, “पूर्वतर विवरणी” शब्दों के पश्चात्, “, यदि कोई हो,” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे और अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे ।

धारा 142 का
संशोधन ।

71. आय-कर अधिनियम की धारा 142 में,—

(क) उपधारा (2क) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(2क) यदि निर्धारण अधिकारी के समक्ष कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम पर, उसकी लेखाओं की प्रकृति और जटिलता, लेखाओं की मात्रा, लेखाओं के सही होने के बारे में संदेहों, लेखाओं में संव्यवहारों की बहुलता या निर्धारिती के कारबार क्रियाकलाप की विशेषीकृत प्रकृति को ध्यान में रखते हुए तथा राजस्व के हित में, यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक है तो वह प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से निर्धारिती को निम्नलिखित एक या दोनों, अर्थात् :—

(i) प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा इस निमित्त नामनिर्देशित, धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित किसी लेखाकार द्वारा लेखाओं की संपरीक्षा करवाने तथा ऐसे लेखाकार द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित तथा सत्यापित विहित प्ररूप में ऐसी विशिष्टियां संलग्न करते हुए, जो विहित की जाएं तथा ऐसी अन्य विशिष्टियां, जिनकी निर्धारण अधिकारी अपेक्षा करे, ऐसी संपरीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करने ;

(ii) प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा इस निमित्त नामनिर्देशित लागत लेखाकार द्वारा तालिका का मूल्यांकन करवाने तथा ऐसे लागत लेखाकार द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित तथा सत्यापित विहित प्ररूप में ऐसी विशिष्टियां संलग्न करते हुए, जो विहित की जाएं तथा ऐसी अन्य विशिष्टियां, जिनकी निर्धारण अधिकारी अपेक्षा करे, ऐसी संपरीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करने,

के लिए निदेशित कर सकेगा :

परंतु निर्धारण अधिकारी निर्धारिती को लेखा इस प्रकार संपरीक्षित करवाने या तालिका का इस प्रकार मूल्यांकन करवाने के लिए निदेशित नहीं करेगा, यदि निर्धारिती को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया गया है;”;

(ख) उपधारा (2घ) में,—

(i) “किसी संपरीक्षा के व्यय तथा उसके आनुषंगिक व्यय (जिनके अंतर्गत लेखापाल का पारिश्रमिक भी है)” शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, “किसी संपरीक्षा या किसी तालिका मूल्यांकन, जिनके अंतर्गत, यथास्थिति, लेखापाल या लागत लेखापाल का पारिश्रमिक भी है” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) परंतुक में,—

(I) “किसी ऐसी संपरीक्षा के” शब्दों के स्थान पर, “किसी ऐसी संपरीक्षा या किसी ऐसी तालिका मूल्यांकन के” शब्द रखे जाएंगे ;

(II) “किसी ऐसी संपरीक्षा के और उसके आनुषंगिक व्यय (जिनके अंतर्गत लेखापाल का पारिश्रमिक भी है)” शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, “किसी ऐसी संपरीक्षा या किसी ऐसी तालिका मूल्यांकन (जिनके अंतर्गत, यथास्थिति, लेखापाल या लागत लेखापाल का पारिश्रमिक भी है)” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (3) में, “संपरीक्षा” शब्द के पश्चात् “या तालिका मूल्यांकन”, शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘स्पष्टीकरण’—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “लागत लेखापाल” से लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में यथापरिभाषित लागत लेखापाल अभिप्रेत है और जो उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन व्यवसाय करने का विधिमान्य प्रमाणपत्र धारण करता है ।’।

72. आय-कर अधिनियम की धारा 148 में,—

(क) “ऐसी अवधि के भीतर, जो ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए”, शब्दों के स्थान पर, “उस मास के अंत से, जिसमें सूचना जारी की जाए, से तीन मास की अवधि के भीतर, या ऐसी और अवधि, जो निर्धारिती द्वारा इस संबंध में किए गए आवेदन के आधार पर निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुज्ञात की जाए”, शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) दूसरे परंतुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण 1 से पूर्व, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह भी कि आय की कोई विवरणी, जिसका किसी निर्धारिती द्वारा इस धारा के अधीन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है और जिसे अनुज्ञात अवधि से परे प्रस्तुत किया गया है, को धारा 139 के अधीन विवरणी नहीं समझा जाएगा ।”।

73. आय-कर अधिनियम की धारा 149 की उपधारा (1) में,—

(I) दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे,

धारा 148 का
संशोधन ।

धारा 149 का
संशोधन ।

अर्थात् :—

“परंतु यह भी कि धारा 148 के स्पष्टीकरण 2 के खंड (i), खंड (iii) और खंड (iv) में निर्दिष्ट मामलों के लिए, जहां किसी वित्तीय वर्ष की 15 मार्च के पश्चात्,—

(क) धारा 132 के अधीन कोई तलाशी आरंभ की जाती है ; या

(ख) धारा 132 के अधीन कोई तलाशी, जिसके लिए अंतिम प्राधिकार का निष्पादन किया गया है ; या

(ग) धारा 132क के अधीन कोई अध्यपेक्षा की गई है,

और धारा 148 के अधीन सूचना जारी करने की अवधि ऐसे वित्तीय वर्ष की 31 मार्च को समाप्त हो रही है, वहां इस धारा के अनुसार परिसीमा की अवधि की संगणना के प्रयोजन के लिए पन्द्रह दिन की अवधि को अपवर्जित किया जाएगा और ऐसे किसी मामले में धारा 148 के अधीन जारी सूचना को ऐसे वित्तीय वर्ष की 31 मार्च को जारी किया गया समझा जाएगा :

परंतु यह भी कि जहां धारा 148 के स्पष्टीकरण 1 में यथानिर्दिष्ट जानकारी, यथास्थिति, धारा 131 या धारा 133क के अधीन लेखबद्ध किए गए किसी कथन या जब्त किए गए दस्तावेजों से निम्नलिखित के परिणामस्वरूप किसी वित्तीय वर्ष की 31 मार्च को या उससे पूर्व आती है और जहां किसी वित्तीय वर्ष की 15 मार्च के पश्चात्,—

(क) कोई तलाशी, जो धारा 132 के अधीन आरंभ की जाती है ; या

(ख) कोई तलाशी, जिसके लिए धारा 132 के अधीन अंतिम प्राधिकार का निष्पादन किया गया है ; या

(ग) कोई अध्यपेक्षा, जो धारा 132क के अधीन की गई है,

वहां इस धारा के अनुसार परिसीमा की अवधि की संगणना के प्रयोजन के लिए पन्द्रह दिन की अवधि को अपवर्जित किया जाएगा और ऐसे किसी मामले में धारा 148क के खंड (ख) के अधीन जारी सूचना को ऐसे वित्तीय वर्ष की 31 मार्च को जारी किया गया समझा जाएगा ;”

(II) छठवें परंतुक में, “परिसीमा की अवधि सात दिन से कम है” शब्दों के स्थान पर, “परिसीमा की अवधि सात दिन से अधिक नहीं होती है” शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 151 का
संशोधन ।

74. आय-कर अधिनियम की धारा 151 में,—

(क) खंड (ii) में “जहां कोई प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक नहीं है वहां” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) खंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतुक खंड (i) के प्रयोजनों के लिए, तीन वर्ष की अवधि की संगणना धारा 149 की उपधारा (1) के तीसरे परंतुक या चौथे परंतुक या पांचवें परंतुक द्वारा यथा अपवर्जित या छठवें परंतुक द्वारा बढ़ाई गई परिसीमा अवधि को हिसाब में लेने के पश्चात्, की जाएगी ।”।

धारा 153 का
संशोधन ।

75. आय-कर अधिनियम की धारा 153 में,—

(I) उपधारा (1) में,—

(क) तीसरे परंतुक में, “या उसके पश्चात्” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) तीसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह भी कि 1 अप्रैल, 2022 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से संबंधित निर्धारण के आदेश के संबंध में इस उपधारा के उपबंधों का वैसे ही प्रभाव होगा, मानो “इक्कीस मास” शब्दों के स्थान पर, “बारह मास” शब्द रख दिए गए हों ।”;

(II) उपधारा (1क) में, “नौ मास” शब्दों के स्थान पर, “बारह मास” शब्द रखे जाएंगे ;

(III) उपधारा (3) में,—

(क) “उपधारा (1) और उपधारा (2)” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, “उपधारा (1), उपधारा (1क) और उपधारा (2)” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) “प्रधान आयुक्त या आयुक्त” शब्दों और अंकों के स्थान पर, उन दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, “यथास्थिति, प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त” शब्द रखे जाएंगे ;

(IV) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(3क) उपधारा (1), उपधारा (1क), उपधारा (2) और उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, जहां निर्धारण या पुनः निर्धारण धारा 132 के अधीन तलाशी आरंभ किए जाने की या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा करने की तारीख को लंबित है, वहां उक्त उपधाराओं के अधीन, यथास्थिति, निर्धारण या पुनः निर्धारण के पूरा किए जाने के लिए उपलब्ध अवधि—

(क) उस मामले में, जहां ऐसी तलाशी धारा 132 के अधीन आरंभ की जाती है या ऐसी अध्यपेक्षा धारा 132क के अधीन की जाती है ;

(ख) ऐसे निर्धारिती के मामले में, जिससे अभिगृहीत या अध्यपेक्षित कोई धन, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज संबंधित है ;

(ग) ऐसे निर्धारिती के मामले में, जिससे अभिगृहीत या अध्यपेक्षित कोई लेखाबहियां या दस्तावेज संबंधित है या उनमें अंतर्विष्ट कोई सूचना उससे संबंधित है,

बारह मास तक बढ़ा दी जाएगी ।”;

(V) उपधारा (4) में, “उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3)” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, उन दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, “उपधारा (1), उपधारा (1क), उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (3क)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(VI) उपधारा (5) में, “प्रधान आयुक्त या आयुक्त” शब्दों और अंकों के स्थान

पर, “यथास्थिति, प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त” शब्द रखे जाएंगे ;

(VII) उपधारा (6) में,—

(क) आरंभिक भाग में, “उपधारा (1) और उपधारा (2)” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, “उपधारा (1), उपधारा (1क) और उपधारा (2)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (i) में, “यथास्थिति,” शब्द के पश्चात् “प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(VIII) स्पष्टीकरण 1 में,—

(क) खंड (iv) में,—

(i) आरंभिक भाग में, “संपरीक्षा” शब्दों के पश्चात्, “या तालिका मूल्यांकन” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उपखंड (क) में, “ऐसी संपरीक्षा” शब्दों के पश्चात्, “या तालिका मूल्यांकन” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) पहले परंतुक में, “उपधारा (1), उपधारा (2),” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, “उपधारा (1), उपधारा (1क), उपधारा (2),” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 154 का
संशोधन ।

76. आय-कर अधिनियम की धारा 154 में, उपधारा (2) में, “आयुक्त (अपील)” शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, “संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

धारा 155 का
संशोधन ।

77. आय-कर अधिनियम की धारा 155 में,—

(क) खंड (11क) में, “धारा 10क या” शब्दों, अंकों और अक्षर के पश्चात्, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, “धारा 10कक या” शब्द, अंक और अक्षर, 1 अप्रैल, 2024 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपधारा (18) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(19) जहां किसी निर्धारिती द्वारा, जो चीनी के विनिर्माण के कारबार में नियोजित एक सहकारी समिति है, द्वारा गन्ने के क्रय के लिए उपगत किसी व्यय की बाबत किसी कटौती का दावा किया गया है और ऐसी कटौती को 1 अप्रैल, 2014 को या उससे पूर्व प्रारंभ होने वाले किसी पूर्ववर्ष में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अननुज्ञात कर दिया गया है, तो निर्धारण अधिकारी, इस संबंध में ऐसे निर्धारिती द्वारा किए गए किसी आवेदन के आधार पर उस विस्तार तक कि ऐसा व्यय उस कीमत पर उपगत किया जाता है, जो उस पूर्ववर्ष के लिए सरकार द्वारा नियत या अनुमोदित कीमत के समतुल्य है या उससे कम है, ऐसी कटौती को अनुज्ञात करने के पश्चात् ऐसे पूर्ववर्ष के लिए ऐसे निर्धारिती की कुल आय की पुनःसंगणना करेगा और धारा 154 के उपबंध, जहां तक हो सके, उस पर लागू होंगे तथा उस धारा की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट चार वर्षों की अवधि को 1 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ होने वाले पूर्ववर्ष की समाप्ति से गणना में लिया जाएगा ।”;

(ग) उपधारा (19) के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित उपधारा, 1 अक्टूबर, 2023 से, अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

‘(20) जहां निर्धारिती द्वारा, धारा 139 के अधीन किसी निर्धारण वर्ष (जिसे इसमें “सुसंगत निर्धारण वर्ष” कहा गया है) के लिए प्रस्तुत आय की विवरणी में कोई आय सम्मिलित की गई है और ऐसी आय पर स्रोत से कर की कटौती की गई है और पश्चात्पूर्वी वित्तीय वर्ष में अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुसार केंद्रीय सरकार के खाते में संदत्त की गई है, निर्धारण अधिकारी, उस वित्तीय वर्ष, जिसमें स्रोत पर ऐसे कर की कटौती की गई थी, की समाप्ति से दो वर्ष के भीतर ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, निर्धारिती द्वारा किए गए आवेदन पर निर्धारण के आदेश या सुसंगत निर्धारण वर्ष में स्रोत पर कटौती किए गए ऐसे कर के प्रत्यय को अनुज्ञात करते हुए किसी सूचना का संशोधन करेगा और धारा 154 के उपबंध जहां तक हो सके, उस पर लागू होंगे और उस धारा की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट चार वर्षों की अवधि को वित्त वर्ष के अंत से जिसमें ऐसे कर की कटौती की गई है, गणना में लिया जाएगा :

परंतु स्रोत पर कटौती किए गए ऐसे कर के प्रत्यय को किसी अन्य निर्धारण वर्ष में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।’।

78. आय-कर अधिनियम की धारा 158क में, स्पष्टीकरण में, “आयुक्त (अपील)” शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, “संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

धारा 158क का संशोधन ।

79. आय-कर अधिनियम की धारा 158कख में, “आयुक्त (अपील)” शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, “संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

धारा 158कख का संशोधन ।

80. आय-कर अधिनियम की धारा 170क के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

धारा 170क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

‘170क. (1) धारा 139 में अंतर्विष्ट तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, कारबार पुनर्गठन की दशा में, जहां, यथास्थिति, उच्च न्यायालय या अधिकरण या दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 5 के खंड (1) में यथापरिभाषित न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के आदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् कारबार पुनर्गठन के संबंध में आदेश कहा गया है) की तारीख से पूर्व, उस पूर्ववर्ष, जिसको ऐसा आदेश लागू होता है, से सुसंगत किसी निर्धारण वर्ष के लिए धारा 139 के उपबंधों के अधीन इकाई द्वारा आय की कोई विवरणी प्रस्तुत की गई है, तो ऐसा उत्तराधिकारी, उस मास, जिसमें उक्त आदेश जारी किया गया था, के अंतिम दिन से छह मास की अवधि के भीतर, उक्त आदेश के अनुसार और उस तक सीमित, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, उपांतरित विवरणी प्रस्तुत करेगा ।

किसी कारबार पुनर्गठन के संबंध में अधिकरण या न्यायालय के किसी आदेश का प्रभाव ।

(2) जहां उस पूर्ववर्ष से, जिसको कारबार पुनर्गठन के संबंध में आदेश लागू होता है, सुसंगत किसी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण या पुनःनिर्धारण कार्यवाहियां, —

(क) उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उपांतरित विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख को पूर्ण हो गई हैं, तो निर्धारण अधिकारी, ऐसे आदेश के अनुसार और इस प्रकार प्रस्तुत उपांतरित विवरणी को ध्यान में रखते हुए, ऐसे निर्धारण

या पुनःनिर्धारण में अवधारित सुसंगत निर्धारण वर्ष की कुल आय को उपांतरित करने वाला कोई आदेश पारित करेगा ;

(ख) उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उपांतरित विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख को लंबित हैं, वहां निर्धारण अधिकारी, कारबार पुनर्गठन के आदेश के अनुसार और इस प्रकार प्रस्तुत उपांतरित विवरणी को ध्यान में रखते हुए, सुसंगत निर्धारण वर्ष की कुल आय का निर्धारण या पुनः निर्धारण करने वाला आदेश पारित करेगा ।

(3) इस धारा में यथा उपबंधित के सिवाय, इस धारा के अधीन किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में किए गए किसी निर्धारण या पुनः निर्धारण में इस अधिनियम के अन्य सभी उपबंध लागू होंगे तथा ऐसे निर्धारण वर्ष को यथा लागू दर या दरों पर कर प्रभाय होंगे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में,—

(i) “कारबार पुनर्गठन” पद से एक या अधिक व्यक्तियों के कारबार का समामेलन या निर्विलयन या विलयन अंतर्वलित करने वाला कारबार का पुनर्गठन अभिप्रेत है ;

(ii) “उत्तराधिकारी” पद से किसी कारबार पुनर्गठन में सभी परिणामी कंपनियां अभिप्रेत हैं, चाहे वह कंपनी ऐसे कारबार पुनर्गठन के पूर्व अस्तित्व में थी या नहीं ।’।

धारा 177 का संशोधन ।

81. आय-कर अधिनियम की धारा 177 में, उपधारा (2) में, “आयुक्त (अपील)” शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, “संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

धारा 189 का संशोधन ।

82. आय-कर अधिनियम की धारा 189 में, उपधारा (2) में, “आयुक्त (अपील)” शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, “संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

धारा 192क का संशोधन ।

83. आय-कर अधिनियम की धारा 192क के दूसरे परंतुक का लोप किया जाएगा ।

धारा 193 का संशोधन ।

84. आय-कर अधिनियम की धारा 193 के परंतुक में खंड (ix) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

‘(ix) धारा 10 के खंड (23चग) के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट किसी विशेष प्रयोजन यान द्वारा किन्हीं प्रतिभूतियों के संबंध में, धारा 2 के खंड (13क) में यथापरिभाषित, “कारबार न्यास” को संदेय कोई ब्याज ।’।

धारा 194ख का संशोधन ।

85. आय-कर अधिनियम की धारा 194ख में,—

(i) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात्:—

“लाटरी या वर्ग पहेली, आदि से जीत ।”;

(ii) दीर्घ पंक्ति में, “दस हजार रुपए से अधिक रकम” शब्दों के स्थान पर, “या जुआ से या किसी प्रकार के या किसी भी प्रकृति का दांव लगाने से, जो ऐसी रकम या रकमों का योग है जो वित्तीय वर्ष के दौरान दस हजार रुपए से अधिक है” शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘परंतु यह और कि इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात, 1 अप्रैल, 2023 को या उसके पश्चात् किसी आनलाइन खेल से जीत पर आय-कर की कटौती को लागू नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “आनलाइन खेल” का वही अर्थ होगा, जो धारा 115खखज के स्पष्टीकरण के खंड (iii) में उसका है ।’।

86. आय-कर अधिनियम की धारा 194ख के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

नई धारा
194खक का
अंतःस्थापन ।

‘194खक. (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वित्तीय वर्ष के दौरान किसी आनलाइन खेल से जीत के माध्यम से किसी आय को किसी व्यक्ति को संदत्त करने के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति, प्रवृत्त दरों पर वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर, विहित रीति में संगणित उसके उपयोक्ता खाते में शुद्ध जीत पर आय-कर की कटौती करेगा :

आनलाइन खेल
से जीत ।

परंतु उस मामले में, जहां वित्तीय वर्ष के दौरान उपयोक्ता खाते से रकम निकाली जाती है, तो आय-कर, ऐसी निकासी से मिलकर बनी शुद्ध जीत के साथ-साथ उपयोक्ता खाते में शुद्ध जीत की शेष रकम पर ऐसी निकासी के समय वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उस रीति में, जो विहित की जाए, संगणित किया जाएगा ।

(2) उस मामले में, जहां शुद्ध जीत पूर्णतः वस्तु रूप में है अथवा भागतः नकद रूप में और भागतः वस्तु रूप में है किन्तु नकदी का भाग संपूर्ण जीत की बाबत कर की कटौती के दायित्व को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, वहां ऐसा संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति जीत का निर्गम करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी शुद्ध जीत की बाबत कर का संदाय कर दिया गया है ।

(3) यदि इस धारा के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो बोर्ड, केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करेगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन बोर्ड द्वारा जारी किया गया प्रत्येक मार्गदर्शक सिद्धांत, इसे जारी करने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा, और आय-कर प्राधिकारियों तथा आय-कर की कटौती करने के लिए दायी व्यक्ति पर बाध्यकारी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “कंप्यूटर संसाधन”, “इंटरनेट” और “आनलाइन खेल” के वही अर्थ होंगे, जो क्रमशः धारा 115खखज में उनके हैं ;

(ख) “आनलाइन खेल मध्यवर्ती” से कोई मध्यवर्ती अभिप्रेत है, जो एक या एक से अधिक आनलाइन खेल का प्रस्ताव करता है ;

(ग) “उपयोक्ता” से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो आनलाइन खेल मध्यवर्ती के किसी कंप्यूटर संसाधन तक पहुंचता है या उसका उपयोग करता है ;

(घ) “उपयोक्ता खाता” से किसी आनलाइन खेल मध्यवर्ती के साथ रजिस्ट्रीकृत किसी उपयोक्ता का खाता अभिप्रेत है ।’।

87. आय-कर अधिनियम की धारा 194खख में “दस हजार रुपए से अधिक रकम

धारा 194खख

की”, शब्दों के स्थान पर, “वित्तीय वर्ष के दौरान दस हजार रुपए से अधिक की रकम या रकमों के योग की” शब्द रखे जाएंगे।

का संशोधन।

88. आय-कर अधिनियम की धारा 194ठग में, 1 जुलाई, 2023 से,—

धारा 194ठग का संशोधन।

(i) उपधारा (1) में परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह और कि उपधारा (2) के खंड (iग) में निर्दिष्ट ब्याज के माध्यम से किसी आय की दशा में, आय-कर नौ प्रतिशत की दर से कटौती किया जाएगा।”;

(ii) उपधारा (2) में,—

(I) खंड (iख) में, “और” शब्द के स्थान पर, “या” शब्द रखा जाएगा ;

(II) खंड (iख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(iग) 1 जुलाई, 2023 को या उसके पश्चात् इसके द्वारा भारत से बाहर किसी स्रोत से कोई दीर्घ अवधि बंधपत्र या रुपए मूल्यांकित बंधपत्र जारी करके उधार लिए गए धन के संबंध में, जो किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में अवस्थित केवल किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध है ; और ”।”।

धारा 194ढ का संशोधन।

89. आय-कर अधिनियम की धारा 194ढ में, दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक, 1 अप्रैल, 2023 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह भी कि जहां प्राप्तिकर्ता कोई सहकारी सोसाइटी है, वहां इस धारा के उपबंधों का वैसे ही प्रभाव होगा, मानो “एक करोड़ रुपए” शब्दों के स्थान पर, “तीन करोड़ रुपए” शब्द रख दिए गए हों।”।

धारा 194द का संशोधन।

90. आय-कर अधिनियम की धारा 194द में, स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण 2—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि उपधारा (1) के उपबंध किसी फायदे या परिलब्धि को लागू होंगे, चाहे वह नकद रूप में या वस्तु रूप में या भागतः नकद रूप में और भागतः वस्तु रूप में हो।”।

धारा 196क का संशोधन।

91. आय-कर अधिनियम की धारा 196क की उपधारा (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु जहां धारा 90 की उपधारा (1) या धारा 90क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई करार पाने वाले को लागू होता है और यदि पाने वाले ने, यथास्थिति, धारा 90 की उपधारा (4) या धारा 90क की उपधारा (4) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिया है, तब, उस पर आय-कर की, बीस प्रतिशत की दर पर या ऐसे करार में ऐसी आय के लिए उपबंधित आय-कर की दर पर या दरों पर, जो भी निम्नतर हो, कटौती की जाएगी।”।

धारा 197 का संशोधन।

92. आय-कर अधिनियम की धारा 197 की उपधारा (1) में, “धारा 194ठक” शब्द, अंकों और अक्षरों के पश्चात्, “, धारा 194ठखक” शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 206कख

93. आय-कर अधिनियम की धारा 206कख में,—

का संशोधन ।

(i) उपधारा (1) में, “194ख” अंकों और अक्षर के पश्चात्, “194खक” अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उपधारा (3) में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा,—

“परंतु यह कि विनिर्दिष्ट व्यक्ति में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित नहीं होगा,—

(i) कोई अनिवासी व्यक्ति, जिसका भारत में स्थायी स्थापन नहीं है ; या

(ii) ऐसा व्यक्ति, जिससे उक्त पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जाती है और जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में इस निमित्त अधिसूचित किया गया है ।”।

94. आय-कर अधिनियम की धारा 206ग की उपधारा (1छ) में, 1 जुलाई, 2023 से,—

धारा 206ग
का संशोधन ।

(i) खंड (क) में, “भारत के बाहर”, शब्दों का, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, लोप किया जाएगा ;

(ii) दीर्घ पंक्ति में, “पांच”, शब्द के स्थान पर, “बीस” शब्द रखा जाएगा ;

(iii) पहले परंतुक में, “तथा वह विदेशी पर्यटन कार्यक्रम पैकेज के क्रय से प्रयोजन के लिए भिन्न है” शब्दों के स्थान पर, “तथा वह शिक्षा या चिकित्सा उपचार के प्रयोजनों के लिए है” शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) दूसरे परंतुक में, “विदेशी पर्यटन कार्यक्रम पैकेज के क्रय से भिन्न प्रयोजन के लिए है” शब्दों के स्थान पर, “शिक्षा या चिकित्सा उपचार के प्रयोजनों के लिए हैं” शब्द रखे जाएंगे ।

95. आय-कर अधिनियम की धारा 206गग की उपधारा (1) में, निम्नलिखित परंतुक 1 जुलाई, 2023 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

धारा 206गग
का संशोधन ।

“परंतु इस धारा के अधीन स्रोत पर कर संग्रहण की दर बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।”।

96. आय-कर अधिनियम की धारा 206गगक में,—

धारा
206गगक का
संशोधन ।

(i) उपधारा (1) में निम्नलिखित परंतुक 1 जुलाई, 2023 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु इस धारा के अधीन स्रोत पर कर संग्रहण की दर बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।”;

(ii) उपधारा (3) में परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह कि विनिर्दिष्ट व्यक्ति में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित नहीं होगा,—

(i) कोई अनिवासी व्यक्ति, जिसका भारत में स्थायी स्थापन नहीं है ; या

(ii) ऐसा व्यक्ति, जिससे उक्त पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष के

लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जाती है और जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में इस निमित्त अधिसूचित किया गया है।”।

धारा 241क का संशोधन।

97. आय-कर अधिनियम की धारा 241क में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु इस धारा के उपबंध 1 अप्रैल, 2023 से लागू नहीं होंगे।”।

धारा 244क का संशोधन।

98. आय-कर अधिनियम की धारा 244क में,—

(क) उपधारा (1) के खंड (क) में, उपखंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक 1 अक्टूबर, 2023 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु जहां निर्धारिती द्वारा धारा 155 की उपधारा (20) के अधीन किए गए आवेदन के परिणामस्वरूप, निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के परिणामस्वरूप प्रतिदाय उद्भूत होता है, वहां ऐसे ब्याज को, ऐसे आवेदन की तारीख से उस तारीख तक, जिसको प्रतिदाय प्रदान किया जाता है, की अवधि में समाविष्ट प्रत्येक मास या मास के किसी भाग के लिए आधा प्रतिशत की दर से संगणित किया जाएगा।”;

(ख) उपधारा (1क) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु किसी निर्धारिती की दशा में, जहां निर्धारण या पुनर्निर्धारण के लिए कार्यवाहियां लंबित हैं, वहां इस उपधारा के अधीन ऐसे निर्धारिती को संदेय अतिरिक्त ब्याज का अवधारण करने के लिए अवधि की संगणना करने में उस तारीख से आरंभ होने वाली अवधि, जिसको धारा 245 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार और उसके अधीन रहते हुए, उस तारीख तक ऐसे प्रतिदाय को निर्धारण अधिकारी द्वारा रोक कर रखा जाता है, जिसको ऐसे मामले में ऐसा निर्धारण या पुनर्निर्धारण किया जाता है, अपवर्जित की जाएगी।”।

धारा 245 के स्थान पर, नई धारा का प्रतिस्थापन।

99. आय-कर अधिनियम की धारा 245 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

कतिपय मामलों में प्रतिदायों का मुजरा किया जाना और उनको रोके रखना।

“245. (1) जहां इस अधिनियम के उपबंधों में से किसी उपबंध के अधीन किसी व्यक्ति को कोई प्रतिदाय देय हो जाता है या देय होना पाया जाता है, वहां, यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी या आयुक्त या प्रधान आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान मुख्य आयुक्त, प्रतिदाय के संदाय के बदले में, उस रकम का या उस रकम के किसी भाग का, जो प्रतिदत्त की जानी है, मुजरा ऐसी राशि के प्रति, यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन उस व्यक्ति द्वारा संदत्त की जानी बाकी है, जिसे प्रतिदाय देय है, इस उपधारा के अधीन किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाई ऐसे व्यक्ति को लिखित प्रज्ञापना देने के पश्चात् कर सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन प्रतिदाय के किसी भाग का मुजरा किया गया है या जहां ऐसी किसी रकम का मुजरा नहीं किया गया है और प्रतिदाय किसी व्यक्ति को देय हो जाता है, वहां निर्धारण अधिकारी की, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस निर्धारण या पुनः निर्धारण के लिए कार्यवाहियां ऐसे व्यक्ति की दशा में लंबित हैं, यह राय है कि प्रतिदाय की मंजूरी से राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव

पड़ने की संभावना है, वहां वह उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, और यथास्थिति, प्रधान आयुक्त या आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से उस तारीख तक, जिसको ऐसा निर्धारण या पुनर्निर्धारण किया जाता है, प्रतिदाय को रोक सकेगा ।”।

100. आय-कर अधिनियम की धारा 245घ की उपधारा (9) में, खंड (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा और 1 फरवरी, 2021 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

धारा 245घ
का संशोधन ।

“(iv) जहां उपधारा (6ख) के अधीन किसी आदेश को संशोधित करने या उसमें सुधार के लिए कोई आवेदन फाइल करने की समय-सीमा 1 फरवरी, 2021 को या उसके पश्चात्, किंतु 1 फरवरी, 2022 के पूर्व समाप्त होती है, तो ऐसी समय-सीमा का 30 सितंबर, 2023 तक विस्तार किया जाएगा ।”।

101. आय-कर अधिनियम की धारा 245डक की उपधारा (4) में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

धारा 245डक
का संशोधन ।

“परंतु यह और कि केंद्रीय सरकार, इस उपधारा के अधीन 31 मार्च, 2023 को या उसके पूर्व जारी किसी निदेश का, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, संशोधन कर सकेगी ।”।

102. आय-कर अधिनियम की धारा 245द की उपधारा (10) में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

धारा 245द का
संशोधन ।

“परंतु यह और कि केंद्रीय सरकार, इस उपधारा के अधीन 31 मार्च, 2023 को या उसके पूर्व जारी किसी निदेश का, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, संशोधन कर सकेगी ।”।

103. आय-कर अधिनियम के अध्याय 20 में,—

अध्याय 20
का संशोधन ।

(क) उपशीर्ष “क. उपायुक्त (अपील) और आयुक्त (अपील) को अपीलें” के स्थान पर, “क. संयुक्त आयुक्त (अपील) और आयुक्त (अपील) को अपीलें” उपशीर्ष रखा जाएगा ;

(ख) धारा 246 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“246. (1) किसी निर्धारण अधिकारी (संयुक्त आयुक्त की पंक्ति से नीचे) के किसी भी निम्नलिखित आदेश से व्यथित कोई निर्धारिती—

संयुक्त
आयुक्त
(अपील) के
समक्ष अपील
योग्य आदेश ।

(क) धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन संसूचना का कोई आदेश, जहां निर्धारिती कोई समायोजन करने के विरुद्ध आक्षेप करता है या धारा 143 की उपधारा (3) या धारा 144 के अधीन निर्धारण का कोई आदेश, जहां निर्धारिती, निर्धारित की गई आय की रकम के प्रति आक्षेप करता है या अवधारित कर की रकम या संगणित हानि की रकम या प्रास्थिति, जिसके अधीन उसका निर्धारण किया गया है, के किसी आदेश ;

(ख) धारा 147 के अधीन निर्धारण, पुनःनिर्धारण या पुनःसंगणना के किसी आदेश ;

(ग) धारा 200क की उपधारा (1) के अधीन संसूचना के किसी आदेश ;

(घ) धारा 201 के अधीन किसी आदेश ;

(ड) धारा 206ग की उपधारा (6क) के अधीन संसूचना के किसी आदेश ;

(च) धारा 206गख की उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश ;

(छ) अध्याय 21 के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के आदेश ;

(ज) धारा 154 या धारा 155 के अधीन पूर्वोक्त (क) से (छ) में उल्लिखित किसी भी आदेश को संशोधित करने के किसी आदेश, के विरुद्ध संयुक्त आयुक्त (अपील) को अपील कर सकेगा :

परंतु संयुक्त आयुक्त (अपील) के विरुद्ध कोई अपील फाइल नहीं की जाएगी, यदि इस उपधारा में निर्दिष्ट कोई आदेश, उपायुक्त की पंक्ति से ऊपर के किसी आय-कर प्राधिकारी द्वारा या उसके पूर्वानुमोदन से पारित किया गया है ।

(2) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी आदेश के विरुद्ध फाइल की गई कोई अपील आयुक्त (अपील) के समक्ष लंबित है, बोर्ड या आय-कर प्राधिकारी, जिसे इस संबंध में बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया गया है, ऐसी अपील और उससे उद्भूत किसी मामले को या ऐसी अपील के साथ संबंधित मामले को, जो लंबित है, संयुक्त आयुक्त (अपील) को अंतरित कर सकेगा, जो ऐसी अपील या मामले में उस प्रक्रम से अग्रसर हो सकेगा, जिस पर वह उसे अंतरित किए जाने से पूर्व था ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी बोर्ड या इस प्रकार बोर्ड द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत आय-कर प्राधिकारी किसी अपील को, जो संयुक्त आयुक्त (अपील) के समक्ष लंबित है और उससे उद्भूत या ऐसी अपील से संबंधित मामले को और जो लंबित है, को आयुक्त (अपील) को अंतरित कर सकेगा, जो ऐसी अपील या मामले में उस प्रक्रम से अग्रसर होगा, जिस पर वह उसे अंतरित किए जाने से पूर्व था ।

(4) जब किसी अपील को उपधारा (2) या उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन अंतरित किया जाता है, अपीलार्थी को सुने जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा ।

(5) केंद्रीय सरकार, संयुक्त आयुक्त (अपील) द्वारा किसी अपील का निपटारा करने के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक स्कीम बना सकेगी, जिससे अपीलों का त्वरित रीति में पारदर्शिता और जवाबदेही सहित संयुक्त आयुक्त (अपील) और अपीलार्थी के बीच अपील कार्यवाहियों के अनुक्रम में अंतरापृष्ठ का निरसन करके प्रौद्योगिकीय रूप से साध्य परिमाण तक निपटान किया जा सके और यह निदेश दे सकेगी कि संयुक्त आयुक्त (अपील) द्वारा अपीलों के निपटान के लिए क्षेत्राधिकार और प्रक्रिया से संबंधित इस अधिनियम के उपबंध लागू नहीं होंगे या ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों के साथ लागू होंगे, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(6) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, बोर्ड यह विनिर्दिष्ट कर सकेगा कि उस उपधारा के उपबंध किसी मामले या मामलों के किसी वर्ग को लागू नहीं होंगे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “प्रास्थिति” से वह श्रेणी अभिप्रेत है, जिसके अधीन निर्धारिती को “व्यष्टि”, “हिन्दू अविभक्त कुटुंब” और वैसे ही निर्धारित किया गया है ।”।

धारा 249 का
संशोधन ।

104. आय-कर अधिनियम की धारा 249 में,—

(क) उपधारा (1) के आरंभिक भाग में, “1 अक्टूबर, 1998 को या उसके पश्चात् आयुक्त (अपील) को की गई”, अंकों, शब्दों और कोष्ठकों के पश्चात्, “या 1 अप्रैल, 2023 को या उसके पश्चात् संयुक्त आयुक्त (अपील) को की गई” शब्द, अंक और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपधारा (3) में, “आयुक्त (अपील)”, शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, “संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)”, शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (4) के परंतुक में, “आयुक्त (अपील)”, शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, “संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)”, शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

105. आय-कर अधिनियम की धारा 250 में,—

धारा 250 का
संशोधन ।

(क) उपधारा (1), उपधारा (3), उपधारा (4), उपधारा (5), उपधारा (6) और उपधारा (7) में, “आयुक्त (अपील)” शब्दों और कोष्ठकों, जहां कहीं वे आते हैं, के स्थान पर, “संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (6क) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(6क) प्रत्येक अपील में, जहां यह संभव हो, संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील) उस वित्तीय वर्ष जिसमें, यथास्थिति, धारा 246 की उपधारा (1) के अधीन उसके समक्ष ऐसी अपील फाइल की गई थी या उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन उसे अंतरित की गई थी या धारा 246क की उपधारा (1) के अधीन उसके समक्ष फाइल की गई थी, की समाप्ति से एक वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी अपील की सुनवाई और उसका विनिश्चय कर सकेगा ।”;

(ग) उपधारा (6ग) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2022 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह और कि केंद्रीय सरकार, इस उपधारा के अधीन 31 मार्च, 2022 को या उसके पूर्व जारी किसी निदेश का, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, संशोधन कर सकेगी ।”।

106. आय-कर अधिनियम की धारा 251 में,—

धारा 251 का
संशोधन ।

(i) पार्श्व शीर्ष में, “उपायुक्त (अपील)” शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, “संयुक्त आयुक्त (अपील)” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(1क) किसी अपील का निपटारा करते समय, संयुक्त आयुक्त (अपील) के पास निम्नलिखित शक्तियां होंगी,—

(क) किसी निर्धारण आदेश के विरुद्ध किसी अपील में वह किसी निर्धारण की पुष्टि, उसमें कमी, उसमें वृद्धि या उसे रद्द कर सकेगा ;

(ख) शास्ति अधिरोपित करने वाले किसी आदेश के विरुद्ध किसी अपील में वह ऐसे किसी आदेश की पुष्टि या उसे रद्द कर सकेगा या उसे इस प्रकार परिवर्तित कर सकेगा कि उसके द्वारा लगाई गई शास्ति में या तो वृद्धि या उसमें कमी कर सकेगा ;

(ग) किसी अन्य मामले में, वह अपील में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जिसे वह उचित समझे ।”;

(iii) उपधारा (2) में, “आयुक्त (अपील)”, शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, “संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)”, शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(iv) स्पष्टीकरण में,—

(क) आरंभिक भाग में, “आयुक्त (अपील)”, शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, “संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)”, शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ख) “उपायुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)” शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, “उपायुक्त (अपील) या संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)”, शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

धारा 253 का
संशोधन ।

107. आय-कर अधिनियम की धारा 253 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(अ) खंड (क) में, “धारा 271क,” शब्द, अंकों और अक्षर के पश्चात् “धारा 271ककख, धारा 271ककग, धारा 271ककघ,” शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(आ) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(कक) धारा 154, धारा 250, धारा 270क, धारा 271, धारा 271क, धारा 271ककग, धारा 271ककघ या धारा 271ज के अधीन संयुक्त आयुक्त (अपील) द्वारा पारित कोई आदेश ; या”;

(इ) खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(ग) निम्नलिखित द्वारा पारित कोई आदेश,—

(i) धारा 12कक या धारा 12कख के अधीन या धारा 80छ की उपधारा (5) के खंड (vi) के अधीन या धारा 263 के अधीन या धारा 270क के अधीन या धारा 271 के अधीन या धारा 272क के अधीन प्रधान आयुक्त या आयुक्त या उसके द्वारा ऐसे किसी आदेश का संशोधन करने वाला धारा 154 के अधीन पारित कोई आदेश ; या

(ii) धारा 263 या धारा 272क के अधीन किसी प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक या प्रधान निदेशक या निदेशक या उसके द्वारा किसी ऐसे आदेश का संशोधन करने वाला धारा 154 के अधीन पारित कोई आदेश ;

या”;

(ख) उपधारा (2) में, “आयुक्त (अपील)” शब्दों और कोष्ठकों, जहां कहीं वे आते हैं, के स्थान पर, “संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (4) में,—

(i) “आयुक्त (अपील) के आदेश के विरुद्ध” शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, “संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील) के आदेश के विरुद्ध” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ii) “आयुक्त (अपील) के आदेश के किसी भाग” शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, “संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील) के ऐसे आदेश के किसी भाग” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

108. आय-कर अधिनियम की धारा 264 में, उपधारा (4) में, “आयुक्त (अपील)” शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, “संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

धारा 264 का संशोधन ।

109. आय-कर अधिनियम की धारा 267 में, “आयुक्त (अपील)” शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, “संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

धारा 267 का संशोधन ।

110. आय-कर अधिनियम की धारा 269धध में,—

धारा 269धध का संशोधन ।

(क) दूसरे परंतुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पहले, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘परंतु यह भी कि किसी निक्षेप या उधार की उस दशा में जहां,—

(क) किसी प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा अपने सदस्य से ऐसे निक्षेप स्वीकार किए जाते हैं ; या

(ख) जहां ऐसा उधार किसी प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से उसके सदस्य द्वारा लिया जाता है,

वहां इस धारा के उपबंधों का वहीं प्रभाव होगा मानो “बीस हजार रुपए” के स्थान पर “दो लाख रुपए” रखे गए हों ।’;

(ख) स्पष्टीकरण में, खंड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

‘(ii) “सहकारी बैंक”, “प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी”, “प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक” का वही अर्थ होगा, जो धारा 80त की उपधारा (4) के स्पष्टीकरण में क्रमशः उनका हैं ;’।

111. आय-कर अधिनियम की धारा 269न में,—

धारा 269न का संशोधन ।

(क) दूसरे परंतुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पहले, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह भी कि किसी निक्षेप या उधार की उस दशा में जहां,—

(क) किसी प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा अपने सदस्य को ऐसा निक्षेप संदत्त किया जाता है ; या

(ख) जहां ऐसा उधार किसी प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को उसके सदस्य द्वारा प्रतिसंदत्त किया जाता है,

वहां इस धारा के उपबंधों का वहीं प्रभाव होगा मानो “बीस हजार रुपए” के स्थान पर “दो लाख रुपए” रखे गए हों ।’;

(ख) स्पष्टीकरण में खंड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

‘(ii) “सहकारी बैंक”, “प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी”, “प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक” का वही अर्थ होगा, जो धारा 80त की उपधारा (4) के स्पष्टीकरण में क्रमशः उनका हैं ;’।

धारा 270क का संशोधन ।

112. आय-कर अधिनियम की धारा 270क में, “आयुक्त (अपील)” शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, “संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

धारा 270कक का संशोधन ।

113. आय-कर अधिनियम की धारा 270कक की उपधारा (6) में, “वहां धारा 246क के अधीन कोई अपील” शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, “वहां धारा 246 या धारा 246क के अधीन कोई अपील” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 271 का संशोधन ।

114. आय-कर अधिनियम की धारा 271 में, “आयुक्त (अपील)” शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, “संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

धारा 271क का संशोधन ।

115. आय-कर अधिनियम की धारा 271क में, “आयुक्त (अपील)” शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, “संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

धारा 271ककग का संशोधन ।

116. आय-कर अधिनियम की धारा 271ककग में, “आयुक्त (अपील)” शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, “संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

धारा 271ककघ का संशोधन ।

117. आय-कर अधिनियम की धारा 271ककघ में, “आयुक्त (अपील)” शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, “संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

धारा 271ग का संशोधन ।

118. आय-कर अधिनियम की धारा 271ग की उपधारा (1) में,—

(अ) खंड (ख) में,—

(I) “संपूर्ण कर या उसके भाग का संदाय करने में” शब्दों के स्थान पर, “संपूर्ण कर या उसके भाग का संदाय करने या संदाय सुनिश्चित करने में” शब्द रखे जाएंगे ;

(II) उपखंड (i) में, “या” शब्द का लोप किया जाएगा ;

(III) उपखंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किए

जाएंगे, अर्थात् :—

“(iii) धारा 194द की उपधारा (1) का पहला परंतुक ; या

(iv) धारा 194ध की उपधारा (1) के परंतुक ;”;

(IV) वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा यथा अंतःस्थापित उपखंड (iv) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड, 1 जुलाई, 2023 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(v) धारा 194खक की उपधारा (2) ;”;

(आ) दीर्घ पंक्ति में, “कटौती करने में या उसका संदाय” शब्दों के स्थान पर, “कटौती करने में या उसका संदाय करने में या संदाय सुनिश्चित करने में” शब्द रखे जाएंगे ।

119. (1) आय-कर अधिनियम की धारा 271चकक को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) की दीर्घ पंक्ति के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

धारा 271चकक का संशोधन ।

“वहां, धारा 285खक की उपधारा (1) के अधीन विहित आय-कर प्राधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति शास्ति के रूप में पचास हजार रुपए की राशि का संदाय करेगा ।

(2) जहां, धारा 285खक की उपधारा (1) के खंड (ट) में निर्दिष्ट व्यक्ति की दशा में, जिससे उस धारा के अधीन विवरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा है, (जिसे इसमें इसके पश्चात् रिपोर्टकारी वित्तीय संस्था के रूप में निर्दिष्ट किया गया है), विवरण में गलत सूचना प्रदान करता है और ऐसे विवरण में गलती सुसंगत रिपोर्ट योग्य लेखे या लेखाओं के धारक या धारकों द्वारा प्रस्तुत मिथ्या या गलत सूचना के परिणामस्वरूप है, धारा 285खक की उपधारा (1) में विहित आय-कर प्राधिकारी यह निदेश देगा कि रिपोर्टकारी वित्तीय संस्था शास्ति के माध्यम से प्रत्येक रिपोर्ट योग्य गलत खाते के लिए उपधारा (1) के अधीन शास्ति, यदि कोई हो, के अतिरिक्त, पांच हजार रुपए की राशि का संदाय करेगी और रिपोर्टकारी वित्तीय संस्था, ऐसे रिपोर्ट योग्य खाताधारक के निमित्त इस प्रकार संदत्त धनराशि को वसूल करने की या उसके कब्जे में की, किन्हीं धनराशियों को या जो उसे ऐसे प्रत्येक रिपोर्ट योग्य खाताधारक से प्राप्त हो, इस प्रकार संदत्त धनराशि के समतुल्य रकम को प्रतिधारित करने की हकदार होगी ।”।

120. आय-कर अधिनियम की धारा 271ज में, “आयुक्त (अपील)” शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, “संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

धारा 271ज का संशोधन ।

121. आय-कर अधिनियम की धारा 274 की उपधारा (2ख) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2022 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

धारा 274 का संशोधन ।

“परंतु यह और कि केंद्रीय सरकार, इस उपधारा के अधीन 31 मार्च, 2022 को या उसके पूर्व जारी किसी निदेश का, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, संशोधन कर सकेगी ।”।

122. आय-कर अधिनियम की धारा 275 में,—

धारा 275 का संशोधन ।

(क) “आयुक्त (अपील)” शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते

हैं, “संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ख) “आयुक्त (अपील) को” शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, “संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील) को” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

धारा 276क का
संशोधन ।

123. आय-कर अधिनियम की धारा 276क में परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह और कि इस धारा के अधीन 1 अप्रैल, 2023 को या उसके पश्चात् कोई कार्यवाही आरंभ नहीं की जाएगी ।”।

धारा 276ख का
संशोधन ।

124. आय-कर अधिनियम की धारा 276ख में,—

(अ) आरंभिक भाग में, “केंद्रीय सरकार के जमा खाते में” शब्दों का लोप किया जाएगा;

(आ) खंड (क) में, “कटौती किए गए कर” शब्दों के स्थान पर, “कटौती किए गए कर का केन्द्रीय सरकार के जमा खाते में” शब्द रखे जाएंगे;

(इ) खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

‘(ख) केंद्रीय सरकार के जमा खाते में,—

(i) धारा 115ण की उपधारा (2) ;

(ii) धारा 194ख के परंतुक ;

(iii) धारा 194द की उपधारा (1) के पहले परंतुक ;

(iv) धारा 194ध की उपधारा (1) के परंतुक; या,

की अपेक्षानुसार या उसके अधीन केंद्रीय सरकार के जमा खाते में कर का संदाय करने या कर का संदाय सुनिश्चित करने ,’;

(ई) वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा प्रतिस्थापित खंड (ख) के उपखंड (iv) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड, 1 जुलाई, 2023 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(v) धारा 194खक की उपधारा (2) ;”।

धारा 279 का
संशोधन ।

125. आय-कर अधिनियम की धारा 279 की उपधारा (1) में, “आयुक्त (अपील)” शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, “संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

धारा 287 का
संशोधन ।

126. आय-कर अधिनियम की धारा 287 में, उपधारा (2) में, “आयुक्त (अपील)” शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, “संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

धारा 295 का
संशोधन ।

127. आय-कर अधिनियम की धारा 295 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (डडग) में, “लेखापरीक्षा” शब्द के पश्चात्, “या तालिका मूल्यांकन” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) खंड (डड) में, “आयुक्त (अपील)” शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, “संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

अध्याय 4

अप्रत्यक्ष कर

सीमाशुल्क

1962 का 52

128. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 25 की उपधारा (4क) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

धारा 25 का
संशोधन ।

“परंतु यह और कि इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात, निम्नलिखित को या उसके संबंध में प्रदान की गई ऐसी किसी छूट को लागू नहीं होगी,—

(क) बहुपक्षीय या द्विपक्षीय व्यापार करार ;

(ख) अंतर्राष्ट्रीय करारों, संधियों या अभिसमयों के अधीन बाध्यताएं या ऐसी अन्य बाध्यताएं जिनके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र अभिकरणों, राजनयिकों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संबंध में बाध्यताएं भी हैं ;

(ग) सांविधानिक प्राधिकारियों के विशेषाधिकार ;

(घ) विदेशी व्यापार नीति के अधीन स्कीमें ;

(ङ) केंद्रीय सरकार की ऐसी स्कीमें, जिनकी दो वर्ष से अधिक विधिमान्यता है ;

(च) उपहार या वैयक्तिक सामान के रूप में पुनःआयात किए गए माल, अस्थायी आयात या आयातित माल ;

1975 का 51

(छ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कोई सीमाशुल्क, जिसके अंतर्गत सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 12 के अधीन उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क से भिन्न, धारा 3 की उपधारा (7) के अधीन उद्ग्रहणीय एकीकृत कर सम्मिलित है ।”।

129. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 65 की उपधारा (1) में, “ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए” शब्दों के स्थान पर, “धारा 65क के उपबंधों तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए” शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 65
का संशोधन ।

130. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 65 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

नई धारा 65क
का अन्तःस्थापना।

“65क. (1) इस अधिनियम या सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के किसी उपबंध में तत्प्रतिकूल किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, निम्नलिखित उपबंध ऐसी तारीख से, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, ऐसे माल के संबंध में लागू होंगे, जिन पर धारा 65 के निबंधनों में कोई विनिर्माणकारी प्रक्रिया या अन्य संक्रियाएं की गई हैं, अर्थात् :—

भांडागार में
संक्रियाओं के
लिए लाए गए
मालों को
सामान्यतया
कतिपय कर संदत्त
करना ।

1975 का 51

(अ) शुल्क्य माल, जो भांडागार में जमा किए जाते हैं, ऐसे माल होंगे, जिन पर उपधारा (7) के अधीन एकीकृत कर और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उपधारा (9) के अधीन सेवा कर प्रतिकर उपकर संदत्त किए गए हैं और केवल संदेय शुल्क के प्रयोजन के लिए, जो उक्त कर और संदत्त उपकर से भिन्न हैं, ऐसे शुल्क्य माल भांडागार माल होंगे ;

(आ) भांडागार में जमा किए जाने के प्रयोजन के लिए शुल्क्य माल वहां हटाए जाने के लिए अनुज्ञात किए जाएंगे, जहां—

(i) माल के संबंध में, उसकी कोई प्रविष्टि सीमाशुल्क स्वचालित प्रणाली पर इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत की गई हो, धारा 46 के अधीन घरेलू खपत के लिए प्रवेशपत्र और यथास्थिति, धारा 17 या धारा 18 के अधीन धारा 15 की उपधारा (1) के खंड (क) के अनुसार शुल्क के लिए माल का निर्धारण किया गया हो ;

(ii) उपधारा (7) के अधीन एकीकृत कर और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उपधारा (9) के अधीन माल और सेवा कर प्रतिकर उपकर धारा 47 के अनुसार संदत्त किए गए हों ;

1975 का 51

(iii) धारा 67 के निबंधनों के अनुसार, अन्य भांडागार से माल के हटाए जाने पर धारा 68 के खंड (क) के अधीन घरेलू खपत के लिए प्रवेशपत्र पेश किया गया हो और उस अन्य भांडागार से माल को इस प्रकार हटाए जाने से पूर्व धारा 7 के अधीन एकीकृत कर तथा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उपधारा (9) के अधीन माल और सेवा कर प्रतिकर उपकर, संदत्त कर दिए गए हों ;

1975 का 51

(iv) धारा 59 के उपबंधों का, उसमें के निम्नलिखित उपांतरणों के अध्यधीन रहते हुए, अनुपालन किया गया है, अर्थात् :—

(क) “भांडागारण के लिए प्रवेशपत्र” शब्दों के स्थान पर, “घरेलू खपत के लिए प्रवेशपत्र” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) “निर्धारित शुल्क की रकम” शब्दों के स्थान पर, “निर्धारित शुल्क की रकम किन्तु जिसे संदत्त नहीं किया गया है,” शब्द रखे जाएंगे ।

(इ) खंड (अ) में निर्दिष्ट भांडागार माल के संबंध में संदेय शुल्क, उस विस्तार तक असंदत्त, माल को संदत्त किए गए हैं, भांडागार से ऐसी रीति में जो विहित किया जाए ।

(2) उपधारा (1) के उपबंध, उस उपधारा के अधीन अधिसूचित तारीख के पूर्व धारा 65 के निबंधनों के अनुसार विनिर्माण प्रक्रिया या अन्य संक्रियाओं के लिए भांडागार में जमा करने या भांडागार में पहले से जमा किए जाने के प्रयोजन के लिए हटाए जाने के लिए पहले से अनुज्ञात शुल्क्य माल के संबंध में लागू नहीं होंगे ।

(3) केंद्रीय सरकार, किसी एक या अधिक मानदंड, जिसमें माल की प्रकृति या वर्ग या प्रवर्ग या आयातकों या निर्यातकर्तों का वर्ग या औद्योगिक क्षेत्र सम्मिलित है, किन्तु उस तक ही सीमित नहीं है, जो आवश्यक या समीचीन हों, अधिसूचना द्वारा ऐसे माल के लिए, जिसके संबंध में धारा 65 के निबंधनों में कोई विनिर्माणकारी प्रक्रिया या अन्य संक्रियाएं की गई है, जैसा कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, इस धारा के लागू होने से छूट प्रदान कर सकेगी ।”।

धारा 127ग का
संशोधन ।

131. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127ग में, उपधारा (8) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(8क) उपधारा (5) के अधीन कोई आदेश उस मास, जिसमें धारा 127ख के अधीन कोई आवेदन किया जाता है, के अंतिम दिन से नौ मास की अवधि के भीतर पारित किया जाएगा, और यदि उक्त अवधि के भीतर कोई आदेश पारित नहीं किया

जाता है, तो समझौता कार्यवाहियों का उपशमन हो जाएगा तथा ऐसा न्यायनिर्णयन प्राधिकारी, जिसके समक्ष आवेदन करने के समय कार्यवाही लंबित थी, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार आवेदन का ऐसे निपटारा करेगा, मानो उक्त धारा के अधीन कोई आवेदन नहीं किया गया था :

परंतु इस उपधारा के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि, उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, तीन मास से अनधिक की और अवधि के लिए समझौता आयोग द्वारा बढ़ायी जा सकेगी :

परंतु यह और कि उस तारीख को, जिसको वित्त विधेयक, 2023 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, उपधारा (5) के अधीन लंबित किसी आवेदन के संबंध में नौ मास की उक्त अवधि की गणना उस तारीख से की जाएगी, जिसको उक्त वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है ।”।

132. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 157 की उपधारा (2) के खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

धारा 157 का संशोधन ।

“(गक) धारा 65क की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन शुल्क के संदाय तथा माल को हटाए जाने की रीति और शर्तें”।

133. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 159 में, “43” अंक के पश्चात् “65क” अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 159 का संशोधन ।

सीमाशुल्क टैरिफ

1975 का 51

134. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) में, 1 जनवरी, 1995 से,—

धारा 9, धारा 9क और धारा 9ग का संशोधन ।

(i) धारा 9 में,—

(क) उपधारा (6) के पहले परंतुक में, “किसी पुनर्विलोकन में” शब्दों के स्थान पर, “किसी पुनर्विलोकन पर विचार किए जाने पर” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (7) में, “और अवधारित” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ii) धारा 9क में,—

(क) उपधारा (5) के पहले परंतुक में, “किसी पुनर्विलोकन में” शब्दों के स्थान पर, “किसी पुनर्विलोकन पर विचार किए जाने पर” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (6) में, “और अवधारित” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(iii) धारा 9ग में,—

(क) उपधारा (1) में, “के आदेश” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (2) में, “आदेश” शब्द के स्थान पर, “अवधारण या पुनर्विलोकन” शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (3) में, “आदेश” शब्द के स्थान पर, “अवधारण या पुनर्विलोकन” शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “अवधारण” या “पुनर्विलोकन” से अधिनियम की धारा 8ख, धारा 9, धारा 9क और

धारा 9ख के अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट रीति में किया गया अवधारण या पुनर्विलोकन अभिप्रेत है ।'।

पहली अनुसूची
का संशोधन ।

135. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची का,—

- (क) दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा ;
- (ख) तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में भी संशोधन किया जाएगा ;
- (ग) 1 मई, 2023 से चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में भी संशोधन किया जाएगा ;
- (घ) 1 अप्रैल, 2023 से सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में भी संशोधन किया जाएगा ।

दूसरी अनुसूची
का संशोधन ।

136. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची में 1 मई, 2023 से पांचवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा ।

केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम

धारा 10 का
संशोधन ।

137. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम कहा गया है) की धारा 10 में,—

2017 का 12

- (क) उपधारा (2) के खंड (घ) में, “माल या” शब्दों का लोप किया जाएगा ;
- (ख) उपधारा (2क) के खंड (ग) में, “माल या” शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 16 का
संशोधन ।

138. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 16 में, उपधारा (2) में,—

- (i) दूसरे परंतुक में, “उस पर के ब्याज के साथ, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उसके आउटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जाएगा” शब्दों के स्थान पर, “धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उसके द्वारा संदत्त किया जाएगा” शब्द और अंक रखे जाएंगे ;
- (ii) तीसरे परंतुक में, “उसके द्वारा किए गए संदाय” शब्दों के स्थान पर, “उसके द्वारा आपूर्तिकर्ता को किए गए संदाय” शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 17 का
संशोधन ।

139. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 17 में,—

(क) उपधारा (3) के स्पष्टीकरण में, “अनुसूची 3 के पैरा 5 में विनिर्दिष्ट के सिवाय उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट कार्यकलापों या संव्यवहारों का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा ।” शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“निम्नलिखित के सिवाय, अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट कार्यकलापों या संव्यवहारों का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा,—

- (i) उक्त अनुसूची के पैरा 5 में विनिर्दिष्ट कार्यकलापों या संव्यवहारों का मूल्य ; और
 - (ii) उक्त अनुसूची के पैरा 8 के खंड (क) के संबंध में ऐसे कार्यकलापों या संव्यवहारों का मूल्य, जो विहित किए जाएं”;
- (ख) उपधारा (5) के खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(चक) किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए गए माल या सेवाओं या दोनों का, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में निर्दिष्ट निगम सामाजिक उत्तरदायित्व के अधीन उसकी बाध्यताओं से संबंधित कार्यकलापों के

2013 का 18

लिए उपयोग किए जाते हैं या उपयोग किए जाने के लिए आशयित हैं ;”।

धारा 23 का
संशोधन ।

140. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी और 1 जुलाई, 2017 से रखी गई समझी जाएगी, अर्थात् :—

‘(2) धारा 22 की उपधारा (1) या धारा 24 में अंतर्विष्ट प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, ऐसे व्यक्तियों का वर्ग, जिन्हें इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट दी जा सकती है, विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।’।

141. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) में,—

धारा 30 का
संशोधन ।

(क) “रद्दकरण आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को विहित रीति में” शब्दों के स्थान पर, “ऐसी रीति में, ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन, जो विहित किए जाएं, ऐसे अधिकारी को” शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) परंतुक का लोप किया जाएगा ।

142. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

धारा 37 का
संशोधन ।

“(5) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उक्त ब्यौरे प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात्, कर अवधि के लिए उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को उपधारा (1) के अधीन कर अवधि के लिए जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए उक्त ब्यौरों को प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् भी अनुज्ञात कर सकेगी ।”।

143. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (10) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

धारा 39 का
संशोधन ।

“(11) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, किसी कर अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात्, उक्त विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को, किसी अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करने के लिए, उक्त विवरणी को प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् भी अनुज्ञात कर सकेगी ।”।

144. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 44 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

धारा 44 का
संशोधन ।

“(2) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन किसी वित्तीय वर्ष के लिए उक्त वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के

पश्चात् वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को, उपधारा (1) के अधीन वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए उक्त वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् भी अनुज्ञात कर सकेगी।”।

धारा 52 का
संशोधन।

145. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (14) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(15) किसी प्रचालक को, उपधारा (4) के अधीन विवरण प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् उक्त विवरण प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी प्रचालक या प्रचालकों के वर्ग को उपधारा (4) के अधीन उक्त विवरण प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख से उक्त तीन वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् भी अनुज्ञात कर सकेगी।”।

धारा 54 का
संशोधन।

146. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (6) में, “जिसके अंतर्गत अंतिमतः स्वीकृत इनपुट कर प्रत्यय की रकम नहीं है,” शब्दों का लोप किया जाएगा।

धारा 56 का
संशोधन।

147. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 56 में, “आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के अवसान के पश्चात् की तारीख से ऐसे कर का प्रतिदाय करने की तारीख तक” शब्दों के स्थान पर, “ऐसी शर्तों तथा निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, तथा ऐसी रीति में संगणित किए जाने वाले, ऐसे आवेदन के प्राप्ति की तारीख से ऐसे कर के प्रतिदाय की तारीख तक, साठ दिन से परे विलंब की ऐसी अवधि के लिए” शब्द रखे जाएंगे।

धारा 62 का
संशोधन।

148. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 62 की उपधारा (2) में,—

(क) “तीस दिन” शब्दों के स्थान पर, “साठ दिन” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन निर्धारण आदेश की तामील के साठ दिन के भीतर विधिमान्य विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है, वहां वह साठ दिन की अतिरिक्त अवधि के भीतर उक्त निर्धारण आदेश की तामील के साठ दिन से परे विलंब के प्रत्येक दिन के लिए एक सौ रुपए अतिरिक्त विलंब शुल्क के संदाय पर कर सकेगा और यदि वह ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर विधिमान्य विवरणी प्रस्तुत करता है तो उक्त निर्धारण आदेश का प्रतिसंहरण किया गया समझा जाएगा, किन्तु धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन ब्याज के संदाय का या धारा 47 के अधीन विलंब फीस के संदाय का दायित्व बना रहेगा।”।

धारा 109 का
प्रतिस्थापन।

149. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 109 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

अपील अधिकरण
और उसकी
न्यायपीठों का
गठन ।

“109. (1) सरकार, अधिसूचना द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए माल और सेवा कर अपील अधिकरण के नाम से ज्ञात एक अपील अधिकरण ऐसी तारीख से, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, स्थापित करेगी ।

(2) अपील अधिकरण को प्रदत्त अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग उपधारा (3) और उपधारा (4) के अधीन गठित प्रधान न्यायपीठ और राज्य न्यायपीठों द्वारा किया जाएगा ।

(3) सरकार, अधिसूचना द्वारा, अपील अधिकरण की नई दिल्ली में प्रधान न्यायपीठ का गठन करेगी, जो अध्यक्ष, एक न्यायिक सदस्य, एक तकनीकी सदस्य (केंद्रीय) और एक तकनीकी सदस्य (राज्य) से मिलकर बनेगी ।

(4) सरकार, राज्य के अनुरोध पर, अधिसूचना द्वारा उतनी संख्या में, ऐसे स्थानों पर और ऐसी अधिकारिता के साथ, जितनी परिषद् द्वारा सिफारिश की जाए, राज्य न्यायपीठों का गठन कर सकेगी, जो दो न्यायिक सदस्यों, एक तकनीकी सदस्य (केंद्रीय) और एक तकनीकी सदस्य (राज्य) से मिलकर बनेगी ।

(5) प्रधान न्यायपीठ और राज्य न्यायपीठ, अपील प्राधिकरण या पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करेंगी :

परंतु ऐसे मामले, जिनमें से कोई एक मुद्दा आपूर्ति के स्थान से संबंधित है, की सुनवाई प्रधान न्यायपीठ द्वारा की जाएगी ।

(6) अध्यक्ष, समय-समय पर, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, न्यायपीठों के बीच अपील अधिकरण के कारबार का वितरण करेगा और एक न्यायपीठ से दूसरी न्यायपीठ में मामलों का अंतरण कर सकेगा ।

(7) राज्य न्यायपीठों के भीतर ज्येष्ठतम न्यायिक सदस्य, जो अधिसूचित किया जाए, ऐसी राज्य न्यायपीठों के लिए उपाध्यक्ष से रूप में कार्य करेगा और वह अध्यक्ष की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो विहित की जाएं, किन्तु सभी अन्य प्रयोजनों के लिए उसे एक सदस्य ही समझा जाएगा ।

(8) अपीलों, जिसमें अंतर्वलित कर या इनपुट कर प्रत्यय या जुर्माने, फीस या किसी आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, में अवधारित शास्ति की रकम पचास लाख रुपए से अधिक नहीं है और जिसमें विधि का कोई प्रश्न अंतर्वलित नहीं है, अध्यक्ष के अनुमोदन से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो परिषद् की सिफारिशों पर विहित की जाएं, एकल सदस्य द्वारा सुनी जा सकेंगी और अन्य सभी मामलों में, एक न्यायिक सदस्य और एक तकनीकी सदस्य द्वारा एक साथ सुनी जाएगी ।

(9) मामले की सुनवाई के पश्चात्, यदि सदस्यों की राय में किसी बिन्दु या किन्हीं बिन्दुओं पर भिन्नता है तो ऐसे सदस्य ऐसे बिन्दु या बिन्दुओं का कथन करेंगे, जिन पर वे मत भिन्नता रखते हैं और अध्यक्ष ऐसे मामले को सुनवाई के लिए,—

(क) जहां अपील की किसी राज्य न्यायपीठ के सदस्यों द्वारा मूलतः सुनवाई की गई थी वहां राज्य के भीतर किसी राज्य न्यायपीठ के किसी दूसरे सदस्य द्वारा वहां राज्य के भीतर कोई दूसरी राज्य न्यायपीठ उपलब्ध नहीं है,

अन्य राज्य में किसी राज्य न्यायपीठ के किसी सदस्य को निर्दिष्ट की जाएगी;

(ख) जहां अपील की सुनवाई मूलतः प्रधान न्यायपीठ के सदस्यों द्वारा की गई थी, वहां प्रधान न्यायपीठ के किसी अन्य सदस्य को या जहां ऐसा अन्य सदस्य उपलब्ध नहीं है, किसी राज्य न्यायपीठ के सदस्य को,

निर्दिष्ट की जाएगी और ऐसे बिंदु या बिंदुओं का बहुमत के अनुसार विनिश्चय किया जाएगा, जिसके अंतर्गत उन सदस्यों, जिन्होंने मामले को प्रथम बार सुना था, की राय भी सम्मिलित है।

(10) सरकार, अध्यक्ष के परामर्श से, प्रशासनिक दक्षता के लिए, सदस्यों को एक न्यायपीठ से दूसरी न्यायपीठ को अंतरित कर सकेगी :

परंतु राज्य न्यायपीठ के किसी तकनीकी सदस्य (राज्य) को केवल उसी राज्य में, जिसमें वह मूलतः नियुक्त किया गया था, राज्य सरकार के परामर्श से, राज्य न्यायपीठ में अंतरित किया जा सकेगा।

(11) अपील अधिकरण का कोई कृत्य या कार्यवाहियां, अपील अधिकरण के गठन में किसी रिक्ति या त्रुटि की विद्यमानता के आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएंगी या अविधिमान्य नहीं मानी जाएंगी।”।

150. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 110 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“110. (1) कोई व्यक्ति निम्नलिखित की नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं होगा—

(क) अध्यक्ष के लिए, जब तक कि वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश न रहा हो, या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति न हो या न रहा हो ;

(ख) न्यायिक सदस्य के लिए, जब तक कि वह—

(i) उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न रहा हो ; या

(ii) दस वर्ष की संयुक्त अवधि के लिए जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश न रहा हो;

(ग) एक तकनीकी सदस्य (केन्द्रीय), जब तक वह केंद्रीय सरकार में विद्यमान विधि या माल और सेवा कर के प्रशासन में कम से कम तीन वर्ष के अनुभव के साथ भारतीय राजस्व (सीमाशुल्क और अप्रत्यक्ष कर) सेवा, समूह क या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य नहीं हो या नहीं रहा हो और उसने समूह क में कम से कम पच्चीस वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं की हो ;

(घ) एक तकनीकी सदस्य (राज्य), जब तक वह मूल्य संवर्धित कर या राज्य माल और सेवा कर के अतिरिक्त आयुक्त या ऐसी पंक्ति, जो प्रथम अपील प्राधिकारी, जैसा संबंध राज्य सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचित किया जाए, से अन्यून पंक्ति का राज्य सरकार का अधिकारी या अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी नहीं है या नहीं रहा है और उसने विद्यमान विधि या माल और सेवा कर अथवा राज्य सरकार में वित्त और कराधान के क्षेत्र में प्रशासन में कम से कम तीन वर्ष के अनुभव के साथ समूह क या समतुल्य सेवा में पच्चीस वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं की हो :

परंतु राज्य सरकार, परिषद् की सिफारिश पर, अधिसूचना द्वारा, समूह क या समतुल्य सेवा में पच्चीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने की अपेक्षा, ऐसे राज्य, जहां किसी

धारा 110 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

अपील अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य, उनकी अर्हता, नियुक्ति, सेवा की शर्तें, आदि।

व्यक्ति ने समूह क या समतुल्य में पच्चीस वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं की हो, परंतु उसने सरकार में पच्चीस वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, के अधिकारियों की बाबत ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसी अवधि तक, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, शिथिल कर सकेगी।

(2) अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य, तकनीकी सदस्य (केन्द्रीय) और तकनीकी सदस्य (राज्य), सरकार द्वारा, उपधारा (4) के अधीन गठित खोज-सह-चयन समिति की सिफारिशों पर नियुक्त या पुनःनियुक्त किए जाएंगे :

परंतु अध्यक्ष के पद पर, उसकी मृत्यु, त्यागपत्र या अन्यथा कारण से हुई किसी रिक्ति की दशा में, प्रधान न्यायपीठ का न्यायिक सदस्य या, उसकी अनुपस्थिति में, ज्येष्ठतम तकनीकी सदस्य, अध्यक्ष के पद पर उस तारीख तक कार्य करेगा, जिस तारीख तक, ऐसी रिक्ति को भरने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नियुक्त, कोई नया अध्यक्ष अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है :

परंतु यह और कि जहां अध्यक्ष, अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, वहां प्रधान न्यायपीठ का न्यायिक सदस्य या, उसकी अनुपस्थिति में, ज्येष्ठतम तकनीकी सदस्य, उस तारीख तक अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा, जिस तारीख तक अध्यक्ष अपने कृत्यों को फिर से संभाल लेता है ।

(3) किसी राज्य न्यायपीठ के तकनीकी सदस्य (राज्य) का चयन करते समय, ऐसे अधिकारियों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्होंने उस राज्य की राज्य सरकार में कार्य किया है, जिस पर न्यायपीठ की अधिकारिता का विस्तार है ।

(4) (क) राज्य न्यायपीठ के लिए तकनीकी सदस्य (राज्य) के लिए खोज-सह-चयन समिति, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(i) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, जिसकी अधिकारिता में राज्य न्यायपीठ अवस्थित है, समिति का अध्यक्ष होगा ;

(ii) उस राज्य का ज्येष्ठतम न्यायिक सदस्य और जहां कोई न्यायिक सदस्य उपलब्ध नहीं है, वहां उच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्ति न्यायाधीश, जिसकी अधिकारिता में राज्य न्यायपीठ अवस्थित है, जिसे उस न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए ;

(iii) उस राज्य का मुख्य सचिव, जिसकी अधिकारिता में राज्य न्यायपीठ अवस्थित है ;

(iv) उस राज्य, जिसकी अधिकारिता में राज्य न्यायपीठ अवस्थित है, का एक अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव, जो राज्य कर के प्रशासन के लिए उत्तरदायित्व विभाग का भारसाधक नहीं है, जिसे ऐसी राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए ; और

(v) उस राज्य, जिसकी अधिकारिता में राज्य न्यायपीठ अवस्थित है, के राज्य कर के प्रशासन के लिए उत्तरदायित्व विभाग का एक अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव, जिसे ऐसी राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए ; और

(ख) अन्य सभी मामलों के लिए खोज-सह-चयन समिति, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(i) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट उच्चतम

न्यायालय का कोई न्यायाधीश, समिति का अध्यक्ष होगा ;

(ii) मंत्रिमंडल सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट केंद्रीय सरकार का सचिव-सदस्य;

(iii) परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला राज्य का मुख्य सचिव-सदस्य;

(iv) एक सदस्य, जो,—

(अ) अधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति की दशा में, अधिकरण का पद छोड़ने वाला अध्यक्ष होगा ; या

(आ) अधिकरण के सदस्य की नियुक्ति की दशा में, अधिकरण का पीठासीन अध्यक्ष ; या

(इ) पुनर्नियुक्ति चाहने वाले अध्यक्ष की दशा में या जहां पद छोड़ने वाला अध्यक्ष अनुपलब्ध है या जहां अध्यक्ष के हटाए जाने पर विचार किया जा रहा है, उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामनिर्दिष्ट उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति होगा ; और

(v) केंद्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का सचिव - सदस्य सचिव ।

(5) अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा और सदस्य सचिव का मत नहीं होगा ।

(6) किसी न्यायालय के किसी निर्णय, आदेश या डिक्री या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी समिति, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के पद पर नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए दो नामों के पैनल की सिफारिश करेगी ।

(7) अपील अधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं हो जाएगी कि खोज-सह-चयन समिति में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है ।

(8) किसी न्यायालय के किसी निर्णय, आदेश या डिक्री या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अपील अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन ऐसा होगा, जो विहित किया जाए और उनके भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जो केंद्रीय सरकार के समान वेतनधारी अधिकारियों को लागू होती हैं :

परंतु अपील अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति के पश्चात्, न तो उनके वेतन और भत्तों में और न ही अन्य निबंधनों और शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन किया जाएगा :

परंतु यह और कि यदि अध्यक्ष या सदस्य कोई घर किराए पर लेता है, उसे ऐसी सीमाओं और शर्तों, जो विहित की जाए, के अध्यक्षीन रहते हुए, समान वेतनधारी पदों को धारण करने वाले केंद्रीय सरकार के अधिकारियों को अनुज्ञेय मकान किराया भत्ते से अधिक मकान किराए की प्रतिपूर्ति की जा सकेगी ।

(9) किसी न्यायालय के किसी निर्णय, आदेश या डिक्री या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अपील अधिकरण का कोई अध्यक्ष, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, चार वर्ष की अवधि

के लिए या सड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, पद धारण करेगा और दो वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा ।

(10) किसी न्यायालय के किसी निर्णय, आदेश या डिक्री या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अपील अधिकरण का कोई न्यायिक सदस्य, तकनीकी सदस्य (केंद्रीय) या तकनीकी सदस्य (राज्य), उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, चार वर्ष की अवधि के लिए या पैसठ वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, पद धारण करेगा और दो वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा ।

(11) अध्यक्ष या कोई सदस्य, सरकार को संबोधित करते हुए, लिखित नोटिस द्वारा, अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा :

परंतु अध्यक्ष या सदस्य, सरकार द्वारा ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के अवसान तक या उसके उत्तराधिकारी के रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त व्यक्ति के पद धारण करने तक या उसकी पदावधि की समाप्ति तक, जो भी पहले हो, पद पर बना रहेगा ।

(12) सरकार, खोज-सह-चयन समिति की सिफारिशों पर, अध्यक्ष या किसी सदस्य को उसके पद से हटा सकेगी, जो,—

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है ; या

(ख) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित है ; या

(ग) जो ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से अक्षम हो गया है ; या

(घ) जिसने ऐसे वितीय या अन्य हित अर्जित किए हैं, जिससे उसके ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(ङ) उसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है, जिसके कारण उसका पद पर बने रहना लोकहित के प्रतिकूल है :

परन्तु किसी अध्यक्ष या सदस्य को, खंड (घ) और खंड (ङ) में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर तब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक उसे उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की सूचना नहीं दे दी गई हो और सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो ।

(13) सरकार, खोज-सह-चयन समिति की सिफारिशों पर, अध्यक्ष या किसी न्यायिक या तकनीकी सदस्य को, जिसके संबंध में उपधारा (12) के अधीन कार्यवाहियां आरंभ की गई हैं, उसके पद से निलंबित कर सकेगी ।

(14) संविधान के अनुच्छेद 220 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य, उसके पद पर नहीं बने रहने पर, प्रधान न्यायपीठ या राज्य न्यायपीठ, जिसमें वह, यथास्थिति, अध्यक्ष या कोई सदस्य था, के समक्ष उपस्थित होने, कार्य करने या अभिवचन करने का पात्र नहीं होगा ।

151. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 114 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“114. अध्यक्ष, अपील अधिकरण पर ऐसी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो विहित की जाए।”।

धारा 114 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन। अध्यक्ष की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां।

धारा 117 का संशोधन।

152. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 117 में,—

(क) उपधारा (1) में, “राज्य न्यायपीठ या अपील अधिकरण की क्षेत्रीय न्यायपीठों” शब्दों के स्थान पर, “अपील अधिकरण की राज्य न्यायपीठों” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (5) के खंड (क) और खंड (ख) में, “राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठों” शब्दों के स्थान पर, “राज्य न्यायपीठों” शब्द रखे जाएंगे।

धारा 118 का संशोधन।

153. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 118 की उपधारा (1) के खंड (क) में, “राष्ट्रीय न्यायपीठ या अपील अधिकरण की प्रादेशिक न्यायपीठों” शब्दों के स्थान पर, “अपील अधिकरण की प्रधान न्यायपीठ” शब्द रखे जाएंगे।

धारा 119 का संशोधन।

154. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 119 में,—

(क) “राष्ट्रीय या प्रादेशिक न्यायपीठों” शब्दों के स्थान पर, “प्रधान न्यायपीठ” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) “राज्य न्यायपीठों या क्षेत्रीय न्यायपीठों” शब्दों के स्थान पर, “राज्य न्यायपीठों” शब्द रखे जाएंगे।

धारा 122 का संशोधन।

155. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 122 में, उपधारा (1क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(1ख) कोई इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक, जो—

(i) इस अधिनियम के अधीन जारी अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकरण से छूट प्राप्त व्यक्ति से भिन्न, किसी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति ऐसी पूर्ति करने के लिए अनुज्ञात करता है ;

(ii) इसके माध्यम से किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की अंतर्राज्यिक पूर्ति अनुज्ञात करता है, जो ऐसी अंतर्राज्यिक पूर्ति करने के लिए पात्र नहीं है ; या

(iii) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने से छूट प्राप्त किसी व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से की गई माल की किसी जावक पूर्ति के धारा 52 की उपधारा (4) के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण में सही ब्यौरे प्रस्तुत करने में असफल रहता है,

धारा 10 के अधीन कर संदाय करने वाले व्यक्ति से भिन्न, यदि ऐसी पूर्ति किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा की गई होती, तो दस हजार रुपए या अंतर्वर्तित कर की रकम के समतुल्य रकम, जो भी उच्चतर हो की शास्ति का संदाय करने का दायी होगा।”।

धारा 132 का संशोधन।

156. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) में,—

(क) खंड (छ), खंड (ज) और खंड (ट) का लोप किया जाएगा ;

(ख) खंड (ठ) में, “खंड (क) से खंड (ट)” शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, “खंड (क) से खंड (च) और खंड (ज) से खंड (झ)” शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ग) खंड (iii) में, “जहां कर अपवंचन” शब्दों के स्थान पर, “खंड (ख) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध की दशा में, जहां कर अपवंचन” शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(घ) खंड (iv) में, “या खंड (छ) या खंड (ज)” शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों का लोप किया जाएगा ।

157. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 138 में,—

धारा 138 का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) के पहले परंतुक में,—

(i) खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(क) किसी व्यक्ति, जिसे धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (च), खंड (ज), खंड (झ) तथा खंड (ठ) में विनिर्दिष्ट अपराधों में से किन्हीं के संबंध में एक बार शमन के लिए अनुज्ञात किया गया है;”;

(ii) खंड (ख) का लोप किया जाएगा ;

(iii) खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(ग) कोई व्यक्ति, जो धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन कोई अपराध करने का अभियुक्त रहा है ;”;

(iv) खंड (ड) का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (2) में “न्यूनतम दस हजार रुपए या अंतर्वलित कर के पचास प्रतिशत से, इनमें से जो भी उच्चतर हों, के अधीन रहते हुए और अधिकतम रकम तीस हजार रुपए या कर के एक सौ पचास प्रतिशत, इनमें से जो भी उच्चतर हो,” शब्दों के स्थान पर “अंतर्वलित कर के पच्चीस प्रतिशत और अधिकतम रकम अंतर्वलित कर के सौ प्रतिशत से अनधिक” शब्द रखे जाएंगे ।

158. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 158 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

नई धारा 158क का अंतःस्थापन ।

“158क. (1) धारा 133, धारा 152 और धारा 158 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित ब्यौरों को, उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केंद्रीय सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, ऐसी अन्य प्रणालियों के साथ, अधिसूचित सामान्य पोर्टल द्वारा साझा किया जा सकेगा, अर्थात्:—

कराधेय व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना को सम्मति के आधार पर साझा करना ।

(क) धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में प्रस्तुत विशिष्टियां या धारा 39 या धारा 44 के अधीन फाइल की गई विवरणी में प्रस्तुत किए गए ब्यौरे ;

(ख) बीजक तैयार करने के लिए सामान्य पोर्टल पर अपलोड की गई विशिष्टियां, धारा 37 के अधीन प्रस्तुत जावक पूर्तियों के ब्यौरे और धारा 68 के अधीन दस्तावेजों के सृजन के लिए सामान्य पोर्टल पर अपलोड की गई

विशिष्टियां ;

(ग) ऐसे अन्य ब्यौरे, जो विहित किए जाएं ।

(2) उपधारा (1) के अधीन ब्यौरों को साझा करने के प्रयोजनों के लिए,—

(क) उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन प्रस्तुत ब्यौरों के संबंध में प्रदायकर्ता की सहमति ; और

(ख) उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन और उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन प्रस्तुत ब्यौरों के संबंध में प्राप्तिकर्ता की सहमति, केवल जहां ऐसे ब्यौरों के अंतर्गत प्राप्तिकर्ता की पहचान संबंधी जानकारी भी सम्मिलित है, ऐसे प्ररूप और रीति में अभिप्राप्त की जाएगी, जो विहित की जाए ।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन साझा की गई जानकारी के पारिणामिक उद्भूत होने वाले किसी दायित्व के संबंध में सरकार या सामान्य पोर्टल के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी तथा सुसंगत पूर्ति पर या सुसंगत विवरणी के अनुसार कर संदाय करने के दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं होगा ।”।

केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की अनुसूची 3 में कतिपय क्रियाकलापों और संव्यवहारों के लिए भूतलक्षी छूट ।

159. (1) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की अनुसूची 3 के पैरा 7 और पैरा 8 तथा उसके स्पष्टीकरण 2 (2018 का अधिनियम सं. 31) की धारा 32 द्वारा यथा अंतःस्थापित) को 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी रूप से उसमें अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा ।

(2) ऐसे सभी कर का कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिसे संग्रहित किया गया है किंतु जिसे संग्रहित नहीं किया गया होता यदि उपधारा (1) सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त हुई होती ।

एकीकृत माल और सेवा कर

धारा 2 का संशोधन ।

160. एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,—

2017 का 13

(क) खंड (16) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(16) “गैर-कराधेय ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता” से ऐसा कोई अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अभिप्रेत है, जो कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनःप्राप्य सेवाओं को प्राप्त करता है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, “अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति” पद के अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी सम्मिलित है, जो केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के खंड (vi) के निबंधनानुसार एकमात्र रूप से रजिस्ट्रीकृत है ।”;

2017 का 12

(ख) खंड (17) में, “आवश्यक रूप से स्वचालित कर देती है और जिसमें न्यूनतम मानव मध्यक्षेप है और जिसे” शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 12 का संशोधन ।

161. एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (8) के परंतुक का लोप किया जाएगा ।

धारा 13 का

162. एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 13 में, उपधारा (9) का लोप

संशोधन ।

किया जाएगा ।

माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियमअनुसूची का
संशोधन ।**163. माल और सेवा कर अधिनियम (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 की अनुसूची में,—**

2017 का 15

(क) क्रम सं0 1 में, टैरिफ मद 2106 90 20 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “प्रति इकाई खुदरा विक्रय मूल्य का इक्यावन प्रतिशत” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) क्रम सं0 2 में, अध्याय 24 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “चार हजार एक सौ सत्तर रुपए प्रति हजार यष्टि या मूल्यानुसार दो सौ नब्बे प्रतिशत या उसका समुच्चय, किन्तु मूल्यानुसार चार हजार एक सौ सत्तर रुपए प्रति हजार यष्टि जमा दो सौ नब्बे प्रतिशत या प्रति इकाई खुदरा विक्रय कीमत के सौ प्रतिशत से अधिक नहीं” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ग) अंत में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘स्पष्टीकरण—इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए,—

(i) “खुदरा विक्रय कीमत” से वह अधिकतम विक्रय कीमत अभिप्रेत है, जिस पर पैक की गई अवस्था में संबद्ध माल को अंतिम उपभोक्ता को विक्रय किया जा सके और उसमें सभी कर, स्थानीय या अन्यथा, भाड़ा, परिवहन प्रभार, व्यौहारियों को संदेय कमीशन, और विज्ञापन, परिदान, पैक करने, अग्रेषित करने के लिए और ऐसे समान सभी प्रभार सम्मिलित हैं तथा ऐसे विक्रय के लिए कीमत एकमात्र प्रतिफल है :

परंतु जहां विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन, पैकेज के ऊपर किन्हीं करों, स्थानीय या अन्यथा के सिवाय, खुदरा विक्रय कीमत घोषित करना अपेक्षित हो, वहां खुदरा विक्रय कीमत का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(ii) जहां किसी संबद्ध माल के पैकेज पर एक से अधिक खुदरा विक्रय कीमत घोषित की जाती है, वहां ऐसी खुदरा विक्रय कीमतों के अधिकतम को, खुदरा विक्रय कीमत समझा जाएगा ;

(iii) जहां किसी संबद्ध माल के पैकेज पर विनिर्माण स्थल से उसकी निकासी के समय घोषित खुदरा विक्रय कीमत को खुदरा विक्रय कीमत बढ़ाने के लिए परिवर्तित किया जाता है, वहां ऐसी परिवर्तित खुदरा विक्रय कीमत को, खुदरा विक्रय कीमत समझा जाएगा ;

(iv) जहां विभिन्न क्षेत्रों में पैक की गई अवस्था में किसी संबद्ध माल के विक्रय के लिए भिन्न-भिन्न पैकेजों पर भिन्न-भिन्न खुदरा विक्रय कीमत घोषित की जाती है, वहां प्रत्येक ऐसी खुदरा विक्रय कीमत, उस क्षेत्र, जिससे खुदरा विक्रय कीमत संबद्ध है, में विक्रय किए जाने के लिए आशयित उक्त माल के लिए उपकर की दर के अवधारण के प्रयोजनों के लिए खुदरा विक्रय कीमत समझी जाएगी ।’।

अध्याय 5**प्रकीर्ण**

भाग 1

सरकारी बचत संवर्द्धन अधिनियम, 1873 का संशोधन

164. इस भाग के उपबंध ऐसी तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

इस भाग का प्रारंभ।

165. सरकारी बचत संवर्द्धन अधिनियम, 1873 में,—

1873 के अधिनियम सं0 5 का संशोधन।

(क) धारा 4क में, उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(4) यदि किसी जमाकर्ता की मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के समय कोई नामनिर्देशन प्रवृत्त नहीं है तथा उसकी विल का प्रोबेट या संपदा का प्रशासन पत्र या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के अधीन अनुदत्त उत्तराधिकार-प्रमाणपत्र या अधिकारिता रखने वाले तहसीलदार से अन्यून रैंक के राजस्व प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया विधिक उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र, प्राधिकृत अधिकारी को जमाकर्ता की मृत्यु होने की तारीख से छह मास के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो जहां पात्र अतिशेष ऐसी सीमा से, जो विहित की जाए, अधिक नहीं है, तो प्राधिकृत अधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किए जाएं, पात्र अतिशेष का ऐसे किसी व्यक्ति को ऐसी प्रक्रिया और रीति के अनुसार, जो विहित की जाए, संदाय कर सकेगा, जो उसको प्राप्त करने के लिए या मृतक की संपदा का प्रशासन करने के लिए विधिक रूप से हकदार हो।”;

1925 का 39

(ख) धारा 15 की उपधारा (2) में, खंड (झ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(i) धारा 4क की उपधारा (4) के अधीन सीमा, प्रक्रिया और रीति ;”;

(ग) अनुसूची के भाग क में, क्रम संख्यांक 7 और 8 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“7. लोक भविष्य निधि स्कीम

8. राष्ट्रीय बचत पत्र (आठवां इश्यू) स्कीम, 2019

9. किसान विकास पत्र स्कीम, 2019

10. बालकों के लिए पीएम केयर्स स्कीम, 2021”।

भाग 2

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 का संशोधन

1899 के अधिनियम सं0 2 का संशोधन।

166. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1 के अनुच्छेद 47 के प्रभाग घ में, “छूट” शीर्ष के अधीन “डाक विभाग महानिदेशालय” से प्रारंभ होने वाले और “बीमा के नियमों के अनुसार निगमित की गई है।” पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“जीवन बीमा पालिसियां—

(क) केंद्रीय सरकार के प्राधिकार के अधीन डाकघर महानिदेशक द्वारा जारी डाक जीवन बीमा नियमों के अनुसार अनुदत्त ; और

(ख) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीवाई) के अधीन।”।

भाग 3

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 का संशोधन

1956 के
अधिनियम सं0
42 का संशोधन ।

167. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 18क के खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘(खक) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 4 के अधीन स्थापित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा विनियमित और विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता द्वारा जारी ।

2019 का 50

1999 का 42

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, “विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता” पद का वही अर्थ होगा, जो इसका विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 46 के अधीन बनाए गए विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 के नियम 2 के खंड (प) में है ;’।

भाग 4

केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 का संशोधन

1956 का 74

168. केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे इसमें इसके पश्चात् केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम कहा गया है) की धारा 19 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

धारा 19 के
स्थान पर नई
धारा का
प्रतिस्थापन ।

1962 का 52

“19. इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में प्रतिकूल अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 129 के अधीन गठित सीमाशुल्क, उत्पाद-शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण इस अधिनियम के अधीन धारा 6क और धारा 9 के अधीन आने वाले अंतरराज्यीय विवादों का निपटारा करने के लिए प्राधिकरण होगा ।”।

इस अधिनियम
के अधीन
सीमाशुल्क,
उत्पाद-शुल्क
और सेवा कर
अपील अधिकरण
के प्राधिकारी के
रूप में कार्य
करना ।

169. केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 24 का लोप किया जाएगा ।

धारा 24 का
लोप ।

170. केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 25 में, उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

धारा 25 का
संशोधन ।

“(3) धारा 20 के अधीन फाइल की गई तथा तत्कालीन अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी के समक्ष उस तारीख को लंबित सभी अपीलों, जिसको वित्त विधेयक, 2023 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, धारा 19 में निर्दिष्ट प्राधिकरण को अंतरित हो जाएंगी ।”।

भाग 5

बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988 का संशोधन

171. बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988 में, 1 अप्रैल, 2023 से,—

1988 के
अधिनियम
सं0 45 का
संशोधन ।

(क) धारा 2 के खंड (18) में,—

(I) उपखंड (i) के अंत में आने वाले “और” शब्द का लोप किया जाएगा;

(II) उपखंड (ii) के अंत में, “और” शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा ;

(III) उपखंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(iii) वह उच्च न्यायालय, जिसकी अधिकारिता के भीतर प्रारंभक

अधिकारी का कार्यालय अवस्थित है,—

(क) जहां व्यथित पक्षकार किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता के भीतर मामूली तौर से निवास नहीं करता है या कारबार नहीं करता है या अभिलाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य नहीं करता है ;

(ख) जहां सरकार एक व्यथित पक्षकार है और प्रत्यर्थियों में से कोई भी प्रत्यर्थी किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता के भीतर मामूली तौर से निवास नहीं करता है या कारबार नहीं करता है या अभिलाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य नहीं करता है ;”;

(ख) धारा 46 में,—

(i) उपधारा (1) में, “उस आदेश की तारीख से” शब्दों के स्थान पर, “उस तारीख से, जिसको ऐसा आदेश प्रारंभक अधिकारी या ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (1क) में, “उस आदेश की तारीख से” शब्दों के स्थान पर, “उस तारीख से, जिसको ऐसा आदेश ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है,” शब्द रखे जाएंगे ।

भाग 6

वित्त अधिनियम, 2001 का संशोधन

2001 के
अधिनियम सं0
14 की सातवीं
अनुसूची का
संशोधन ।

172. वित्त अधिनियम, 2001 की सातवीं अनुसूची का, छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा ।

भाग 7

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 का संशोधन

2002 के अधिनियम
संख्यांक सं0 58 का
संशोधन ।

173. भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 में, 1 अप्रैल, 2023 से,—

(क) धारा 8 की उपधारा (1) में, “विनिधानकर्ताओं को संपूर्ण रकम का संदाय हो जाने पर” शब्दों के स्थान पर, “विनिधानकर्ताओं को संपूर्ण रकम का संदाय हो जाने पर या ऐसी तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाए, इनमें से जो भी पूर्वतर हों” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) धारा 13 की उपधारा (1) में, “31 मार्च, 2023” अंकों और शब्द के स्थान पर, “31 मार्च, 2025” अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

भाग 8

वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2004 का संशोधन

धारा 98 का
संशोधन ।

174. वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 की धारा 98 की सारणी की क्रम सं. 4 के स्तंभ (2) में—

2004 का 23

(i) प्रविष्टि (क) के सामने, स्तंभ (3) में, “प्रविष्टि” के स्थान पर, “0.021 प्रतिशत” अंक और शब्द रखे जाएंगे ; और

(ii) प्रविष्टि (ग) के सामने, स्तंभ (3) में, “प्रविष्टि” के स्थान पर, “0.0125 प्रतिशत”अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

पहली अनुसूची

(धारा 2 देखिए)

भाग 1

आय-कर

पैरा क

(I) इस पैरा की मद (II) और मद (III) में निर्दिष्ट व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसमें इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,—

आय-कर की दरें

- (1) जहां कुल आय 2,50,000 रुपए से अधिक नहीं है कुछ नहीं ;
- (2) जहां कुल आय 2,50,000 रुपए से अधिक है किंतु 5,00,000 रुपए से अधिक नहीं है उस रकम का 5 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रुपए से अधिक हो जाती है ;
- (3) जहां कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक है किंतु 10,00,000 रुपए से अधिक नहीं है 12,500 रुपए धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ;
- (4) जहां कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक है 1,12,500 रुपए धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ।

(II) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है—

आय-कर की दरें

- (1) जहां कुल आय 3,00,000 रुपए से अधिक नहीं है कुछ नहीं ;
- (2) जहां कुल आय 3,00,000 रुपए से अधिक है किंतु 5,00,000 रुपए से अधिक नहीं है उस रकम का 5 प्रतिशत, जिससे कुल आय 3,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ;
- (3) जहां कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक है किंतु 10,00,000 रुपए से अधिक नहीं है 10,000 रुपए धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ;
- (4) जहां कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक है 1,10,000 रुपए धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ।

(III) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी

समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है—

आय-कर की दरें

- (1) जहां कुल आय 5,00,000 रुपए से कुछ नहीं ;
अधिक नहीं है
- (2) जहां कुल आय 5,00,000 रुपए से उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय अधिक है किंतु 10,00,000 रुपए से अधिक 5,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ;
नहीं है
- (3) जहां कुल आय 10,00,000 रुपए से 1,00,000 रुपए धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों या धारा 115खकग के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यक्ति-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय या लाभांश के रूप में आय सम्मिलित है) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ख) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय या लाभांश के रूप में आय सम्मिलित है) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(ग) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय या लाभांश के रूप में आय सम्मिलित नहीं है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

(घ) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय या लाभांश के रूप में आय सम्मिलित नहीं है) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पैंतीस प्रतिशत की दर से ; और

(ङ) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय या लाभांश के रूप में आय सम्मिलित है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु वह खंड (ग) और खंड (घ) के अंतर्गत नहीं आती है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से,

संगणित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु उस दशा में, जहां कुल आय में लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय सम्मिलित है, वहां आय के उस भाग के संबंध में संगणित आय-कर की रकम पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक

नहीं होगी :

परन्तु यह और कि व्यक्तियों के संगम की दशा में, जो केवल कंपनियों से उसके सदस्यों के रूप में मिलकर बनी है, आय-कर की रकम पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी:

परन्तु यह भी कि ऊपर उल्लिखित व्यक्तियों की दशा में,—

(क) जिनकी कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, पचास लाख रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के पचास लाख रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ;

(ख) जिनकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ;

(ग) जिनकी कुल आय दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दो करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के दो करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ; और

(घ) जिनकी कुल आय पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, पांच करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के पांच करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,—

आय-कर की दरें

- (1) जहां कुल आय 10,000 रुपए से अधिक कुल आय का 10 प्रतिशत ;
नहीं है
- (2) जहां कुल आय 10,000 रुपए से अधिक है 1,000 रुपए धन उस रकम का 20 प्रतिशत
किंतु 20,000 रुपए से अधिक नहीं है जिससे कुल आय 10,000 रुपए से अधिक हो
जाती है ;
- (3) जहां कुल आय 20,000 रुपए से अधिक है 3,000 रुपए धन उस रकम का 30 प्रतिशत
जिससे कुल आय 20,000 रुपए से अधिक हो
जाती है ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसी प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक

नहीं है, ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से;

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से;

संगणित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है :

परन्तु यह और कि प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, उस आय की रकम, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है से अधिक एक करोड़ रुपए की रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय कुल रकम से अधिक नहीं होगी ।

पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर

30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसी प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु ऊपर उल्लिखित प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, उस आय की रकम, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है से अधिक एक करोड़ रुपए की रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय कुल रकम से अधिक नहीं होगी ।

पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर

30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से संगणित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु ऊपर उल्लिखित प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय

की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा ड

किसी कंपनी की दशा में,—

आय-कर की दरें

I. देशी कंपनी की दशा में,—

- | | | |
|--|-----------|----|
| (i) जहां पूर्ववर्ष 2020-2021 में इसका कुल आवर्त या कुल प्राप्तियां | कुल आय का | 25 |
| चार अरब रुपए से अधिक न हो | प्रतिशत ; | |
| (ii) मद (i) में निर्दिष्ट के सिवाय | कुल आय का | 30 |
| | प्रतिशत । | |

II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,—

(i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,—

(क) 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व ; या

(ख) 29 फरवरी, 1964 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुत्थान से तकनीकी सेवाएं देने के लिए प्राप्त फीसें,

और जहां, दोनों में से किसी भी दशा में, ऐसा करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है

50 प्रतिशत ;

(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो

40 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में निम्नलिखित दर से,—

(i) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अनधिक है, ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अनधिक है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु

दस करोड़ रुपए से अनधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है :

परन्तु यह और कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय उस रकम से, उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के दस करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

भाग 2

कतिपय दशाओं में स्रोत पर कर की कटौती की दरें

ऐसी प्रत्येक दशा में, जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 193, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194खक, धारा 194खख, धारा 194घ, धारा 194ठखक, धारा 194ठखख, धारा 194ठखग और धारा 195 के उपबंधों के अधीन कर की कटौती प्रवृत्त दरों से की जानी है, आय में से कटौती निम्नलिखित दरों पर कटौती के अधीन रहते हुए की जाएगी:—

आय-कर की दर

1. कंपनी से भिन्न व्यक्ति की दशा में,—

(क) जहां व्यक्ति भारत में निवासी है,—

- | | |
|--|--------------|
| (i) “प्रतिभूतियों पर ब्याज” से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर | 10 प्रतिशत ; |
| (ii) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत (आनलाइन खेल से जीत से भिन्न) के रूप में आय पर | 30 प्रतिशत ; |
| (iii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर | 30 प्रतिशत ; |
| (iv) आनलाइन खेलों से जीत के रूप में आय | 30 प्रतिशत ; |
| (v) बीमा कमीशन के रूप में आय पर | 5 प्रतिशत ; |
| (vi) निम्नलिखित पर संदेय ब्याज के रूप में आय पर— | 10 प्रतिशत ; |

(अ) किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम द्वारा या उसकी ओर से धन के लिए पुरोधृत किए गए कोई डिबेंचर या प्रतिभूतियां ;

(आ) किसी कंपनी द्वारा पुरोधृत किए गए कोई डिबेंचर, जहां ऐसे डिबेंचर, भारत में मान्यताप्राप्त किसी स्टाक एक्सचेंज में प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसार सूचीबद्ध हैं ;

(इ) केंद्रीय या राज्य सरकार की कोई प्रतिभूति ;

(vii) किसी अन्य आय पर 10 प्रतिशत ;

(ख) जहां व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है,—

(i) किसी अनिवासी भारतीय की दशा में,—

(अ) विनिधान से किसी आय पर	20 प्रतिशत ;
(आ) धारा 115ड या धारा 112 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(इ) धारा 112क में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में एक लाख रुपए से अधिक आय पर	10 प्रतिशत ;
(ई) दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों [जो धारा 10 के खंड (33) और खंड (36) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं हैं] के रूप में अन्य आय पर	20 प्रतिशत ;
(उ) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	15 प्रतिशत ;
(ऊ) सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर (जो धारा 194ठख या धारा 194ठग में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है)	20 प्रतिशत ;
(ऋ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परन्तुक में निर्दिष्ट किसी विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परन्तुक में निर्दिष्ट किसी कम्प्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है	20 प्रतिशत ;
(ए) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में [जो उपमद (ख)(i)(ऋ) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है], आय पर	20 प्रतिशत ;
(ऐ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है या जहां वह भारत	20 प्रतिशत

सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा तकनीकी सेवाओं के लिए संदेय फीस के रूप में आय पर

(ओ) लाटरी, वर्ग पहली, ताश के खेल और किसी प्रकार के खेलों से जीत (आनलाइन खेलों से जीत से भिन्न) के रूप में आय पर 30 प्रतिशत ;

(औ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर 30 प्रतिशत ;

(अं) आनलाइन खेलों से जीत से आय पर 30 प्रतिशत ;

(अः) धारा 115क की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (अ) के परंतुक में निर्दिष्ट लाभांश के माध्यम से आय पर 10 प्रतिशत ;

(ऑ) उपमद (ख)(i)(अः) में निर्दिष्ट आय से भिन्न लाभांश के माध्यम से आय पर 20 प्रतिशत ;

(क्ष) अन्य संपूर्ण आय 30 प्रतिशत ;

(ii) अन्य व्यक्ति की दशा में,—

(अ) सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर (जो धारा 194ठख या धारा 194ठग में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है) 20 प्रतिशत ;

(आ) सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ उसके द्वारा किए गए किसी करार के अनुसरण में, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परन्तुक में निर्दिष्ट किसी विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परन्तुक में निर्दिष्ट किसी कम्प्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है 20 प्रतिशत ;

(इ) सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ उसके द्वारा किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां यह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में [जो उपमद (ख)(ii)(आ) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है], आय पर 20 प्रतिशत ;

(ई) सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ उसके द्वारा किए 20 प्रतिशत ;

गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा तकनीकी सेवाओं के लिए संदेय फीस के रूप में आय पर

(उ) लाटरी, वर्ग पहली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेलों से जीत (आनलाइन खेलों से जीत से भिन्न) के रूप में आय पर 30 प्रतिशत ;

(ऊ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर 30 प्रतिशत ;

(ऋ) आनलाइन खेल से जीत के रूप में आय 30 प्रतिशत ;

(ए) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर 15 प्रतिशत ;

(ऐ) धारा 112 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर 10 प्रतिशत ;

(ओ) धारा 112क में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में एक लाख रुपए से अधिक अन्य आय पर 10 प्रतिशत ;

(औ) अन्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर 20 प्रतिशत ; [जो धारा 10 के खंड (33) और खंड (36) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं हैं]

(अं) धारा 115क की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (अ) के परंतुक में निर्दिष्ट लाभांश के माध्यम से आय पर 10 प्रतिशत ;

(अः) उपमद (ख)(ii)(अं) में निर्दिष्ट आय से भिन्न लाभांश के माध्यम से आय पर 20 प्रतिशत ;

(ऑ) अन्य संपूर्ण आय 30 प्रतिशत ;

2. कंपनी की दशा में,—

(क) जहां कंपनी देशी कंपनी है,—

(i) “प्रतिभूतियों पर ब्याज” से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर 10 प्रतिशत ;

(ii) लाटरी, वर्ग पहली, ताश के खेल और अन्य प्रकार के अन्य खेलों से जीत (आनलाइन खेलों से जीत से भिन्न) के रूप में आय पर 30 प्रतिशत ;

(iii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर 30 प्रतिशत ;

(iv) आनलाइन खेलों से जीत के रूप में आय 30 प्रतिशत ;

(v) किसी अन्य आय पर 10 प्रतिशत ;

(ख) जहां कंपनी देशी कंपनी नहीं है,—

(i) लाटरी, वर्ग पहली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेलों से जीत (आनलाइन खेलों से जीत से भिन्न) के रूप में आय पर 30 प्रतिशत ;

;

- (ii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर 30 प्रतिशत ;
- (iii) आनलाइन खेलों से जीत के रूप में आय 30 प्रतिशत ;
- (iv) सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा किसी विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर (जो धारा 194ठख या धारा 194ठग में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है) 20 प्रतिशत ;
- (v) उसके द्वारा 31 मार्च, 1976 के पश्चात् सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परन्तुक में निर्दिष्ट विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परन्तुक में निर्दिष्ट किसी कंप्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है 20 प्रतिशत ;
- (vi) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है अथवा जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसरण में है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर [जो उपमद (ख)(iv) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है]—
- (अ) जहां करार 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है 50 प्रतिशत ;
- (आ) जहां करार 31 मार्च, 1976 के पश्चात् किया गया है 20 प्रतिशत ;
- (vii) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है अथवा जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा, तकनीकी सेवाओं के लिए, संदेय फीस के रूप में आय पर,—

(अ) जहां करार 29 फरवरी, 1964 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है	50 प्रतिशत ;
(आ) जहां करार 31 मार्च, 1976 के पश्चात् किया गया है	20 प्रतिशत ;
(viii) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	15 प्रतिशत ;
(ix) धारा 112 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(x) धारा 112क में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में एक लाख रुपए से अधिक आय पर	10 प्रतिशत ;
(xi) अन्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर [जो धारा 10 के खंड (33) और खंड (36) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं हैं]	20 प्रतिशत ;
(xii) धारा 115क की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (अ) के परंतुक में निर्दिष्ट लाभांश के माध्यम से आय पर	10 प्रतिशत ;
(xiii) उपमद (ख)(xii) में निर्दिष्ट आय से भिन्न लाभांश के माध्यम से आय पर	20 प्रतिशत ;
(xiv) किसी अन्य आय पर	30 प्रतिशत ।

स्पष्टीकरण—इस भाग की मद 1(ख)(i) के प्रयोजनों के लिए, “विनिधान से आय” और “अनिवासी भारतीय” के वही अर्थ हैं, जो आय-कर अधिनियम के अध्याय 12क में उनके हैं ।

आय-कर पर अधिभार

उस आय-कर की रकम में जिसकी,—

(i) इस भाग की मद 1 के उपबंधों के अनुसार कटौती की गई हो, संघ के प्रयोजनों के लिए,—

(क) प्रत्येक व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यक्ति-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो अनिवासी है,—

I. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित है) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

II. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन

कोई आय सम्मिलित है) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

III. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित नहीं है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

IV. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित नहीं है) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से ; और

V. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु वह उपखंड III और उपखंड IV के अंतर्गत नहीं आती है, ऐसे कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से :

परन्तु उस दशा में, जिसमें कुल आय में लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित है, आय के उस भाग के संबंध में अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

परंतु यह और कि जहां ऐसे व्यक्ति की आय आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है, अधिभार की दर पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ;

(ख) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, जो अनिवासी है, की दशा में,—

I. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, वहां ऐसे कर के सात प्रतिशत की दर से ;

II. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, दस करोड़ रुपए से अधिक है, वहां ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से,

(ग) प्रत्येक फर्म, जो अनिवासी है, की दशा में जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, वहां ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से,

(ii) इस भाग की मद 2 के उपबंधों के अनुसार, संघ के प्रयोजनों के लिए, किसी देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(क) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य और कटौती के अधीन रहते हुए, आय अथवा ऐसी आय का योग, एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ;

(ख) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य और कटौती के अधीन रहते हुए, आय अथवा ऐसी आय का योग दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

संगणित अधिभार, बढ़ा दिया जाएगा ।

भाग 3

कतिपय दशाओं में आय-कर के प्रभारण, "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय से आय-कर की कटौती और "अग्रिम कर" की संगणना के लिए दरें

उन दशाओं में, जिनमें आय-कर, प्रवृत्त दर या दरों से, आय-कर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) या उक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित किया जाना है अथवा "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय में से उक्त अधिनियम की धारा 192 के अधीन काटा जाना है या उस पर संदाय किया जाना है या उक्त अधिनियम की धारा 194त के अधीन काटा जाना है अथवा जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की संगणना की जानी है, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" [आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115त्रख या धारा 115जग या अध्याय 12चक या अध्याय 12चख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के अधीन, उस अध्याय या धारा में विनिर्दिष्ट दरों पर कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में "अग्रिम कर" नहीं है या धारा 115क या धारा 115कख या धारा 115कग या धारा 115कगक या धारा 115कघ या धारा 115ख या धारा 115खक या धारा 115खकक या धारा 115खकख या धारा 115खकग या धारा 115खकघ या धारा 115खकड या धारा 115खख या धारा 115खखक या धारा 115खखग या धारा 115खखड या धारा 115खखच या धारा 115खखछ या धारा 115खखज या धारा 115खखझ या धारा 115खखत्र या धारा 115ड या धारा 115जख या धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में ऐसे "अग्रिम कर" पर अधिभार नहीं है] निम्नलिखित दर या दरों से, प्रभारित किया जाएगा, काटा जाएगा या संगणित किया जाएगा :—

पैरा क

(I) इस पैरा की मद (II) और मद (III) में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यक्ति-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसे इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,—

आय-कर की दरें

- | | |
|---|---|
| (1) जहां कुल आय 2,50,000 रुपए से अधिक नहीं है | कुछ नहीं ; |
| (2) जहां कुल आय 2,50,000 रुपए से अधिक है किंतु 5,00,000 रुपए से अधिक नहीं है | उस रकम का 5 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रुपए से अधिक हो जाती है ; |
| (3) जहां कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक है किंतु 10,00,000 रुपए से अधिक नहीं है | 12,500 रुपए धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ; |
| (4) जहां कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक है | 1,12,500 रुपए धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है । |

(II) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है—

आय-कर की दरें

- | | |
|---|--|
| (1) जहां कुल आय 3,00,000 रुपए से अधिक नहीं है | कुछ नहीं ; |
| (2) जहां कुल आय 3,00,000 रुपए से अधिक है किंतु 5,00,000 रुपए से अधिक नहीं है | उस रकम का 5 प्रतिशत, जिससे कुल आय 3,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ; |
| (3) जहां कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक है किंतु 10,00,000 रुपए से अधिक नहीं है | 10,000 रुपए धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ; |
| (4) जहां कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक है | 1,10,000 रुपए धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है । |

(III) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है—

आय-कर की दरें

- | | |
|---|--|
| (1) जहां कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक नहीं है | कुछ नहीं ; |
| (2) जहां कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक है किंतु 10,00,000 रुपए से अधिक नहीं है | उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ; |
| (3) जहां कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक है | 1,00,000 रुपए धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है । |

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यक्ति-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित है) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ख) जिसकी कुल आय (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित है) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(ग) जिसकी कुल आय (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की

धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित नहीं है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

(घ) जिसकी कुल आय (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित नहीं है) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से ;

(ङ) जिसकी कुल आय (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु वह खंड (ग) और खंड (घ) के अंतर्गत नहीं आती है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से,

संगणित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु उस दशा में, जिसमें कुल आय में लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित है, आय के उस भाग के संबंध में संगणित आय-कर की रकम पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह और कि व्यक्तियों के संगम की दशा में, जो केवल कंपनियों से उसके सदस्यों के रूप में मिलकर बनी है, आय-कर की रकम पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह भी कि ऊपर उल्लिखित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय,—

(क) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, पचास लाख रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के पचास लाख रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ;

(ख) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ;

(ग) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दो करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के दो करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ; और

(घ) जिसकी कुल आय पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, पांच करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के पांच करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 10,000 रुपए से कुल आय का 10 प्रतिशत ;

अधिक नहीं है

(2) जहां कुल आय 10,000 रुपए से 1,000 रुपए धन उस रकम का 20 प्रतिशत, अधिक है किंतु 20,000 रुपए से अधिक नहीं है जिससे कुल आय 10,000 रुपए से अधिक हो जाती है ;

(3) जहां कुल आय 20,000 रुपए से 3,000 रुपए धन उस रकम का 30 प्रतिशत, अधिक है जिससे कुल आय 20,000 रुपए से अधिक हो जाती है ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसी प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,—

क. जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से ;

ख. जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से,

परिकल्पित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु प्रत्येक ऐसी सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है :

परन्तु यह और कि प्रत्येक ऐसी सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस करोड़ रुपए की कुल रकम पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के दस करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर

30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम को, ऐसी प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से संगणित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु ऊपर उल्लिखित फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर

30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से संगणित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु ऊपर उल्लिखित स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा ड

कंपनी की दशा में,—

आय-कर की दरें

I. देशी कंपनी की दशा में,—

- | | |
|---|------------------------|
| (i) जहां पूर्ववर्ष 2021-2022 में उसका कुल आवर्त या सकल प्राप्तियां चार सौ करोड़ रुपए से अधिक नहीं हैं | कुल आय का 25 प्रतिशत ; |
| (ii) मद (i) में निर्दिष्ट से भिन्न | कुल आय का 30 प्रतिशत ; |

II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,—

- | | |
|--|--------------|
| (i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,— | 50 प्रतिशत ; |
|--|--------------|

(क) उसके द्वारा 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व ; या

(ख) उसके द्वारा 29 फरवरी, 1964 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त फीस,

और जहां, ऐसा करार दोनों में से प्रत्येक दशा में, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है

- (ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो

40 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में निम्नलिखित दर से,—

(i) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

संगणित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है :

परन्तु यह और कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के दस करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

भाग 4**[धारा 2(13)(ग) देखिए]****शुद्ध कृषि-आय की संगणना के नियम**

नियम 1—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन “अन्य स्रोतों से आय” शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उस अधिनियम की धारा 57 से धारा 59 के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे :

परन्तु धारा 58 की उपधारा (2) इस उपांतरण के साथ लागू होगी कि उसमें धारा 40क के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत धारा 40क की उपधारा (3), उपधारा (3क) और उपधारा (4) के प्रति निर्देश नहीं हैं ।

नियम 2—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (ख) या उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय [जो ऐसी आय से भिन्न है, जो ऐसे भवन से व्युत्पन्न होती है, जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट भाटक या आमदनी के पाने वाले को या खेतिहर को या वस्तु रूप में भाटक के पाने वाले को निवास-गृह के रूप में आवश्यकता हो] इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और आय-कर अधिनियम की धारा 30, धारा 31, धारा 32, धारा 36, धारा 37, धारा 38, धारा 40, धारा 40क [उसकी उपधारा (3), उपधारा (3क) और उपधारा (4) से भिन्न]

धारा 41, धारा 43, धारा 43क, धारा 43ख और धारा 43ग के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे ।

नियम 3—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय, जो ऐसी आय है, जो ऐसे भवन से व्युत्पन्न होती है, जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट भाटक या आमदनी के पाने वाले को या खेतिहर को या वस्तु रूप में भाटक के पाने वाले को निवास-गृह के रूप में आवश्यकता हो, इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन “गृह-संपत्ति से आय” शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उस अधिनियम की धारा 23 से धारा 27 के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे ।

नियम 4—इन नियमों के किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, उस दशा में—

(क) जहां निर्धारिती को भारत में उसके द्वारा ऊपजाई गई और विनिर्मित चाय के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 8 के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के साठ प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ;

(ख) जहां निर्धारिती को, भारत में उसके द्वारा उगाए गए रबड़ के पौधों से उसके द्वारा विनिर्मित या प्रसंस्कृत तकनीकी रूप से विनिर्दिष्ट ब्लाक रबड़ के सेंट्रीफ्यूज लेटेक्स या सिनेक्स या क्रेप्स पर आधारित लेटेक्स (जैसे पेल लेटेक्स क्रेप) या ब्राउन क्रेप (जैसे एस्टेट ब्राउन क्रेप, रिमिल्ड क्रेप, स्माक्ड ब्लेन्केट क्रेप या फ्लेट बार्क क्रेप) के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 7क के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के पैंसठ प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ;

(ग) जहां निर्धारिती को भारत में उसके द्वारा उपजाई गई और विनिर्मित कॉफी के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 7ख के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के, यथास्थिति, साठ प्रतिशत या पचहत्तर प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ।

नियम 5—जहां निर्धारिती किसी ऐसे व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय (हिन्दू अविभक्त कुटुंब, कंपनी या फर्म से भिन्न) का सदस्य है, जिसकी पूर्ववर्ष में आय-कर अधिनियम के अधीन कर से प्रभार्य या तो कोई आय नहीं है या जिसकी कुल आय किसी व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय (हिन्दू अविभक्त कुटुंब, कंपनी या फर्म से भिन्न) की दशा में कर से प्रभार्य न होने वाली अधिकतम रकम से अधिक नहीं है किंतु जिसकी कोई कृषि-आय भी है वहां उस संगम या निकाय की कृषि-आय या हानि, इन नियमों के अनुसार संगणित की जाएगी और इस प्रकार संगणित कृषि-आय या हानि में निर्धारिती के अंश को, निर्धारिती की कृषि-आय या हानि समझा जाएगा ।

नियम 6—जहां कृषि-आय के किसी स्रोत के संबंध में पूर्ववर्ष के लिए संगणना का परिणाम हानि है, वहां ऐसी हानि, कृषि-आय के किसी अन्य स्रोत से उस पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की आय के प्रति, यदि कोई हो, मुजरा की जाएगी :

परन्तु जहां निर्धारिती किसी व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय का सदस्य है और, यथास्थिति, संगम या निकाय की कृषि-आय में निर्धारिती का अंश हानि है, वहां ऐसी हानि, कृषि-आय के किसी अन्य स्रोत से निर्धारिती की किसी आय के प्रति मुजरा नहीं की जाएगी ।

नियम 7—राज्य सरकार द्वारा कृषि-आय पर उद्गृहीत किसी कर निर्धारिती द्वारा संदेय राशि की, कृषि-आय की संगणना करने में, कटौती की जाएगी ।

दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vi) 2021 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2022 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2023 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vii) 2022 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2023 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(viii) 2023 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि,

2024 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कृषि-आय के प्रति मुजरा की जाएगी ।

(3) जहां किसी स्रोत से कृषि-आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति का, कोई अन्य व्यक्ति, विरासत से भिन्न रीति से, उसी हैसियत में उत्तराधिकारी हो गया है, वहां उपनियम (1) या उपनियम (2) की कोई बात, हानि उठाने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मुजरा कराने का हकदार नहीं बनाएगी ।

(4) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी हानि, जिसे निर्धारण अधिकारी द्वारा इन नियमों के या वित्त अधिनियम, 2015 (2015 का 20) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की पहली अनुसूची या वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का 23) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का 12) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का 6) की पहली अनुसूची में अंतर्विष्ट नियमों के उपबंधों के अधीन अवधारित नहीं किया गया है, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मुजरा नहीं की जाएगी ।

नियम 9—जहां इन नियमों के अनुसार की गई संगणना का अंतिम परिणाम हानि है, वहां इस प्रकार संगणित हानि पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और शुद्ध कृषि-आय को शून्य समझा जाएगा ।

नियम 10—आय-कर अधिनियम के निर्धारण की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध (जिनके अंतर्गत आय के पूर्णांकन से संबंधित धारा 288क के उपबंध भी हैं) आवश्यक उपांतरणों सहित, निर्धारिती की शुद्ध कृषि-आय की संगणना के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे कुल आय के निर्धारण के संबंध में लागू होते हैं ।

नियम 11—निर्धारिती की शुद्ध कृषि-आय की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, निर्धारण अधिकारी को वही शक्तियां होंगी, जो उसे कुल आय के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए आय-कर अधिनियम के अधीन हैं ।

दूसरी अनुसूची
[धारा 135(क) देखिए]

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,—

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(1) अध्याय 29 में,—

(i) टैरिफ मद 2902 50 00 के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “2.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 2903 21 00 के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “2.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(2) अध्याय 40 में, शीर्ष 4005 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “25% या 30 रु. प्रति किलोग्राम, जो भी कम हो” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(3) अध्याय 71 में,—

(i) शीर्ष 7113 और शीर्ष 7114 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, “25%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) शीर्ष 7117 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “25% या 600 रु. प्रति किलोग्राम, जो भी कम हो” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(4) अध्याय 84 में, टैरिफ मद 8414 60 00 के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “15%” प्रविष्टि रखी जाएगी;

(5) अध्याय 87 में, टैरिफ मद 8712 00 10 के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “35%” प्रविष्टि रखी जाएगी;

(6) अध्याय 95 में, शीर्ष 9503 की सभी टैरिफ मदों सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, “70%” प्रविष्टि रखी जाएगी ।

तीसरी अनुसूची [धारा 135(ख) देखिए]

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,—

(1) अध्याय 40 में, टैरिफ मद 4011 30 00 के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “2.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(2) अध्याय 71 में,—

(i) शीर्ष 7106 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “10%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 7107 00 00 के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “10%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) शीर्ष 7108 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “10%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) टैरिफ मद 7109 00 00 के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “10%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) टैरिफ मद 7110 11 00, 71101120, 71101900, 7110 21 00, 7110 29 00, 7110 41 00 और 7110 49 00 के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “10%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) टैरिफ मद 711100 00 के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “10%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) शीर्ष 7112 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “10%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) शीर्ष 7118 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “10%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(3) अध्याय 88 में, टैरिफ मद 8802 20 00, 8802 30 00 और 8802 40 00 के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “2.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(4) अध्याय 98 में,—

(क) टैरिफ मद 9801 के स्तंभ (2) में,—

(i) मद 3 के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(3) सौर विद्युत संयंत्र या सौर विद्युत परियोजना से भिन्न विद्युत परियोजना”;

(ii) मद (6) में, “ऐसी अन्य परियोजनाएं जिन्हें केंद्रीय सरकार इस निमित्त राजपत्र में देश के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए अधिसूचित करे” शब्दों के स्थान पर, “सौर विद्युत संयंत्र या सौर विद्युत परियोजना से भिन्न ऐसी अन्य परियोजनाएं जिन्हें केंद्रीय सरकार इस निमित्त राजपत्र में देश के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए अधिसूचित करे” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपशीर्ष 9801 00 के स्तंभ (2) में,—

(i) मद 3 के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(3) सौर विद्युत संयंत्र या सौर विद्युत परियोजना से भिन्न विद्युत परियोजना”;

(ii) मद (6) में, “ऐसी अन्य परियोजनाएं जिन्हें केंद्रीय सरकार इस निमित्त राजपत्र में देश के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए अधिसूचित करे” शब्दों के स्थान पर, “सौर विद्युत संयंत्र या सौर विद्युत परियोजना से भिन्न ऐसी अन्य परियोजनाएं जिन्हें केंद्रीय सरकार इस निमित्त राजपत्र में देश के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए अधिसूचित करे” शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) टैरिफ मद 9801 00 13 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“..... सौर विद्युत संयंत्र या सौर विद्युत परियोजना से भिन्न विद्युत परियोजना के लिए ”;

(घ) टैरिफ मद 9801 00 19 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“..... सौर विद्युत संयंत्र या सौर विद्युत परियोजना से भिन्न विद्युत परियोजना के लिए”।

चौथी अनुसूची

[धारा 135(ग) देखिए]

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,—

(1) साधारण स्पष्टीकारक टिप्पणों के पैरा 1 में, “जहां किसी वस्तु या वस्तुओं के समूह का वर्णन” शब्दों से आरंभ होने वाले भाग और वस्तु या वस्तु के समूह, जो “-” या “--” है। शब्दों के साथ समाप्त होता है, के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘जहां किसी वस्तु या वस्तुओं के समूह का वर्णन “----” से पहले आता है, “-” या “--” का उपवर्गीकरण होने के अतिरिक्त, उक्त वस्तु या वस्तुओं के समूह को ऐसी वस्तु या वस्तुओं के समूह से ठीक पहले के उपवर्गीकरण के रूप में भी माना जा सकेगा है, जो “---” रखता है।’;

(2) प्रयुक्त संक्षेपाक्षरों की सूची के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“प्रयुक्त संक्षेपाक्षरों की सूची

संक्षेपाक्षर	शब्द
“एसी	से अभिप्रेत है
एमपीएस	से अभिप्रेत है
एसटीएम	से अभिप्रेत है
बीक्यू	से अभिप्रेत है
बीक्यू/जी	से अभिप्रेत है
°सी	से अभिप्रेत है
सीसी	से अभिप्रेत है
सीजी	से अभिप्रेत है
सीआई/जी	से अभिप्रेत है
सीआईएफ	से अभिप्रेत है
सी/के	से अभिप्रेत है
सीएम	से अभिप्रेत है
सीएम ²	से अभिप्रेत है
सीएम ³	से अभिप्रेत है
सीएन	से अभिप्रेत है
डीसी	से अभिप्रेत है
डीवाईएनई/सीएम	से अभिप्रेत है
जी	से अभिप्रेत है
जी/सीएम ³	से अभिप्रेत है
जी/एम ²	से अभिप्रेत है
जीआई/एफएस	से अभिप्रेत है
जीवीडब्ल्यू	से अभिप्रेत है
जीवाई	से अभिप्रेत है
एचपी	से अभिप्रेत है
एचजेड	से अभिप्रेत है
आईआर	से अभिप्रेत है
	प्रत्यावर्ती धारा
	एम्पियर
	अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मैटेरियल्स
	बेक्करेल (बेक्करेल्स)
	प्रति ग्राम बेक्करेल (बेक्करेल्स)
	डिग्री सेल्सियस
	घन सेंटीमीटर
	सेंटीग्राम
	क्यूरी प्रति ग्राम
	लागत, बीमा और माल भाड़ा
	कैरेट (1 मिट्रिक कैरेट = 2×10^{-4} किलोग्राम)
	सेंटीमीटर
	वर्ग सेंटीमीटर
	घन सेंटीमीटर
	सेंटीन्यूटन
	दिष्ट धारा
	डायन प्रति सेंटीमीटर
	ग्राम
	ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर
	ग्राम प्रति वर्ग मीटर
	फिसाइल आइसोटोप का ग्राम
	सकल यान भार
	ग्रे
	अश्व शक्ति
	हर्ट्ज
	इन्फ्रा-रेड

के	से अभिप्रेत है	केल्विन
केसीएएल	से अभिप्रेत है	किलोकैलोरी
केसीएएल/ केजी	से अभिप्रेत है	किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम
केजीएफ	से अभिप्रेत है	किलोग्राम बल
केएन	से अभिप्रेत है	किलोन्यूटन
केएन/एम	से अभिप्रेत है	किलोन्यूटन प्रति मीटर
केपीए	से अभिप्रेत है	किलो पास्कल
केपीए.एम ² /जी	से अभिप्रेत है	प्रति ग्राम किलो पास्कल वर्ग मीटर
केवी	से अभिप्रेत है	किलोवोल्ट
केवीए	से अभिप्रेत है	किलोवोल्ट-एम्पियर
केवीएआर	से अभिप्रेत है	किलोवोल्ट-एम्पियर - प्रति क्रियाशील
केडब्ल्यू	से अभिप्रेत है	किलोवाट
केडब्ल्यूएच	से अभिप्रेत है	किलोवाट घंटे
एल	से अभिप्रेत है	लीटर
एम	से अभिप्रेत है	मीटर
एम-	से अभिप्रेत है	मेटा-
एम ²	से अभिप्रेत है	वर्गमीटर
एम ³	से अभिप्रेत है	घन मीटर
एम ³ /एच	से अभिप्रेत है	घनमीटर प्रतिघंटा
μसीआई	से अभिप्रेत है	माइक्रोक्यूरी
एमएम	से अभिप्रेत है	मिलीमीटर
एमएन	से अभिप्रेत है	मिलीन्यूटन
एमपीए	से अभिप्रेत है	मिलीपास्कल
एमटी	से अभिप्रेत है	मिट्रिकटन
एमडब्ल्यू	से अभिप्रेत है	मेगावाट
एन	से अभिप्रेत है	न्यूटन
एन/एम	से अभिप्रेत है	न्यूटन प्रति मीटर
एनओ.	से अभिप्रेत है	संख्या
ओ-	से अभिप्रेत है	आर्थो-
पी-	से अभिप्रेत है	पैरा-
पीए	से अभिप्रेत है	जोड़ों की संख्या
आरएडी	से अभिप्रेत है	अवशोषित विकिरण खुराक
आरएस.	से अभिप्रेत है	रूपया
एसक्यू.	से अभिप्रेत है	वर्ग
एसडब्ल्यूजी	से अभिप्रेत है	मानक वायर गेज
टी	से अभिप्रेत है	टन
टीयू	से अभिप्रेत है	हजार की संख्या में
यू	से अभिप्रेत है	संख्या
यूएस\$	से अभिप्रेत है	अमेरिकी डालर
यूवी	से अभिप्रेत है	परा-बैंगनी
वी	से अभिप्रेत है	वोल्ट

वीओएल.	से अभिप्रेत है	वाल्चूम
डब्ल्यू	से अभिप्रेत है	वाट
%	से अभिप्रेत है	प्रतिशत
x°	से अभिप्रेत है	एक्स डिग्री
1000 केडब्ल्यूएच	से अभिप्रेत है	1000 किलोवाट घंटे”;

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(3) अध्याय 3 में,—

(i) शीर्ष 0302 में,—

(क) उपशीर्ष 0302 91, टैरिफ मद 0302 91 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“0302 91 00 -- यकृत, मत्स्यांड और मत्स्यशुक्र कि.ग्रा. 30% -”;

(ख) उपशीर्ष 0302 92, टैरिफ मद 0302 92 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“0302 92 00 -- शार्क मीनपक्ष कि.ग्रा. 30% -”;

(ii) शीर्ष 0303 में, उपशीर्ष 0303 92, टैरिफ मद 0303 92 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“0303 92 00 -- शार्क मीनपक्ष कि.ग्रा. 30% -”;

(iii) शीर्ष 0307 में, टैरिफ मद 0308 4330 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“0307 43 90 --- अन्य कि.ग्रा. 30% -”;

(iv) शीर्ष 0308 में, टैरिफ मद 0308 30 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“0308 30 90 --- अन्य कि.ग्रा. 30% -”;

(4) अध्याय 4 के शीर्ष 0406 में, टैरिफ मद 0406 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“0406 10 - ताजा (अपक्व या असंसाधित) पनीर,
जिसके अंतर्गत छेना पानी पनीर और दही
है

0406 10 10 --- मोजरैला पनीर कि.ग्रा. 30% -

0406 10 90 --- अन्य कि.ग्रा. 30% -”;

(5) अध्याय 9 के शीर्ष 0910 में, टैरिफ मद 0910 99 29 से टैरिफ मद 0910 99 39 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“0910 99 29 ---- अन्य कि.ग्रा. 30% -

0910 99 30 --- भूसी कि.ग्रा. 30% -”;

(6) अध्याय 10 के शीर्ष 1008 में,—

(i) टैरिफ मद 1008 21 30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“1008 21 40	---	सांवां (एकिनोकलोवा एस्कुलेन्टा (एल.))	कि.ग्रा.	50%	-
1008 21 50	---	प्रोसो(पैनिकममिलिएसियम(एल.))	कि.ग्रा.	50%	-
1008 21 60	---	बांदा(सेटेरियाइटेल्का(एल.))	कि.ग्रा.	50%	-
1008 21 70	---	कोदो(पासपेलमस्क्रोबिकोलेटम(एल.))	कि.ग्रा.	50%	-
1008 21 80	---	कुटकी(पैनिकमसुमात्रेन्सी(एल.))	कि.ग्रा.	50%	-
	---	अन्य:			
1008 21 91	----	चौलाई(एमेरेंथस(एल.))	कि.ग्रा.	50%	-
1008 21 99	----	अन्य	कि.ग्रा.	50%	-”;

(ii) टैरिफ मद 1008 29 30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“1008 29 40	---	सांवां (एकिनोकलोवा एस्कुलेन्टा (एल.))	कि.ग्रा.	50%	-
1008 29 50	---	प्रोसो (पैनिकममिलिएसियम(एल.))	कि.ग्रा.	50%	-
1008 29 60	---	बांदा (सेटेरियाइटेल्का(एल.))	कि.ग्रा.	50%	-
1008 29 70	---	कोदो (पासपेलमस्क्रोबिकोलेटम(एल.))	कि.ग्रा.	50%	-
1008 29 80	---	कुटकी (पैनिकमसुमात्रेन्सी(एल.))	कि.ग्रा.	50%	-
	---	अन्य:			
1008 29 91	----	चौलाई (एमेरेंथस(एल.))	कि.ग्रा.	50%	-
1008 29 99	----	अन्य	कि.ग्रा.	50%	-”;

(7) अध्याय 12 में, शीर्ष 1211 के उपशीर्ष 1211 90, टैरिफ मद 1211 90 11 to 1211 90 99 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“1211 90	-	अन्य :			
	---	बीज, गिरी, बीजकवच, फल, फलावरण, फल छिलका, एंडोस्पर्म, मीजोकार्प, एन्डोकार्प :			
1211 90 11	----	मुश्कदानाबीज	कि.ग्रा.	30%	-
1211 90 12	----	नक्सवोमिका, सूखे पके बीज	कि.ग्रा.	30%	-
1211 90 13	----	इसबगोलबीज (इसबगोल)	कि.ग्रा.	30%	-
1211 90 14	----	नीम बीज	कि.ग्रा.	30%	-
1211 90 15	----	जोजोबा बीज	कि.ग्रा.	30%	-
1211 90 16	----	गार्सीनिया	कि.ग्रा.	30%	-
1211 90 19	----	अन्य	कि.ग्रा.	30%	-
	---	पतियां, पत्ती की कली, वृक्षव्रण, पुष्प, पुष्पक्रम, फूल मंजरी, पुष्पकली, स्टाइल			

और स्टिग्मा, स्टेमेन और फलियां :					
1211 90 21	----	बेलाडोना पत्तियां	कि.ग्रा.	30%	-
1211 90 22	----	सेना पत्तियां और फलियां	कि.ग्रा.	30%	-
1211 90 23	----	नीम पत्तियां	कि.ग्रा.	30%	-
1211 90 24	----	जिम्नेमा	कि.ग्रा.	30%	-
1211 90 25	----	क्यूबेब	कि.ग्रा.	30%	-
1211 90 26	----	पाइरेथ्रम	कि.ग्रा.	30%	-
1211 90 29	----	अन्य	कि.ग्रा.	30%	-
	---	छाल, भूसी और छिलका :			
1211 90 31	----	कैसकारा सैग्राडा छाल	कि.ग्रा.	30%	-
1211 90 32	----	इसबगोल भूसी (इसबगोल भूसी)	कि.ग्रा.	30%	-
1211 90 33	----	कांबोज फल छिलका	कि.ग्रा.	30%	-
1211 90 34	----	अशोक (सैरेका असोका.)	कि.ग्रा.	30%	-
1211 90 35	----	अर्जुन (टर्मिनेलिया अर्जुन)	कि.ग्रा.	30%	-
1211 90 39	----	अन्य	कि.ग्रा.	30%	-
	---	जड़ें, जड़ वृंत, बल्व, कार्न, ट्यूबर, स्टोलन और राइजोम :			
1211 90 41	----	बेलाडोना जड़ें	कि.ग्रा.	30%	-
1211 90 42	----	गलनगल राइजोम और जड़ें	कि.ग्रा.	30%	-
1211 90 43	----	इपेकाक सूखे राइजोम और जड़ें	कि.ग्रा.	30%	-
1211 90 44	----	सर्पगंधा जड़ें (राउवाल्फिया सरपेंटिना और अन्य राउवाल्फिया की अन्य प्रजातियां)	कि.ग्रा.	30%	-
1211 90 45	----	जेडोवरी जड़ें	कि.ग्रा.	30%	-
1211 90 46	----	कुथ जड़ें	कि.ग्रा.	30%	-
1211 90 47	----	सारासेपरिल्ला जड़ें	कि.ग्रा.	30%	-
1211 90 48	----	स्वीट फ्लैट राइजो	कि.ग्रा.	30%	-
1211 90 49	----	अन्य	कि.ग्रा.	30%	-
	---	पूर्ण पौधा, वायुवीयर भाग, तना, टहनी और काष्ठ :			
1211 90 51	----	चंदन चिप्स और बारीक चूर्ण	कि.ग्रा.	30%	-
1211 90 52	----	विन्का रोजिया शाक	कि.ग्रा.	30%	-
1211 90 53	----	पुदीना	कि.ग्रा.	30%	-
1211 90 54	----	अगरवुड	कि.ग्रा.	30%	-
1211 90 55	----	चिरायता	कि.ग्रा.	30%	-
1211 90 56	----	बेसिल, पाइसोप, रोजमैरी, सेज और सेवरी	कि.ग्रा.	30%	-

1211 90 57	----	अश्वगंधा (विदनिया सोम्नीफेरा)	कि.ग्रा.	30%	-
1211 90 58	----	गिलोय (टिनोस्फोराकार्डिफोलिया)	कि.ग्रा.	30%	-
1211 90 59	----	अन्य	कि.ग्रा.	30%	-
1211 90 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	30%	-";

(8) अध्याय 13 में,—

(i) अध्याय टिप्पण के खंड (छ) में, “(शीर्ष 3006)”, कोष्ठकों, शब्द और अंकों के स्थान पर, “(शीर्ष 3822)” कोष्ठक, शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ii) शीर्ष 1302 में,—

(क) टैरिफ मद 1302 32 30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“--- ग्वारगमः

1302 32 31	----	रासायनिक रूप से उपचारित	कि.ग्रा.	30%	-
1302 32 39	----	अन्य	कि.ग्रा.	30%	-";

(ख) टैरिफ मद 1302 32 40 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ग) टैरिफ मद 1302 39 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“1302 39	--	अन्य :			
1302 39 10	---	इमलीगिरीचूर्ण	कि.ग्रा.	30%	-
1302 39 20	---	कप्पा कैरागीनन	कि.ग्रा.	30%	-
1302 39 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	30%	-";

(9) अध्याय 19 में, शीर्ष में 1904, टैरिफ मद 1904 20 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“1904 20	-	न भुने गए धान्य च्यूड़े या न भुने गए धान्य च्यूड़े और भुने गए धान्य च्यूड़े या भुना हुआ अनाज के मिश्रण से अभिप्राप्त तैयार खाद्य			
1904 20 10	---	15% या अधिक वजन वाले मोटे अनाज अंतर्वस्तु के साथ	कि.ग्रा.	30%	-
1904 20 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	30%	-";

(10) अध्याय 27 में, शीर्ष 2701, टैरिफ मद 2701 12 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“2701 12	--	बिटुमनी कोयला :			
2701 12 10	---	कुकिंग कोयला	कि.ग्रा.	5%	-
2701 12 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	5%	-";

(11) अध्याय 29 में,—

(i) शीर्ष 2916 में, टैरिफ मद 2916 20 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्,

निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“2916 20 20 --- बिफैन्थ्रिन (आइएसओ) कि.ग्रा. 7.5% -”;

(ii) शीर्ष 2924 में, टैरिफ मद 2924 29 60 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“2924 29 70 --- प्रैटिलाक्लोर(आइएसओ) कि.ग्रा. 7.5% -”;

(iii) शीर्ष 2930 में,—

(क) टैरिफ मद 2930 20 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“2930 20 - थायोकार्बामेट्स और डाइथायोकार्बामेट्स :

2930 20 10 --- कैरटैप हाइड्रोक्लोराइड(आइएसओ) कि.ग्रा. 7.5% -

2930 20 90 --- अन्य कि.ग्रा. 7.5% -”;

(ख) टैरिफ मद 2930 90 91 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“2930 90 92 ---- एसीफेट(आइएसओ) कि.ग्रा. 7.5% -”;

(iv) शीर्ष 2931 में, टैरिफ मद 2931 49 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“2931 49 30 --- ग्लाइफोसेट (आइएसओ) कि.ग्रा. 7.5% -”;

(v) शीर्ष 2932 में, टैरिफ मद 2932 99 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“2932 99 20 --- एमामैक्टेनबेन्जोएट(आइएसओ) कि.ग्रा. 7.5% -”;

(vi) शीर्ष 2933 में,—

(क) टैरिफ मद 2933 29 50 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“2933 29 60 --- इमिडैक्लोप्रिड(आइएसओ) कि.ग्रा. 7.5% -”;

(ख) टैरिफ मद 2933 39 16 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“2933 39 17 ---- क्लोरैट्रैनीलिप्रोल(आइएसओ) कि.ग्रा. 7.5% -”;

(ग) टैरिफ मद 2933 39 19 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“2933 39 21 ---- एसीटैमिप्रिड(आइएसओ) कि.ग्रा. 7.5% -

2933 39 22 ---- इमाजैथापायर(आइएसओ) कि.ग्रा. 7.5% -

2933 39 29 --- अन्य कि.ग्रा. 7.5% -”;

(घ) टैरिफ मद 2933 59 40 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“2933 59 50 --- बिस्पायरीबैक-सोडियम(आइएसओ) कि.ग्रा. 10% -”;

(ङ) टैरिफ मद 2933 99 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित

अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“2933 99 20 --- कार्बोन्डाजिम(आइएसओ) कि.ग्रा. 7.5% -”;

(vii) शीर्ष 2934 में, टैरिफ मद 2934 99 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“2934 99 30 --- ब्यूप्रोफैजिन(आइएसओ) कि.ग्रा. 7.5% -”;

(viii) शीर्ष 2935 में, टैरिफ मद 2935 50 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“2935 50 - अन्य परफ्लूओरोआक्टेनसल्फोनामाइड्स:

2935 50 10 --- फ्लूबैन्डियामाइड(आइएसओ) कि.ग्रा. 7.5% -

2935 50 90 --- अन्य कि.ग्रा. 7.5% -”;

(12) अध्याय 31 में,—

(i) टिप्पण 6 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुपूरक टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“अनुपूरक टिप्पण :

(I) इस अध्याय में, भारतीय मानक ब्यूरो के किसी मानक के प्रतिनिर्देश उस मानक के अंतिम प्रकाशित संस्करण के प्रतिनिर्देश है ।

उदाहरण : आईएस 1459 से आईएस 1459: 2018 निर्दिष्ट है और आईएस 1459: 1974 नहीं ।”;

(ii) शीर्ष 3102 में, टैरिफ मद 3102 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“3102 10 - यूरिया चाहे जलीय विलयन में हो या नहीं :

3102 10 10 --- आईएस मानक 5406 के अनुरूप उर्वरक कि.ग्रा. 10% -
श्रेणी

3102 10 90 --- अन्य कि.ग्रा. 10% -”;

(13) अध्याय 38 में,—

(i) उपशीर्ष टिप्पण 4 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुपूरक टिप्पण अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“अनुपूरक टिप्पण:

1. टैरिफ मद 3808 91 41 के अंतर्गत उपशीर्ष 3808 91 के निम्नलिखित माल हैं : आईएस-12915 के अनुरूप ऐसीफेट (आइएसओ); आईएस-14159 के अनुरूप कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड (आइएसओ); आईएस-15443 के अनुरूप इमिडैक्लोप्रिड (आइएसओ); आईएस-15981 के अनुरूप एसीटैमीप्रिड (आइएसओ) ।

2. टैरिफ मद 3808 91 42 के अंतर्गत उपशीर्ष 3808 91 के 90% से अधिक वजन की अंतर्वस्तु वाले निम्नलिखित माल हैं : क्लोरैन्ट्रैनीलीप्रौल(आइएसओ); ब्यूप्रोफैजिन (आइएसओ); फ्लूबैन्डियामाइड(आइएसओ); एमामैक्टेन बेन्जोएट (आइएसओ) ।

3. टैरिफ मद 3808 91 51 के अंतर्गत उपशीर्ष 3808 91 के माल के केवल मिश्रण

और निर्मितियां हैं, जिसमें निम्नलिखित में से एक या अधिक है : आईएस-12916 के अनुरूप ऐसीफेट (आइएसओ); आईएस-14183 के अनुरूप कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड (आइएसओ); आईएस-15335 के अनुरूप इमिडैक्लोप्रिड (आइएसओ); आईएस-16328 के अनुरूप एसीटैमीप्रिड (आइएसओ) ।

4. टैरिफ मद 3808 91 52 के अंतर्गत उपशीर्ष 3808 91 के माल के 90% से अधिक वजन की अंतर्वस्तु वाले, केवल मिश्रण और निर्मितियां हैं, जिसमें निम्नलिखित में से एक या अधिक है: क्लोरैनट्रैनीलीप्रौल (आइएसओ); ब्यूप्रोफैजिन (आइएसओ); फ्लूबैन्डियामाइड (आइएसओ); एमामैक्टेन बेन्जोएट (आइएसओ) ।

5. टैरिफ मद 3808 92 60 के अंतर्गत उपशीर्ष 3808 92 के निम्नलिखित कोई माल हैं : आईएस-8445 के अनुरूप कार्बैन्डाजिम (आइएसओ) ।

6. टैरिफ मद 3808 92 70 के अंतर्गत उपशीर्ष 3808 92 के माल के केवल मिश्रण और निर्मितियां हैं जिसमें निम्नलिखित में से एक या अधिक है: आईएस-8446 के अनुरूप कार्बैन्डाजिम (आइएसओ) ।

7. टैरिफ मद 3808 93 61 के अंतर्गत उपशीर्ष 3808 93 के निम्नलिखित कोई माल हैं : आईएस-15158 के अनुरूप प्रेटिलाक्लोर (आइएसओ); आईएस-12502 के अनुरूप ग्लाइफोसेट (आइएसओ)।

8. टैरिफ मद 3808 93 62 के अंतर्गत उपशीर्ष 3808 93 वाले 90% से अधिक वजन की अंतर्वस्तु के साथ निम्नलिखित माल हैं : बिस्पायरीबैक सोडियम (आइएसओ); इमैजैथापायर (आइएसओ) ।

9. टैरिफ मद 3808 93 71 के अंतर्गत उपशीर्ष 3808 93 के जिसमें निम्नलिखित में से एक या अधिक है एक या अधिक को अंतर्विष्ट करने वाले मिश्रण और निर्मितियां हैं : आईएस-15160 के अनुरूप प्रेटिलाक्लोर (आइएसओ)।

10. टैरिफ मद 3808 93 72 के अंतर्गत उपशीर्ष 3808 93 वाले 90% से अधिक वजन की अंतर्वस्तु के साथ केवल निम्नलिखित मिश्रण और निर्मितियां हैं : बिस्पायरी बैकसोडियम (आइएसओ); इमैजैथापायर (आइएसओ) ।”

(ii) शीर्ष 3808 में,—

(क) टैरिफ मद 3808 91 37 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

	“---	इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 1 और 2 में विनिर्दिष्ट माल :		
3808 91 41	----	इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 1 में कि.ग्रा. 10% - विनिर्दिष्ट माल :		
3808 91 42	----	इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 2 में कि.ग्रा. 10% - विनिर्दिष्ट माल :		
	---	इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 3 और 4 में विनिर्दिष्ट माल :		
3808 91 51	----	इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 3 में कि.ग्रा. 10% - विनिर्दिष्ट माल :		

3808 91 52 ---- इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 4 में कि.ग्रा. 10% -";
विनिर्दिष्ट माल :

(ख) टैरिफ मद 3808 92 50 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"3808 92 60 --- इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 5 में कि.ग्रा. 10% -
विनिर्दिष्ट माल :

3808 92 70 --- इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 6 में कि.ग्रा. 10% -";
विनिर्दिष्ट माल :

(ग) टैरिफ मद 3808 93 50 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"--- इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 7 और 8
में विनिर्दिष्ट माल :

3808 93 61 ---- इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 7 में कि.ग्रा. 10% -
विनिर्दिष्ट माल :

3808 93 62 ---- इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 8 में कि.ग्रा. 10% -
विनिर्दिष्ट माल :

--- इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 9 और
10 में विनिर्दिष्ट माल :

3808 93 71 ---- इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 9 में कि.ग्रा. 10% -
विनिर्दिष्ट माल :

3808 93 72 ---- इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 10 में कि.ग्रा. 10% -";
विनिर्दिष्ट माल :

(14) अध्याय 39 में, शीर्ष 3915 में, टैरिफ मद 3915 90 75 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"3915 90 79 ---- अन्य कि.ग्रा. 7.5% -";

(15) अध्याय 48 में, शीर्ष 4811 में, टैरिफ मद 4811 90 94 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"4811 90 94 ---- जंबो रोलों में (1 मीटर और उससे ऊपर की कि.ग्रा. 10% -
चौड़ाई तथा 5000 मीटर और उससे ऊपर
की लंबाई में) थर्मल कागज

4811 90 95 ---- जंबो रोलों में (1 मीटर और उससे ऊपर की कि.ग्रा. 10% -
चौड़ाई तथा 5000 मीटर और उससे कम
की लंबाई में) थर्मल कागज

4811 90 96 ---- एक मीटर से कम की चौड़ाई में रोलों में कि.ग्रा. 10% -";
थर्मल कागज

(16) अध्याय 52 में, शीर्ष 5201 में, टैरिफ मद 5201 00 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	“---	अन्य:				
5201 00 21	----	20.0 मिमी से अनधिक स्टेपल लंबाई का	कि.ग्रा.	5%	-	
5201 00 22	----	20.0 मिमी से अधिक किंतु 24.5 मिमी से अनधिक स्टेपल लंबाई का	कि.ग्रा.	5%	-	
5201 00 23	----	24.5 मिमी से अधिक किंतु 27.0 मिमी से अनधिक स्टेपल लंबाई का	कि.ग्रा.	5%	-	
5201 00 24	----	27.0 मिमी से अधिक किंतु 32.0 मिमी से अनधिक स्टेपल लंबाई का	कि.ग्रा.	5%	-	
5201 00 25	----	32.0 मिमी से अधिक स्टेपल लंबाई का	कि.ग्रा.	5%	-”;	

(17) अध्याय 54 में, शीर्ष 5402 में,—

(i) टैरिफ मद 5402 11 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“5402 11 00	--	एरामाइड के	कि.ग्रा.	5%	-”;
-------------	----	------------	----------	----	-----

(ii) उपशीर्ष 5402 59, टैरिफ मद 5402 59 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“5402 59 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	5%	-”;
-------------	----	------	----------	----	-----

(18) अध्याय 57 में, शीर्ष 5702 में, टैरिफ मद 5702 39 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“5702 39 90	---	अन्य	वर्ग	20%	-”;
			मीटर		

(19) अध्याय 61 में, शीर्ष 6115 में, उपशीर्ष 6115 21 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“- अन्य पैंटी होज और टाइट्स :”;

(20) अध्याय 62 में,—

(i) शीर्ष 6213 में,—

(क) उपशीर्ष 6213 90 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“- अन्य टैक्सटाइल सामग्रियों के :”;

(ख) टैरिफ मद 6213 90 90 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“--- अन्य” ;

(ii) शीर्ष 6217 में,—

(क) टैरिफ मद 6217 10 10 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“--- सूत के वस्त्रों की वस्तुओं के लिए”;

(ख) टैरिफ मद 6217 10 20 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“--- कृत्रिम फाइबर के वस्त्रों की वस्तुओं के लिए”;

(ग) टैरिफ मद 6217 10 30 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“--- ऊन के वस्त्रों की वस्तुओं के लिए”;

(घ) टैरिफ मद 6217 10 40 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“--- रेशम के वस्त्रों की वस्तुओं के लिए”;

(ङ) टैरिफ मद 6217 10 50 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“--- पुनः जनित फाइबर के वस्त्रों की वस्तुओं के लिए”;

(च) टैरिफ मद 6217 10 60 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“--- अन्य फाइबर के वस्त्रों की वस्तुओं के लिए”;

(छ) टैरिफ मद 6217 10 70 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“--- सूत की स्टार्किंग, जुराबें, साकेट और वैसी ही वस्तुएं”;

(21) अध्याय 63 में,—

(i) शीर्ष 6301 में, टैरिफ मद 6301 20 00 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“- ऊन या सूक्ष्म प्राणी रोम के कंबल (विद्युत कंबलों से भिन्न) और यात्रा रग”;

(ii) शीर्ष 6304 में, टैरिफ मद 6304 20 00 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“- इस अध्याय के उपशीर्ष के टिप्पण 1 में विनिर्दिष्ट बेड नेट”;

(iii) शीर्ष 6310 में, टैरिफ मद 6310 10 90 से 6310 90 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“6310 10 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	20%	-
6310 90	-	अन्य:			
6310 90 10	---	उनी रग	कि.ग्रा.	20%	-”;

(22) अध्याय 69 में,—

(i) टिप्पण 1 के आरंभिक भाग में, “आकार देने” शब्दों के स्थान पर “आकार देने” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) शीर्ष 6907 में, उपशीर्ष 6907 30, टैरिफ मद 6907 30 10, उपशीर्ष 6907 40, टैरिफ मद 6907 40 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“6907 30 00	-	उपशीर्ष 6907 40 में से भिन्न मोजाइक व.मी.	15%	-
		क्यूबों और वैसी ही वस्तुएं		
6907 40 00	-	चीनी मिट्टी के उत्पादों का परिष्करण	व.मी.	15% -”;

(23) अध्याय 71 में,—

(i) उपशीर्ष टिप्पण 3 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुपूरक टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“अनुपूरक टिप्पण :

शीर्ष 7104 के प्रयोजनों के लिए, “हीरक” से,—

(क) रसायनिक रूप से उत्पादित ऐसे रत्न अभिप्रेत हैं, जिनमें आवश्यक रूप से वही रसायनिक संयोजन और क्रिस्टल संरचना है जैसी कि विशिष्ट प्राकृतिक हीरक में होती है। इन्हें विभिन्न पद्धतियों का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है, जिनके अंतर्गत उच्च दाब, उच्च ताप पद्धति (एचपीएचटी) और रसायनिक वाष्प निक्षेप पद्धति (सीबीडी) भी है ; या

(ख) विभिन्न साधनों द्वारा कृत्रिम रूप से प्राप्त रत्न अर्थात् संपीड़ित करके, दाब करया (प्रायिकतः धमन पाइप की सहायता से) प्राकृतिक हीरकों के ऐसे टुकड़ों के साथ संगलित करके, जिन्हें साधारणतया चूर्ण के रूप में बनाया गया है।”;

(ii) शीर्ष 7104 में,—

(क) टैरिफ मद 7104 21 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“7104 21	--	हीरक :		
7104 21 10	---	औद्योगिक	सी/के	10% -
7104 21 20	---	गैर-औद्योगिक	सी/के	10% -”;

(ख) टैरिफ मद 7104 91 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“7104 91	--	हीरक :		
7104 91 10	---	औद्योगिक	सी/के	10% -
7104 91 20	---	गैर-औद्योगिक	सी/के	10% -”;

(iii) शीर्ष 7105 में, टैरिफ मद 7105 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“7105 10	-	हीरक का:		
7105 10 10	---	शीर्ष 7102 का	सी/के	10% -

7105 10 20 --- शीर्ष 7104 का सी/के 10% -”;

(iv) शीर्ष 7113 में,—

(क) टैरिफ मद 7113 11 20 और 7113 11 30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“--- अन्य आभूषण :

7113 11 41	----	बिना जड़ा हुआ	कि.ग्रा.	25%	-
7113 11 42	----	मोती जड़ित	कि.ग्रा.	25%	-
7113 11 43	----	शीर्ष 7102 के हीरक जड़ित	कि.ग्रा.	25%	-
7113 11 44	----	शीर्ष 7104 के हीरक जड़ित	कि.ग्रा.	25%	-
7113 11 45	----	अन्य बहुमूल्य और अर्ध बहुमूल्य रत्न जड़ित	कि.ग्रा.	25%	-
7113 11 49	----	अन्य	कि.ग्रा.	25%	-”;

(ख) टैरिफ मद 7113 19 10 से 7113 19 50 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“--- स्वर्ण का :

7113 19 11	----	बिना जड़ा हुआ	कि.ग्रा.	25%	-
7113 19 12	----	मोती जड़ित	कि.ग्रा.	25%	-
7113 19 13	----	शीर्ष 7102 के हीरक जड़ित	कि.ग्रा.	25%	-
7113 19 14	----	शीर्ष 7104 के हीरक जड़ित	कि.ग्रा.	25%	-
7113 19 15	----	अन्य बहुमूल्य और अर्ध बहुमूल्य रत्न जड़ित	कि.ग्रा.	25%	-
7113 19 19	----	अन्य	कि.ग्रा.	25%	-

--- प्लेटिनम का :

7113 19 21	----	बिना जड़ा हुआ	कि.ग्रा.	25%	-
7113 19 22	----	मोती जड़ित	कि.ग्रा.	25%	-
7113 19 23	----	शीर्ष 7102 के हीरक जड़ित	कि.ग्रा.	25%	-
7113 19 24	----	शीर्ष 7104 के हीरक जड़ित	कि.ग्रा.	25%	-
7113 19 25	----	अन्य बहुमूल्य और अर्ध बहुमूल्य रत्न जड़ित	कि.ग्रा.	25%	-
7113 19 29	----	अन्य	कि.ग्रा.	25%	-”;

(24) अध्याय 84 में,—

(i) शीर्ष 8414 में, टैरिफ मद 8414 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“8414 10 - निर्वात पम्प :

8414 10 10	---	जिनकी अधिकतम प्रभाव दर 5 एम ³ /एच इ (मानक तापमान (273 के (0 °से)) और	7.5%	-
------------	-----	---	------	---

दाब (101.3 केपीए) दशा) के अधीन

8414 10 90	---	अन्य	इ	7.5%	-";
------------	-----	------	---	------	-----

(ii) शीर्ष 8419 में,—

(क) टैरिफ मद 8419 50 10 से 8419 50 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“--- 0.15 मी² से अधिक और 20 मी² से कम
के ताप अंतरण सतह क्षेत्र सहित :

8419 50 11	----	शेल और ट्यूब प्रकार के	इ	7.5%	-
8419 50 12	----	प्लेट प्रकार के	इ	7.5%	-
8419 50 13	----	स्पाइरल प्रकार के	इ	7.5%	-
8419 50 19	----	अन्य	इ	7.5%	-
	---	अन्य :			
8419 50 91	----	शेल और ट्यूब प्रकार के	इ	7.5%	-
8419 50 92	----	प्लेट प्रकार के	इ	7.5%	-
8419 50 93	----	स्पाइरल प्रकार के	इ	7.5%	-
8419 50 99	----	अन्य	इ	7.5%	-";

(ख) टैरिफ मद 8419 89 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“--- दाब वाले बर्तन, रिएक्टर्स, कालम्स या
टावर्स या रासायनिक भंडारण टैंक :

8419 89 11	----	दाब जलयान	इ	10%	-
8419 89 12	----	0.1 मी ³ (100 ली) से अधिक और 20 मी ³ (20000 ली) से कम के कुल आंतरिक (ज्यामिति) आयतन वाले रिएक्टर्स	इ	10%	-
8419 89 13	----	अन्य रिएक्टर्स	इ	10%	-
8419 89 14	----	0.1 मी से अधिक आंतरिक अर्ध व्यास के आसवन या अवशोधन कालम	इ	10%	-
8419 89 15	----	अन्य आसवन या अवशोधन कालम	इ	10%	-
8419 89 16	----	0.1 मी ³ (100 ली) से अधिक कुल आंतरिक (ज्यामिति) आयतन वाले रासायनिक भंडारण टैंक	इ	10%	-
8419 89 17	----	अन्य रासायनिक भंडारण टैंक	इ	10%	-
8419 89 19	----	अन्य	इ	10%	-";

(25) अध्याय 85 में,—

(i) शीर्ष 8517 में,—

(क) टैरिफ मद 8517 62 30 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“--- वायरलाइन टेलीफोनी आधारित
एक्सडीएसएल के लिए मोडेम (मोडुलेटर-
डिमोडुलेटर)”;

(ख) टैरिफ मद 8517 62 40 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ग) टैरिफ मद 8517 62 70 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“--- पीडीएच आधारित वायरलाइन टेलीफोनी के
लिए बहुसंकेतक, सांख्यिकीय बहुसंकेतक”;

(घ) उपशीर्ष 8517 69 में,—

(अ) टैरिफ मद 8517 69 50 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(आ) टैरिफ मद 8517 69 60 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“--- वायरलाइन टेलीफोनी के लिए इंटरनेट तक
पहुंच प्राप्त करने हेतु सेट टाप बाक्स”;

(ii) शीर्ष 8524, टैरिफ मद 8524 11 00 से टैरिफ मद 8524 99 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“8524	फ्लैट पैनल डिसप्ले मोड्यूल, जिनमें चाहे टच-सेन्सटिव स्क्रीन समाविष्ट हैं या नहीं				
	-	ड्राइवर या नियंत्रण परिपथ रहित :			
8524 11	--	तरल क्रिस्टल के:			
8524 11 10	---	उपशीर्ष 8471 30 या 8471 41 के माल के लिए	इ	15%	-
8524 11 20	---	उपशीर्ष 8517 13 या 8517 14 के माल के लिए	इ	15%	-
8524 11 30	---	उपशीर्ष 8528 72 या 8528 73 के माल के लिए	इ	15%	-
8524 11 90	---	अन्य	इ	15%	-
8524 12	--	कार्बनिक प्रकाश-उत्सर्जक डायोड (ओएलईडी) :			
8524 12 10	---	उपशीर्ष 8471 30 या 8471 41 के माल के लिए	इ	15%	-
8524 12 20	---	उपशीर्ष 8517 13 या 8517 14 के माल के लिए	इ	15%	-
8524 12 30	---	उपशीर्ष 8528 72 या 8528 73 के माल के लिए	इ	15%	-
8524 12 90	---	अन्य	इ	15%	-

8524 19	--	अन्य :					
8524 19 10	---	उपशीर्ष 8471 30 या 8471 41 के माल के लिए	इ	15%	-		
8524 19 20	---	उपशीर्ष 8517 13 या 8517 14 के माल के लिए	इ	15%	-		
8524 19 30	---	उपशीर्ष 8528 72 या 8528 73 के माल के लिए	इ	15%	-		
8524 19 90	---	अन्य	इ	15%	-		
	-	अन्य :					
8524 91	--	तरल क्रिस्टल के :					
8524 91 10	---	उपशीर्ष 8471 30 या 8471 41 के माल के लिए	इ	15%	-		
8524 91 20	---	उपशीर्ष 8517 13 या 8517 14 के माल के लिए	इ	15%	-		
8524 91 30	---	उपशीर्ष 8528 72 या 8528 73 के माल के लिए	इ	15%	-		
8524 91 90	---	अन्य	इ	15%	-		
8524 92	--	कार्बनिक प्रकाश-उत्सर्जक डायोड (ओएलईडी):					
8524 92 10	---	उपशीर्ष 8471 30 या 8471 41 के माल के लिए	इ	15%	-		
8524 92 20	---	उपशीर्ष 8517 13 या 8517 14 के माल के लिए	इ	15%	-		
8524 92 30	---	उपशीर्ष 8528 72 या 8528 73 के माल के लिए	इ	15%	-		
8524 92 90	---	अन्य	इ	15%	-		
8524 99	--	अन्य :					
8524 99 10	---	उपशीर्ष 8471 30 या 8471 41 के माल के लिए	इ	15%	-		
8524 99 20	---	उपशीर्ष 8517 13 या 8517 14 के माल के लिए	इ	15%	-		
8524 99 30	---	उपशीर्ष 8528 72 या 8528 73 के माल के लिए	इ	15%	-		
8524 99 90	---	अन्य	इ	15%	-";		
(26) अध्याय 87 में, शीर्ष 8704 में, टैरिफ मद 8704 10 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—							
"8704 10 90	---	अन्य	इ	40%	-";		

पांचवी अनुसूची

[धारा 136 देखिए]

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची में, क्रम संख्यांक 8 और 9 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

क्र. सं.	अध्याय/शीर्ष/उप शीर्ष/टैरिफ मद	माल का विवरण	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
“8.	“1202 41	मूंगफली कवचयुक्त	1,125 रुपए प्रति टन
9.	1202 42	मूंगफली गिरी	1,500 रुपए प्रति टन”।

छठवीं अनुसूची**(धारा 171 देखिए)**

वित्त अधिनियम, 2001 की सातवीं अनुसूची में,—

- (i) टैरिफ मद 2402 20 10 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “230 रु. प्रति हजार” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (ii) टैरिफ मद 2402 20 20 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “290 रु. प्रति हजार” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (iii) टैरिफ मद 2402 20 30 और 2402 20 40 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “510 रु. प्रति हजार” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (iv) टैरिफ मद 2402 20 50 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “630 रु. प्रति हजार” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (v) टैरिफ मद 2402 20 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “850 रु. प्रति हजार” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (vi) टैरिफ मद 2402 90 10 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “690 रु. प्रति हजार” प्रविष्टि रखी जाएगी ।

“सातवीं अनुसूची

[धारा 135(घ) देखिए]

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के अध्याय 90 में,—

(i) टैरिफ मद 9022 14 10 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “15%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 9022 14 20 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “15%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) टैरिफ मद 9022 14 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “15%” प्रविष्टि रखी जाएगी ।”।

डॉ० राजीव मणि,
सचिव, भारत सरकार